

भारत में मुद्रा और बैंकिंग का विकास

भारत में मुद्रा और बैंकिंग का विकास

लेखक

डा० अवधविहारी मिश्र

एम० ए०, पी-एच० डी०, डा० लिट्

अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय

हिन्दी समिति, सूचना विभाग

उत्तर प्रदेश

लखनऊ

प्रथम संस्करण

१९६३

मूल्य

चार रुपये

मुद्रक

माया प्रेस प्राइवेट लि०, इलाहाबाद

प्रकाशकीय

इस पुस्तक के लेखक डाक्टर अवध बिहारी मिश्र गोरखपुर विश्व-विद्यालय में वाणिज्यविभाग के अध्यक्ष हैं। आपने अपने विस्तृत अनुभव एवं गभीर अध्ययन के आधार पर इसकी रचना की है। भारत में मुद्रा-नीति के विकास और समय समय पर उसमें किये गये परिवर्तनों तथा सुधारों का एवं पत्र-मुद्रा के प्रचलन, सुवर्ण-मान के परित्याग आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन इसमें बड़ी सरल भाषा में किया गया है। इसमें यह भी दिखलाया गया है कि भारत में आधुनिक ढंग के बैंको की स्थापना का आरम्भ किस तरह हुआ और अनेक सकटों को झेलते हुए भी किस तरह उनकी क्रमिक उन्नति होती गयी। रिजर्व बैंक की स्थापना और अनुसूचित बैंको पर उसके नियंत्रण के परिणाम स्वरूप आजकी सुधरी हुई स्थिति की चर्चा करते हुए अन्त में आपने यह मत व्यक्त किया है कि यहाँ के प्रमुख बैंको को विदेशों में भी अधिकाधिक सख्या में अपनी शाखाएँ खोलनी चाहिए, जिससे भारत के विदेशी व्यापार की सबृद्धि में वे समुचित रूप से हिस्सा बटा सके।

हमें आशा है कि भारत में मुद्रा और बैंकिंग के विकास में दिलचस्पी लेने वाले प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को इस छोटी सी पुस्तक से यथेष्ट जानकारी प्राप्त हो जायगी और आगे चल कर यदि वह इस विषय का विशिष्ट अध्ययन करना चाहे तो इससे उसे पर्याप्त सहायता मिल सकेगी।

ठाकुरप्रसाद सिंह

सचिव, हिन्दी समिति

विषय-सूची

प्रकाशकीय	—५—
आलेख	—७—

अध्याय

१	मुद्रा का विकास	१
२	मौद्रिक मान	९
३	बैंकिंग का विकास	६०
४	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	८४
५	द्वितीय महायुद्ध के बाद बैंकिंग का विकास	१३५
६	बैंकिंग सविधान	१५७
७	विदेशी विनिमय बैंक	१६८
८	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग संस्थाएँ	१७८

आलेख

मुद्रा और बैंकिंग का इतिहास उतना पुराना है जितना समाज और सभ्यता का। सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि होती गयी और उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में तथा उनके आदान-प्रदान के माण में कठिनाइयाँ आने लगी। व्यापार की मात्रा बढ़ने पर आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की समुचित व्यवस्था आवश्यक हो गयी। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न देशों ने कई प्रकार की मुद्रा-प्रणालियाँ अपनायी, परन्तु सभी प्रकार की मुद्राएँ सोने के मूल्य पर आधारित थी और सोना ही अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का माध्यम था।

उद्योगीकरण के उपरान्त बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण आरम्भ हुआ और कच्चा तथा तैयार किया हुआ माल एक देश से दूसरे देश भेजा जाने लगा। इसके लिए मुद्रा के सचय और ऋण की आवश्यकता हुई। बैंकिंग का इतिहास उन सभी कार्यों का लेखा है जो मुद्रा के बड़ी मात्रा में सचय और ऋण की व्यवस्था के लिए अपनाये गये। उत्पादन और उपभोग की विभिन्न क्रियाओं में बैंकिंग प्रणाली बहुत सहायक सिद्ध हुई और धीरे-धीरे मुद्रा के आदान-प्रदान में बैंकिंग एक आवश्यक अंग बन गया और हमारे दैनिक जीवन की सभी आर्थिक क्रियाओं में बैंकिंग प्रणाली का प्रयोग होने लगा।

देश की आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का मुद्रा और बैंकिंग के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आर्थिक उन्नति के साथ बैंकिंग का विकास भी सम्बद्ध है और ढाँवाडोल राजनीतिक अवस्था मुद्रा और बैंकिंग के विस्तार के लिए घातक सिद्ध हुई है। भारत की वर्तमान मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप प्राप्त हुई और भारतीय मुद्रा 'रुपया' इसी समय से सारे देश की मुद्रा बन गया। देश में शान्ति

और आर्थिक उन्नति के अनुरूप मुद्रा और बैंकिंग का विकास होता गया।

इस पुस्तक का ढग इस विषय पर लिखी अन्य पुस्तको से कुछ भिन्न है। इसमे भारतीय मुद्रा और बैंकिंग के विकास का इतिहास समय-समय पर हुई देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार दिया गया है। मुद्रा के मान को स्थायी रखने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नो तथा उनके प्रभावो को भी क्रमबद्ध कर दिया गया है। आशा है, पाठक इसके द्वारा भारतीय मुद्रा और बैंकिंग के विकास पर पडे विभिन्न प्रभावो से भी अवगत हो सकेगे।

अवधविहारी मिश्र

मुद्रा का विकास

प्राचीन काल में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के आदान-प्रदान द्वारा करते थे। किंतु अपनी-अपनी वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय से मूल्यांकन में बड़ी कठिनाई होती थी। समाज और सभ्यता के विकास के साथ-साथ आवश्यकताओं की वृद्धि हुई, जिससे यह कठिनाई और बढ़ गयी। ऐसी स्थिति में वस्तु-विनिमय द्वारा प्रति दिन की रहन-सहन में बड़ी असुविधा होने लगी। साथ-ही-साथ सर्वमान्य मूल्यमापक साधन का अभाव होने के कारण विनिमय-कर्ताओं को यह सदेह रहता था कि उनको अपनी वस्तु के विनिमय से प्राप्त दूसरी वस्तु कम मूल्य की होती है। इन कठिनाइयों से समाज के आर्थिक विकास का क्षेत्र सदा सीमित और सकुचित रहता था और किसी भी वस्तु का आदान-प्रदान बड़े पैमाने पर अथवा दूर के स्थानों से नहीं हो पाता था।

इन दोषों को दूर करने के लिए आवश्यक समझा गया कि प्रयोग में आने वाली समस्त वस्तुओं के मूल्यांकन का एक ही मापदण्ड होना चाहिए। अतः विभिन्न देशों ने इस मापदण्ड के अलग-अलग ढंग अपनाये। जो वस्तु आसानी से मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मानी गयी उसका ही मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। कई वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग होने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि धातुमुद्रा ही सर्वमान्य होती है, क्योंकि किसी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग करने के लिए उसमें (१) उपयोगिता, (२) टिकाऊपन, (३) वहनीयता, (४) विभाजकता तथा (५) समानता के गुणों का होना आवश्यक है। अर्थात् मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तु की स्वतः उपयोगिता भी होनी चाहिए और वह स्वयं मूल्यवान् हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी से स्वीकार

कर ले। मुद्रा में टिकाऊपन का गुण भी बहुत आवश्यक है ताकि उसका संचय किया जा सके और वह शीघ्र नष्ट न हो। मुद्रा थोड़ी अथवा अधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकने वाली होनी चाहिए जिससे वाणिज्य तथा व्यापार में असुविधा न हो। साथ ही साथ मुद्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाटा भी जा सके जिससे उसके द्वारा कम मात्रा में भी वस्तु प्राप्त की जा सके।

भारत में मुद्रा व्यवहार के विकास की गति मन्थर रही। इस पर कई प्रकार की सस्थाओं का असर पडा। हमारी मुद्रा-प्रणाली में देशी और विदेशी ढगों का विलक्षण समन्वय पाया जाता है। अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप हमारी मुद्रा-प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ईस्ट इन्डिया कम्पनी के पहले सोने और चाँदी की मुद्राओं का स्वतन्त्र रूप में चलन था। १८वीं शताब्दी के अन्त तक देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार की सोने और चाँदी की मुद्राएँ पायी जाती थी। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग मुद्रा-प्रणाली होती थी। इस ढग में बड़ी कठिनाई होती थी। अंग्रेजी राज्य आने पर १८३५ में एक कानून द्वारा चाँदी की मुद्रा ही समस्त देश की मुद्रा घोषित कर दी गयी। यह रजत-मुद्रा पूर्ण रूप से प्रामाणिक मुद्रा थी।

उद्योग और व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति के फलस्वरूप अधिक मात्रा में मुद्रा का आदान-प्रदान आवश्यक हो गया। ऐसी परिस्थिति में, देश में साकेतिक तथा पत्र-मुद्रा का चलन प्रारम्भ हुआ। साकेतिक मुद्रा निम्न कोटि की धातुओं अथवा उनके मिश्रण से तैयार की जाती थी।

मूल्यवान् धातुओं की मुद्रा के चलन में सबसे बड़ा अवगुण यह है कि ये मुद्राएँ प्रयोग में आने पर घिस जाया करती हैं और इनका भार कम हो जाता है। अतः लोग नयी मुद्रा को अधिक प्रधानता देते हैं और घिसी मुद्रा को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इंग्लैन्ड में जब अधिक मात्रा में नयी मुद्राएँ बनने के बाद भी पुरानी घिसी हुई मुद्राएँ चलती रहीं तो सर टामस गेशम ने मुद्रा का यह नियम प्रतिपादित किया कि घिसी हुई खराब मुद्रा अच्छी नयी मुद्रा को चलन में आने से रोकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति

नयी मुद्रा को सचय के लिए लेना चाहता है और पुरानी मुद्रा देना चाहता है। यह कमी दूर करने के लिए साकेतिक मुद्रा का प्रारम्भ हुआ।

साकेतिक मुद्रा निम्न कोटि की धातुओं अथवा उनके मिश्रण से तैयार की जाने लगी। इस पर अंकित मूल्य इसकी धातु के मूल्य से कहीं अधिक होता था और सरकारी कानून द्वारा यह सर्वमान्य होती थी। हमारी वर्तमान धातु-मुद्राएँ इसी प्रकार की साकेतिक मुद्राएँ हैं।

पत्र-मुद्रा का चलन बड़े-बड़े भुगतानों को करने के लिए प्रयोग में आया। देश में बैंकों के विस्तार के फलस्वरूप पत्र-मुद्रा का चलन व्यापक हो गया। पत्र-मुद्रा का मूल्य उस पत्र पर छपे हुए मूल्य के बराबर माना जाता है और वह उस धातु की मात्रा का प्रतीक होता है जो उस पत्र-मुद्रा के बदले में प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी पत्र-मुद्रा पर दस रुपये लिखा हो तो इसका अभिप्राय यह होता है कि उस पत्र-मुद्रा के देने से दस रुपये मूल्य के बराबर की धातु अथवा अन्य वस्तु प्राप्त की जा सकती है। प्रारम्भिक अवस्था में भारत में पत्र-मुद्रा का जनता द्वारा स्वागत नहीं किया गया, परन्तु उसको मान्यता न देने वालों को सरकार द्वारा दण्ड देने का विधान होने के बाद पत्र-मुद्रा सार्वजनिक प्रयोग में आने लगी। इस प्रकार की मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित होती है।

सरकार रिजर्व बैंक के द्वारा उपयुक्त मात्रा में पत्र-मुद्रा छापकर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने में सहायता देती है। इस पत्र-मुद्रा की मात्रा आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जाती है, परन्तु प्रत्येक पत्र-मुद्रा पर छपे हुए मूल्य के बदले सोना या चादी द्वारा भुगतान करना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं समझ लेना चाहिए कि जितने मूल्य की पत्र-मुद्रा सरकार छापती है उतने मूल्य का सोना या चादी उसके पास होगा। पत्र-मुद्रा के भुगतान का सरकार पर उत्तरदायित्व जनता में पत्र-मुद्रा पर विश्वास उत्पन्न करने के लिए होता है और जितनी मात्रा में नोट छापे जाते हैं उस मूल्य का केवल एक अंश मात्र सरकारी कोष में

सोना या चाँदी के रूप में रखा जाता है, क्योंकि एक बार में बहुत कम नोट भुगतान के लिए आ सकते हैं और पत्र-मुद्रा का बहुत बड़ा भाग लेन-देन की क्रिया में लगा रहता है।

इन मुद्राओं के साथ-साथ, उद्योग और व्यापार की उन्नति से, हुण्डी अथवा साख-मुद्रा भी प्रयोग में आने लगी। साख-मुद्रा को चलाने का श्रेय बैंको को है। बैंको के विकास से उद्योग और व्यापार में बहुत सहायता मिली है। इंग्लैन्ड, अमेरिका जैसे देशों में द्रव्य सम्बन्धी लेन-देन का ९० प्रतिशत साख-मुद्रा द्वारा ही होता है। साख-मुद्रा में किसी मूल्य के निर्धारित समय पर भुगतान करने का वचन होता है। जैसे यदि कोई दूकानदार किसी उत्पादक का सामान इस शर्त पर खरीदना चाहे कि उसे बेचने के बाद वह उत्पादक को उसका मूल्य दे देगा, तो इस आशय का जो लिखित पत्र दूकानदार उत्पादक को उसकी वस्तु लेने पर देगा, यह पत्र साख-मुद्रा (Credit money) माना जायगा। इस ढंग में यह आवश्यक है कि साख-मुद्रा देने वाले का विश्वास आर्थिक दृष्टि से साख-मुद्रा पाने वाले पर होना चाहिए। जैसे कोई महाजन किसी को रुपया उधार देने से पहले यह जान लेता है कि उधार लेने वाला उन रुपयों को अवश्य लौटा सकेगा। साख-मुद्रा हुण्डी, आज्ञा-पत्र, (Order note), प्रतिज्ञा-पत्र, (Promissory note), पुस्तक-साख (Book Credit) तथा चेक इत्यादि के रूप में प्रचलित है। हुण्डियाँ तथा आज्ञा-पत्र प्रायः दूर के स्थानों पर भुगतान के लिए प्रयोग में आते हैं। परन्तु प्रतिज्ञा-पत्र वस्तुओं का मूल्य चुकाने अथवा रुपया उधार लेने के रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं। प्रतिज्ञा-पत्र में साक्षी का हस्ताक्षर आवश्यक माना जाता है। साख-पत्र द्वारा यह विनिमय के भुगतान का सबसे सरल ढंग है और दिन-प्रति-दिन के छोटे छोटे लेन-देन इसी के द्वारा होते हैं।

लेन-देन में बैंक नोट भी प्रयोग में आते हैं जो किसी देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।

प्रतिज्ञा-पत्र और बैंक नोट में केवल यह अन्तर होता है कि प्रतिज्ञा-पत्र पर सूद दिया जाता है और वह व्यक्तिगत होता है एवं उसके भुगतान

की माँग निश्चित अवधि पूर्ण होने से पहले नहीं की जा सकती। बैंक नोट पर सूद नहीं दिया जाता और किसी भी समय उसके मूल्य की कीमत मुद्रा में परिणत की जा सकती है। बैंको द्वारा इस सुविधा के फलस्वरूप चेक भुगतान का सामान्य साधन बन गया है। चेक वह लिखित आज्ञा है, जो किसी बैंक में रुपया जमा करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान के लिए बैंक के नाम देता है। चेक लिखने वाला व्यक्ति पूँजी उस बैंक में जमा कर देता है और समयानुसार चेक द्वारा भुगतान के लिए उस बैंक को लिखित आज्ञा देता है, परन्तु यह आज्ञा उसकी अधिकतम पूँजी की सीमा के अन्दर ही होती है। अनधिकारी व्यक्तियों को चेक का रुपया न मिल सके इसकी सुरक्षा के लिए प्रायः दो समानान्तर रेखाएँ चेक के आरपार खींच दी जाती हैं। ऐसी दशा में उस चेक का रुपया पाने वाले व्यक्ति के हिसाब में जमा हो जाता है जो बाद में वह अपने चेक द्वारा निकाल सकता है।

पुस्तक-साख का प्रयोग दिन-प्रति-दिन के भुगतान के कार्यों में नहीं होता है। खरीदने वाला बेचने वाले की बही अथवा पुस्तक में खरीदे हुए सामान का मूल्य लिख देता है जो एक निश्चित समय के बाद बेचने वाला बिल के रूप में भुगतान के लिए खरीदने वाले के पास भेज देता है और खरीदने वाला उसका भुगतान कर देता है।

साख-मुद्रा (Credit money) की विशेषताएँ

साख-मुद्रा से उत्पादन में बहुत सहायता मिलती है। उपयुक्त धन-राशि न होने पर भी साख-मुद्रा द्वारा उत्पादन के साधन एकत्रित हो सकते हैं और किसी सच्चे तथा मेहनती व्यापारी के लिए मुद्रा की कठिनाई सुलझ जा सकती है। साख-मुद्रा द्वारा बड़ी मात्रा में भुगतान सुविधापूर्ण और सुरक्षित होता है। साख-मुद्रा पूँजी के बढ़ाने में भी सहायक होती है। साख-मुद्रा से मूल्यवान् धातुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग कम हो जाता है और ये धातुएँ नष्ट होने से बच जाती हैं। बारहवीं शताब्दी से भारत में हुण्डी का प्रचलन माना जाता है। हुण्डी के व्यापक प्रयोग से भारत में आन्तरिक व्यापार की बहुत वृद्धि हुई। हुण्डी का लेन-देन स्वयं ही एक

व्यापार बन गया था। मुगल कालीन भारत में विभिन्न प्रकार की धातु-मुद्रा के चलन से भारतीय व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला जिससे सारे देश में द्रव्य के लेन-देन के कार्य को यथेष्ट बढ़ावा मिला। यह लेन-देन का काम सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से ही होता था। इसमें व्याज की दर सदा परिवर्तनशील होती थी और उसकी मात्रा अलग-अलग कार्य करने वालों के द्वारा ही निर्धारित होती थी।

सत्रहवीं शताब्दी में जब पश्चिमी देश वालों ने भारत से व्यापार आरम्भ किया उस समय उन्हें इन महाजनों से बहुत सहायता मिली, लेकिन उनके यहाँ की प्रथा भारतीय ढंग से भिन्न थी अतः शीघ्र ही उन्हें कई प्रकार की भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयाँ व्यापार में आने लगीं और शीघ्र लेन-देन की सुविधा के लिए उन लोगों ने भारत में पश्चिमी ढंग के बैंक की स्थापना शुरू कर दी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपना व्यापार मुख्यतः कलकत्ता और बम्बई में बनाये हुए दो कोषागारों द्वारा चालू कर दिया। इसका भारतीय महाजनों की प्रथा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में विदेशी व्यापार के विस्तार के साथ कोषागारों की प्रगति भी तेजी से हुई। धीरे-धीरे लगभग सभी बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों में इनकी शाखाएँ खुल गयीं। यातायात तथा रेलों के प्रचार से इनको और प्रोत्साहन मिला और महाजनों की प्रथा अपने क्षेत्र में सकीर्ण होती गयी।

कोषागार की सफलता से भारत में शीघ्र ही विदेशी ढंग के संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित होने लगे परन्तु इनका क्षेत्र व्यापार तक ही सीमित रहा। बड़े पैमाने पर रुपये के लेन देन की सुविधा होने के कारण इससे भारत के व्यापार की बड़ी प्रगति हुई, परन्तु छोटे पैमाने पर उद्योग तथा लगभग कृषि सम्बन्धी सभी कार्यों के लिए देशी बैंक अब भी काम में लाये जाते थे। अंग्रेजी ढंग के कलकत्ता और बम्बई में बने कोषागारों ने अपना कार्य-क्षेत्र धीरे-धीरे बड़ा व्यापक कर लिया। ये कोषागार एक प्रकार के बैंक के रूप में कार्य करने लग गये थे। इन कोषागारों से जनता और सरकार दोनों व्यापार अथवा उद्योग के लिए धन उधार ले सकती

थी। इन कोषागारों द्वारा पत्र-मुद्रा का चलन होने पर भारत में सयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना में बड़ी सहायता मिली।

समाज और उद्योग के विकसित होने पर द्रव्य की माँग बहुत बढ़ गयी और पत्र-मुद्रा तथा साख-पत्रों के चलने से मुद्रा का कई रूपों में विस्तार हो गया। अतः वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता रखने के लिए मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण रखना आवश्यक हो गया। मुद्रा का मूल्य वस्तुओं के मूल्यों के उतार-चढ़ाव का द्योतक होता है। यदि एक वस्तु का मूल्य ५० प्रतिशत घट जाय और दूसरी का ५० प्रतिशत बढ़ जाय तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि मुद्रा के मूल्य-स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मूल्य-स्तर तो इस बात पर निर्भर होगा कि बढ़े हुए दाम वाली वस्तु का घटे हुए दाम वाली वस्तु के अनुपात में कितना आदान-प्रदान हुआ और सामान्य आर्थिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ा। यदि सभी वस्तुओं का मूल्य एक ही अनुपात में घटे या बढ़े तो अवश्य मुद्रा के मूल्य में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। परन्तु सामान्यतः ऐसा नहीं हो पाता है।

वस्तुओं के मूल्य घटने और बढ़ने का द्रव्य के अर्घ पर उसी अनुपात में प्रभाव पड़ता है जिस अनुपात में मूल्य बढ़ता है, क्योंकि द्रव्य की माँग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ही होती है और वस्तु की उपयोगिता का द्रव्य की उपयोगिता पर प्रभाव पड़ता है। यदि मूल्य-स्तर बढ़ जाय तो उसी से कम वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार यदि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो द्रव्य का अर्घ घटता है। सभी वस्तुओं के मूल्यों के घटने अथवा बढ़ने का द्रव्य के अर्घ पर प्रभाव पड़ता है, अतः द्रव्य के अर्घ में स्थिरता बनाये रखना बहुत आवश्यक है। इस स्थिरता के लिए मुद्रा-पारिमाणिक कई सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रा के प्रसार से वस्तुओं के मूल्य-स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक है और मुद्रा के सकोचन से यह मूल्य-स्तर नीचा हो जाता है। जैसे, यदि मुद्रा की मात्रा दूनी हो जाय तो उतनी ही वस्तु प्राप्त करने के लिए दूना मूल्य देना पड़ेगा और यदि मुद्रा की मात्रा आधी ही होगी तो उस वस्तु के लिए मूल्य भी आधा ही देना होगा। इसी आधार पर मुद्रा का पारिमाणिक सिद्धान्त

बना। यह सिद्धान्त धातु-मुद्रा, पत्र-मुद्रा तथा साख-मुद्रा सभी पर लागू है। इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा के मूल्य को मापने के लिए उसका औसत चलन-वेग और कुल व्यवसाय की मात्रा मालूम होना आवश्यक है। तभी मुद्रा का मूल्य-स्तर मालूम किया जा सकता है। अतः द्रव्य का परिमाण \times चलन का औसत वेग = मूल्य का स्तर \times कुल व्यवसाय। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी समय देश में ५ करोड़ रुपया हो और प्रत्येक रुपये के चलन का औसत वेग दस हो, अर्थात् प्रत्येक रुपया दस बार विनिमय का कार्य करे तो उस समय $५ \times १० = ५०$ करोड़ रुपये का व्यय माना जायगा। यदि इस काल में १० करोड़ मन गेहूँ पर यह रुपया व्यय हुआ हो तो प्रति मन गेहूँ का मूल्य $५/२५$ रु० होगा। इसी आधार पर मुद्रा के अर्थ में परिवर्तन होते रहते हैं।

द्रव्य के अर्थ (value) में जल्दी-जल्दी परिवर्तन होने से देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उद्योग एवं व्यापार की प्रगति रुक जाती है, क्योंकि इस परिवर्तन से हानि और लाभ की मात्रा का ठीक अनुमान बहुत समय बाद मालूम पड़ता है। घटते-बढ़ते मूल्य-स्तर के कारण नये उद्योग भी नहीं खुल पाते हैं और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता करता है। आर्थिक उन्नति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि मुद्रा का अर्थ एक-सा बना रहे।

अध्याय २

मौद्रिक मान

मुद्रा का प्रयोग धीरे-धीरे हमारे दैनिक जीवन में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापने के काम आने लगा। अतः यह अति आवश्यक हो गया कि मुद्रा मूल्यवान् धातु की बनायी जाय जो सभी को मान्य हो। सोना अथवा चाँदी ही इस योग्य माने गये कि इनकी मुद्राएँ सर्वमान्य हो। इस प्रकार किसी देश ने एक धातु की मुद्रा प्रचलित की और किसी ने दूसरी धातु की मुद्रा का प्रयोग किया। सोने और चाँदी दोनों की मुद्राएँ प्रयोग में लायी गयीं। कहीं-कहीं दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्रित धातु की मुद्रा भी प्रयोग में आयी। बाद में पत्र-मुद्रा का प्रयोग बहुत व्यापक हो गया।

मुद्रा-पद्धति देश की आर्थिक परिस्थितियों और देश-वासियों की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। एक धातु वाली प्रणाली में एक ही धातु की प्रमुख मुद्रा देश की समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करती है। अन्य प्रकार की मुद्राएँ उसी एक मुद्रा के मूल्य से सम्बन्धित रहती हैं। एक धातुवाद में निम्नलिखित तीन विशेषताएँ होती हैं।

(१) एक ही मुद्रा देश की प्रमुख मुद्रा हो जो असीमित संख्या में प्रयोग में लायी जा सकती हो।

(२) मुद्रा की ढलाई स्वतन्त्र रूप से हो सकती हो, अर्थात् कोई भी नागरिक उस धातु से सरकारी टकसाल में मुद्रा बनवा सके।

(३) अन्य सभी प्रकार की मुद्राएँ साकेतिक मुद्राएँ मानी जायँ जिन्हें किसी भी समय प्रमुख मुद्रा में परिणित किया जा सके।

भारतवर्ष में १८९३ ई० के पूर्व देश की प्रमुख मुद्रा चाँदी का रूप था

था। रुपये की तोल १६५ ग्रेन शुद्ध चाँदी की होती थी। इसी प्रकार १९३३ से पूर्व शुद्ध सोने का डालर अमेरिका की प्रमुख मुद्रा थी।

देश की आर्थिक परिस्थितियों के कारण तथा आयात और निर्यात की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतवर्ष की मुद्रा-प्रणाली में समय समय पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और स्वर्णमान तथा रजतमान दोनों प्रकार के ढग अपनाये गये। इंग्लैन्ड से राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध रहने के कारण वहाँ की मुद्रा का हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा। कई बार तो हमारे मुद्रा-मान में महत्वपूर्ण परिवर्तन केवल इसलिए करने पड़े कि इंग्लैन्ड की मुद्रा डावाडोल स्थिति में थी। देश की विभिन्न मुद्रा-प्रणालियाँ तथा उनके परिवर्तन निम्नलिखित ढग से हुए हैं।

स्वर्णमान (Gold Standard)—स्वर्णमान में प्रचलित मुद्रा का मूल्य वास्तविक होता है। यह मान एक धातुमान का सबसे प्रसिद्ध तथा अधिक प्रचलित मान रहा है। स्वर्णमान की परिभाषा अर्थशास्त्र के अन्य शब्दों की भाँति कई प्रकार से की गयी है। निम्नलिखित विद्वानों ने इस शब्द की इस तरह की परिभाषा की है—

काल बोरन—स्वर्णमान ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक चलन की मुद्रा की मुख्य इकाई निश्चित किस्म के सोने की एक निश्चित मात्रा में बदली जा सकती है।

प्रो० राबर्टसन—स्वर्णमान वह अवस्था है जिसमें कोई देश अपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य और सोने की एक निश्चित मात्रा का मूल्य एक दूसरे के बराबर रखता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि स्वर्णमान देश की धारा-सभा द्वारा पारित किये गये अन्य नियमों की भाँति एक नियम है जिसके द्वारा मुद्रा-अधिकारी देश की मुद्रा-इकाई को सोने की निश्चित मात्रा में बराबर बदलते रहे। कभी-कभी देश की मुद्रा को एक दूसरे रूप अर्थात् परोक्ष रूप में भी सोने में बदला जा सकता है। स्वर्ण-मान के प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायित्व का उदाहरण उस समय मिलता है जब कि प्रथम महायुद्ध के पहले बैंक आफ इंग्लैन्ड की यह जिम्मेदारी

थी कि बेचने वाले से ४ २४०९ पौण्ड प्रति औंस की दर पर वह सोना खरीदे और ४ २४७७ पौण्ड प्रति औंस की दर प्रत्येक को सोना बेचे। यह प्रत्यक्ष रीति से सोना बदलने का उदाहरण है। देश की मुद्रा स्वर्ण में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी रूप में परिवर्तनशील हो, प्रत्येक दशा में इस मान के अन्तर्गत स्वर्ण मुद्रा में तथा मुद्रा स्वर्ण में बदली जा सकती है।

स्वर्णमान को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य यह है कि देश की मुद्रा की कीमत स्वर्ण में एक निश्चित मात्रा के बराबर रहे। सरकार को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नियम बनाना आवश्यक होता है। मुद्रा की प्रत्येक इकाई की कीमत का स्वर्ण से उचित अनुपात होना चाहिए, चाहे वह धातु के सिक्के के रूप में हो अथवा पत्र-मुद्रा या साख-मुद्रा के रूप में हो। स्वर्ण को किस रूप में ग्रहण किया जाय, इस बात पर भी सरकार को निश्चयात्मक रूप से विचार करना पड़ता है।

स्वर्णमान को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए सरकार को निम्न-लिखित बातों की आवश्यकता पड़ती है।

(१) अपने देश की मुद्रा-इकाई की कीमत सोने की एक निश्चित मात्रा में निर्धारित करनी पड़ती है। यह कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है—

(अ) सोने की मात्रा का उल्लेख मुद्रा-इकाई में ही कर दिया जाय, जिस का प्रमाण हमें इंग्लैण्ड में मिलता है।

(ब) सोने की टकसाली कीमत निश्चित हो। इस रीति का उदाहरण हमें अमेरिका तथा भारत द्वारा प्राप्त होता है। भारत-सरकार ने २१ रु० ७ आना १० पाई बराबर एक तोले सोने की कीमत निश्चित की थी तथा अमेरिका ने ३५ डालर बराबर १ औंस सोने की सरकारी अथवा टकसाली कीमत निश्चित की थी।

(२) मुद्रा-अधिकारी को इस बात का प्रबन्ध करना पड़ता है कि असीमित मात्रा में एक निश्चित दर पर सोना बिके।

(३) जितना भी सोना निर्धारित दर पर बिकने के लिए आता है उसे मुद्रा-अधिकारी को क्रय करना चाहिए।

(४) सोने का व्यापार स्वतन्त्र होना चाहिए अर्थात् उसके आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध या रुकावट नहीं होनी चाहिए।

(५) देश की चालू मुद्राएँ मुख्य मुद्रा में परिवर्तनशील होनी चाहिए। इसके लिए सभी मुद्राओं की आपसी विनिमय दर निश्चित होती है।

स्वर्णमान की ऐतिहासिक विवेचना—द्विधातुमान को १९वीं शताब्दी में स्थापित करने के लिए कितने ही यत्न अवश्य किये गये, परन्तु इससे सम्बन्धित कठिनाइयों ने यह प्रयत्न सफल न होने दिया। उस समय स्वर्णमान काफी जोर पर था, क्योंकि चाँदी की कीमतों में इतना अधिक फेर-बदल होता था कि रजतमान का जीवित रहना सम्भव न था। उस समय सोना ही मूल्यमाप^१ के रूप में अधिक उपयुक्त समझा गया, क्योंकि इसके मूल्य में काफी स्थिरता थी तथा इसके कई कारण भी थे, जैसे सोने का अधिक मूल्यवान् धातु होना तथा इसके वार्षिक उत्पादन की कमी। साथ ही साथ ससार के अन्य देशों ने भी स्वर्णमान को ग्रहण करने के लिए उत्सुकता दिखायी। प्रथम महायुद्ध के पूर्व जिन देशों में स्वर्णमान प्रचलित था उन्होंने स्वर्ण-मुद्रामान^२ ग्रहण किया था। इस मान के अन्तर्गत सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं तथा सोना ही मूल्यमापक तथा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कि विदेशी विनिमय भी स्वर्ण पर ही आधारित होता है। चलार्थमुद्रा की स्वर्ण खरीदने की शक्ति की समानता के द्वारा विदेशी विनिमय दर निश्चित होती है। इसमें परिवर्तन होना भी सम्भव है, परन्तु ये परिवर्तन स्वर्ण-आयात तथा निर्यात बिन्दु तक ही सीमित होते हैं।

इसी समय स्वर्ण-विनिमय-मान^३ जो कि स्वर्ण-मान का दूसरा रूप है

- 1 Denomination
- 2 Gold currency Standard
3. Gold exchange Standard

कुछ देशों में प्रचलित था। यह पद्धति गरीब देशों द्वारा, जिनके पास सोने की कमी होती है, अपनायी जाती है। इस प्रणाली में सोने के सिक्के के उपयोग में बचत होती है, क्योंकि सोने के सिक्के का प्रचलन नहीं होता। इस मान में स्वर्ण से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक दूसरी ही नीति अपनायी जाती है, जिसमें किसी शक्तिशाली मुद्रा से, जो स्वर्ण पर आधारित होती है, देश की मुद्रा का सम्बन्ध जोड़ दिया जाता है। देशी चलन, विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण का एक कोष बनाया जाता है जो नियत दर पर विदेशी विनिमय क्रय करने तथा बेचने की सुविधा प्रदान करता है। भारतवर्ष में यह प्रणाली १९०७-८ से १९१७ तक प्रचलित थी। विश्व के अन्य देशों, जैसे हॉलैण्ड, जावा, आस्ट्रेलिया तथा हंगरी में भी यह प्रचलित थी। विदेशी ऋण का सोने में भुगतान करने का भारत सरकार का वैधानिक उत्तरदायित्व था। सरकार एक निर्धारित दर अर्थात् १ शिलिंग ४ पेन्स प्रति रुपये की दर से, रुपये को स्टर्लिंग में बदलती थी। आन्तरिक उपयोग के लिए देश में चाँदी के सिक्के का प्रामाणिक मुद्रा के रूप में प्रचलन था। स्वर्णमान बिना किसी कठिनाई के प्रथम महायुद्ध तक चलता रहा। आर्थिक परिस्थितियों में भिन्नता होते हुए भी विभिन्न देशों में मौद्रिक सहयोग था तथा आन्तरिक और विदेशी विनिमय दर स्थायी रही। परन्तु स्वर्णमान वाले देशों ने युद्ध आरम्भ होते ही कठिनाईयों का अनुभव किया तथा सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। सोने के सिक्को की निकासी बन्द हो गयी। लोग सोना इकट्ठा करने लगे। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने भी सोने के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस प्रकार स्वर्णमान के नियमों का उल्लंघन होने के कारण इस मान का लोप हो गया। स्वर्णमान वाले देशों ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कागज के नोट छापना प्रारम्भ कर दिया तथा स्वर्णकोषों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

युद्ध के बाद स्वर्णमान की स्थापना—युद्ध के अन्त के बाद कुछ देशों ने स्वर्णमान की स्थापना के लिए अधिक प्रयत्न किये। एक अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्रा सम्मेलन ब्रुसेल्स में सन् १९२० में हुआ। इस सम्मेलन ने स्वर्ण को फिर से स्थापित करने का आदेश दिया। १९१९ में सोने के आयात-निर्यात से प्रतिबन्ध हटा लिये गये थे। स्वर्णमान की स्थापना के लिए सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सन् १९२२ में एक और अर्थ-सम्मेलन हुआ जिसने यह आदेश दिया कि सभी देशों को अपने देश की मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रखनी चाहिए, जो आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक थी। पहले जैसी परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए १९२५ में फ्रांस तथा इंग्लैण्ड और १९२८ में भारत ने भी स्वर्णमान को फिर से स्थापित किया। मुद्रा-स्फीति ने भी युद्धोत्तर काल में भीषण रूप धारण कर लिया था, अतः इससे स्वर्णमान को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला।

युद्ध के उपरान्त अमेरिका ने स्वर्ण के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाकर स्वर्णमान को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उसके सामान्य मूल्य-स्तर में बहुत कम वृद्धि हुई थी। अन्य देशों के सम्मुख भी स्वर्णमान के पुनः स्थापित करने की समस्या उत्पन्न हुई। स्वीडन, नार्वे, हालैण्ड और स्विटजरलैण्ड ऐसे देशों में, जिन पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, स्वर्णमान पुनः ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इंग्लैण्ड तथा जर्मनी में पत्र-मुद्रा का निर्गमन अधिक हो गया था। इस लिए बिना सकोचन किये स्वर्ण-विनिमय-मान का ग्रहण करना कठिन था। स्पेन को छोड़कर लगभग सभी देशों ने स्वर्णमान को स्थापित किया, किन्तु शीघ्र ही कठिनाईयों ने भीषण रूप ले लिया तथा मौद्रिक सहयोग बनाये रखना कठिन हो गया। अन्य देशों का ध्येय उचित तथा अनुचित रूप से सोना प्राप्त करना था ताकि विदेशी व्यापार द्वारा उनका आर्थिक विकास हो। ऐसी भावना के जागृत होते ही १९३१ में इंग्लैण्ड तथा १९३३ में अमेरिका ने स्वर्ण-पाट-मान^१ को छोड़ दिया। इस प्रकार शीघ्र ही स्वर्णमान समाप्त हो

गया। सबसे बाद, लगभग १९३६ में फ्रान्स ने स्वर्णमान को त्याग कर इसे ससार से लुप्त कर दिया।

स्वर्णमान की समाप्ति का कारण—युद्धोत्तर काल में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं जिनकी उद्‌स्थिति में स्वर्णमान का चलन संभव न था। इसी से विश्व में पुनः स्थापित होने के बाद यह शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसके टूटने के कई कारण थे, जो निम्नलिखित हैं।

(१) सबसे पहला कारण यह कहा जा सकता है कि लगभग सभी देशों ने इसके नियमों की अवहेलना की। फ्रान्स तथा अमेरिका ने स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस प्रकार इन देशों ने सब से पहले इसके नियम का उल्लंघन किया। इंग्लैंड ने स्वर्णमान ग्रहण करने के बाद अपने देश की मुद्रा का अधिमूल्यन कर दिया, जिससे व्यापार-सन्तुलन उसके प्रतिकूल हो गया और सोना बराबर बाहर जाने लगा। इस प्रकार इंग्लैंड ने भी नियम का उल्लंघन किया। ऐसी दशा में तो इंग्लैंड को मुद्रा-संकोचन तथा अवमूल्यन करना चाहिए था परन्तु प्रतिभूतियों का ऋय करके उसने मुद्रा का मूल्य गिरने नहीं दिया, जिसका परिणाम हानिकारक हुआ। इसके विपरीत फ्रान्स ने ऐसी नीति अपनायी जिससे उसका व्यापार-सन्तुलन अनुकूल रहा और सोना बराबर आता रहा जिसका वह संचय करता गया। इस प्रकार ससार में स्वर्ण का असमान वितरण हो गया जो कि स्वयं-संचालन में बाधक था।

(२) स्वर्ण के असमान वितरण ने देशों को स्वर्णमान का परित्याग करने पर विवश कर दिया। जर्मनी तथा यूरोप के अन्य देशों में स्वर्ण की काफी कमी थी तथा फ्रान्स और अमेरिका में अधिकता। स्वर्ण की कमी के कारण स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिससे स्वयं-संचालन भग्न हो गया और स्वर्णमान टूट गया।

(३) आर्थिक राष्ट्रीयवाद का विकास—युद्ध काल में एक प्रकार से विदेशी व्यापार नहीं के बराबर था जिससे देश में उन वस्तुओं की अधिक कमी हो गयी जिनके लिए विदेशी व्यापार पर निर्भर रहना

पड़ता था। उन देशों को अधिक कष्ट हुआ जो कि कच्चे माल के लिए दूसरों पर आश्रित थे। इस कष्ट को दूर करने के लिए कितने ही देशों ने उद्योग-संरक्षण तथा अन्य कृत्रिम रीतियाँ अपनायीं। प्रशुल्कनीति, आयातों पर नियंत्रण तथा अभ्युन्नत प्रणाली ने स्वर्णमान के नियमों को तोड़ दिया।

(४) अन्य सभी देशों ने युद्धोत्तर काल में स्वर्ण-मुद्रा मान को त्याग दिया तथा स्वर्ण-विनिमय मान और और स्वर्ण-पाट मान को अपनाया, जिसमें स्वयं-संचालितता का गुण इतना अधिक नहीं पाया जाता। इस में सरकारी हस्तक्षेप की काफी आवश्यकता पड़ती थी तथा कुछ देशों ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया।

(५) बैंकिंग और साख-मुद्रा का अत्यधिक विकास हो जाने के कारण उनके नियंत्रण में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। साख-मुद्रा का नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक था परन्तु उसके उपाय सरल नहीं थे, इसलिए नियंत्रण ढीला पड़ गया। बैंक-दर, खुले बाजार की क्रिया तथा अन्य उपायों द्वारा भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई।

(६) युद्धोत्तर काल में राजनीतिक परिस्थितियाँ—जो देश युद्ध में विजयी हुए थे उन्होंने भी स्वर्णमान के परित्याग में पर्याप्त साथ दिया। उनकी नीतियाँ घातक सिद्ध हुईं। डालर की मांग अत्यधिक बढ़ने लगी, क्योंकि अमेरिका ने पराजित देशों से सन्धि करके उन्हें युद्ध-कालीन ऋण वापस करने पर विवश किया, जिससे सोना और भी अमेरिका में आने लगा। जर्मनी इन ऋणों के भार से व्याकुल हो गया और उसने घबराकर स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। युद्ध के पश्चात् ससार्ग के देशों की आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार बदली कि स्वर्णमान का अन्त हो गया।

(७) इसके पतन का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि यह मान समान परिस्थिति का दोस्त कहलाता है और विषम परिस्थिति में यह साथ नहीं देता है। यह गिरे हुए देश को और गिरा देता है, इसलिए इसको त्याग दिया गया।

(८) शरणार्थी पूँजी का आतक—बहुत दिनों से यह प्रथा चली आ रही थी कि विदेशों के छोटे-छोटे अल्पकालीन कोषों में बहुत से देश अपनी पूँजी जमा करते थे। परन्तु युद्धकाल में लगभग सभी देशों ने ऐसी पूँजी पर रोक लगा दी, व्याज ही नहीं, उन्होंने मूलधन तक वापस करना बन्द कर दिया। परिणाम यह हुआ कि ऐसी पूँजी सुरक्षा की खोज में मारी-मारी फिरने लगी।

(९) स्वर्णमान वाले देश को दूसरे स्वर्णमान वाले देशों की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात् वह उनका दास बन जाता है। यदि किसी भी कारण से एक स्वर्णमान वाले देश की आर्थिक परिस्थितियों में कोई भारी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अन्य स्वर्णमान देशों पर भी पड़ता है। स्वर्णमान आधी के समान है जो कि स्वर्णमान देशों को वृक्ष की भाँति झकझोर कर रख देता है। यदि एक देश में कीमते बढ़ती हैं तो उस देश में आयात अधिक बढ़ जाता है तथा अन्य स्वर्णमान देश में भी वस्तु और सेवाओं की माग बढ़ने लगती है। स्वर्णमान ग्रहण करने वाले देशों को तो इसकी आपत्तियों तथा गलतियों का फल मिलता ही है, साथ ही दूसरे देश भी बिना इससे प्रभावित हुए नहीं रह सकते। क्या स्वर्णमान फिर से स्थापित किया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए यह आवश्यक है कि उन सब आवश्यकताओं का अध्ययन कर लिया जाय जिन पर यह मान आधारित है। यह निम्नोक्त परिस्थितियाँ चाहता है। •

(१) इस मान की सफलता के लिए ससार में स्वर्ण पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए तथा उसका असमान वितरण नहीं होना चाहिए।

(२) स्वर्णमान की सफलता इस बात पर भी निर्भर है कि ससार के अधिकतर देश इसको अपनायें, तभी इसके संचालन में सफलता हो सकती है।

(३) स्वर्णमान वाले देशों को इसके नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

(४) व्यापार स्वतन्त्र होना चाहिए, इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए ।

(५) देश की मौद्रिक प्रणाली में लोच होनी चाहिए ।

(६) समस्त स्वर्णमान देशों में राजनीतिक सहयोग तथा शान्ति होनी चाहिए ।

इस मान के अन्तर्गत इतनी शर्तें हैं कि इनका ससार में पाया जाना संभव नहीं है, जिससे इसकी स्थापना में काफी कठिनाई है । कीन्ज तथा कैसल का विचार है कि भविष्य में स्वर्णमान की स्थापना लगभग असंभव है, क्योंकि मूल्य की अस्थिरता के कारण स्वर्ण ने मौद्रिक क्षेत्रों में अपना महत्व खो दिया है । इस लिए भविष्य में निश्चित-पत्र-मुद्रा-मान ही सम्भव है ।

क्राउथर का विचार है कि स्वार्थी व्यापारिक प्रणाली के सहारे चल कर किसी भी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राप्रणाली, चाहे वह राष्ट्र के हित में ही क्यों नहीं हो, सफल नहीं हो सकती । आजकल ससार में निजी स्वार्थ इतना जोर पकड़ता जा रहा है कि स्वर्णमान की सफलता सम्भव नहीं है । स्वर्णमान पर विचार करने का मुख्य कारण यह है कि पत्र-मुद्रा प्रणाली में अधिक निकासी से जनता का विश्वास कम रहता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कठिनाई होती है ।

ब्रेटेन-वूड्स में एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-परिषद् की बैठक जुलाई सन् १९४४ में हुई थी । इस परिषद् ने स्वर्णमान टूट जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो गड़बड़ी हो गयी थी उसको समाप्त करने के लिए विचार किया । परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास-बैंक की स्थापना पर जोर देकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-सहयोग की नीति स्वीकार की थी । इसको कार्यान्वित भी किया गया । स्वर्ण की कीमत के अन्तिम मान के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय दरों का आधार माना गया, परन्तु स्वर्णमान की स्थापना नहीं हुई । स्वर्णमान की स्थापना की आशा उस समय तक नहीं की जा सकती है जब तक स्वर्ण का समान वितरण तथा स्वर्णमान-

देशो मे सहयोग न हो और मुद्रा-स्फीति की नीति न छोड़ी जाय । इसके अतिरिक्त धनवान् देशो को स्वर्ण-नीति मे अधिक मात्रा मे परिवर्तन करना पड़ेगा ।

स्वर्णमान के रूप—स्वर्णमान को वैसे तो चार रूप दिये गये हैं परन्तु इन चार रूपो मे से तीन तो प्रचलित है, चौथा केवल नाम मात्र का है, इसके प्रचलन का उदाहरण भी किसी देश मे नहीं मिलता । अर्थशास्त्रियो का विचार था कि भविष्य मे ऐसी सम्भावना हो सकती है जब कि चौथे प्रकार का स्वर्णमान ग्रहण करना पड़े । ये चार रूप निम्न लिखित है ।

- १ स्वर्ण-मुद्रा-मान (पृ० १९)
- २ स्वर्ण-पाट-मान (पृ० २३)
- ३ स्वर्ण-विनिमय-मान (पृ० २७)
- ४ स्वर्ण-निधि-मान (पृ० ३१)

इनमे से प्रत्येक का अलग अलग अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है । इनका वर्णन निम्न पक्तियो मे किया गया है ।

१ स्वर्णमुद्रा-मान (Gold currency standard)

स्वर्णमान का यह सबसे अधिक विख्यात मान है । इसको लेखको ने कई सजाए दी है, जैसे स्वर्ण-प्रचलन-मान, स्वर्ण-टकन-मान तथा स्वर्णमान (मुख्य) । बडे देशो, जैसे अमेरिका, इंग्लैन्ड, फ्रान्स, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशो मे यह मान प्रथम महायुद्ध के पूर्व प्रचलित था । यद्यपि इसके बाद भी यह मान प्रचलित था परन्तु युद्ध के समय इसका प्रचलन नही के बराबर था । इस मान की निम्नलिखित विशेषताए है ।

(१) एक निश्चित मात्रा मे स्वर्ण की मुद्रा-इकाई की कीमत निर्धारित की जाती है ।

(२) स्वर्ण-मुद्रा भुगतान के लिए असीमित विधि ग्राह्य होती है ।

(३) सोने की ढलाई स्वतन्त्र होती है ।

(४) देश के अन्तर्गत स्वर्ण-मुद्रा का चलन होता है तथा गौण और पत्र-मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है ।

(५) देश में प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का चलन होता है । सभी प्रकार की साख-मुद्रा कीमत के अनुसार सोने में बदली जाती है ।

(६) स्वर्णनिधि पर देश में चलन की मात्रा अवलम्बित होती है । इस में घटबढ़ के कारण चलन की मात्रा में कमी या वृद्धि होती है ।

(७) सोने के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं होता ।

इन विशेषताओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस मान के अन्तर्गत गुणों का भण्डार है । जैसा कि इसकी एक विशेषता से पता चलता है, देश में चलन की मात्रा स्वर्णनिधि पर आधारित होती है । इससे मुद्रा तथा साख की उत्पत्ति पर नियंत्रण रहता है । केन्द्रीय सत्ता द्वारा व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण नहीं किया जाता । इसे प्राकृतिक शक्तियों की स्वयं-संचालकता पर स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता है । देश में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी यह मान नियंत्रण का कार्य करता है । लगभग सभी देशों को भुगतान के लिए पर्याप्त मात्रा में सोना आसानी से प्राप्त हो जाता है । लगभग सभी स्वर्णमान देशों की विनिमय दर में परिवर्तन केवल आयात और निर्यात क्रय तक ही संकुचित रहते हैं । स्वर्ण-कोषों में आयात-निर्यात द्वारा जो विनिमय दर का परिवर्तन होता है वह अपने आप संतुलित हो जाता है । प्रथम महायुद्ध के काल में प्रत्येक देश को युद्ध के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता प्रतीत होती थी, जिसे पूरा करने के लिए कागज के नोट छापना आरम्भ किया गया । पर इस प्रकार स्वर्णमान बनाये रखना कठिन था । यदि कागज के नोट न छापे जाते तो बिना स्वर्णकोष में वृद्धि किये मुद्रा प्राप्त करना कठिन था और युद्ध के समय सोना आता कहाँ से । इसलिए विवश होकर स्वर्ण-मुद्रा-मान को त्यागना पड़ा । यूरोप के देशों ने इसे फिर से ग्रहण किया परन्तु सफल नहीं हुए ।

स्वर्ण-मुद्रा-मान के लाभ तथा हानि—इस मान के पक्ष में बहुत से तर्क रखे गये हैं तथा इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं।

पहले हम इसके लाभों पर विचार करते हैं। ये निम्नलिखित हैं—

(१) मुद्रा-प्रणाली की स्वयं-संचालितता—इस मान का महत्वपूर्ण लाभ स्वयं-संचालितता है। इस मान के संचालन के लिए सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। प्रो० कैनन ने तो इस मान को मूर्ख-सिद्ध तथा मक्कार-सिद्ध कहा है।

यदि किसी देश की मुद्रा-संचालन प्रणाली में कोई गलती होती है तथा वह किसी दूसरे देश को अपनी आर्थिक परिस्थिति के बारे में धोखा देना चाहता है तो उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति में स्वयं सुधार हो जाता है। सरकार को केवल कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं और इन नियमों का पालन करने से स्वर्ण-चलन-मान अपने आप चलता रहता है। सोने के आयात-निर्यात से प्रतिबन्ध हटा लिये जाते हैं तथा स्वर्ण-कोष के परिवर्तन के कारण मुद्रा में परिवर्तन होता है। इसकी स्वयं-संचालितता प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है।

(२) विश्वास—इस मान में विश्वास न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इसका बाह्य तथा आन्तरिक मूल्य दोनों बराबर होते हैं। यदि मुद्रा का मूल्य समाप्त भी हो जाय तो स्वर्ण के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। पत्र-मुद्रा प्रणाली में यह गुण नहीं पाया जाता। क्योंकि विमुद्रीकरण होने पर कुछ भी मूल्य शेष नहीं रह जाता है। स्वर्ण-कोष पर मुद्रा की मात्रा निर्भर होती है, इसलिए अधिक निकासी का भी भय नहीं रहता तथा जनता का विश्वास बना रहता है।

(३) देश में कीमत-स्तर की स्थिरता—इस मान के पक्ष में सब से अधिक महत्वपूर्ण तर्क यही रखा जाता है कि इसके द्वारा देश में कीमत का स्तर स्थिर रहता है। स्वर्ण का मूल्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है इस लिए क्रय-शक्ति में परिवर्तन होने की संभावना कम होती है तथा आर्थिक साम्य भी भग नहीं होता। आर्थिक जीवन

को किसी प्रकार का धक्का नहीं लगता। अन्य वस्तुओं की भांति स्वर्ण-कीमत-स्तर में परिवर्तन बहुत कम होता है।

(४) विदेशी विनिमय दर की स्थिरता—यदि विदेशी व्यापार में अस्थिरता की संभावना होती है तो विदेशी व्यापार उन्नति नहीं करता। वह देश भी उन्नति नहीं करता जो विदेशी विनिमय पर ही आश्रित है। विनिमय वाले देश की परिस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण उस समय मिलता है जब कि प्रथम महायुद्ध के बाद स्वर्णमान के त्यागने पर विदेशी व्यापार में काफी कमी हुई थी। यह भी स्वर्णमान का महत्वपूर्ण लाभ है जिसे अब सब स्वीकार करते हैं।

हानि—ऐसा कहा जाता है कि ऊपर बताये गये इसके सभी लाभ कल्पना मात्र है तथा व्यावहारिक जीवन में इसके दोष ही दृष्टिगोचर होते हैं जो निम्नलिखित हैं—

(क) स्वर्ण-मुद्रा-मान में लोच का अभाव है। युद्ध तथा सकट के समय चलन की मात्रा बढ़ाने के लिए स्वर्ण-कोष को भी बढ़ाना पड़ता है। युद्ध के समय स्वर्ण का प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए स्वर्ण-मान से देश के सम्मुख सकट की स्थिति आ जाती है और इससे निकलने का एक मात्र उपाय यही बचता है कि देश सकटकालीन समय के लिए स्वर्ण-चलन-मान को समाप्त कर दे। इसलिए इसको कुछ विद्वानों ने अनुकूल परिस्थिति का मित्र कहा है।

(ख) कीमतों की स्थिरता काल्पनिक है। कुछ विद्वानों ने यह तर्क रखा है कि मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर रखने का उपाय स्वयं कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। सोने की कीमत के प्रत्येक परिवर्तन से कीमत-स्तर में भी परिवर्तन होता है, जिससे इस नीति को अपनाना अंधेरे में छलांग लगाने के बराबर है। सोने की कीमत में कई कारणों से परिवर्तन की सम्भावना रहती है, जैसे नयी खानों का पता लगना तथा खानों का समाप्त होना।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव। स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वयं-

संचालितता का गुण पाया जाता है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सभी देशों द्वारा इसके नियमों का पालन करने पर ही संभव है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ऐसा अनुभव किया गया था कि कोई भी देश इसके नियमों का पालन नहीं करता। किसी देश में यदि सोने पर प्रतिबन्ध था तो मुद्रा की मात्रा में स्वर्ण-कोष की मात्रा के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ था, जिससे स्वयं-संचालितता का गुण समाप्त हो जाता है। युद्ध के समय स्वर्ण का असमान वितरण हो गया था। अनेक देशों को तो स्वर्ण की कमी के कारण इस मान को त्यागना पड़ा तथा कुछ देशों में स्वर्ण की अधिकता के कारण मुद्रा-प्रसार हो गया।

(घ) कुछ विद्वानों का कहना है कि कीमत तथा विदेशी विनिमय में स्थिरता के लिए स्वर्णमान का होना आवश्यक नहीं है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष बिना स्वर्णमान के ही आवश्यक कार्य कर रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कीमतों की स्थिरता सदा लाभदायक नहीं है। इसमें कुछ अंशों तक फेर-बदल होना चाहिए। कुछ विद्वान् इसके स्थान पर एक यह उपाय बताते हैं कि कीमत-स्तर में स्थिरता रहे तथा विदेशी विनिमय-दर में भारी परिवर्तन न होने पाये, इसके लिए स्वर्णमान की अपेक्षा प्रतिबन्धित मुद्रा-प्रणाली अधिक लाभदायक है।

२ स्वर्ण-पाट-मान (Gold Bullion standard)

इस मान को स्वर्ण-धातु-मान भी कहा जाता है। इसे प्रथम महायुद्ध के बाद ही अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों ने ग्रहण किया था। यह स्वर्ण-मुद्रा-मान से मिलता-जुलता है या यों कहिए कि यह उसका दूसरा रूप है। स्वर्णमान युद्ध के समय छोड़ना पड़ा था क्योंकि चलन को बढ़ाने के लिए स्वर्ण-कोष अधिक नहीं था, इसलिए इसके नियमों का पालन करना कठिन हो गया। युद्ध के समय चलन का अधिक विस्तार हुआ परन्तु इसको आधार (आड) प्रदान करने के लिए सोना अधिक नहीं था तथा यह भी भय था कि यदि मुद्रा की मात्रा में कमी की जाय तो मुद्रा-

सकोच न हो जाय। स्वर्ण को पुनः स्थापित करना भी अभीष्ट था, परन्तु एक परिवर्तित रूप में। इसलिए स्वर्ण-पाट-मान का जन्म हुआ, क्योंकि इसमें स्वर्ण-कोष की अधिक आवश्यकता नहीं थी। अन्य मानों की भांति इसकी भी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(१) इस स्वर्णमान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता। उसके स्थान पर छोटे सिक्के तथा कागज के नोट प्रचलन में होते हैं जिनकी कीमत स्वर्ण में निर्धारित रहती है।

(२) स्वर्ण की ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती।

(३) कागजी मुद्रा के पीछे शत-प्रति-शत निधि नहीं होती है। यह निधि प्रायः ३० प्रतिशत या ४० प्रतिशत होती है। परन्तु सरकार यह वचन देती है कि वह कागज के सभी नोटों को स्वर्ण में बदल देगी। शत-प्रति-शत कोष इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी व्यक्ति एक साथ स्वर्ण में 'रूपये' को बदलने के लिए नहीं लायेंगे। थोड़ा-सा आधार होने के कारण जनता का विश्वास भी बना रहता है।

(४) एक निश्चित कीमत पर सरकार सोना क्रय करने तथा बेचने का प्रबन्ध करती है जिसकी परिवर्तन-दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सैद्धान्तिक रूप में सरकार असीमित मात्रा में सोना बेचने को कहती है किन्तु बार-बार बेचने से जो कठिनाई उत्पन्न होती है उससे बेचने के लिए एक निश्चित मात्रा नियत कर दी जाती है, जैसे भारत में ४० तोला तथा इंग्लैण्ड में ४०० औंस थी।

(५) सरकार एक स्वर्ण-कोष रखती है जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि विदेशी भुगतानों के लिए पर्याप्त मात्रा में सोना जनता प्राप्त कर सके।

इस मान की विशेषताओं को देखने से पता चलता है कि इसमें सोने के सिक्कों का चलन नहीं होता है तथा इनके स्थान पर निम्न कोटि की धातविक मुद्रा तथा कागज के नोट चलन में होते हैं, जिनको एक निश्चित दर पर सोने में बदलने की गारन्टी दी जाती है। भारत ने इस मान को

१९२७ में अपनाया। भारत सरकार ने देश की मुद्रा को २१ रुपया ७ आना १० पाई प्रति तोला सोने की दर से ४० ४० तोले के सिक्को में बदलने की गारन्टी दी थी। १९३१ में भारत ने इंग्लैन्ड के स्वर्णमान परित्याग करने पर इसे छोड़ दिया। भारत इंग्लैन्ड का बराबर अनुकरण करता रहा, पर धीरे-धीरे सभी देशों ने इसका परित्याग कर दिया। लगभग १९३६ के बाद यह मान ससार से उठ गया।

स्वर्ण-पाट-मान के लाभ—स्वर्ण-पाट-मान स्वर्ण-चलन-मान का एक परिवर्तित रूप है इसलिए इसको कुछ विद्वानों ने स्वर्ण-चलन-मान से अच्छा बताया है। इसमें स्वर्ण के सिक्को का प्रचलन नहीं होता है। इसके और भी लाभ हैं, जैसे स्वर्ण के सिक्को के मुद्रण की बचत, चलन में सोना घिसता नहीं है तथा सोने के उपयोग में बचत होती है।

इस प्रणाली के अन्तर्गत लोच की प्रचुरता होती है क्योंकि चलन और सुरक्षित कोष के बीच के अनुपात में केवल परिवर्तन करके तथा बिना सोना प्राप्त किये हुए मुद्रा की मात्रा बढ़ायी जा सकती है। इस प्रणाली को सभी देश अपना सकते हैं, क्योंकि थोड़े से स्वर्णकोष के द्वारा इस स्वर्ण-मान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सोना छोटे-छोटे व्यक्तियों के पास रहने के स्थान पर सरकारी कोषागार में रहता है, इसलिए और भी उपयुक्त माना जाता है। सोने के सिक्को के चलन में रहने से कोई विशेष लाभ नहीं रहता। साधारण परिस्थिति में लोग कागजी मुद्रा तथा धातु के छोटे सिक्को को लेना अधिक पसन्द करते हैं। केवल असाधारण परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न होती है जो भी बहुत कम आती है। सोने का एक निश्चित प्रतिशत आड में रहने के कारण जनता का विश्वास भी बना रहता है तथा स्वर्ण के राजकीय कोष में रहने के कारण सार्वजनिक लाभों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है।

इस दृष्टि से भी स्वर्ण-पाट-मान अधिक उपयुक्त है कि स्वर्ण-निधि मुद्रा-संचालक के पास रहती है इसलिए विनिमय दर की स्थिरता बनाये रखने के लिए वह अधिक लाभदायक होती है। यदि स्वर्णमान के नियमों का भली भाँति पालन किया जाय तो सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता

नहीं पड़ती। जिस समय मुद्रा की माँग कम होती है तो लोग सोना खरीदते हैं तथा स्वर्ण-कोष में कमी आ जाती है और मुद्रा की मात्रा कम हो जाने के कारण इसकी पूर्ति उसकी माँग के बराबर हो जाती है। सोना लोग उस समय बेचना आरम्भ कर देते हैं जब कि मुद्रा की माँग अधिक होती है। इससे स्वर्ण-कोष में वृद्धि होती है और चलन बढ़ जाने के कारण पूर्ति में बराबर सन्तुलन होता रहता है। विनिमय दर भी स्थिर रहती है। स्वर्ण-चलन-मान की भाँति स्वर्ण-पाट-मान में भी स्वयं-संचालितता का गुण पाया जाता है।

दोष—स्वर्ण-चलन-मान के परित्याग के बाद इसी मान को अधिक उपयुक्त समझा गया, क्योंकि इसमें सोने की इतनी अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं पड़ती है। परन्तु यह मान भी दोष-रहित नहीं है। इस मान के निम्नलिखित प्रमुख दोष हैं।

(१) इस मुद्रा-मान में स्वर्ण-चलन-मान की तुलना में विश्वास कम रहता है। स्वर्ण-चलन-मान में सोने के सिक्कों का चलन होता है परन्तु इसमें कागजी मुद्रा तथा निम्नकोटि मुद्राओं का चलन होता है, जो कि स्वर्ण में परिवर्तनशील अवश्य होती है परन्तु जनता का उतना अधिक विश्वास उनमें नहीं होता।

(२) इस मान को सकट काल तथा अन्य असाधारण परिस्थिति में बर्नाये रखना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव-सा हो जाता है। इस प्रकार यह मान भी स्वर्ण-चलन-मान की भाँति अनुकूल परिस्थितियों में ही साथ देता है।

(३) धोखे तथा भूल की सम्भावना अधिक रहती है क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है।

(४) सुरक्षित कोष में सोना बेकार पड़ा रहता है तथा मुद्रा और साख-नियंत्रण पर व्यय अधिक करना पड़ता है, इसलिए यह प्रणाली अधिक व्ययपूर्ण है।

(५) स्वर्ण-विनिमय-मान इस मान की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है तथा उसमें कम स्वर्ण-भंडार से भी काम चलाया जा सकता है।

३ स्वर्ण-विनिमय-मान (Gold Exchange standard)

यह मान भी प्रथम महायुद्ध के बाद ही अपनाया गया था। भारत तथा अन्य देशों में इस प्रकार का स्वर्णमान लगभग २०वीं शताब्दी में ही अपनाया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत देश के चलन को किसी ऐसे देश के चलन में परिवर्तित कराने का विश्वास दिलाया जाता है जो कि स्वर्ण में परिवर्तनशील होता है, अर्थात् मुद्रा-अधिकारी का यह उत्तर-दायित्व नहीं होता कि चलन की मुद्रा को स्वर्ण में बदले। इस प्रकार स्वर्ण-विनिमय-मान में स्वर्ण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता बल्कि देश की मुद्रा को एक ऐसे देश की मुद्रा से, एक निश्चित दर पर, सम्बन्धित किया जाता है जो कि स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। इस तरह देश की मुद्रा को परोक्ष रूप से स्वर्ण में बदला जा सकता है। देश की सरकार स्वयं मुद्रा को स्वर्ण में नहीं बदलती बल्कि विदेशी मुद्रा में बदलती है जिसको बेचकर विदेशी केन्द्रीय बैंक से सोना प्राप्त किया जा सकता है। यह मान निर्धन देशों द्वारा ग्रहण किया जाता है। देश की सरकार नियत विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की माँग पूरी करती है। कुछ देशों ने देश के भीतर स्वर्ण-कोष बिल्कुल ही नहीं रखे थे। उन्हें अपनी समस्त स्वर्ण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों के स्वर्ण-कोषों पर निर्भर रहना पड़ता था। कुछ देशों ने अपने सुरक्षित कोष विदेशी मुद्रा तथा विदेशी विनिमय-पत्र के रूप में विदेशों में रखे थे। इस प्रकार स्वर्ण-विनिमय-मान हमारे समक्ष दो रूपों में आता है परन्तु दूसरा रूप केवल नाम मात्र का है। कुछ विद्वान् तो इसको स्वर्ण-विनिमय-मान मानने से सहमत ही नहीं हैं। इस प्रणाली को भारत सरकार ने सन् १९०० में अपनाया था। भारतीय रुपये की विनिमय-दर १ शिलिंग ४ पेन्स थी तथा इसका सम्बन्ध ब्रिटिश पाउण्ड से था। सन् १९१४ में भारत सरकार को इस मान को बनाये रखने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। किसी प्रकार यह मान १९१७ तक सफलतापूर्वक चलता रहा। १९१७ से १९२० तक स्वर्ण-विनिमय मान को स्थगित कर दिया गया था। सन् १९२० में भारत सरकार ने २ शिलिंग पर इस मान को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया परन्तु

सफलता प्राप्त नहीं हुई। चाँदी की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव ही भारत में स्वर्ण-विनिमय मान के सफल न होने का प्रमुख कारण था।

स्वर्ण-विनिमय-मान की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) देश में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है और न तो प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का और न परिवर्तनशील मुद्रा का ही। केवल अपरिवर्तन-शील मुद्रा का चलन होता है। निम्न धातुओं के सिक्के तथा साकेतिक मुद्रा भी चलन में होती हैं।

(२) देश की प्रामाणिक मुद्रा का एक निश्चित दर पर किसी ऐसे देश की मुद्रा से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है जो कि स्वर्ण-चलन-मान तथा स्वर्ण-पाट-मान को अपनाये रहता है अर्थात् जिसकी मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तन-शील होती है। इस प्रकार देश की मुद्रा का स्वर्ण से परोक्ष रूप में सम्बन्ध होता है।

(३) व्यावहारिक रूप में सोना केवल विदेशी भुगतान के लिए दिया जाता है। वह भी विदेशी विनिमय के रूप में। परन्तु सैद्धान्तिक रूप में सरकार देश की पत्र-मुद्रा को एक निश्चित दर पर सोने अथवा विदेशी विनिमय में बदलने की जिम्मेदारी लेती है।

(४) सोने का प्रयोग मूल्यमान तथा विनिमय मान माध्यम के रूप में नहीं होता परन्तु कीमत-स्तर परोक्ष रूप से स्वर्ण द्वारा ही निश्चित होता है।

(५) विदेशों में भुगतान सोने अथवा किसी स्वीकृत विदेशी मुद्रा के रूप में लिये जाते हैं।

स्वर्ण-विनिमय-मान के लाभ—(१) यह मान बहुत ही मितव्ययी माना जाता है। क्योंकि इसमें सोने का आयात-निर्यात नहीं होता, इसलिए इसके खर्चे बच जाते हैं। इसमें पैकिंग, ऋय, यातायात तथा बीमा के व्यय सभी बच जाते हैं क्योंकि सोना न तो बाहर जाता है और न बाहर से आता है। सोना सुरक्षित कोषों में बेकार नहीं पड़ा रहता वरन् इसका अन्य उचित स्थानों पर प्रयोग होता है। सोने का सिक्का प्रचलन

मे नहीं होता, इसलिए घिसावट द्वारा भी नुकसान होने का भय नहीं रहता है।

(२) निर्धन देश भी इस मान को ग्रहण करके स्वर्णमान का लाभ प्राप्त कर सकता है। सोने की मात्रा का अधिक होना आवश्यक नहीं है। किसी शक्तिशाली देश के साथ, जिसने स्वर्णमान ग्रहण किया है, एक निश्चित दर पर सम्बन्ध स्थापित करके तथा उस पर नियंत्रण करके विनिमय-दर में स्थिरता लायी जा सकती है। परन्तु इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी मुद्रा का चुनाव सावधानी से किया जाय ताकि विदेशी भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(३) देश की सरकार विदेशी विनिमय खरीदने तथा बेचने की दरों में अन्तर रखकर लाभ कमा सकती है। देशी सरकार को केवल विदेशी विनिमय दर की स्थिरता पर ध्यान देना पड़ता है, स्वर्णमान संचालन सम्बन्धी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। विदेशों में जो निक्षेप रखे जाते हैं उनको विनियोजित कर दिया जाता है तथा इससे मिलने वाला व्याज भी लाभ का एक साधन है।

स्वर्ण-विनिमय-मान के दोष—यह प्रणाली मितव्ययी तो अवश्य होती है परन्तु सदा यह भय बना रहता है कि सोने की सीमित मात्रा स्वर्णमान के सभी कार्यों को भली भाँति चला सकेगी या नहीं। इसके अतिरिक्त इस मान की सबसे बड़ी कमी यह है कि एक सुरक्षित कोष पर कितने ही देशों की मुद्राएँ आधारित होती हैं। इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं।

(१) स्वर्ण-विनिमय-मान सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विदेशों में प्रतिबन्ध की आवश्यकता पड़ती है। यह मितव्ययी तो अवश्य है परन्तु सकटकालीन परिस्थितियों की संभावना बहुत होती है। यदि आधारित देश स्वर्णमान का परित्याग कर देता है तो उससे सम्बन्धित सभी देशों की मुद्राओं की परिवर्तनशीलता अपने आप समाप्त हो जाती है।

(२) आधार-देश के पास स्वर्णकोष तो सीमित ही होता है परन्तु

उस पर और भी सम्बन्धित देशों का अधिकार होता है जिन्होंने कि अपनी मुद्रा का सम्बन्ध उससे जोड़ा हो। इस प्रकार यह आधार-देश की मुद्रा-प्रणाली को भी असुरक्षित तथा सकटमय बना सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अन्य देशों से मुद्रा की माँग इतनी बढ़ जाय कि आधार-देश की मुद्रा-प्रणाली का संचालन करना कठिन हो जाय।

(३) स्वर्ण-मुद्रा-मान तथा स्वर्ण-पाट-मान की भांति इस मान के अन्तर्गत तरल आदयों का हस्तान्तरण उतनी सुगमता तथा सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन में बाधा पड़ती है। विभिन्न देशों के बीच यदि समुचित तथा ठीक-ठीक साधनों का वितरण होता रहे तो आन्तरिक कीमतों में स्थिरता तथा साम्य प्राप्त किया जा सकता है।

१९२५-२६ में हिल्टन यंग-आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था तथा इसने स्वर्ण-विनिमय-मान के व्यावहारिक संचालन की जाँच की थी। जाँच करने के पश्चात् निम्नलिखित दोषों को इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था।

(१) यह प्रणाली अत्यधिक सैद्धान्तिक है। साधारण जनता की समझ से बाहर है। यह बहुत ही जटिल प्रणाली है। मुद्रा-संचालक को जनता सदा शका की दृष्टि से देखती है। इस प्रणाली पर जनता का पूर्ण विश्वास प्राप्त करना कठिन है। इसकी जटिलता इसका सबसे बड़ा दोष है।

(२) स्वर्णमान के अन्य रूपों की भांति इसमें स्वयं-संचालितता का गुण नहीं पाया जाता। अधिकांशतः इसका संचालन मुद्रा की उपयोगिता पर निर्भर होता है।

(३) इस प्रणाली में तीन प्रकार के कोष रखे जाते हैं—

सुरक्षित कोष अर्थात् स्वर्णमान-कोष, पत्र-मुद्रा-कोष तथा भारत सरकार की रोकड़ भारत तथा इंग्लैन्ड दोनों देशों में रखी जाती है। इस प्रकार इस प्रणाली में कोषों की अधिकता का दोष पाया जाता है।

(४) देश में चलन का विस्तार तो सरलतापूर्वक किया जा सकता

दूसरे कोषों को वह सोना दे देता है तो अमेरिकन कोष डालर लेकर उसके बदले में इंग्लैंड के कोष को उनकी कीमत का सोना दे देगा।

एक देश के कोष से दूसरे देश के कोष में सोने का हस्तान्तरण होता रहता है, इसलिए ऐसी प्रणाली को स्वर्ण-निधि-प्रणाली के नाम से पुकारा गया है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि ब्याज की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना ही तथा देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये बिना ही विदेशी विनिमय दर का स्थायित्व प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली का एक यह भी गुण होता है कि देश के चलन में सोने की कीमत को निश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रणाली के प्रचलित रहने तक सोने के मूल्य में स्थायित्व रहा। दूसरे महायुद्ध के पूर्व तक यह प्रणाली सफलतापूर्वक चलती रही परन्तु युद्ध-काल में इसका चलना संभव न रह गया, क्योंकि इस पद्धति के जीवन-काल में सभी देशों ने इसके कार्यवहन को गुप्त रखा। इस प्रकार इस प्रणाली का अन्त हो गया।

हरशैल कमेटी^१

रजत मान प्रणाली की कठिनाइयाँ सामने आने पर भारत सरकार ने १८९२ में श्री हरशैल की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिस को निम्नलिखित बातों पर पूर्ण रूप से विचार करके अपने सुझाव प्रस्तुत करने थे।

(१) क्या भारत सरकार को चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर देना चाहिए।

(२) क्या स्वर्णमान को स्थापित करके सोने के सिक्कों का चलन किया जाय।

(३) क्या रुपये की स्टैलिंग में विनिमय दर घटा कर प्रति रुपया १ शिल्लिंग ६ पेन्स कर दी जाय। जाँच के पश्चात् समिति का यह विचार

हुआ कि भारत में स्वर्ण के सिक्को का चालू करना आवश्यक नहीं और न तो उपयुक्त ही है। स्वर्ण के सिक्को को चलाये बिना भी स्वर्णमान को ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस बात की भी संभावना है कि कहीं इसको स्थापित करने से सोने में चाँदी की कीमत और न गिर जाय। देश के व्यापार, उद्योग तथा आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण १ शिलिंग ६ पेन्स की विनिमय दर भी अनुपयुक्त बतायी गयी।

कमेटी ने इन बातों पर विचार करके भारतीय मुद्रा-प्रणाली में निम्नलिखित सुधार के लिए सुझाव भी दिये—

(१) चाँदी का स्वतन्त्र रूप से सिक्को में ढाला जाना बन्द होना चाहिए, परन्तु सरकार अपनी टकसालों में १ शिलिंग ४ पेन्स प्रति रुपये की कीमत पर चाँदी के सिक्को को ढालने का कार्य सदा करती रहेगी और यही विनिमय दर स्थायी होनी चाहिए।

(२) रुपये को असीमित रूप से विधिग्राह्य घोषित कर देना चाहिए तथा सरकारी खजानों में सभी प्रकार के लोक-दायित्व के भुगतान के लिए सोना इसी दर पर स्वीकार होना चाहिए।

कमेटी के सुझावों को कार्य रूप देने के लिए १८९३ में एक नया ऐक्ट बनाया गया और १८८२ के पत्र-मुद्रा करेन्सी ऐक्ट में कुछ संशोधन हुए। इनके परिणाम निम्नलिखित हुए।

(१) सोने और चाँदी दोनों का स्वतन्त्र टकन बन्द कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि रुपये की विदेशी विनिमय दर ऊँची बनी रहे।

(२) रुपये को साकेतिक सिक्का भी बना दिया गया क्योंकि इसके मुद्रण का अधिकार केवल सरकार को ही था। इसका अंकित मूल्य घातविक मूल्य से अधिक भी था।

(३) रुपये की विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेन्स रखी गयी। उसकी यह विनिमय दर चाँदी के मूल्य से प्रभावित नहीं होती थी।

(४) १५ रुपये की दर से सरकार को भुगतान में सावरेन (गिनी) दी जा सकती थी।

(५) कलकत्ता तथा बम्बई की टकसालो को पत्र-मुद्रा के निर्गमन का अधिकार दिया गया तथा १ शिलिंग ४ पेन्स की दर से पत्र-मुद्रा को स्वर्ण में बदलने की व्यवस्था की गयी।

इस प्रकार से हरशैल कमेटी के सुझावों पर भारत सरकार ने अपूर्ण द्विधातुमान अपनाया। केवल चाँदी के सिक्के असीमित विधिग्राह्य थे। सोने की ढलाई जनता द्वारा नहीं की जा सकती थी।

चेम्बरलेन कमीशन

पूर्ण स्वर्णमान स्थापित करने के लिए सर हेनरी फाऊलर की अध्यक्षता में फाऊलर कमेटी स्थापित की गयी। परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण स्वर्णमुद्रा मान के स्थान पर स्वर्ण-विनिमय मान ही स्थापित हुआ, जिसमें बहुत-सी त्रुटियाँ दिखाई देने लगी, इसलिए इस मौद्रिक मान की देश भर में बहुत अधिक आलोचना होने लगी। इस आलोचना के आधार पर १९१३ में श्री चेम्बरलेन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया जिसे चेम्बरलेन कमीशन^१ कहते हैं।

इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे।

(१) भारत सरकार तथा सिक्रेटरी-ऑफ-स्टेट फार इण्डिया द्वारा किये गये उपायों की जाँच करना जो कि फाऊलर कमेटी के सुझावों के आधार पर भारत में विनिमय दर स्थिर करने के लिए किये गये थे।

(२) स्वर्णमान के लिए जो सोना संचित किया जाता था उसकी जाँच करना।

(३) उस समय प्रचलित प्रणाली की जाँच करना और यह मालूम करना कि यह प्रणाली उपयोगी है कि नहीं।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चेम्बरलेन कमीशन ने निम्न-लिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

(क) इस कमीशन ने इस बात का सुझाव दिया कि भारत में स्वर्ण-

विनिमय मान को चालू रखा जाय। उसने यह भी सुझाव दिया कि देश में सोने का प्रयोग अधिक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत की जनता इसको कम चाहती है।

(ख) जब तक जनता माँग न करे उस समय तक सोने के सिक्को को ढालने के लिए देश में एक नयी टकसाल खोलने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु अगर लोग इसकी माँग करे तो ऐसी टकसाल स्थापित की जा सकती है। इसके साथ-साथ बम्बई की टकसाल को रुपया देकर बराबर सोना लेते रहना चाहिए।

(ग) स्वर्णमान के सचय की कोई भी अधिकतम सीमा निश्चित नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस सचय निधि में अधिक से अधिक सोना जमा रहना चाहिए और उसे लन्दन में जमा रखना चाहिए।

(घ) पत्र-मुद्रा-प्रणाली के अधिक-से-अधिक लोचदार होने का सुझाव दिया गया और कहा गया कि नोटों के असचित भाग को १४ करोड़ रुपये कर देना चाहिए। इस बात के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए कि लोग स्वर्ण-मुद्रा के स्थान पर सोने का अधिक उपयोग करे।

(ङ) स्वर्णमान की चाँदी शाखा को बन्द कर देना चाहिए।

(च) भारत सरकार को इस बात की गारन्टी देनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर, मुख्य रूप से विनिमय दरो के गिरने की हालत में वह १ शि० ३ पेन्स प्रति रुपये की दर पर भारत में लन्दन के बिल बेचेगी।

चेम्बरलेन कमीशन के सुझाव भारत तथा इंग्लैन्ड में फरवरी सन् १९१४ में प्रकाशित हुए, परन्तु जुलाई १९१४ में युद्ध छिड़ गया। इस कारण सरकार इस कमीशन के अधिकांश सुझावों को कार्य रूप में न ला सकी तथा व्यवसायों में भारी अनिश्चितता और अस्थिरता आ गयी। विनिमय दर के पतन से इसके परिणाम सेविंग बैंक से जमानिकालने, कागज के नोटों को रुपये के सिक्को में अथवा सोने में बदलने तथा भारत सरकार के स्वर्णकोष से सोना माँगने के रूप में प्रकट हुए। इन सब को रोकने के लिए सरकार ने बहुत से प्रयत्न किये परन्तु जब तक युद्ध रहा दशा खराब ही

होती गयी। शान्ति स्थापित होने पर सरकार ने एक दूसरी कमेटी बैठायी जिसका नाम बैंकिंगटन स्मिथ कमेटी^१ था।

इस प्रकार चेम्बरलेन कमीशन के सुझावों का यहाँ की मौद्रिक प्रणाली पर अथवा अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक सुझाव मात्र ही रह गया।

पत्र-मुद्रा प्रचलन—ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पत्र-मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ और चीन ने ही ९वीं शताब्दी में हेसेनटुंग के राज्यकाल में पत्र-मुद्रा प्रचलित की। इसके चालू करने का मुख्य ध्येय धातु की बचत था। पत्र-मुद्रा का प्रयोग लगभग १७वीं शताब्दी तक होता रहा। चीन के बाद जापान और ईरान ने भी पत्र-मुद्रा चालू की। इस प्रकार १७वीं शताब्दी के अन्तिम काल में परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा चलती रही, परन्तु १८वीं शताब्दी में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का भी चलन हुआ।

एशिया के बाद यूरोप आदि देशों में भी पत्र-मुद्रा चालू की गयी। पत्र-मुद्रा को सबसे अधिक प्रोत्साहन प्रथम महायुद्ध काल में मिला, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्णमान लगभग स्थगित कर दिया गया। उपयोगी लाभों के कारण इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और द्वितीय महायुद्ध काल में इसकी सख्या या विस्तार में बहुत वृद्धि हो गयी। आधुनिक युग में पत्र-मुद्रा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके लाभों से ससार मली भाँति परिचित है और इसमें पूर्ण विश्वास कर रहा है।

पत्र-मुद्रा के लाभ—(१) मितव्ययिता—पत्र-मुद्रा एक अत्यन्त मितव्ययी मुद्रा है। इससे धातु-प्रयोग में बचत होती है और व्यय भी कम पड़ता है। इस प्रकार चलन से बचायी गयी धातु-मुद्रा विदेशी व्यापार आदि में काम आती है।

(२) इसमें वहनीयता होती है। पत्र-मुद्रा ऐसी मुद्रा है जिसमें कागज के एक टुकड़े पर सैकड़ों रुपये सन्निहित होते हैं। इस प्रकार धातु-मुद्रा के विपरीत इसमें बहुत कम भार होता है और भेजने में कम खर्च

पडता है। व्यापारिक भुगतानों में हम पत्र-मुद्रा का ही प्रयोग करते हैं।

(३) यह एक लोचदार मुद्रा-प्रणाली है। इसी कारण यह और भी महत्वपूर्ण है। किसी भी आवश्यक समय पर इसकी मात्रा में बिना अधिक व्यय के वृद्धि की जा सकती है। यह लाभ धातविक मुद्रा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी धातु की मात्रा निश्चित है और उसकी ढलाई इत्यादि में व्यय अधिक होता है, इस कारण आवश्यकतानुसार इसमें पूर्ण रूप से घट-बढ़ नहीं की जा सकती है।

(४) पत्रमुद्रा से सरकार को लाभ होता है—इसके छापने में सरकार का उत्पादन व्यय बहुत कम होता है और नोट पर अधिकाधिक मूल्य अंकित किया जा सकता है। इस प्रकार उससे जो भी बचत होती है वह सरकार को अन्य कार्यों में व्यय करने के लिए मिल जाती है।

पत्र-मुद्रा के दोष—पत्र-मुद्रा के अनेकों लाभ होते हुए भी इसमें कई दोष भी हैं जिनसे गम्भीर हानियाँ होती हैं। पत्र-मुद्रा के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं—

(१) पत्र-मुद्रा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मुद्रा-प्रसार (मुद्रास्फीति) का डर रहता है। सरकार अपनी इच्छानुसार किसी भी संख्या में इसे छाप सकती है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी का दशा तो बहुत ही खराब हो गयी थी जिसका प्रभाव यह हुआ कि उसकी सारी अर्थ-व्यवस्था को बहुत बड़ा वक्का लगा। इसका प्रमुख कारण जर्मनी में बढ़ा हुआ मुद्रा-प्रसार ही था। भारत में ही द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् कीमते इतनी बढ़ गयीं कि उन कीमतों पर कन्ट्रोल लगाना पड़ा। इस प्रकार पत्र-मुद्रा के प्रसार से भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं।

(२) पत्र-मुद्रा में अविनाशिता नहीं है। नोटों के कटने-फटने आदि से उनके रखने वाले को हानि उठानी पड़ती है। तेल और इसी प्रकार के गहरे धब्बे पड़ जाने के कारण पत्र-मुद्रा के नम्बर की क्षति हो जाती है और वह बेकार हो जाती है।

(३) पत्र-मुद्रा एक निश्चित सीमा क्षेत्र तक ही मान्य है। पत्र-मुद्रा में एक दोष यह भी है कि यह जिस देश की सरकार द्वारा

प्रचलित है उसी देश में स्वीकार की जा सकती है। विदेशों में यह मुद्रा नहीं स्वीकार की जा सकती।

(४) पत्र-मुद्रा का वास्तविक मूल्य कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कागज और छपाई का व्यय नाम मात्र का होता है और कोई भी व्यक्ति-पत्र मुद्रा को केवल सरकार के प्रति विश्वास पर ही स्वीकार करता है।

(५) कागजी नोटों का मूल्य साधारणतया बहुत अनिश्चित और अस्थिर होता है। पत्र-मुद्रा में थोड़े समय में अधिक घट-बढ़ होने के कारण इसके मूल्य में अकस्मात् घोर उच्चावच हो सकता है। पत्र-मुद्रा के घटने-बढ़ने से विदेशी विनिमय दर पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में पत्र-मुद्रा का मूल्य बिल्कुल गिर गया था जिसके कारण जनता में बड़ा असंतोष फैला।

(६) कागजी नोटों द्वारा सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। कागजी मुद्रा और साख मुद्रा की मात्रा की अनियमितता और अनिश्चितता के कारण पूँजी-वादी देशों में व्यापारचक्रों का जन्म होता है। इसी कारण कभी-कभी पत्र-मुद्रा एक सामाजिक धोखा कहा जाता है।

पत्र-मुद्रा के उपरिलिखित गुण एवं दोषों को देखकर यह निर्णय करना है कि दोष मनुष्य के प्रयोग करने में हे या पत्र-मुद्रा में। यह बात ठीक है कि पत्र-मुद्रा का वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता, परन्तु जहाँ तक मुद्रा प्रसार और सट्टे का सवाल है यह तो सरकार के नियंत्रण से दूर हो सकता है। इस प्रकार इसके उचित नियन्त्रित उपयोग से देश को सम्पन्न किया जा सकता है।

पत्र-मुद्रा का वर्गीकरण—कागजी मुद्रा को दो बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है—पत्र-मुद्रा चलन और पत्र-मुद्रा मान।

पत्र-मुद्रा-चलन का अध्ययन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। अब हम पत्र-मुद्रा-मान का पूर्ण अध्ययन करेंगे। पत्र-मुद्रा-मान में मुद्रा का आधार पत्र हुआ करता है। देश का प्रामाणिक द्रव्य अपरिवर्तन-शील पत्र-मुद्रा होती है।

पत्र-मुद्रा-मान—पत्र-मुद्रा के ही प्रामाणिक होने के कारण सरकार या मुद्रा संचालक किसी भी प्रकार मुद्रा के बदले सोना या कोई अन्य धातु देने का जिम्मेदार नहीं है। १९२९ के महान् अवसाद के बाद ससार के बहुत से देशों ने स्वर्णमान छोड़कर पत्र-मुद्रा-मान अपना लिया। इस प्रकार पत्र-मुद्रा का विनिमय-माध्यम और अन्य सभी कार्यों में प्रयोग किया जाने लगा। इस मान की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(१) पत्र-मुद्रा देश में प्रामाणिक एवं अपरिमित विधिग्राह्य तथा अपरिवर्तनशील होती है। (२) पत्र-मुद्रा का मूल्य स्वतन्त्र रूप से निश्चित होता है। स्वर्ण या अन्य कोई धातु द्वारा उसका मूल्य नियत नहीं किया जाता। इस प्रकार इसको बदलने की कोई व्यवस्था नहीं होती। (३) पत्र-मुद्रा-मान में वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करने के लिए देश का मुद्रा-संचालक चलन के नियम और प्रबन्ध करता है। इस प्रकार इस मान में मूल्य की स्थिरता, मुद्रा की माँग और पूर्ति समान रखकर की जाती है। (४) इस मुद्रा-मान में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए सोने की आवश्यकता तो जरूर पड़ती है परन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना से ऋणों के भुगतान में सोने की आवश्यकता नहीं रही।

पत्र-मुद्रा-मान के गुण—सन् १९२९ के आर्थिक संकट से बहुत से देशों ने स्वर्णमान छोड़कर पत्र-मुद्रा मान को ग्रहण किया। भारत में १९३१ में स्वर्णमान का अन्त होने के बाद स्टर्लिंग-विनिमय मान स्थापित हुआ, भारतीय पत्र-मुद्रा ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग में परिवर्तित की जाती थी। परन्तु अब पाउंड स्वयं पत्र-मुद्रा बन गया तो भारत में भी स्वतः पत्र-मुद्रा-मान स्थापित हो गया। इस मुद्रा-प्रणाली में कुछ गुण हैं जो इस प्रकार हैं—

१ मूल्य-स्थिरता—मुद्रा-चलन अधिकारी या केन्द्रीय बैंक आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा में कमो-बेशी कर सकता है और मूल्य में स्थिरता ला सकता है। इस प्रकार मुद्रा-अधिकारी को किसी प्रकार की स्वर्णनिधि रखने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

२ मुद्रा-मान प्रणाली के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता—पत्र-मुद्रा-मान में

मुद्रा किसी धातु पर आश्रित नहीं होती, इस कारण मुद्रा-अधिकारी मुद्रा-प्रणाली के प्रबन्ध में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहता है और आवश्यकता के अनुसार प्रबन्ध करता है।

३ पत्र-मुद्रा मान में शक्तियों का पूर्ण उपयोग होता है। पत्र-मुद्रा मान के पूर्व स्वर्णमान पद्धति में मुद्रा-संकोचन की सम्भावना होती थी, जिससे देश की सन्निहित शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता था और बेरोजगारी बढ़ती थी। परन्तु पत्र-मुद्रा मान में प्रत्येक देश में मुद्रा-अधिकारी मुद्रा-नीति ऐसी रखता है कि देश में उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है और बेरोजगारी दूर हो सकती है।

पत्र-मुद्रा-मान के दोष—पत्र-मुद्रा-मान के उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त उसमें आलोचकों ने अनेक दोष भी बताये हैं। उनमें से मुख्य दोष इस प्रकार है—

१ इसमें मुद्रा-प्रसार का भय रहता है—पत्र-मुद्रा-मान में किसी भी प्रकार की निधि इसके विकास के पीछे नहीं रहती है, इसलिए इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि सकट काल में या अन्य किसी भी आवश्यकता के समय अधिकाधिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया जाय। इस प्रकार मुद्रा-स्फीति की दशा आ जाने से देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और जनता का मुद्रा में विश्वास खत्म होने लगता है।

२ पत्र-मुद्रा मान में देश की आन्तरिक कीमतों के दबाव के अनुसार विदेशी विनिमय दर पर भी प्रभाव पड़ता है। पत्र-मुद्रा-मान में विदेशी विनिमय दरों में असीमित उच्चावच हो सकता है। इसी कारण देश को विदेशी व्यापार में अनेक अड़चने उठानी पड़ती हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए विनिमय-नियंत्रण-नीति अपनायी जाती है।

३ देश की आर्थिक स्थिति का अन्य देश पर प्रभाव—पत्र-मुद्रा-मान में स्वर्णमान के अनुसार एक देश की आर्थिक स्थिति का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है। परन्तु यह उसी समय होगा जब कि अन्य पत्र-मुद्रा मान के देश अपने व्यापार में स्वतन्त्र हों—लेकिन सामान्यतया देखा जाता है कि पत्र-मुद्रा मान के देशों में विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध भी होते हैं जिससे यह दोष कुछ अधिक प्रभावपूर्ण नहीं होता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना ने ससार में पत्र-मुद्रा-मान के देशों में विदेशी पूँजी के आवागमन को आसान बना दिया है। इस आसानी के लिए द्वितीय महा-युद्ध के बाद १९४४ में ब्रैटन वुड्स कानफ्रेंस में एक योजना के अन्तर्गत इन दो संस्थाओं—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना की गयी, जिनके कई उद्देश्य हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए प्रत्येक देश के चलन का मूल्य सोने में आका जाता है और इसी आधार पर विदेशी विनिमय होता है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता लायी जाती है। विदेशी विनिमय में स्थिरता लाना, सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति में सहयोग दान करना, विदेशी पूँजी के आवागमन में सहायता देना, अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों को प्रोत्साहन देना और उनकी मात्रा बढ़ाना आदि इनके अन्य उद्देश्य हैं। इस प्रकार इस कानफ्रेंस द्वारा पत्र-मुद्रा-मान के प्रमुख दोषों को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है।

नोट निर्गमन के सिद्धान्त—पत्र-मुद्रा के गुण-अवगुण का विवेचन करने के बाद हम अब नोट विकास सिद्धान्त का अध्ययन करेंगे। नोट विकास के सम्बन्ध में दो विपरीत विचारधाराएँ हैं। दोनों के समर्थक अपनी-अपनी धारणाओं की पुष्टि करते हैं। इन सिद्धान्तों को चलन सिद्धान्त तथा बैंकिंग अथवा अधिकोषण सिद्धान्त का नाम दिया जाता है। दोनों सिद्धान्तों में आधारभूत भिन्नता है, इसलिये किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए दोनों सिद्धान्तों का भली भाँति अध्ययन जरूरी है।

(१) चलन या मुद्रा सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के मानने वालों के अनुसार कागजी मुद्रा का निर्गमन केवल बहुमूल्य धातुओं के लिए स्थाना-पन्न मुद्रा के उद्देश्य से होता है, परन्तु परिवर्तनशीलता एवं सुरक्षा की दृष्टि से १०० प्रतिशत सोने या चाँदी की आड़ या आधार होना आवश्यक है ताकि जनता जब चाहे कागजी मुद्रा के बदले सोना-चाँदी ग्रहण कर सके। इस सिद्धान्त के अनुसार स्वर्ण के आगमन या निर्गमन के अनुकूल ही मुद्रा की सख्या घटती बढ़ती रहेगी। इस प्रकार मुद्रा-अधिकारी अपनी इच्छा-

नुसार पत्र-मुद्रा की मात्रा घटा-बढ़ा नहीं सकते। अतः मुद्रा मात्रा कोष के अनुसार स्वतः घटती बढ़ती रहती है।

चलन या मुद्रा सिद्धान्त के गुण—(क) सुरक्षा—चलन सिद्धान्त के गुणों में सुरक्षा सब से अधिक महत्वपूर्ण है। चलन सिद्धान्त में १०० प्रतिशत सोने आदि के आधार पर ही मुद्रा-निकासी की जाती है। इस प्रकार इसमें सुरक्षा का गुण पाया जाता है। क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का चलनाधिक्य नहीं हो सकता।

(ख) जनता का विश्वास—चलन सिद्धान्त के अनुसार प्रचलित मुद्रा के लिए उसके मूल्य के बराबर बहुमूल्य निधि का आधार होना जरूरी है। इस प्रकार ये नोट सर्वदा परिवर्तनीय होते हैं। इसलिए इस सिद्धान्त के आधार पर निर्गमित पत्र-मुद्रा में जनता पूर्ण रूप से विश्वास करती है।

चलन सिद्धान्त के अवगुण—उपर्युक्त गुणों के होते हुए भी इस सिद्धान्त में दोष भी है, जिनको अधिकोषण सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाले बैंकिंग सिद्धान्त का आधार बनाते हैं। दोष निम्नलिखित है।

(क) लोच का अभाव—चलन सिद्धान्त के अनुसार निर्मित मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव होता है। इस अप्राप्त्यता का कारण यह है कि व्यापारिक आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ायी जा सकती, क्योंकि मुद्रा के अंकित मूल्य के बराबर ही निधि का आधार होना आवश्यक है।

(ख) उपर्युक्त दोष के आधार पर दूसरा दोष इस प्रकार है कि यह एक अमितव्ययी सिद्धान्त है, क्योंकि सोने के सिक्कों की जगह परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा निर्गमित की जाती है जिसके पीछे १०० प्रतिशत सोने आदि की आड़ होती है।

(२) बैंकिंग सिद्धान्त—यह चलन-सिद्धान्त के विपरीत है इसको कभी-कभी लोच सिद्धान्त भी कहते हैं। बैंकिंग सिद्धान्त का आधार इस बात पर है कि व्यापारिक आवश्यकताएँ जब भी बाध्य करे मुद्रा के प्रसार और सकोचन को नियमित रखा जा सके। यह लोच उसी समय हो सकती है जब कि देश में बहुत अधिक स्वर्ण हो या फिर देश में

अधिकोषण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा-निर्गमन हो। व्यावहारिक जीवन में देखा जाता है कि चलन सिद्धान्त के अनुसार १०० प्रतिशत धरोहर या निधि स्वर्ण की आड लेकर होती है। किंतु बहुत थोड़े अनुपात में जनता मुद्रा के बदले स्वर्ण लेने आती है। इसलिए यदि इस आड या आधार के स्वर्ण की मात्रा में कमी हो जाय तो भी जनता का विश्वास मुद्रा पर रहेगा। इसलिए रक्षित निधि को १०० प्रतिशत से कम कर दिया जाता है। अतः बैंकिंग सिद्धान्त यह बताता है कि पत्र-मुद्रा की निर्गमन मात्रा के बराबर सोने चाँदी की निधि नहीं रखनी चाहिए। बल्कि केन्द्रीय बैंक को इसकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह देश में यथेष्ट मुद्रा निर्गमित करे और उसके पीछे यथेच्छ निधि रखे। इस प्रकार मुद्रा-प्रणाली पूर्ण रूप से लोचदार रहेगी और साख का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा।

बैंकिंग सिद्धान्त के गुण—बैंकिंग सिद्धान्त के उपर्युक्त विवेचन से पाठक को यह अवश्य प्रतीत होगा कि चलन सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण बैंकिंग सिद्धान्त में वही गुण है जो कि चलन सिद्धान्त के अवगुण है। इसलिए अब हम बैंकिंग सिद्धान्त के गुणों की विवेचना करेंगे।

१ लोचदार पत्र-मुद्रा निर्गमन के लिए बैंकिंग सिद्धान्त नितान्त उपर्युक्त सिद्धान्त है, क्योंकि इस पद्धति के अनुसार निर्गमित मुद्रा के पीछे १०० प्रतिशत निधि नहीं रखनी पड़ती। इसलिए, कम निधि रखकर अधिक मात्रा में आवश्यकतानुसार मुद्रा निर्गमित की जा सकती है जिससे देश को लाभ होगा। इस प्रकार नोटों की परिवर्तनशीलता कायम रहेगी और जनता को उस पर विश्वास भी रहेगा।

२ कागजी मुद्रा के निकास के लिए अधिकोषण सिद्धान्त यह बात प्रतिपादित करता है कि मुद्रा पर १०० प्रतिशत निधि न रखी जाय। इसलिए पत्र-मुद्रा के अंकित मूल्य और निधि में जो अन्तर होगा वह अन्य व्यापारिक कार्यों में खर्च किया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य धातुओं के उपयोग में बहुत बचत होती है।

बैंकिंग सिद्धान्त के दोष—बैंकिंग सिद्धान्त के उपर्युक्त गुण होते

हुए भी उसमें अवगुण पाये जाते हैं जिनके आधार पर उसकी आलोचना होती है। यथा—

१ निर्गमनाधिक्य का भय—बैंकिंग सिद्धान्त में चूँकि १०० प्रतिशत निधि नहीं रखी जाती इसलिए इसके अनुसार कम निधि रखकर केन्द्रीय बैंक जब चाहे मनमानी सख्या में पत्र-मुद्रा निर्गमित कर सकता है। जिससे देश में पत्र-मुद्रा का चलनाधिक्य हो सकता है और देश आर्थिक संकट में पड़ सकता है।

२ सुरक्षा की कमी—चलन या मुद्रा सिद्धान्त के प्रतिकूल होने की वजह से इसमें सुरक्षा कम हो जाती है। आधुनिक समय में यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दोनों सिद्धान्तों में कौन-सा सिद्धान्त व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है। बैंकिंग सिद्धान्त के आधार पर ही मुद्रा-प्रणाली का निर्माण उपयुक्त है क्योंकि ऐसी प्रणाली में जनता के विश्वास और लाभ दोनों की संतोषजनक व्यवस्था की जाती है। बैंकिंग सिद्धान्त के अपनाने से कम निधि रखी जाती है। इस प्रकार इसको चलन सिद्धान्त के विपरीत लोचपूर्ण बनाया जाता है। इसी कारण से बैंकिंग सिद्धान्त को संसार के अधिकांश राष्ट्रों ने अपनाया है। इंग्लैंड में १८४४ में चलन सिद्धान्त, बैंक चार्टर ऐक्ट के अनुसार, अपनाया गया था परन्तु बाद की हालत में बैंकिंग सिद्धान्त ही सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण में उपयुक्त सिद्ध हुआ। १९वीं शताब्दी के अन्तिम समय में इंग्लैंड की प्रगति धनादेश-विधि को अपनाने के कारण ही हुई थी जिसके कारण बैंक चार्टर ऐक्ट १८४४ के अनुसार अपनाये गये सिद्धान्त की बुराइयों को दूर किया गया।

परन्तु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि चलन सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वालों ने मिश्रित पूँजी वाले बैंकों के इतिहास के कारण ही ऐसा किया था, क्योंकि बिना संतोषजनक निधि के ही उन्होंने नोट छापे थे जिसके कारण मुद्रा-स्फीति का सामना करना पड़ा था।

नोट विकास-पद्धतियाँ—नोट निर्गम सिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना करने के बाद अब नोट निर्गम की विधियों का विचार भी आवश्यक है,

ताकि यह पता चल सके कि पत्र-मुद्रा निर्गम की कौन-कौन-सी विधियाँ हैं तथा इनको किस प्रकार सुव्यवस्थित किया जा सकता है। नोट निर्गम की रीतियाँ इस प्रकार हैं—

(१) निश्चित असुरक्षित नोट चलन पद्धति—जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, यह विधि १८४४ के बैंक चार्टर ऐक्ट के अनुसार इंग्लैन्ड में अपनायी गयी। भारत में भी १८६१ से १९२० के बीच इस प्रणाली को अपनाया गया, परन्तु इसमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और यह अलोचदार प्रणाली थी। इंग्लैन्ड के अलावा भारत, इटली, जापान, फिनलैन्ड और नार्वे ने भी इसे अपनाया था।

इस पद्धति में केन्द्रीय बैंक या मुद्रा-संचालक को इस बात का अधिकार दिया जाता है कि वह एक निश्चित मात्रा तक मुद्रा का बिना किसी निधि के निर्गम कर सकता है, परन्तु इस मात्रा के बाद हर नोट पर १०० प्रतिशत निधि रखना आवश्यक है।

इन विधि में दो गुण हैं—(क) इस रीति में सुरक्षा का गुण पाया जाता है अर्थात् इसमें पत्र-मुद्रा के बदले सोना मिलना निश्चित होता है। कुछ नोट ऐसे भी होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता परन्तु सभी नोट कभी भी बदलने के लिए नहीं आते। इसलिए इस विधि में परिवर्तन-शीलता अवश्य पायी जाती है।

(ख) मुद्रा-स्फीति का भय नहीं होता—इस चलन विधि में चलना-धिक्य पर रोक रहती है, क्योंकि निर्धारित सीमा से जितने अधिक नोटों की निकासी की जाती है उतनी ही कीमत का सोना या ऐसी बहुमूल्य धातु की निधि रखी जाती है। इसलिए न इतनी अधिक धातु-निधि होगी और न अधिक मुद्रा छपी जा सकेगी। 'निश्चित असुरक्षित नोट चलन विधि' के उपर्युक्त गुण होते हुए भी इसमें दो अवगुण हैं—

१ लोच का अभाव इस विधि का मुख्य दोष है। मुद्रा की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाने के लिए सीमा-विशेष के बाढ़ १०० प्रतिशत निधि आवश्यक होती है। आर्थिक सकट या ऐसे ही जरूरत के समय में सोने

के न होने के कारण किसी भी आवश्यकता के अनुकूल मुद्रा निर्गमित नहीं की जा सकती है।

२ अलोचता के अतिरिक्त यह एक व्ययपूर्ण विधि है। इस विधि को केवल उसी देश में सफलता मिल सकती है जिसमें सोने की मात्रा बहुत अधिक हो। दूसरे उस देश में यह रीति सफल हो सकती है जिसमें साख का अधिक प्रचार हो और मुद्रा-निर्गमन की अधिक मात्रा की आवश्यकता न हो। भारत में चलन के लिए समय-समय पर इतनी अधिक माँग हुई कि १०० प्रतिशत निधि नहीं रखी जा सकी, इसलिए यह १९२० में छोड़ दी गयी। इन्हीं कारणों से मैकमिलन कमेटी ने इस रीति को छोड़ने का सुझाव दिया था।

(२) अधिकतम असुरक्षित नोट चलन की पद्धति—मैकमिलन कमेटी के सुझाव के अनुसार यह रीति इंग्लैंड में अपनायी गयी। फ्रांस में यह रीति १८७० से १९२८ तक प्रचलित रही। इस रीति के अनुसार सरकार या मुद्रा-संचालक मुद्रा-निर्गमन के लिए एक सीमा-विशेष निर्धारित कर देता है और उस निर्धारित सीमा की सख्या तक बिना निधि रखे ही मुद्रा-निकास अधिकारी मुद्रा निर्गमित कर सकता है। परन्तु इस सीमा के बाद निधि रखना आवश्यक है। इसी लिए इस रीति में यह अधिकतम सीमा लोचता के लिए घटायी-बढ़ायी जाती रहती है।

उपर्युक्त वर्णन से इस पद्धति के कुछ गुणों का पता चलता है जिनका विश्लेषण इस प्रकार है—

क स्वर्ण का सदुपयोग—इस रीति का सबसे बड़ा गुण यही है कि इस पद्धति में स्वर्ण को बेकार बन्द नहीं रखा जाता है। फिर भी जनता में विश्वास लाने के लिए मुद्रा-अधिकारी एक निश्चित निधि रखता है, लेकिन वह उतनी नहीं होती जितनी कि किसी अन्य पद्धति में होती है।

ख यह एक लोचपूर्ण पद्धति है—इस पद्धति में वाणिज्य एवं व्यापार के अनुसार मुद्रा की अधिकतम निर्धारित सीमा घटायी-बढ़ायी जा सकती है। इस प्रकार जब कभी जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही मुद्रा निर्गमित की जायगी और चलनाधिक्य का भय नहीं रहेगा। इन गुणों

का मतलब यह नहीं है कि इस रीति में दोष नहीं है। यदि बिना सोचे समझे मुद्रा छापी गयी तो चलनाधिक्य हो जायगा, और यदि नियन्त्रित रूप से छापी गयी तो यह लाभदायक प्रणाली सिद्ध होगी।

(३) आनुपातिक निधि-पद्धति—इस प्रणाली में जितना भी मुद्रा का निर्गमन किया जाता है उसका एक निर्धारित प्रतिशत अश्वर्ण अथवा रजत की निधि में रखा जाता है। साधारणतया यह आनुपातिक प्रतिशत २५ से ४० प्रतिशत होता है। इस पद्धति को फ्रांस ने, १९२८ में अधिकतम असुरक्षित नोट चलन का त्याग कर, अपनाया। भारत में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट में हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के अनुसार इस प्रणाली को अपनाया गया। इसमें कोष की प्रतिशत मात्रा सरकार की आज्ञा से कम-ज्यादा की जा सकती है। इस प्रकार इस रीति को बैंकिंग या अधिकोषण सिद्धान्त पर अवलम्बित समझा जाता है।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण इसकी लोचता है। इस मुद्रा-चलन प्रणाली के अनुसार चलन अधिकारी जितनी सख्या में चाहे आवश्यकता-नुसार मुद्रा छाप सकता है। अर्थात् थोड़े कोष से अत्यधिक मुद्राओं का निर्गमन किया जा सकता है। मान ले, यदि बैंक या मुद्राधिकारी नोट के बदले एक सिक्का दे देता है तो उसको उस सिक्के के बदले दो या तीन (पूर्ण अनुपात के अनुसार) नोट चलन से निकालने पड़ते हैं। इस प्रकार जितना अधिक स्वर्ण या उसका सिक्का होगा उतने ही अधिक अनुपात में नोट छापे जा सकते हैं।

इस प्रणाली का दोष सोने का बेकार बँधा रहना भी गिना जाता है, जिसको विशेषतः कीन्स महोदय ने बताया है। इसी प्रकार यह प्रणाली मुद्रा-प्रसार को प्रोत्साहन देकर मुद्रा-संकोचन को हतोत्साहित करती है। मुद्रा का आवश्यकता से भी अधिक निर्गमन किया जा सकता है परन्तु मुद्रा-संकोचन में अथवा जब अधिक मुद्रा की आवश्यकता न हो तब उसका चलन रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अर्थात् नोटों का प्रचलन उसी समय बन्द हो सकता है जब वे वापस ले लिये जायँ। इस प्रकार रक्षित निधि का सर्वदा पालन नहीं हो सकता।

(४) न्यूनतम स्वर्ण-निधि की आनुपातिक पद्धति—यह रीति आनुपातिक निधि पद्धति की बदली हुई शकल है। इस पद्धति में भी पत्र-मुद्रा की कुल संख्या का एक निश्चित प्रतिशत स्वर्ण या रजत निधि रूप में रखा जाता है। परन्तु धातु रूप में जो निधि रखी जाती है वह कुल नोट का एक न्यूनतम भाग होती है और निश्चित निधि का जो भाग बचता है वह विदेशी साख-पत्रों, विदेशी बैंकों की हण्डियो एंव विनिमय विपत्रों के रूप में रखा जाता है। इस प्रणाली में जो निधि सोने-चाँदी के रूप में रखी जाती है वह निश्चित रहती है और उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने पाती।

यह पद्धति विशेषतः सोने की बचत के लिए अपनायी गयी, क्योंकि निश्चित निधि का एक न्यूनतम भाग स्वर्ण में रखा जाता है। इस रीति में आनुपातिक निधि पद्धति के ही अनुकूल लोचता और मितव्ययिता पायी जाती है।

(५) साधारण जमा पद्धति—इस रीति में नोट-निर्गमन अधिकारी को नोटों की कीमत के बराबर सोना चाँदी एक कोष में जमा रखना होता है। इस प्रकार इस रीति के अनुसार १०० प्रतिशत निधि रखी जाती है और यह प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा के रूप में नोटों का निर्गम करती है।

१०० प्रतिशत निधि होने के कारण इसमें जनता का विश्वास होता है। मुद्रा प्रसार का किसी भी दशा में डर नहीं होता। परन्तु १०० प्रतिशत निधि रखनेसे देश का सोना बेकार करना पड़ता है। इस रीति में लोच बिलकुल नहीं है। यदि देश में आवश्यकता हो तो अधिक मुद्रा छापी नहीं जा सकती क्योंकि सोने की मात्रा निश्चित होती है। यही कारण है कि यह पद्धति मान्य नहीं है।

(६) सरकारी बाड जमा-पद्धति—यह पद्धति सरकारी साख-पत्रों एंव कोषागार-विपत्रों के आधार पर भारत में १९०२ में अपनायी गयी, परन्तु विदेशी विनिमय संकट काल के कारण इसको १९०५ में त्याग दिया गया। इसके बाद अमेरिका ने १९१३ तक इसको अपनाया था। इस पद्धति में धातुकोष की जगह सरकारी साख-पत्र इत्यादि नोट-निर्गमन

के लिए निधि के रूप में रखे जाते हैं। ये सरकारी कोषागार-विपत्र आदि प्रतिभूति रूप में बैंको द्वारा रखे जाते हैं जिनके मूल्य के बराबर बैंक नोट जारी कर देते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस पद्धति में १०० प्रतिशत जमा रखी जाती है। इस प्रकार यह एक बेलोच मुद्रा-निर्गमन पद्धति है—लेकिन इसका गुण यह है कि इस रीति में चलनाधिक्य का डर नहीं रहता।

बेविगटन स्मिथ कमेटी

पहली लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद भी विश्व में युद्धकालीन परिस्थितियाँ बनी रही। युद्ध-कार्यों के लिए भारतीय माल की माँग अबिक न रह गयी, फिर भी शान्तिमय वातावरण स्थापित हो जाने से भारतीय माल की माँग कुछ हद तक बढ़ती रही। इस प्रकार एक अश तक व्यापार सतुलन भारत के अनुकूल रहा। नोटों को चाँदी में बदलने के लिए कठिनाई होती थी। क्योंकि चाँदी की कीमत बराबर बढ़ती जा रही थी। इन सब कार्यों की जाँच करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की। इस समिति के अध्यक्ष सर हेनरी बेविगटन स्मिथ थे इसलिए समिति का नाम बेविगटन स्मिथ कमेटी पड़ा।

कमेटी का कार्य—(१) व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार चलन में हेर-फेर के लिए समय-समय पर सुझाव देना, (२) स्वर्ण-विनिमय मान की स्थिरता के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करना और (३) युद्ध का भारतीय चलन तथा विनिमय पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको देखना था।

इस समिति के मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं—

(१) समिति ने १ रुपया = २ शिलिंग की विनिमय दर को स्थिर रखने का सुझाव दिया। समिति का विचार था कि यदि सोने में २ शिलिंग के बराबर विनिमय दर रखी जाय तो कोई लाभ नहीं होगा। समिति ने अनुमान लगाया था कि अभी कई वर्ष तक चाँदी की कीमत ऊँची ही रहेगी। इसके अतिरिक्त इस विनिमय दर से अन्य लाभ भी थे, यथा—

(क) विनिमय दर ऊँची रहने से कीमत के ऊपर उठने की प्रवृत्ति रुक जायगी जिससे गृह-व्यय में बचत होगी।

(ख) ऊँची दर से भारतीय व्यापार के घटने का भय नहीं होगा, क्योंकि भारतीय कच्चे माल तथा खाद्य पदार्थों की ससार में अधिक माँग है, इसलिए ऊँची दर होने के कारण भारतीय निर्यात का देश को अधिक मूल्य मिलेगा। समिति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विदेशी इस ऊँची दर से माल नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि युद्ध-विध्वंस के कारण उनके माल का उत्पादन-व्यय अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। अतः उपर्युक्त तर्क के आधार पर समिति ने इस बात का सुझाव दिया कि विनिमय दर स्वर्ण में २ शिलिंग बनी रहे।

(२) रुपया पहले की तरह रहना चाहिए, अर्थात् शुद्धता और तोल वही होनी चाहिए और वह असीमित-विधि-ग्राह्य भी रहना चाहिए।

(३) सावरेन (गिनो) के बदले में रुपये देने की सरकारी जिम्मेदारी बन्द होनी चाहिए। भारत में सावरेन असीमित-विधि-ग्राह्य रहनी चाहिए तथा इसकी विनिमय दर १० रुपया प्रति सावरेन होनी चाहिए।

(४) भारत में स्वर्ण का आयात-निर्यात स्वतन्त्र रहना चाहिए तथा सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए।

(५) तट-कर को समाप्त कर देना चाहिए जिससे चाँदी के निर्यात पर रोक तथा आयात को प्रोत्साहन मिले।

(६) स्वर्ण से सावरेन ढलवाने के लिए बम्बई में जनता द्वारा एक टकसाल खोली जानी चाहिए।

(७) स्वर्णकोषों का लगभग आधा भाग भारत में रखा जाय तथा शेष भाग लन्दन में रहना चाहिए। रिजर्व में सोने की मात्रा अधिक होनी चाहिए।

(८) भारतीय मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करने के लिए देश में आनुपातिक निधि प्रणाली अपनायी जानी चाहिए।

(९) एक सीमित समय तक के लिए अरक्षित मुद्रा का प्रकाशन १२० करोड़ रुपये तक होना चाहिए। यदि मुद्रा की माँग बढ़ जाय तो

निर्यात बिलो पर ५ करोड रुपये की अधिक पत्र-मुद्रा चालू करने का अधिकार होना चाहिए।

श्री डी० एम० दलाल जो इस आयोग के एक मात्र भारतीय सदस्य थे, इस समिति की बहुमतीय रिपोर्ट से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसका काफी विरोध भी किया। दलाल महोदय ने समिति की चलन नीति का घोर विरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विनिमय दर स्वर्ण में केवल १ शिलिंग ४ पेन्स ही रहनी चाहिए, क्योंकि २ शिलिंग की विनिमय दर बहुत ऊँची है जो भारतीय व्यापार तथा उद्योग के लिए बड़ी हानिकारक है। उनका यह भी मत था कि स्वर्ण-विनिमय-मान के स्थान पर भारत में पूर्ण स्वर्ण-मान स्थापित होना चाहिए।

472616

समिति के बहुमतीय सुझावों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा भारतीय विरोधी सदस्य श्री दलाल की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। सन् १९२० के भारतीय मुद्रण-संशोधन ऐक्ट के अनुसार सावजन १० रु० पर विधि-ग्राह्य घोषित कर दी गयी, अर्थात् १ रु० = २ शिलिंग स्वर्ण हो गया। सरकार ने समिति की रिपोर्ट को जैसे ही प्रकाशित किया भारत में रिवर्स-कौन्सिल-बिल्स की माँग तुरन्त ही बढ़ गयी। भारत सरकार ने १ रु० = २ शिलिंग की विनिमय दर को बनाये रखने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु अन्त में उसको काफी हानि उठानी पड़ी। धीरे-धीरे बाजार की वास्तविक तथा सरकारी विनिमय दर में काफी अन्तर होने लगा। सरकार द्वारा जो विनिमय दर निर्धारित की गयी थी वह भारतीय आयातकर्त्ताओं के लिए लाभप्रद थी। इसी लिए भारतीयों ने विदेशों से अधिक मात्रा में माल मँगाना प्रारम्भ कर दिया जिससे रिवर्स-कौन्सिल-बिल्स (उलटी टुडियो) की माँग और अधिक बढ़ गयी तथा इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय निर्यात हतोत्साहित होने लगा। आयात में अधिकता तथा निर्यात में कमी के कारण भारतीय व्यापार-संतुलन प्रतिकूल हो गया। बाजार में चाँदी की कीमत २ शिलिंग सोने से अधिक थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने डालर और स्टर्लिंग पर से नियन्त्रण उठा लिया। व्यापारतुला के प्रतिकूल होने के कारण कौन्सिल-

बिल्स की माँग अधिक बढ़ गयी। सरकार को उन्हें काफी मात्रा में बेचना पड़ा जो कि लगभग ५ करोड़ रुपये तक की थी। परन्तु इस पर भी विनिमय दर २ शिलिंग पर स्थिर नहीं रही। जून सन् १९२० के अन्त तक दर १ शिलिंग ८ पेन्स हो गयी। कुछ समय तक भारत सरकार ने इसको २ शिलिंग तक बनाये रखने का प्रयत्न किया परन्तु इससे भारतीय कोषागार को और भी हानि हुई।

भारत सरकार ने विनिमय दर को ऊपर उठाने के लिए मुद्रा सकोचन भी किया परन्तु इसके द्वारा भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब सरकार के सभी प्रयत्न असफल हो गये तो उसने विनिमय दर पर नियंत्रण करना ही त्याग दिया। विनिमय दर गिरकर १ शिलिंग ५ पेन्स तक आयी। १९२१ के आरम्भ तक यह १ शिलिंग ३ पेन्स तक आ गयी। चूँकि सरकार की विनिमय नियंत्रण की नीति असफल रही तथा इसमें बराबर कमी होती चली गयी, इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय व्यापारियों को अत्यधिक मात्रा में हानि उठानी पड़ी। कितनों का तो दिवाला ही निकल गया।

यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने बेवैगटन स्मिथ समिति के सुझावों को स्वीकार करने में जो जल्दी की उससे काफी हानि हुई। जिस समय समिति के सुझावों को कार्य रूप में परिणत किया गया उस समय सत्सार की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ही अनिश्चित थी। सरकार की गलत नीति के कारण व्यापारी वर्ग को काफी हानि उठानी पड़ी। परन्तु विनिमय-दर के घटने की प्रवृत्ति काफी समय तक नहीं रही तथा परिस्थितियों के बदल जाने के कारण विनिमय की दर धीरे-धीरे बढ़ने लगी। इसमें तो कोई सदेह ही नहीं कि सरकारी विनिमय दर सदा ही २ शिलिंग के बराबर बनी रही, केवल बाजारी दर में परिवर्तन होते रहे। १९२१ के आरम्भ में ही विनिमय दर १ शिलिंग ३ पेन्स स्टर्लिंग तथा १ शिलिंग स्वर्ण से भी नीचे गिर गयी। १९२३ में परिस्थितियों ने दूसरा रुख बदला और विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेन्स हो गयी। अक्तूबर १९२४ में यह बढ़कर १ शिलिंग ६ पेन्स हो गयी।

१९२६ तक यह दर बढ़ती गयी। अन्त में १ शिलिंग ६ पेन्स के आस-पास ही स्थिर रही। १९२६ में जब कि विनिमय दर ऊपर उठ रही थी इसी बीच इंग्लैन्ड ने स्वर्णमान ग्रहण करके स्टर्लिंग और स्वर्ण की कीमतों में स्थिरता उत्पन्न कर दी। तब से रुपये की कीमत बराबर १ शिलिंग ६ पेन्स के बराबर ही बनी रही। ससार की आर्थिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित हो जाने के कारण विनिमय दर में भी स्थिरता कायम रही। युद्धकालीन परिस्थितियों का अन्त हो जाने के कारण मन्दी का आना आवश्यक ही था और इस प्रकार आर्थिक जीवन की सामान्यता एक बार फिर से स्थापित हो गयी।

आलोचकों का कहना है कि सरकार ने बेविगटन स्मिथ समिति के सुझावों को इतनी जल्दी अपना कर बड़ी भूल की। उसने इनको अनिश्चित राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में कार्य रूप देकर भारतीय व्यापारियों को अधिक हानि पहुँचायी। यदि भारत सरकार ने समझ से काम लिया होता तो उसकी मौद्रिक नीति से देश को इतनी अधिक हानि नहीं उठानी पड़ती।

हिल्टन यंग कमीशन—१९२५ से पूर्व का काल आर्थिक रूप से एक अस्थिर काल था। आर्थिक जीवन को युद्धकाल के पश्चात् शान्ति से सतुलित किया जा रहा था। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी युद्ध के प्रभाव आर्थिक जीवन में वर्तमान थे जिनको किसी प्रकार खत्म करना था। इसी लिए इस युग को हम कभी-कभी सक्रान्ति का युग कहते हैं। इस काल में सरकार ने २ शिलिंग पर विनिमय दर स्थापित करने की योजना की परन्तु इस दर में स्थिरता न आ सकी जिसके फलस्वरूप सरकार ने माँग और पूर्ति को विनिमय दर स्थिर बनाने के लिए अपनाया। इस प्रकार माँग और पूर्ति की शरण के बाद १९२५ तक आर्थिक विनिमय दर में काफी स्थिरता आयी। परन्तु इसके बाद सरकार ने देश की मुद्रा सम्बन्धी पद्धति में सुधार के लिए ११ सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जिसमें लेफ्टिनेन्ट कर्नल हिल्टन यंग* को अध्यक्ष बनाया। देश में एक ऐसी मुद्रा पद्धति का आयोजन जिससे विनिमय दर

में स्थिरता आ सके, स्वर्ण-विनिमय-मान की कार्य प्रणाली की जाँच करना, चलन एवं अधिकोषण सिद्धान्तों का एकीकरण तथा इनको कार्य रूप में परिणत करने के सुझाव प्रस्तुत करना आदि इसके मुख्य उद्देश्य थे। इस कमीशन ने जुलाई १९२६ में अपनी रिपोर्ट मुद्रा-प्रणालियों के पूर्ण अध्ययन के बाद पेश की। रिपोर्ट में मुख्य रूप से तीन सुझाव थे— (१) नव-मुद्रा मान सम्बन्धी सुझाव, (२) विनिमय दर सम्बन्धी सुझाव, (३) मुद्रा-नियन्त्रण-अधिकार सम्बन्धी सुझाव।

(१) **मुद्रा-मान का चुनाव**—कमीशन ने, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, स्टर्लिंग-विनिमय-मान, स्वर्ण-विनिमय-मान, स्वर्ण-मुद्रा-मान तथा स्वर्ण-पाट-मान का पूर्ण अध्ययन किया और देश में प्रचलित मुद्रा-पद्धति का विश्लेषण किया। इस गहन विचार के बाद कमीशन ने देश में स्वर्ण-पाट मान (Gold Bullion Standard) की स्थापना के लिए सुझाव दिया।

अन्य मुद्रा-मानों के अनुपयुक्त समझे जाने के कई कारण थे जिनका विश्लेषण निम्नलिखित है।

स्वर्ण-विनिमय-मान के सम्बन्ध में कमीशन को भारतीय परिस्थिति में कई दोष मिले जो इस प्रकार हैं—(१) मुद्रा के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए कौन्सिल-बिल्स इत्यादि के जटिल और कठिन तरीकों को अपनाना पड़ता था जो भारतीय जनता के लिए प्रायः असम्भव कार्य था।

(२) इस प्रणाली में जनता का कम विश्वास था क्योंकि मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-संकोच पूर्ण रूप से मुद्रा-अधिकारी के हाथ में होता था और इस प्रणाली में लोच नहीं थी और स्वतः यह आयात-निर्यात के समय विदेशी विनिमय में सुधार नहीं कर सकती थी।

(३) साख एवं मुद्रा के नियन्त्रण की विभाजित जिम्मेदारी के कारण इसका कार्य ठीक ठीक नहीं हो पाता था।

(४) निधि के गतिशील होने के कारण सोना भी बेकार होता था और इस प्रकार एक मितव्ययी पद्धति होते हुए भी यह अपव्ययी प्रणाली ही साबित होती थी।

(५) इंग्लैन्ड से सम्बन्धि होने के कारण वहा के मुद्रा सम्बन्धी परिवर्तनो का प्रभाव भारत पर भी पडता था जिससे यह प्रणाली रुपये के मूल्य मे स्थिरता न ला सकी। उपर्युक्त कारणो से ही कमीशन ने भारत के सदर्थ मे इस प्रणाली को अनुपयुक्त बताया।

स्टर्लिंग-विनिमय-मान के सम्बन्ध मे भी हिल्टन यग कमीशन को अध्ययन के पश्चात् दोष मिले जो कि इस मान को देश मे लागू करने के बिल्कुल विपरीत थे। स्टर्लिंग-विनिमय-मान के अनुसार रुपये से स्टर्लिंग का बदला होना था, स्टर्लिंग को रुपये के बदले खरीदते थे। यग कमीशन के अनुसार इस तरीके मे भारत के इंग्लैन्ड पर निर्भर रहने के कारण यह पद्धति भारत मे इंग्लैन्ड की मुद्रा-प्रणाली पर अधिक निर्भर रहती है। इस प्रकार देश के लिए यह एक अनुपयुक्त प्रणाली समझी गयी।

स्वर्ण-मुद्रा मान की ओर विचार करने पर हिल्टन यग कमीशन ने इसमे भी कई दोष पाये जिसके कारण कमीशन ने इसको भी देश के लिए अस्वीकार कर दिया। दोष निम्नोक्त थे।

१ देश मे अपर्याप्त मात्रा मे स्वर्ण का पाया जाना सबसे बडा दोष था। परन्तु फिर भी अगर किसी प्रकार स्वर्ण प्राप्त करने के लिए चेष्टाएँ की जाती तो भी स्वर्ण की मात्रा पर्याप्त नहीं होती।

२. धातुओ का मूल्य कम होने के कारण यह रीति देश के लिए परित्यक्त कर दी गयी। इस प्रकार अन्य सब तरीको को त्याग कर हिल्टन यग कमीशन ने देश मे स्वर्ण-पाठ-मान को स्थापित करने की स्वीकृति दी।

इसमे निम्नलिखित मुख्य बाते होती थी।

१. मुद्रा-अधिकारी या रिजर्व बैंक मुद्रा-अधिकार मिल जाने पर कम-से-कम ४०० औंस शुद्ध सोना खरीदेगा और इस स्वर्ण का केवल मुद्रा कार्यों मे ही उपयोग किया जा सकेगा।

२ सावरेन या अर्ध-सावरेन विधि-ग्राह्य न होंगे अर्थात् सोने के सिक्को का प्रचलन नहीं होगा। परन्तु रुपया पूर्ण विधि-ग्राह्य नहीं रहेगा।

३ वर्तमान नोट तो रुपयो मे बदले जा सकेंगे पर नये नोट कानूनी

रूप से परिवर्तनीय नहीं होंगे, परन्तु छोटे नोटों को और रुपये के सिक्कों को बदले जाने की सुविधा होगी।

४ देश में १ रुपये के नोट चालू किये जायेंगे पर वे विधि-ग्राह्य होते हुए भी सिक्को में परिवर्तनीय नहीं होंगे।

५ कमीशन के सुझावों के अनुसार स्वर्ण-मान-निधि एवं पत्र-चलन निधि दोनों को एक कर दिया जाय। निधि में स्वर्ण एवं स्वर्ण-प्रतिभूतियाँ ४० प्रतिशत और शेष भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ एवं व्यापारिक विपत्र ६० प्रतिशत होंगे।

६ कमीशन ने देश में आनुपातिक मुद्रा-पद्धति को लागू करने की स्वीकृत दी।

(२) विनिमय दर सम्बन्धी सुझाव—चलन एवं अधिकोषण सिद्धान्तों की समस्त समस्याओं के अध्ययन के बाद, हिल्टन यंग कमीशन ने देश में विनिमय-सम्बन्धी अनुपात के वाद-विवाद का भी अध्ययन किया। वाद-विवाद के समय १६ पेन्स एवं १८ पेन्स की बातें चल रही थीं। कमीशन के सदस्यों में भी इस प्रकार का कोई पूण समझौता नहीं हो पा रहा था। परन्तु बाद में कमीशन ने रुपये का अनुपात १८ पेन्स के साथ स्वीकार किया। कमीशन के इस सुझाव के बाद देश में इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क-वितर्क होने आरम्भ हो गये। कुछ महत्वपूर्ण तर्क जो इस सुझाव के पक्ष में दिये गये, अध्ययन योग्य हैं—

(१) भारत में विनिमय की दर १८ पेन्स पिछले दो वर्षों से चली आ रही थी और ससार की अन्य शक्तियों के पूण समायोजन द्वारा ही निर्धारित की गयी थी। इसलिए भी इसका वर्तमान रहना एक स्वाभाविक बात मानी गयी। (२) देश में भी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का समायोजन इसी दर को अपना चुका था, जिसको छिन्न-भिन्न करना अनुचित-सा था।

(३) देश में १९१७ से १९२५ तक १६ पेन्स की दर असफल रही और इसके कारण मजदूरी और वस्तुओं के मूल्य में समायोजना असफल हो गयी। इससे मूल्य अधिक ऊँचे हो जाते थे और मजदूरों को हानि होती थी।

(४) इसी कारण पिछले वर्षों से देश का बजट भी १८ पेन्स की दर

पर ही निर्भर रहता था। यदि यह दर फिर १६ पेन्स पर लायी जाती तो वस्तुओं के मूल्य और मजदूरी में सामंजस्य की स्थापना का प्रश्न फिर खड़ा हो जाता। (५) व्यापारिक सतुलन की दृष्टि से भी १८ पेन्स की दर को ही अच्छा समझा गया, क्योंकि देश को १६ पेन्स की दर पर भी पर्याप्त निधि रखनी पड़ती जो १८ पेन्स की दर पर भी ठीक है। अतः कमीशन ने इन कारणों से देश में १ शिलिंग ६ पेन्स की विनिमय दर के लिए स्वीकृति दी।

उपर्युक्त कारणों से देश में १८ पेन्स की दर लागू की गयी, परन्तु इसके विपक्ष में भी तर्क उपस्थित किये गये—(१) जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिए भारत में भी १६ पेन्स की दर रखी जानी चाहिए, क्योंकि देश में गत १२ वर्षों से मूल्य-स्तर समान ही है और किसी अन्य देश में भी प्रथम महायुद्ध की विनिमय दर से अधिक ऊँची दर नहीं अपनायी। (२) उद्योग-धन्वों के प्रति सरकार की विवेचनात्मक सरक्षण-नीति असफल हो जायगी और फिर उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिसका कारण विदेशी उत्पादकों को अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय उत्पादन न्यय पर १२ प्रतिशत का लाभ प्राप्त होना है। (३) चूँकि सरकार ने अपनी सुविधा के लिए १८ पेन्स से नाता जोड़ लिया था इसलिए वह मुद्रा-संकोच भी करेगी ताकि अन्य देशों में मूल्य समायोजन हो सके। परन्तु मुद्रा-संकोच के कुपरिणाम से देश को और जनता को हानि ही हानि थी जिसका नतीजा बेरोजगारी, निर्यात की कमी इत्यादि होगा। (४) १८ पेन्स की विनिमय दर के विपक्षी दल का कहना था कि यह दर केवल स्वर्ण-निर्यात से ही कायम रखी जा सकती है परन्तु ऐसा करना देश के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए १६ पेन्स की दर ही ठीक है।

फिर भी कमीशन के समक्ष ये आलोचनाएँ बहुमत के मुकाबले में असफल हो गयी और कमीशन के सुझाव के अनुसार देश की विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेन्स रखी गयी।

(३) मुद्रा नियन्त्रण अधिकार [सम्बन्धी सुझाव—कमीशन-नियुक्ति

के समय में मुद्रा-नियंत्रण का कार्य सरकार द्वारा किया जाता था परन्तु साख-नियंत्रण इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया किया करता था। इस प्रकार इन दोनों कामों को एक अधिकारी द्वारा करने के बजाय दो पृथक्-पृथक् संस्थाएँ किया करती थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों में कोई सहयोग नहीं होता था और इस असहयोग के कारण ही विनिमय की दर अस्थिर रहती थी। इसी बैषम्य को दूर करने के विचार से हिल्टन यंग कमीशन ने सरकार के सामने एक नया केन्द्रीय बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसको रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के नाम से पुकारा जाय। इस बैंक को कमीशन ने मुद्रा-नियंत्रण एवं साख-नियंत्रण आदि साख एवं मुद्रा सम्बन्धी सभी कार्य सौंप देने का सुझाव रखा था।

कमीशन का सुझाव स्वीकार करने के बाद सरकार ने १९२७ में एक करेन्सी ऐक्ट पास किया जो उसी वर्ष पहली अप्रैल से लागू हो गया। इस ऐक्ट के अनुसार सोने का क्रय-विक्रय सरकार के हाथ में सौंपा गया। देश में १ शिलिंग ६ पेन्स की विनिमय दर घोषित की गयी। परन्तु स्वर्ण-पाट-मान की स्थापना के पश्चात् भी देश में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की स्थापना के प्रयास को कुछ समय के लिए दबा दिया गया, लेकिन फिर बाद में इस पर विचार किया गया और १९३५ में इस बैंक की स्थापना हुई।

ऊपर हिल्टन यंग कमीशन के सुझावों का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ यह भी बतलाया गया है कि सरकार ने कौन-कौन से सुझावों को कार्यान्वित किया था। सरकार ने कमीशन के सुझाव के अनुसार स्वर्ण-पाट-मान की स्थापना की परन्तु वह एक सैद्धान्तिक रूप से ही हुआ था क्योंकि सरकार ने रुपये का सम्बन्ध स्वर्ण से न करके स्टर्लिंग से कायम किया। यानी रुपये का स्वर्ण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होकर परोक्ष सम्बन्ध हुआ जिसके कारण विदेशों में रुपये को स्टर्लिंग के ही माध्यम से जाना जाता था। स्टर्लिंग से रुपये के इस परोक्ष सम्बन्ध के नाते ही जब स्वर्ण में स्टर्लिंग का ह्रास होता था तब सरकार रुपये और स्टर्लिंग की विनिमय दर अपने हस्तक्षेप द्वारा कायम रखती थी। यह हाल सन् १९२७ से १९३१ तक

ही रहा और १९३१ में सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से स्टैलिंग-विनिमय-मान की स्थापना कर दी। सरकार ने इस प्रकार कमीशन के सुझाव को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया, क्योंकि रुपये का, कमीशन के अनुसार, किसी देश-विशेष की विनिमय-शक्ति से सम्बन्ध नहीं करना चाहिए था और इसी लिए स्वर्ण से उसके प्रत्यक्ष सम्बन्ध का सुझाव दिया गया था। इस प्रकार यदि देश में स्टैलिंग-विनिमय-मान अपनाया गया तो इसका कारण सरकार की नीति थी, क्योंकि उसने स्वर्ण-पाट-मान को अपनाया ही नहीं था।

रुपये की विनिमय दर को तो सरकार ने मान लिया परन्तु कमीशन के सुझाव के विरुद्ध ही मूल्य ह्रास के समय भी हस्तक्षेप करके स्टैलिंग के साथ विनिमय दर को स्थिर बनाया गया। कमीशन ने स्वर्णमान के खत्म होने की भी भविष्यवाणी की थी, फिर भी सरकार ने अपने ही उपायों के आधार पर रुपये की दर स्टैलिंग से क्यों निश्चित की और यदि की गयी तो मूल्य-ह्रास के समय दर में परिवर्तन होना चाहिए था। उपर्युक्त विवेचन से यह अवश्य ही स्पष्ट होगा कि देश में चलन पद्धति के विकास के लिए हिल्टन यंग कमीशन के सुझावों को पूरी तौर पर कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया।

अध्याय ३

बैंकिंग का विकास

वास्तव में बैंकिंग का प्रारम्भ व्यक्ति-विशेष के उस कार्य से प्रारम्भ होता है जो उसने समाज की मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना शुरू किया था। यह केवल समय के विकास का प्रतिफल है कि ऐसे व्यक्ति अपना महत्व शनै-शनै खोते गये और सुसंगठित बैंकिंग संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका कार्य केवल द्रव्य ऋण देने के अतिरिक्त अन्य बैंकिंग सुविधाएँ देने के लिए भी था।

यद्यपि यह कहना कठिन है कि बैंकिंग व्यवसाय का प्रारम्भ कहा और कब हुआ पर यह तो कहा ही जा सकता है कि भारतीय अधिकोषण पद्धति उतनी ही प्राचीन है जितना भारतीय व्यवसाय। भारत में विदेशियों के आने के पूर्व ही यहाँ देशी अधिकोषण प्रथा अपने पूर्ण विकसित रूप में विद्यमान थी। कोई भी शाही अदालत या राजदरबार का राज्य कार्य बैकर (श्रेष्ठी) के अभाव में अधूरा माना जाता था। उसे प्रायः मंत्री के समान अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त होती थी। बैंकिंग क्षेत्र में भारत वर्ष अपनी प्राचीन सफलताओं के लिए वास्तव में प्रशंसा का पात्र है तथा हम इन सफलताओं पर गौरव का अनुभव कर सकते हैं। उस समय जब संसार के अन्य दूसरे भाग बैंकिंग के प्रारम्भिक सिद्धान्तों को समझने का प्रयत्न कर रहे थे, भारत वर्ष में देशी अधिकोषण प्रथा अपने पूर्ण विकास पर थी जिसका भारतीय इतिहास में अपना अलग ही महत्व है तथा जिसकी कार्य विधियाँ संसार की अन्य पद्धतियों से भिन्न थी।

यही नहीं, मुगल इतिहासकारों के उल्लेख में भी इसका प्रमाण मिलता है कि मुद्रा का बड़ी मात्रा में आदान-प्रदान, साख-पत्र तथा हुन्डी प्रचलन इन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, जिनका कार्य न केवल देशी व्यापार में

आर्थिक सहायता करना था बल्कि मुगल शासको के बैंकर के रूप में भी ये कार्य करते थे। ये देशी बैंकर विदेशी व्यापार में भी साख-पत्रों द्वारा सहायक होते थे। यही नहीं, इनका कार्य एक राज्य की मुद्रा को दूसरे राज्य की मुद्रा में परिवर्तित करना भी होता था, जो काफी लाभ-दायक होता था। मुगल शासक भी कुछ प्रमुख देशी बैंकरो को राज्य की सेवाओं के लिए रखते थे। जैसे सरकारी आय को इकट्ठा करना, लगान वसूल करना, आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी देना आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये देशी बैंकर केन्द्रीय बैंक के भी कुछ कार्य करते थे। इन बैंकरो को सामाजिक व राजकीय सम्मान प्राप्त था तथा मुगल दरबार में इन्हें काफी भुविधाएँ मिलती थी। मध्य-कालीन भारत के आर्थिक इतिहास में जगत सेठ का नाम प्रसिद्ध ही है। इसे जो सुविधाएँ और सम्मान प्राप्त था उस की तुलना आज की किसी भी बैंकिंग संस्था से नहीं की जा सकती।

सत्रहवीं व अठारहवीं शताब्दी के यातायात व सवाद-वाहनो की जो अल्प सुविधाएँ उपलब्ध थीं उनको विचार में रखकर अगर इन बैंकरो के विस्तृत कार्यक्षेत्र को देखा जाय, जिसमें ये बैंकिंग सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने में समर्थ थे, तो ये निःसन्देह प्रशंसा एवं बधाई के पात्र हैं। जगतसेठ के व्यापारिक प्रतिनिधि देश के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में रहते थे। वे बराबर एक दूसरे से सम्बन्ध बनाये रखते थे तथा नवीन पद्धतियों से एक दूसरे को अवगत कराते रहते थे। यही नहीं, कभी-कभी सरकार को भी इनकी सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि इनके द्वारा दी गयी सूचनाएँ विश्वसनीय मानी जाती थी। इन बैंकरो ने अपना अलग ही एक साख-पत्र चलाया जो हुन्डी (ड्राफ्ट) के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसका इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी भारतीय बैंकिंग स्वयं। इस प्रकार सुसंगठित व्यवस्था का हमें भान होता है।

इन देशी बैंकरो ने सत्रहवीं से अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में काफी उन्नति की, पर अठारहवीं शती के अन्तिम वर्षों में

इनका व्यवसाय पतन की दिशा में मुड़ने लगा। युद्ध होने के कारण अशांति के फैलने और मुगल शासकों के पतन के कारण इनके व्यवसाय को काफी धक्का लगा। दूसरा कारण यह था कि सन् १८३५ में मुद्रा समानीकरण के कारण इनका मुद्रा-परिवर्तन का कार्य जो बहुत लाभदायक था बन्द हो गया। तीसरे, यातायात व सवाद-वहन साधनों में उन्नति जो जल तथा स्थल दोनों मार्गों में हुई उसने उद्योग और व्यापार के प्रसार में अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिया तथा अधिकोषण की नवीन प्रणालियाँ प्रयोग में आ गयीं, जब कि देशी बैंकरो ने इनका अनुकरण नहीं किया और पुरानी घिसी-पिटी पद्धति पर चलते रहे। इस सर्व-मान्य परिवर्तन को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया।

एजेसी गृह—भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के स्थापित होने के साथ ही पाश्चात्य ढंग पर बैंकिंग प्रणाली का आगमन हुआ। यद्यपि उस समय भी ये देशी बैंकर अपना व्यवसाय कर रहे थे पर वे इन ब्रिटिश व्यवसायियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते थे और दूसरे, विदेशी व्यापारी वर्ग इन देशी बैंकों की भाषा व पद्धति से सर्वथा अनभिज्ञ थे। इन्हीं दो कठिनाइयों को दूर करने के लिए दो उपाय किये गये—पहला था एजेन्सी गृहों का निर्माण, दूसरा, इन देशी बैंकरो का सहयोग। एजेन्सी गृह सर्वप्रथम कलकत्ता और बम्बई में खुले। यहाँ यह सकेत कर देना उचित होगा कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कम्पनी यहाँ पर सयुक्त स्कन्ध अधिकोषण स्थापित करने के पक्ष में नहीं थी। उसके विचार से तो देशी बैंक और ये एजेसी गृह ही उसकी आवश्यकता के अनुरूप थे।

उपर्युक्त सुधार का प्रयत्न भी देशी बैंकरो के मदी काल को न रोक सका। ब्रिटिश व्यापार की शनैः शनैः उन्नति होती गयी और कम्पनी का कार्यक्षेत्र भी उसी गति से बढ़ने लगा। अतः कुछ दिनों बाद कम्पनी को इस बात का अनुभव हुआ कि किसी संगठित व आधुनिक आर्थिक संस्था की स्थापना की जाय, जिससे व्यापार व शासन दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तब शासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु सरकारी

कोषागार खुलने लगे तथा व्यापार की आवश्यकता-पूर्ति हेतु पाश्चात्य पद्धति पर बैंको की स्थापना होने लगी। इस दोनो प्रकार की उन्नति ने देशी बैंकरो के अस्तित्व को लगभग नष्ट ही कर दिया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन आधुनिक पद्धति पर स्थापित बैंको का क्षेत्र केवल बन्दरगाहो वाले नगर व प्रमुख शहरो तक ही सीमित था। अतः देशी बैंकरो ने अपना महत्वपूर्ण स्थान देश के कृषको, वित्त व आन्तरिक व्यापार मे बनाये रखा। वास्तव मे देखा जाय तो आज भी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मे इनका प्रमुख स्थान है। कुछ दशाओ मे ये संयुक्त स्वध-बैंको^१ और व्यापारिक वर्ग के बीच मे मध्यस्थ का भी काम करते है, जैसे ये हुन्डियो का क्रय-विक्रय करते है तथा आवश्यकता पडने पर बडे बैंको के पास उनका पुनर्निर्मातीय^२ काटा करते है। जैसे लन्दन के मुद्रा-बाजार मे विल के दलाल करते है। प्रारम्भिक अवस्था मे यूरोपीय बैंक व एजेन्सी-गृहो का विकास-कार्य जो सत्रहवी व अठारहवी शताब्दी मे हुआ, विवाद-ग्रस्त रहा। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकोषण सम्बन्धी कार्य इन एजेन्सी-गृहो द्वारा संपादित होते थे, जो बैंकिंग व्यवसाय मे अग्रगण्य माने जाते है। उनका बैंकिंग व्यवसाय केवल सहायक कार्य रूप मे ही रहा तथा मुख्य कार्य जहाजी व्यवसाय व एजेन्सी कार्य थे। अधिकतर नील, चाय और पटसन उद्योग को ही आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। वे एजेन्सी-गृह क्रमशः समस्त सैनिक व नागरिक सेवाओ के एजेंट बन गये जो यूरोपीय व्यवसायियों को आवश्यक थी।

प्रारम्भ मे एजेन्सी-गृहो के पास कोई अपनी पूंजी नहीं थी तथा पूर्ण रूप से उन्हे कम्पनी के कर्मचारियों की बचत पर निर्भर रहना पडता था। वे जमा स्वीकार करते थे। फसल के स्थानान्तरण के लिए ऋण देते थे तथा पत्र-मुद्रा निर्गमित करते थे, जो उनके लिए काफी लाभदायक कार्य सिद्ध होता था। विलियम कुक के अनुसार प्रथम अधिकोषण संस्था बैंक अफ हिन्दुस्तान है जो १७७० मे कलकत्ता

में एलेक्जेंडर एन्ड क० एजेंसी-गृह द्वारा स्थापित किया गया । पर कुछ लेखकों ने कुक के इस कथन का खण्डन किया है, इनके मतानुसार प्रथम यूरोपीय बैंक खोलने का श्रेय मद्रास को है । इस तथ्य को वे प्रेसीडेसी गजट व सेक्रेट रिपोर्ट के लेखा से प्रमाणित करते हैं । बैंक आफ हिन्दुस्तान, जिसे नोट जारी करने का भी अधिकार प्राप्त था, सन् १८३२ में बंद हो गया । क्योंकि इसे स्थापित करने वाली कम्पनी भग्न हो गयी । दी बंगाल बैंक एन्ड जेनरल बैंक की स्थापना सन् १७८५ में हुई थी ।

प्रेसीडेसी बैंक—१८०५ व उसके बाद से हम बैंकिंग का क्रमिक इतिहास पाते हैं । दी बैंक आफ बंगाल, जो प्रथम प्रेसीडेसी बैंक था, १८०६ में बैंक आफ कलकत्ता के अन्तर्गत खुला तथा इसे बैंक आफ बंगाल के नाम से १८०९ में सरकार द्वारा मान्यता मिली । इस बैंक की स्थापना सरकार को ऋण की सुविधा देने व साख को बनाये रखने के उद्देश्य से की गयी । इस बैंक के कार्य पर अधिकार पाने के हेतु कम्पनी ने बैंक की अंश-पूजी की योजना में भाग लिया और इस प्रकार उसे अपने तीन सचालक नियुक्त करने का अधिकार मिला । इस बैंक का सचिव प्रायः सिविल सर्विस का सदस्य होता था । सन् १८३२ में इस बैंक को नोट निर्गमित करने का अधिकार मिला तथा १८३९ में नियम हेतु इसे शाखाएँ खोलने का अधिकार भी मिला । पर विदेशी विनिमय के लिए इस पर प्रतिबन्ध लागू रहा । दूसरा प्रतिबन्ध यह था कि इस पर व्याज की दर १२ प्रतिशत तक सीमित कर दी गयी थी । दी बैंक आफ बंबई तथा बैंक आफ मद्रास की स्थापना सन् १८४० और १८४३ में क्रमशः ५० लाख रु० व ३० लाख रु० पूजी से हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कम्पनी ने तीन लाख रुपया लगाया । इन बैंकों को नोट निर्गमित करने के अधिकार दिये गये । इनकी अंश-पूजी का क्रय अधिकांशतः अभावियों द्वारा किया गया । इनके प्रमुख उच्चाधिकारी, जैसे सेक्रेटरी व कोषाध्यक्ष नागरिक सेवा के सदस्य होते थे । १८६२ में इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार ले लिया गया तथा उसे सरकार का

एकाधिकार घोषित कर दिया गया । इसके स्थान पर सरकार की शेष राशि का इन्हे स्वतन्त्रता पूर्वक उपयोग करने की अनुमति दी गयी । बैंक आफ बर्बई का १८६२ में विघटन कर दिया गया पर उसी वर्ष उसी नाम से १ करोड़ की पूंजी से एक नया बैंक खोला गया ।

प्रेसीडेन्सी बैंक ऐक्ट १८७६ के द्वारा सरकार ने जमा करने वालों के हित को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों के कार्य को कुछ सीमित कर दिया । ये बैंक विदेशी बिलों का व्यापार करने से रोक दिये गये और ये विदेशों से ऋण भी न ले सकते थे । ऋण देने की अवधि की अधिकतम सीमा छ महीने कर दी गयी । अचल सम्पत्ति की जमानत द्व रा ऋण देने पर रोक लग गयी । इन प्रेसीडेन्सी बैंकों को सरकारी बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ाने का अवसर मिला ।

यद्यपि इन प्रेसीडेन्सी बैंकों की शाखाएँ देश के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों में थीं, फिर भी इनकी नीति में एकरूपता का अभाव था तथा पारस्परिक सम्बन्ध नहीं था । १८६० से १८७६ तक बंगाल बैंक को अखिल भारतीय बैंक के रूप में परिवर्तित करने की योजना पर विचार किया जाता रहा । भारत सरकार के समक्ष यह योजना प्रेश हुई पर इसे यह कहकर टाल दिया गया कि इतने बड़े बैंक की व्यवस्था करना कठिन हो जायगा । १८९८ में फाउलर करेसी कमेटी के सनक्ष केन्द्रीय बैंक स्थापित करने के विषय में कुछ तर्क रखे गये । सरकार ने उन्हें भी नामजूर कर दिया । वास्तव में ये प्रेसीडेन्सी बैंक स्वयं एकीकरण के पक्ष में नहीं थे । ये अपना अलग अस्तित्व बनाये रखना चाहते थे । सन् १९१३ से १७ तक के बैंकों के सकटकाल ने इन प्रेसीडेन्सी बैंकों के दोषों को सर्वविदित कर दिया । अन्त में यह भय हुआ कि यदि इन बैंकों का पृथक् अस्तित्व बना रहा तो अंग्रेजी, जापानी या अमेरिकन बैंकों में से कोई भी बैंक भारत के कुछ बैंकों का एकीकरण करके भारत की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का मत जनता की तरफ से अधिक

जोर पकड़ता गया। परिणामस्वरूप सरकार को अपना विरोध वापस लेना पड़ा। इस प्रकार १९२० में तत्सम्बन्धी एक ऐक्ट इन प्रेसीडेन्सी बैंको के एकीकरण के लिए बना जो १९२१ में कार्यान्वित किया गया। इस प्रकार इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई जिसने १९२१ से कार्य करना प्रारम्भ किया।

२७ जनवरी १९२१ को जब इन बैंको का एकीकरण किया गया इनकी कुल ५९ शाखाएँ थी, जिनकी कुल चुकता पूँजी ३७५ लाख रुपये व कुल सचय ३४५ लाख रुपये था।

पूँजी का ब्यौरा, करोड़ रुपये में—

वर्ष	चुकता पूँजी	सचय	राजकीय जमा	व्यक्तिगत जमा	नकद बचत
१८७०	३ ३६	२५	५ ४३	६ ४०	९ ९७
१८८०	३ ५०	५५	२ ९१	८ ८९	७ ४१
१८९०	३ ५०	९७	३ ५९	१४ ७६	१२ ९७
१९००	३ ६०	२ ००	२ ८०	१२ ८८	५ ०४
१९१०	३ ६०	३ ३१	२ २४	३२ ३४	११ ३५
१९२०	३ ७५	३ ७८	९ ०३	७८ ०२	२६ ०३

भारत में संयुक्त स्कन्ध बैंक—१८१३ ई० का ऐक्ट, जिसके द्वारा यूरोपीय विनियोजन पर से लगभग सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये, संयुक्त स्कन्ध अधिकोषण की स्थापना व विकास में काफी सहायक सिद्ध हुआ। अंग्रेजी एजेन्सी-गृहो ने भी बहुत से बैंको की स्थापना की जो असीमित दायित्व के स्तर के थे। इनका उद्देश्य सामान्य बैंकिंग के कार्य, जैसे आन्तरिक व्यापार में सहायता, उद्योगों की आर्थिक सहायता तथा विनिमय का कार्य होता था।

इन प्रेसीडेन्सी बैंको के अतिरिक्त निम्नलिखित बैंक ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रारम्भिक दिनों से १८६० ई० तक कार्य करते रहे ।

बैंक का नाम	स्थापित	ह. १५ १८५६	शाखाएँ	पूँजी
१. दी ओरेन्टल बैंक	१८५१	लन्दन		१२,१५,०००
२ दी आगरा एन्ड अवध बैंक	१८३३	कलकत्ता	आगरा, मद्रास, लाहौर और लन्दन	७,००,०००
३ दी नार्थ वेस्ट बैंक	१८४४	लन्दन	बम्बई, सिमला, मन्सूरी, आगरा, दिल्ली, कानपुर	२,२०,५६०
४ दी कामरशियल बैंक	१८५४	बम्बई	ए नेन्ड लन्दन सवाई, कलकत्ता	१०,००,०००
५. दी दिल्ली बैंक	१८४४	दिल्ली	लन्दन, कलकत्ता बम्बई और मद्रास	१,८०,००० ६३,८५० ५०,०००
६ दी शिमला बैंक	१८४४			
७ दी ढाका बैंक	१८४६	ढाका		
८ दी मेरकनटाइल बैंक		बम्बई	लन्दन, कलकत्ता कोलम्बो और सवाई	५,००,०००

ये सभी बैंक असीमित दायित्व के आधार पर स्थापित हुए थे । सट्टे की प्रवृत्ति तब भी इनमे विद्यमान थी जिसके कारण अन्त मे इन्हें काफी नुकसान उठाना पडा तथा आगे प्रभावहीन अकेक्षण, अव्यवस्थित प्रबन्ध आदि के कारण ये असफल रहे ।

सयुक्त स्कन्ध अधिकोषण का इतिहास सन् १८६० ई० से अब तक, जब कि सीमित दायित्व का प्रारम्भ हुआ, काफी रोचक रहा है । कड़ी प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कई बैंक खुलते और बन्द होते रह । बैंकिंग के इतिहास मे सन् १८६० का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी वर्ष सीमित दायित्व वाले बैंको का प्रारम्भ हुआ, जो कि अधिक मात्रा मे पूँजी आकर्षित करने के लिए बहुत आवश्यक थे । पर इसी समय से बैंको से नोट निर्गमित करने का अधिकार वापस ले लिया गया । तत्पश्चात् अमेरिका मे गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया जिसमे इंग्लैण्ड मे अमेरिका से कपास आना बन्द हो गया और इसके फलस्वरूप इंग्लैण्ड मे भारतीय कपास की माग बेहद बढ़ गयी, जिससे भारत का कपास-व्यापार अपने उच्च स्तर पर पहुँच गया । बैंकिंग तथा अन्य आर्थिक संस्थाएँ अवसर का लाभ उठाने के लिए इस व्यापार मे सम्मिलित हो गयी पर थोड़े ही समय मे सभी बैंक फेल हो गये, क्योंकि बाद के अवसाद काल मे आर्थिक सकट का कोई भी सामना न कर सका । बम्बई शहर मे अमेरिकी युद्धकाल मे बैंकों की जितनी उन्नति हुई उससे आश्चर्य ही होता है । तीन वर्ष, सन् १८६३ से ६५ के अन्तर्गत ही २५ बैंक १३ ६ करोड की पूँजी से खुल गये और ३९ विर्त्त-संस्थाओ की ६ २ करोड की चुकता पूँजी हो गयी । इस सट्टे-बाजारी के समय उन्होंने अपनी पूँजी बहुत अधिक बढ़ा ली पर अभाग्यवश यह सब उन्नति सट्टे की आधारहीन स्थिति पर आधारित थी । ज्यो ही सट्टा-बाजार मन्दा पडा, ये बैंक भी मन्दी के काल का सामना न कर सके और असफल हो गये ।

इस सकट काल के कारण जनता का बैंको पर से विश्वास उठ गया । सात बैंको मे से निम्न तीन बैंक ही इस काल मे टिक सके—बैंक आफ अपर इडिया, दी इलाहाबाद बैंक और बगलोर बैंक, जो क्रमश १८६३,

१८६५, १८६८ में स्थापित हुए थे। यद्यपि इलाहाबाद बैंक १८६५ में चालू हो गया था पर २३ वर्ष तक इसकी कोई शाखा नहीं खुल सकी। १८७० से १८९४ के अन्तर्गत सात और नये बैंक खुले जिनमें केवल चार इस सकट काल में टिक सके। दी एलायन्स बैंक आफ शिमला १८७४ में स्थापित हुआ जिसका प्रमुख कार्यालय शिमला में था। इसकी ३९ शाखाएँ व ११ सहायक कार्यालय थे। इसका विघटन १९२३ में इस लिए हो गया कि इसने अपनी अधिकांश जमा का सहायक उद्योगों में विनियोग किया था जो लन्दन के बोल्टन ब्रदर्स द्वारा चलाये गये थे।

दी अवध कमर्शियल बैंक जो कि १८८१ में चालू किया गया प्रथम बैंक था जिसका प्रबन्ध भारतीयों के हित में था। दी पंजाब नेशनल बैंक की १८९४ में तथा पीपुल्स बैंक की १९०१ में स्थापना हुई। इन दो बैंकों ने थोड़े ही समय में काफी उन्नति कर ली और पीपुल्स बैंक की बारह सालों में ही १०० शाखाएँ खुल गयीं और इसकी जमा पूँजी १ २५ करोड़ से अधिक हो गयी। यह बैंक भी १९१३ में असफल हो गया, क्योंकि इसने अपने धन के अधिक भाग का उद्योगों में विनियोग कर दिया था और जब जमा करने वाले अपनी राशि निकालने आये तो बैंक एकाएक उन्हें सतुष्ट न कर सका। दूसरे बैंक भी इसकी मदद करने से अलग हट गये।

कुछ लेखकों का मत है कि इस धीमी प्रगति का कारण विनियमों की अस्थिरता है। पर केवल इसी को बैंकों की मन्द उन्नति का कारण नहीं माना जा सकता है। बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यह तो १९वीं शती के उत्तरार्ध की आर्थिक अवस्था सबकी तटस्थता का प्रतिफल है। बैंकों के विकास में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से कुछ प्रगति होने लगी, क्योंकि १९०६ के स्वदेशी आन्दोलन से इन्हें काफी झल मिला। उस समय इस आन्दोलन का बहुमुखी प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हो जाने से व व्यापार की अनुकूल अवस्था के कारण बैंकों के विस्तार में वास्तविक सहायता मिली। दूसरे शब्दों में स्वदेशी आन्दोलन से भारतीय प्रबन्ध के अन्तर्गत बैंकों को खुलने का प्रलोभन प्राप्त हुआ।

निम्नोक्त वर्तमान सम्पन्न बैंको की स्थापना उसी समय में हुई—दी बैंक आफ इंडिया, दी इंडियन बैंक आफ मद्रास, दी सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, दी बैंक आफ बरोदा, दी बैंक आफ मैसूर। अन्य बड़े बैंक जो असफल हुए वे थे दी बंगाल नेशनल बैंक, दी क्रेडिट बैंक आफ इंडिया, दी बाम्बे मरचेन्ट बैंक, दी स्टैंडर्ड बैंक आफ बाम्बे, दी बैंक आफ अपर इंडिया।

बैंकिंग सकटकाल—१९१३ से २४ तक बैंको के सकट के लिए मदी का काल था जो सयुक्त स्कन्ध बैंको के लिए बहुत कठिन समय रहा। १९१३ से चार वर्ष के अन्तर्गत ८७ बैंक निष्फल हो गये, जिनकी चुकता पूंजी १ ७५ करोड़ से ऊपर थी, जो समस्त सयुक्त स्कन्ध बैंको की कुल चुकता पूंजी का आधे से कुछ अधिक भाग थी।

१९१३ से १९२५ के बीच १६१ बैंक निष्फल हो गये जिनकी चुकता पूंजी ६ ७५ करोड़ के लगभग थी। बैंको की इस घोर निराशाजनक परिस्थिति का कीन्स जैसे प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री ने सकट काल के कुछ महीने पहले ही अनुमान कर लिया था। उनका मत था कि छोटे छोटे बैंक अपना व्यापार अधिकतर बैंकिंग सिद्धान्त से प्रतिकूल व्यवसाय में करते हैं जब कि इस देश में मुद्रा गाड़कर रखने की प्रवृत्ति अब भी प्रचलित है। इन बैंको के पास नकद जमा भी बहुत ही कम है और यह आशंका है कि कुछ ही दिनों में इन्हें विपरीत परिस्थिति का सामना करने में कठिनाई होगी और ये सम्भवतः असफल हो जायेंगे। १९१३ से १९१७ के इस अल्प काल में एक के बाद एक बैंक निष्फल होते गये। यह वास्तविक अर्थ में सकटकाल नहीं था परन्तु भारत में बैंक अधिकतर अपनी व्यक्तिगत कमजोरी के कारण असफल हुए हैं।

सकटकाल के कारण—इस सकट काल के अनेक कारण हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद स्वदेशी आंदोलन की प्रगति होने से बहुत से बैंक बहुत ही अपर्याप्त पूंजी से खुल गये और अपने कार्यों में इन बैंको ने बैंकिंग के सिद्धान्तों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। ये बैंक अनुकूल परिस्थिति में जन्म लेने के कारण कठिन परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि इनकी अधिकृत पूंजी अधिक थी पर जमा और चुकता पूंजी बहुत ही कम थी

—अधिकृत पूँजी का क्रमशः ४० प्रतिशत और १४ प्रतिशत । उस समय इन अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं थी । साधारण जनता को इस तीन प्रकार की पूँजी के अन्तर का ज्ञान नहीं था और वह आसानी से धोखे में आ गयी । इस दूषित पूँजी का स्वाभाविक प्रभाव यह पड़ा कि बैंकों को अपने कार्य के लिए जनता के जमा धन पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ा । अधिक धन आकर्षित करने के लिए ये बैंक जमा पर ऊँची दर से ब्याज देने लगे । ४ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक निश्चित जमा पर व २ से २½ प्रतिशत तक चालू खाते पर सालाना ब्याज की दर तो उस समय सामान्य थी ।

इस प्रकार ऊँची ब्याज की दर के कारण बैंक स्ट्रेटबाजी व अस्थिर उद्योगों में रुपया लगाने के लिए विवश हो गये, क्योंकि इनसे पूँजी पर ब्याज प्राप्त करके ही ये ऊँची दर का ब्याज दे पाते थे । साथ ही माग पर देय जमा को भी ये लम्बी अवधि के लिए ऋण में देने लगे । इस प्रकार बैंकिंग के मूल सिद्धान्त को ये बैंक भूल ही गये । कभी कभी तो उद्योगों को बिना अच्छी तरह जाच किये ही ये ऋण दे देते थे जिससे काफी रुपया एक ही बार में एक उद्योग में डूब जाता था । इस प्रकार जमा करने वाले जब अपना रुपया निकालने के लिए एक साथ पहुँचते तो ये बैंक विनियोजित ऋण ठीक समय पर वापस न होने पर बड़े सकट में पड़ जाते थे । फिर बहुत से बैंकों के संचालक व प्रबन्धक बैंकिंग कार्य-प्रणाली से अनभिज्ञ थे तथा इस व्यवसाय में इनका आना सर्वथा आकस्मिक था । बैंकों के अधिकारी अपने अधिकार के प्रति या तो अनभिज्ञ थे या उदासीन । कम्पनी के प्रबन्धक नियंत्रण में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, जिससे जनता के द्रव्य का उपयोग अवाञ्छनीय रूप से होता था । जमा करने वाले कृत्रिम वार्षिक चिट्ठों के प्रदर्शन और ब्याज की ऊँची दरों के प्रलोभन में आसानी से आ जाते थे । इस प्रकार दायित्व की अपेक्षा नकद जमा का अनुपात बहुत कम रह गया, जो सामान्यतः १० से ११ प्रतिशत तक था । ये एक विशेष कर भारत के लिए तो बहुत ही अपर्याप्त है जहाँ बैंकिंग की आदत अब भी स्थिर रूप से नहीं बन पायी है । केन्द्रीय

बैंकिंग संस्था, जो बैंकिंग की नीति को नियंत्रित कर सके तथा बैंको की स्वार्थ-परता को रोक सके, इसके अभाव ने इस सकटकाल के काले पृष्ठों को और गहरे रंगों में रंग दिया। ऐसे समय सरकार का यह कर्तव्य था कि सकट-काल घोषित करके साख-संस्थाओं की आर्थिक सहायता करती, जिससे वे असफल होने में अपनी रक्षा कर सकती। पर भारत सरकार इस दिशा में सर्वथा उदासीन रही।

उपर्युक्त असफलता के कारण मुख्यतः उन बैंको पर लागू होते हैं जिनकी स्थापना १९०४ के बाद हुई थी। पर इसका आशय यह नहीं है कि हम भारतीय प्रबन्धकों की व्यावसायिक योग्यता पर सन्देह करें, क्योंकि कुछ बड़े बैंक उस सकट काल में भी पर्याप्त लाभ पर भारतीयों द्वारा संचालित होते रहे। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि बैंको के इतिहास में इनकी असफलता के उदाहरण हमें इंग्लैण्ड, अमेरिका में भी मिलते हैं जो आजकल बैंकिंग व्यवसाय में काफी उन्नति कर गये हैं।

वास्तव में भारत में बैंको का विकास व्यक्तिगत रूप से हुआ है। व्यक्ति-विशेष का इनमें अपना निहित स्वार्थ होता था, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना रहता था।

सकटग्रस्त अवस्था का परिणाम—सन् १९१४ के सकट-काल ने नये बैंको को कुछ दिनों के लिए बिलकुल ही न खुलने दिया और मुख्यतः उन प्रांतों में जहाँ इनकी असफलता विशेष रूप से हुई, बैंको के प्रति जनता का बिलकुल विश्वास उठ गया तथा कुछ समय के लिए बैंको से अपना रुपया जनता ने निर्दाल लिया। उपर्युक्त परिणामों के अतिरिक्त इस आपत्ति काल से कुछ लाभ भी हुए। प्रथम तो यह कि भारतीय बैंको के दूषित लक्षण दूर हो गये और एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव हुआ, जिससे बैंकिंग के सिद्धान्तों को संचालित किया जा सके व व्यवस्था में सुधार कराया जा सके। बैंकिंग शिक्षा का महत्व भी मालूम हुआ क्योंकि अन्त में अच्छे बैंकर पर ही उन्नतिशील बैंकिंग निर्भर होती है। जनता में ऊँची परम्पराओं का निर्माण व उत्तरदायित्व का सही रूप से ज्ञान प्रतिभासम्पन्न बैंकिंग विकास के अनिवार्य तत्त्व है। यह शिक्षा भारतीय बैंकरो को इसी सकट-काल में प्राप्त हुई।

पथम महायुद्ध का भारतीय बैंको की दर पर प्रभाव—विश्वयुद्ध का यह प्रथम मुख्य प्रभाव बैंको की जमा मे वृद्धि के रूप मे हुआ। सभी बैंको की जमा, जिनमे प्रेसीडेसी बैंक, सयुक्त बैंक व विनिमय बैंक सम्मिलित है, १७ ५१ करोड से १६३ ६२ करोड हो गयी। यह परिवर्तन १९१३ से १९१८ की ही अल्प अवधि मे हुआ। उपर्युक्त अंको मे विनिमय बैंको की विदेशी राशि सम्मिलित नहीं है। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि उस समय मुख्यत सूती मिलो ने बहुत लाभ उठाया क्योंकि युद्ध के संचालन के लिए कपडे की काफी खपत होती थी, उस कारण युद्ध की आर्थिक अवस्था ने इस लाभ मे और अधिक वृद्धि की जो बैंको मे इकट्ठा होता गया। १९१३ व १८ के बीच प्रेसीडेसी बैंको की जमा मे १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सयुक्त स्कन्ध बैंको मे दस प्रतिशत व विनिमय बैंको की जमा मे ५५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंको मे यह वृद्धि युद्ध के कारण केवल भारत मे ही नहीं हुई बल्कि ससार के अन्य बैंको की जमा मे भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जैसा कि निम्न तालिका से हमे ज्ञात होता है।

देश	१९१३ युद्ध के पूर्व	१९१७ युद्ध के समय	प्रतिशत वृद्धि
अमेरिका	२,१०१	४,०८१	९४
इंग्लैण्ड	१,१०४	१,८७२	७०
जर्मनी	५४३	१,४७२	१७१
फ्रान्स	२६६	४३५	६४
कनाडा	२३३	३२०	३७
आस्ट्रेलिया	१५०	२०९	३९
हिन्दुस्तान	६५	१०७	६५
जापान	१८५	४१६	१२५

भारत मे इस जमा की वृद्धि स्थिर काल जैसी हुई, क्योंकि भारतसरकार को अपने युद्धकालीन व्यय के साथ-साथ लदन के युद्ध के दफ्तर का

और सभी व्ययों का भुगतान करना पड़ता था। बैंको के विनियोग में भी काफी वृद्धि हुई, जिसके दो कारण हैं। प्रथम तो निर्यात व्यापार की उन्नति और दूसरा ट्रेजरी बिल व युद्धकालीन विनियोग में बैंको का जमा करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ससार के अन्य बैंको की भाँति भारतीय बैंको ने लाभांश की दर युद्ध-पूर्व की अपेक्षा बढ़ा दी। १९१८ से १९२१ तक बैंको में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी जो बैंको के समृद्धि-काल की परिचायक है, पर १९२३ से ही युद्धोपरान्त का अवसाद काल आ गया। १९२४ से १९२५ तक स्थिति कुछ अवश्य सुधरी।

लगभग १४ वर्षों के अन्तर्गत ५२७ बैंक असफल हो गये जिनकी चुकता पूँजी २३४ २ लाख ६० थी। अगर हम इस असफलता की १९१३ से १७ तक के सकटकाल से तुलना करें तो पता चलेगा कि इस अवसाद काल में केवल वही बैंक असफल रहे जो कमजोर थे, क्योंकि असफल होनेवाले बैंको की संख्या तो अधिक है पर उनकी चुकता पूँजी कम है।

अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पंजाब, उत्तर प्रदेश और बम्बई में बैंक अधिक असफल रहे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के समय इन्हीं प्रदेशों में नये बैंक खुले थे और यहाँ कपास व चाँदी, गेहूँ का अच्छा बाजार था तथा मदी काल का सबसे बुरा प्रभाव इन्हीं पर पड़ा। अवसाद के कारण भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में बैंक बराबर फेल होते गये पर भारतीय संयुक्त पूँजी बाजार मन्द गति से किन्तु बराबर उन्नति करते गये, क्योंकि १९३९ के अन्त तक बैंको की पूँजी में ५ लाख से ५१ लाख की वृद्धि हुई। कुल चुकता पूँजी में १३ करोड़ ६० की वृद्धि हुई और जमा में १०१ करोड़ ६० की वृद्धि हुई।

इन दोनों प्रकार के बैंको को साथ-साथ देखने से पता चलता है कि १९२६ में इनकी संख्या ७५ थी, १९३९ तक १७० हो गयी तथा इनकी जमा पूँजी १९२६ में ६३ १५ करोड़ थी वह १९३९ तक ११० करोड़ हो गयी। १९३२ तक बैंको की उन्नति बहुत धीमी गति से हुई क्योंकि अवसाद के कारण मूल्यों में बराबर कमी होती गयी। १९२६ से ३९ तक भारतीय संयुक्त स्कन्ध धनराशि में ४७ करोड़ ६० की वृद्धि हुई।

निम्न आँकड़ों से यह ब्यौरा और स्पष्ट हो जायगा

बैंकिंग का विकास

७५

वर्ष	बैंको की सख्या	पूँजी	जमा	नगद राशि	बैंक मख्या	पूँजी	जमा	नगद राशि
१९२६	२८	१० ८४	५९ ६८	९ १२	४७	१ २६	४७	८२
१९२७	२९	११ ०८	६० ८४	७ ७०	४८	१ २२	४६	५२
१९२८	२८	११ १०	६२ ८५	८ १९	४६	१ २०	५०	५२
१९२९	३३	११ ५४	६२ ७२	१ ०५	४५	१ १५	५८	४५
१९३०	३१	११ १०	६३ २५	७ ६८	५४	१ ३७	३१	५२
१९३१	३४	१२ ०८	६२ २६	७ ७१	५१	१ २४	८४	४७
१९३२	३४	१२ २१	७२ ३४	९ ७९	५२	१ २६	१३	६८
१९३३	३४	१२ ३४	७१ ६८	१० ९२	५५	१ ३१	७५	८२
१९३४	३६	१२ ६७	७६ ७७	११ १४	६९	१ ४९	११	७२
१९३५	३८	१३ २०	८४ ४५	१९ १२	६२	१ ३९	२८	८२
१९३६	४२	१३ ९५	९८ १४	१५ २८	७१	१ ४२	४६	१००
१९३७	३९	१२ ७८	१०० २६	१६ ८२	१०८	२ १७	८२	१३३
१९३८	४३	१३ १४	९८ ०८	१४ ००	१२०	२ ४१	८२	१२९
१९३९	५१	१३ ५६	१०० ७३	१६ ७२	११९	२ ३२	९ २७	१ ३७

इम्पीरियल बैंक की स्थापना और १९३४ से पहले की अवस्था—
 इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया की स्थापना १९२० में भारतीय विधान के एक विशेष अधिनियम के अनुसार, जिसे इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट XLVIII कहते हैं, हुई तथा इसने २७ जनवरी १९२१ से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसका निर्माण तीन प्रेसीडेसी बैंकों का एक में समामेलन करके हुआ था, जिन्हें बैंक आफ बंगाल, बैंक आफ बाम्बे व बैंक आफ मद्रास कहते हैं। इसकी स्थापना से पहले भारत में संयुक्त स्कन्ध बैंकों का विकास अखिल भारतीय आधार पर न होकर कुछ थोड़े से क्षेत्र तक ही सीमित था तथा स्थानीय बैंकिंग आवश्यकताओं को ही ये पूरी करते थे। इसके पहले जब-जब केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रयत्न किया गया असफलता ही मिली। इसके दो कारण थे, एक तो भारतसरकार की उदासीनता व दूसरे प्रेसीडेसी बैंकों की आपसी फूट। पर युद्ध के समय में इसकी आवश्यकता समझ में आयी और १९२० तक कुछ विदेशी बैंक काफी विकसित हो गये थे, जिन से यह आशंका की जाने लगी कि यदि किसी केन्द्रीय बैंक की स्थापना न की गयी तो विदेशी बैंकों का प्रभुत्व भारत में जम जायगा, इसीलिए विशेष रूप से इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गयी। इसकी पूँजी ७५,००० हिस्सों में विभक्त थी। प्रत्येक हिस्सा ५०० रु० का था। इसमें प्रेसीडेसी बैंकों के हिस्से स्थानान्तरित कर दिये गये जिनके सभी अंश पूर्ण चुकता थे।

इस बैंक का जैब निर्माण किया गया तो सार्वजनिक जिम्मेदारियों के कारण सरकार का इस पर नियंत्रण हो गया। मुख्यतः प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के क्षेत्र में तथा आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इसका प्रमुख नियंत्रण था। लोक-ऋण का प्रबन्धक सामान्य बैंकिंग कार्य के लिए इसके अधीन रखा गया था। सरकार ने इस बात का समर्थन किया कि वह अपनी जमा बैंक को स्थानान्तरित करत रहेंगे जिसके लिए कोई शुल्क न लेगा तथा बैंक इन सुविधाओं के बदले अगले पाँच वर्षों में १०० नयी शाखाएँ खोलकर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करेगा। मार्च १९२६ के बाद यह बैंक १०२ नयी शाखाएँ

खोलने योग्य हो गया। अधिकतर शाखाएँ वहाँ खोली गयी जहाँ अभी तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस कार्य को दो भागों में बाँट दिया गया, एक तो वह जिसे यह कर सकता था तथा दूसरा वह जिसे यह बैंक नहीं कर सकता था। जैसे यह नोट निर्गमित नहीं कर सकता था, उसका अधिकार एक मात्र सरकार के हाथ में था।

इस बैंक का सारा कार्य सेंट्रल बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा संचालित होता था और प्रेसीडेन्सी बैंको को इसकी शाखाओं के रूप में घोषित कर दिया गया था। प्रत्येक शाखा लोकल बोर्डों के अधीन कर दी गयी। इस बैंक की नीति तथा समस्त काय-प्रणाली गवर्नर जनरल की कौन्सिल द्वारा निर्धारित होती थी।

शुरू में इस बैंक ने अपना कार्य प्रेसीडेन्सी बैंक के ढंग पर ही चलाया और विदेशी व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं रखा। इस बैंक की एक शाखा लन्दन में खोल दी गयी। इस शाखा के द्वारा भारतीय सरकार ने ग्लैण्ड की सरकार से रुपये का लेनदेन बैंक आफ इंग्लैण्ड के द्वारा शुरू कर दिया। १९२१ में भारत सरकार का इस बैंक के सम्बन्ध में सेक्रेटरी आफ स्टेट से समझौता हुआ। इसके द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्ध और सुविधाएँ इस बैंक को प्राप्त हुईं।

(१) भारत सरकार का बैंको से सम्बन्धित सारा कार्य इसी बैंक द्वारा होगा।

(२) इम्पीरियल बैंक शीघ्र ही परन्तु पाँच साल के भीतर देश में १०० नयी शाखाएँ स्थापित करेगा।

(३) समस्त राजकीय कर की व्यवस्था का भार इसी पर होगा।

इसकी स्थापना के प्राय १० साल में इसकी पूँजी लगभग ७६ करोड़ हो गयी, परन्तु शाखाओं के खोलने का उत्तरदायित्व यह बैंक सफलतापूर्वक न निभा सका। कुल ८८ शाखाएँ खोली गयी जिनमें ३२ शाखाएँ तो सफलतापूर्वक कार्य करती रही और शेष ५६ शाखाओं में बराबर हानि ही होती रही। लेकिन कुछ वर्षों बाद इनकी स्थिति सुधर गयी और घाटा कुछ ही वर्षों में पूरा हो गया, परन्तु नयी शाखाओं के खोलने की हिम्मत

न पड़ी। इस बैंक को सरकार से विशेष मान्यता प्राप्त होने के कारण जनता का विश्वास इसमें बढ़ता गया और बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी का लेन-देन इसके द्वारा होने लगा। सयुक्त पूँजी वाले बैंको के विस्तार से इस बैंक के कुछ काम में अड़चन होने लगी। कहीं कहीं तो इस बैंक की सयुक्त पूँजी वाले बैंको से प्रति-स्पर्धा भी होने लगी क्योंकि यह बैंक केवल सरकार के ही रूपों का लेन-देन नहीं करता था बल्कि जनता के व्यापार का भी बहुत अधिक कार्य इसी बैंक के द्वारा होता था। फिर भी इम्पीरियल बैंक सदा यही प्रयत्न करता रहा कि लेन-देन के व्यवसाय से सयुक्त पूँजी वाले बैंको के ऊपर बुरा असर न पड़े। सन् १९२७ ई० के विधान के द्वारा इम्पीरियल बैंक की कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन कर दिये गये।

(१) यह बैंक अपनी सरक्षकता में जहाँ उपयुक्त हो वहाँ शाखा खोल सकता है।

(२) यह बैंक विदेशी हुण्डियों का भी लेन-देन कर सकता है।

(३) पूँजी के लेन-देन पर से भी प्रतिबन्ध हटा लिये गये।

इम्पीरियल बैंक की १९२१ से १९३४ तक की उन्नति जानने में निम्न तालिका सहायक हो सकती है। (रूपों की गणना लाखों में है)

वर्ष का अन्ति	प्राप्त पूँजी	संचित	सरकारी जमा	व्यक्तिगत जमा	चालू पूँजी	बैंको की संख्या
१९२१	५६२	४०२	६,८०	६५,७८	१३,६८	८८
१९२२	५६३	४२३	१४,१६	५७,००	१५,०७	१०६
१९२३	५६३	४४५	८,५०	७४,२०	१५,०१	१४९
१९२४	५६३	४६८	७,५०	७६,७१	१५,६०	१६५
१९२५	५६३	४८३	५,४७	७७,८३	१७,४७	१८१
१९२६	५६३	५००	६,४५	७३,९०	२०,९०	१८६
१९२७	५६३	५१३	७,२०	७२,०७	१०,८९	१९८

१९२८	५६३	५२३	७,९५	७१,३०	१०,५८	२०२
१९२९	५६३	५३३	७,६०	७१,६४	१४,००	२०३
१९३०	५६३	५३९	७,३७	७६,६०	१३,०४	२०६
१९३१	५६३	५,००	८,३२	६३,८६	११,०४	२०१
१९३२	५६३	५,१७	७,०७	६८,३६	२०,९७	२०१
१९३३	५६३	५,२३	६,४४	७४,१३	१८,६०	२०२
१९३४	५६३	५३५	६,७२	७४,२८	१८,९७	२२१

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बैंक की चुकता पूंजी तो यथावत् स्थिर रही पर सचय १९३० तक बराबर बढ़ता चला गया, १९३१ में थोड़ी सी कमी हुई। शायद अवसाद-काल के कारण ऐसा हुआ। फिर अगले तीन वर्षों में वह कमी पूरी हो गयी। जनता का जमा धन एक ही साल में ११२ प्रतिशत बढ़ गया। १९३१ से जमा में बराबर वृद्धि होती रही तथा नकद जमा की स्थिति भी सुविधाजनक रही, क्योंकि बैंक की नयी-नयी शाखाएँ हर साल खुलती रही हैं।

१९२६ के प्रारम्भ तक इम्पीरियल बैंक ने विनिमय बैंक व नये बैंकों की अपेक्षा अपनी दुनी शाखाएँ कर ली। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन दिनों इस बैंक ने जो उन्नति की उसका श्रेय अधिकतर सरकार को है, क्योंकि जनता के ऋण तथा कोषागार से सम्बन्धित सभी कार्य इसके अधीन कर दिये गये थे। साथ ही रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले तो बहुत से बड़े बैंक अपनी जमा राशि इसी बैंक में रखते थे तथा इसे अपना अगुआ मानते थे।

१९२६ में जब केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न चल रहा था, यह अनुमान किया गया कि इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक का रूप दे दिया जायगा। परन्तु हिल्टन यंग कमीशन ने इसका विरोध

किया। यह आशंका की गयी कि इससे व्यापारिक बैंकिंग के विकास को धक्का लगेगा, क्योंकि व्यापारिक बैंक व केन्द्रीय बैंक का कार्य साथ-साथ नहीं चल सकता।

भारतीय मत का एक पक्ष तो इस बात में सहमत था कि इम्पीरियल बैंक को ही पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक बना दिया जाय तथा इस मत को पुष्ट करने के लिए वह बैंक आफ फ्रान्स का उदाहरण प्रस्तुत करता था, क्योंकि यह बैंक व्यापारी बैंक न होते हुए भी व्यापारिक बैंक के सभी काम करता है। इसी प्रकार कामनवेल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया, १९२४ के पहले जब यह केन्द्रीय बैंक न था, व्यापारिक बैंकों के कार्य करता था तथा उसके बाद भी अपने पहले के सभी कार्य करता रहा। पर हम भारत के मुद्रा-बाजार की फ्रांस से तुलना नहीं कर सकते। दोनों की परिस्थितियों में असमानता है। वहाँ बिना किसी दबाव के व्यापारिक बैंक अपना अधिक से अधिक बाकी केन्द्रीय बैंक के पास रखते हैं तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रदत्त अनेक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। केन्द्रीय बैंक को वे अपना अगुआ मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसी मदद व एक दूसरे के प्रति शुभेच्छा की परम्परा कायम कर ली है और उसी का अनुसरण करते हैं। पर भारत में ऐसी अवस्था का सर्वथा अभाव है। इसके विपरीत अनेक बैंक इम्पीरियल बैंक को प्रतिद्वन्द्वी समझते थे।

हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे-जैसे समय बीतता गया बैंकिंग के विकास के साथ-साथ फ्रांस आदि देशों के केन्द्रीय बैंक भी अपना व्यापारिक बैंकिंग का कार्य कम करते गये तथा अपना ध्यान केन्द्रीय बैंकिंग के कार्यों की दिशा में ही रखने गये, क्योंकि बैंक आफ फ्रांस बहुत साल तक अग्रिम देने व बिल भुनाने में अन्य बैंकों का जबर्दस्त प्रतिद्वन्द्वी था, पर बाद में यह कार्य स्वतः कम करता गया।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि एक पृथक् केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव बुद्धिमत्ता थी। इम्पीरियल बैंक को केवल व्यापारिक बैंकिंग के विकास के लिए छोड़ दिया गया। इम्पीरियल बैंक पर जो सब से अधिक दोष लगाया गया वह यह है कि इस बैंक ने अपनी सुदृढ़

स्थिति के कारण अन्य बैंको का बाजार हड़प करते हुए अनुचित फायदा उठाया। क्योंकि सरकार से इसका एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो गया था तथा इसका प्रबन्ध मुख्यतः विदेशियों के हाथ में था, अतः यह अपने लाभ के लिए सभी कार्य करता था और राष्ट्र के हित की अवहेलना करना इसके लिए स्वाभाविक था।

रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद की स्थिति—रिजर्व बैंक की स्थापना सन् १९३४ में हो जाने से इम्पीरियल बैंक के स्वरूप में अन्तर आ गया। इम्पीरियल बैंक एमेडमेन्ट ऐक्ट १९३४ के अनुसार यह अब सरकारी बैंक न रह गया और न सरकार इसके प्रबन्ध में कोई दिलचस्पी ले सकती थी। भारत सरकार केन्द्रीय बोर्ड में अपना एक प्रतिनिधि भेज सकती थी, पर उसे मत-दान का कोई अधिकार न रह गया। इस बैंक पर पहले जो थोड़े से बैंकिंग कार्यों के प्रतिबन्ध लगाये गये थे वे हटा लिये गये। इस ऐक्ट के अनुसार यह बैंक जहाँ चाहे वहाँ शाखा खोलने के लिए स्वतन्त्र हो गया। विदेशी विनिमय कार्य करने की इसे स्वतन्त्रता दे दी गयी। साथ ही साथ विदेश से यह ऋण भी ले सकता है। यह उन विदेशी विनिमय-पत्रों का क्रय-विक्रय भी कर सकता है जो कृषि के लिए सामयिक आर्थिक सहायता के सबंध में लिखे गये हों तथा जिनकी अवधि नौ महीने की हो। और अगर अन्य प्रकार की हो तो वह अवधि छ महीने होनी चाहिए। अब इसे परिकल्पनिक रेहन पर अग्रिम धन देने की स्वतन्त्रता मिल गयी। अब यह रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अंश की प्रतिभूति पर भी ऋण दे सकता है तथा सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के अंश की जमानत पर भी ऋण दे सकता है। पर केन्द्रीय सरकार से इसके लिए अनुमति लेनी होती है।

वास्तव में देखा जाय तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना ने इम्पीरियल बैंक को मुद्रा-बाजार में सही रूप में प्रकट कर दिया। रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में यह अब भी उस स्थान पर कार्य करता है जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं। थोड़ी सी कमी यह हुई है कि जनता को पहले सरकारी बैंक के रूप में यह जितना आकृष्ट करता था उतना

अब नहीं कर पाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारतसरकार का इसे बहुत दिनों तक संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि सरकार इसके पास अपनी जमा बिना किसी ब्याज के रखती थी। पर अधिकतर जनता का विश्वास इस बैंक में इस लिए था कि इसने प्रति वर्ष अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया तथा अपनी सम्पत्ति की तरलता उच्च कोटि की बनाये रखी। अपने केन्द्रीय बैंक के स्वरूप तथा सीमित मात्रा में ऋण देने की क्षमता के कारण भी इसे अपनी सम्पत्ति तरल रखनी पड़ती थी। शुरू में इस बैंक ने अपनी शाखाओं का विस्तार करने की नीति अपनायी, जिससे इसका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया, इसलिए यह देश के कोने कोने में बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सका। १९२६ में इसकी १८६ शाखाएँ थी जो १९३९ तक बढ़कर ३८१ हो गयी। १९३५ से यह बैंक साधारण बैंकिंग के कार्य के साथ विदेशी बिल का कार्य भी कर रहा था। फिर भी अपने विस्तृत साधनों के कारण व रिजर्व बैंक के एजेंट होने के कारण इसकी स्थिति दूसरों से कुछ भिन्न थी। शुरू के कुछ वर्षों में तो व्यापारी लोग बैंक बिलों के पुन भुगतान या ऋण आदि इसी से लेना पसन्द करते थे, रिजर्व बैंक में नहीं। शुरू के तीन वर्षों में रिजर्व बैंक का बिल का कार्य एकदम शून्य रहा तथा ऋण व अग्रिम का कार्य बहुत थोड़ा हुआ। इसके विपरीत इम्पीरियल बैंक की स्थिति इन मामलों में अच्छी रही।

उपर्युक्त संक्षिप्त इतिहास से यह पता चलता है कि अनेक कठिनाइयों के होने पर भी भारत में बैंकिंग का विकास धीरे धीरे पर बराबर होता रहा। संयुक्त स्कन्ध बैंको के विकास से यह बात और स्पष्ट हो जाती है। १९३९ तक उनकी पूँजी तथा सचय ५ लाख का था जो बाद में बढ़कर ५१ लाख हो गया तथा उनकी कुल चुकता पूँजी १३ करोड़ हो गयी तथा जमा बढ़कर १०१ करोड़ रुपये हो गयी। फिर भी इस उन्नति का यह नियोजित व सुव्यवस्थित रूप नहीं कहा जा सकता। इनका विकास अव्यवस्थित रूप से हुआ है, क्योंकि ३८ प्रतिशत शहर जिनकी जनसंख्या २०,००० से भी अधिक थी,

१९३१ के अन्त तक बिना किसी बैंकिंग की सुविधा के थे । इनके दफ्तर पंजाब, उ० प्र०, बंबई, मद्रास, बंगाल में तो उचित रूप से विस्तारित थे पर बिहार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम आदि प्रान्तों में इनका अधिक अभाव था । बैंकों के इस असमान विकास का यह कारण था कि इनकी उन्नति थोड़े से लोगों के हाथों से होती थी । परिणाम यह होता था कि जिस शहर में किसी बैंक ने अपनी कोई शाखा खोली तो दूसरे बैंक उसका अनुकरण करके अपनी-अपनी शाखाएँ उसी शहर में खोलते थे । बड़े बैंक अपनी शाखाएँ बड़े शहरों में ही स्थापित करते थे । इसलिए दो तिहाई शहरों को बैंकिंग सुविधा के लिए छोटे बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता था । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश बैंक भारतीय रियासतों में अपनी शाखाएँ खोलने के पक्ष में भी न थे, क्योंकि वैधानिक व शासन सम्बन्धी कठिनाई होती थी तथा रियासतें इम्पीरियल बैंक को अपने क्षेत्र में शाखाएँ खोलने के लिए कुछ सुविधाएँ भी नहीं देती थी ।

अध्याय ४

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया

सरकारी बैंक के रूप में इम्पीरियल बैंक के किये जाने वाले कार्यों को अपूर्ण पाकर तथा भारतीय साख-प्रणाली के दोषों पर ध्यान देते हुए देश के विभिन्न अधिकारियों एवं अर्थशास्त्रियों ने यह आवश्यकता प्रकट की कि देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। उनका कहना था कि केन्द्रीय बैंक की स्थापना हो जाने से भारत के आन्तरिक एवं बाह्य व्यापार की प्रगति में बाधक होने वाले निम्न दोष दूर हो सकेंगे।

१ भारतीय मुद्रा की आन्तरिक एवं बाह्य क्रय-शक्ति में स्थिरता केन्द्रीय बैंक की ही सहायता से की जा सकती है। मौलिक पतन, जैसे अकाल, बाढ़ एवं युद्ध आदि के कारण उत्पन्न होने वाली आन्तरिक क्रय-शक्ति की अस्थिरता यद्यपि तत्कालीन इम्पीरियल बैंक की सहायता से दूर की जा सकती थी, किन्तु मांग एवं पूर्ति के असन्तुलन के कारण होनेवाली क्रय-शक्ति की अस्थिरता को केवल एक केन्द्रीय बैंक ही सफलतापूर्वक दूर कर सकता था। मुद्रा की क्रयशक्ति उसी समय स्थिर रह सकती है जब कि देश में मुद्रा का चलन उसके विनिमय के माध्यम के रूप में होनेवाली आवश्यकता द्वारा निश्चित किया जाय। यह कार्य केन्द्रीय बैंक की कार्य-प्रणाली में ही सम्भव है। बाह्य व्यापार के क्षेत्र की मौद्रिक क्रय-शक्ति की स्थिरता किसी देश की आन्तरिक क्रय-शक्ति की स्थिरता पर निर्भर होती है। यह बात पूर्णतः सत्य है कि यदि देश के आन्तरिक व्यापार में मुद्रा की क्रयशक्ति स्थिर हो, तो बाह्य व्यापार में भी उसकी क्रयशक्ति स्थिर रहेगी। यदि भारत में निर्मित वस्तुओं का मूल्य विश्व-बाजार के मूल्य की अपेक्षा बढ़ता है तो भारत का आयात-व्यापार उत्थान की ओर अग्रसर होगा, परन्तु दूसरी ओर वही स्थिति निर्यात व्यापार के लिए अभिशाप बन जायगी। इस

प्रकार निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़ जायगा और परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार प्रतिकूल हो जायगा। इसी प्रकार भारत में निर्मित वस्तुओं का मूल्य विदेशी वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा घट जाने पर देश का निर्यात व्यापार तो बढ़ेगा किन्तु आयात-व्यापार बहुत नीचे गिर जायगा। ये दोनों स्थितियाँ देश के लिए अहितकर हैं। केन्द्रीय बैंक की सहायता से यह कठिनाई दूर की जा सकती है, क्योंकि आयात एवं निर्यात व्यापार को सन्तुलित बनाये रखने के लिए देश में निर्मित वस्तुओं के मूल्य में कमी या वृद्धि द्वारा मूल्य नियंत्रित किया जा सकता है। यह कार्य केन्द्रीय बैंक नोट प्रकाशन के एकाधिकार और साख-नियंत्रण की प्रणाली को अपनाकर सम्पादित कर सकेगा।

आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक उचित सीमा तक सोने तथा स्टर्लिंग का क्रय-विक्रय करके मुद्रा के बाह्य मूल्य अर्थात् विनिमय दर को स्थिर रख सकता है। मुद्रा की बाह्य स्थिरता उसकी आन्तरिक मूल्य-स्थिरता पर आधारित होती है। देश में नोटों का निर्गमन उचित प्रतिशत में सोना सुरक्षित रखकर ही होता है और यही सुरक्षित सोना देश के विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने में सहायक सिद्ध होता है।

२ भारतीय बैंकिंग प्रणाली के आधारभूत दोषों को दूर कर मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनाये रखने में भी केन्द्रीय बैंक सहायक होता है। सन् १९३५ तक तो बैंकिंग प्रणाली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। किसी भी आकस्मिक घटना पर, जैसे बड़ी रकम की अचानक निकासी होने अथवा आर्थिक क्रान्ति के आ जाने पर बैंकिंग-व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि नोटों का प्रकाशन बिना किसी प्रकार का सुरक्षित कोष रखे ही किया जाता था। ऋण देते समय भी सोने आदि के रूप में कोई जमानत नहीं रखी जाती थी। इस प्रकार की व्यवस्था कही भी थी तो वह अपर्याप्त थी। देश के व्यापारिक एवं विनिमय बैंक अपनी तरल सम्पत्ति की सहायता से, बिना सुरक्षा का खयाल किये ही बड़े-बड़े व्यापार प्रारम्भ कर देते थे। इस

प्रकार उनकी सारी सम्पत्ति व्यापार में फस जाती थी और किसी भी आकस्मिक घटना, जैसे अकाल, बाढ़, युद्ध अथवा आर्थिक क्रान्ति के समय वे परिस्थिति को सभाल न पाते थे। परिणाम-स्वरूप उन्हें अपना कार्य बंद कर देना पड़ता था।

किसी भी आकस्मिकता के समय जनता को सन्तुष्ट रखने का एक मात्र तरीका यह है कि जनता को उसकी मांग के अनुसार ही उचित समय पर भुगतान कर दिया जाय। इस नीति के अन्तर्गत बैंको को एक-दूसरे बैंक की सहायता लेनी पड़ती है। परन्तु प्रत्येक बैंक की तरल पूँजी कम होने के कारण वे एक-दूसरे की सहायता नहीं कर पाते थे और वे स्वयं अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास में लग जाते थे। इस प्रकार उनमें आपसी शत्रुता के भाव उत्पन्न हो जाते थे। किसी भी बैंक से जनता का विश्वास उठ जाने पर सभी बैंको पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता था। बैंक विघटित होने लगते थे। इसका कारण यह था कि किसी बैंक को किसी अन्य बैंक अथवा किसी अन्य आर्थिक संस्था से कोई सहायता नहीं मिलती थी।

यद्यपि सन् १९२१ से १९३५ तक इम्पीरियल बैंक ने बहुत कुछ एक आर्थिक संस्था के रूप में कार्य सम्पादित किया किन्तु फिर भी वह पूर्ण रूप से बैंको के बैंक का कार्य न कर सका। अन्य बैंको पर उसका कोई नियन्त्रण भी न था, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही थोड़ी रकम सुरक्षित कोष के रूप में इम्पीरियल बैंक में रखी गयी थी।

ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि प्रत्येक बैंक द्वारा एक निश्चित रकम सुरक्षित कोष के रूप में रिजर्व बैंक नामक केन्द्रीय संस्था के पास जमा की जाय। आर्थिक कठिनाइयों में इस कोष का प्रयोग किया जा सकता है। केन्द्रीय बैंक इस रकम से किसी भी बैंक की, उसकी स्थिति अव्यवस्थित एवं डावाडोल होने पर समुचित सहायता तो करेगा ही, साथ ही इसी रकम की आड़ में नोटों का प्रकाशन करके देश के आन्तरिक व्यापार को भी सुव्यवस्थित रख सकेगा। केन्द्रीय बैंक की कार्य-प्रणाली के अन्तर्गत जनता का विश्वास

प्रत्येक बैंक पर बना रहता है, जिससे लोग नकद रुपये के स्थान पर साखपत्रों को स्वीकार करने में सकोच नहीं करते। इस प्रकार वह रकम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगायी जा सकती है और विदेशी व्यापार में भी भुगतान के लिए उसकी सहायता ली जा सकती है।

केन्द्रीय बैंक के पास सुरक्षित कोष रखने से यह भी लाभ होता है कि मुद्रा की गतिशीलता अधिक बढ़ जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया सरलता से स्थानान्तरित किया जा सकता है और रुपये को, जो कि एक स्थान पर अनावश्यक सा है अथवा कम उपयोगी है, दूसरे स्थान को भेजकर उसकी उपयोगिता अत्यधिक बढ़ायी जा सकती है और रुपये की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति की जा सकती है।

इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंकों की साख-नीति में काफी लोच लायी जा सकती है तथा समय समय पर साख आवश्यकतानुसार घटायी-बढ़ायी जा सकती है। विदेशों में तो इस तरह का कोई भी सरकारी नियन्त्रण नहीं है। हा इतना अवश्य है कि केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों के बीच एक समझौता होता है और उसी के अनुसार केन्द्रीय बैंक के पास सुरक्षित कोष रखे जाते हैं। किन्तु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विधान द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया है कि प्रत्येक बैंक एक निश्चित प्रतिशत कोष केन्द्रीय बैंक के पास अवश्य रखे। भारतवर्ष में बैंकों की संख्या कम होने के कारण केन्द्रीय बैंक की शक्ति को मजबूत करने के लिए तथा उसे बैंकों के बैंक (पोषक बैंक) के रूप में कार्य करते रहने के लिए प्रत्येक बैंक को एक निश्चित रकम कोष के रूप में उस के पास रखना विधान द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है।

३ देश की साख-नीति को नियंत्रित रखने एवं उसका समुचित प्रबंध करने के लिए भी एक केन्द्रीय बैंक का होना आवश्यक हो गया। यह प्रबंध तभी ठीक रहेगा जब कि मुद्रा एवं साख को व्यापार और उद्योग को आवश्यकता के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सके। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक मुद्रा और साख पर नियन्त्रण करके वर्तमान मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने में समर्थ होता है।

अब तक तो साख-नियंत्रण का कार्य इम्पीरियल बैंक करता था और नोट निर्गमन का कार्य सरकार करती थी। इस नीति से साख-नियंत्रण में बाधा पड़ती थी। इसी लिए रिजर्व बैंक नामक एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करके ये दोनों कार्य उसे ही सौंपने की बात सोची गयी। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के निम्न अधिकार भी निश्चित किये गये।

(अ) नोट-निर्गमन का एकाधिकार।

(ब) बैंको की माग-देनदारी (Demand Liability) पर ५% तथा कालिक देनदारी (Time Liability) पर २% जमा लेने का अधिकार माना गया, जिससे बैंको एवं उनकी साख पर नियंत्रण रखा जा सके।

(स) सरकारी कोष की राशि भी इस बैंक में जमा रहे।

(द) बिलो की पुन कटौती (Rediscounting) करने का अधिकार इसे प्राप्त हो।

(य) समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसे खुले बाजार की क्रिया (open market operation) अपनाकर सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय करने का भी अधिकार दिया जाय।

(र) समाशोधन-गृह (cleaning home system) का कार्य भी इसे सौंपा गया है।

इन सबके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक अपने विधान द्वारा प्रत्येक बैंक के सदस्यों को बाध्य करे कि वे अपने दायित्व को द्रव्य के रूप में उस के पास जमा कर दिया करें।

४ अब तक देश के बैंको, मुद्रा-मण्डियो, स्वदेशी बैंकरो तथा अन्य प्रकार की मौद्रिक संस्थाओ की आर्थिक स्थिति का ठीक एवं पूर्ण विवरण जनता के सम्मुख प्रकाशित नहीं हो पाता था। अतः इनकी स्थिति से सम्बन्धित आकड़ों के प्रकाशन का कार्य-भार भी रिजर्व बैंक को सौंपा गया। रिजर्व बैंक के इस कार्य में सरकार भी सहायता पहुंचाती है। प्रारम्भ में केन्द्रीय बैंक का यह कार्य बहुत समय तक सन्तोषजनक नहीं था इसका कारण यह था कि विनिमय-बैंक अपने विस्तृत विवरण प्रकाशित

नहीं कराते थे। वे केवल भारत में जमा की गयी रकम तथा नकदी का ही सक्षिप्त लेखा डाइरेक्टर जनरल कामर्शियल इन्टेलीजेन्स, कलकत्ता के द्वारा प्रकाशित कराते थे। बहुत से आकड़े तो डाइरेक्टर जनरल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली विवरणी के द्वारा भी प्राप्त न होते थे, विशेष कर उन बैंको का विवरण प्राप्त न होता था जिनकी पूँजी एक लाख रुपये से कम थी।

केन्द्रीय बैंक अब एक सांख्यिकीय सूची तैयार करता है जिसमें सभी प्रकार के बैंको की स्थिति से सम्बन्धित आकड़े दिये रहते हैं। फिर भी विनिमय-बैंको के भारतीय व्यापार सम्बन्धी आकड़े अलग से नहीं प्राप्त हो पाते हैं। भारतीय सह-कारिता आन्दोलन से सम्बन्धित एक सांख्यिकीय सूची भी यह केन्द्रीय बैंक प्रकाशित करता है।

५ इस बात की भी आवश्यकता हुई कि कोई सस्था सरकारी राशि को सुरक्षित रखकर सरकार की आज्ञानुसार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का प्रबन्ध एवं विदेशी विनिमय का क्रय सरकार के आर्थिक प्रतिनिधि के रूप में करे। यह कार्य रिजर्व बैंक को सौंपा गया, क्योंकि यह मुद्रा-बिपणियों (money markets) से बहुत ही सुगम होता है। रिजर्व बैंक सरकारी ऋण-पत्रों तथा ट्रेजरी-बिलों का भी निपटारा करता है। यह भारत सरकार की ओर से लंदन में होने वाले भारत सम्बन्धी व्ययों (Home expenses) का भुगतान करता तथा समय समय पर सरकार को आर्थिक सलाह देने का कार्य करता है।

६ कृषि के क्षेत्र में मौद्रिक व्यवस्था करने एवं समय समय पर होने वाली कृषकों की मौद्रिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कोई सस्था न थी, इस लिए कृषि की अर्थव्यवस्था का कार्य भी रिजर्व बैंक के हवाले किया गया। इस कार्य के लिए अलग से वह एक कृषि-साख विभाग (Agriculture credit Department) खोले हुए हैं। कृषि के सहायतार्थ रिजर्व बैंक निम्न कार्य करता है—

(क) कृषकों की सामयिक सहायता के लिए सहकारी बैंक द्वारा

निर्गमित विनिमय बिलो एव प्रतिज्ञा-पत्रो (प्रामेसरी नोटो) को समय से पहले ही रिजर्व बैंक भुना देता है। इसके लिए वह कुछ छूट लेता है।

(ख) फसलो को गिरवी रखकर सहकारी समितियों द्वारा निर्गमित प्रतिज्ञा-पत्रो पर कृषको को ऋण देने की व्यवस्था भी रिजर्व बैंक करता है।

(ग) सहकारी समितियों के साख-पत्रो (क्रेडिट) मनीको स्वीकार कर रिजर्व बैंक उन्हें केन्द्रीय मुद्रा विपणियो में कार्य करने की अनुमति देता है।

(घ) रिजर्व बैंक, सरकार की जमा की राशि का एक निश्चित भाग बिना ब्याज के ही प्रान्तीय सहकारी बैंको को दे सकता है।

७ देश की बैंकिंग प्रणाली पर समुचित नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक जैसी एक केन्द्रीय सस्था की आवश्यकता थी। इसको रिजर्व बैंक पूर्णतया पूरा करता है। देश के आन्तरिक व्यापार को साख सम्बन्धी सुविधाएँ भी केन्द्रीय बैंक प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक व्यापार की मौद्रिक आवश्यकता को यह पूरा करता है। जहाँ कहीं केन्द्रीय बैंक की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ देशी बैंको को यह अपना प्रतिनिधि बना देता है। यदि देशी बैंक इसकी शर्तों को पूरी नहीं कर पाते हैं तो कुछ बैंक मिलकर एक एसोसियेशन बना लेते हैं। यही एसोसियेशन केन्द्रीय बैंक की शर्तों को पूरा करके उसका प्रतिनिधि बन सकता है। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक अपने इन प्रतिनिधियों को रुपया अग्रिम देता है तथा उनके द्वारा प्रसारित हुण्डियो को भी भुनाता है। इन प्रतिनिधियों को उनकी सेवाओं के लिए कुछ कमीशन भी रिजर्व बैंक देता है। इस प्रकार जनता में साख-पत्रो के प्रति विश्वास बना रहता है।

स्वदेशी बैंकरो को, जो पूर्णतया स्वतंत्र थे, नियंत्रण में लाने का कार्य-भार भी रिजर्व बैंक को सौंपा गया, क्योंकि इस कार्य के लिए केन्द्रीय बैंक ही उपयुक्त समझा गया।

८ अन्य देशो ने केन्द्रीय बैंक स्थापित कर लिये थे। इसलिए उनके साथ मौद्रिक होड में चलने के लिए भारत में भी एक केन्द्रीय

बैंक स्थापित करना आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त देश के बैंकिंग विकास की गति का सूक्ष्म निरीक्षण एवं संचालन भी केन्द्रीय बैंक ही कर सकता है।

यदि पिछले ५० वर्षों में विश्व के बड़े बड़े व्यापारिक देशों में हुई उलट-फेर पर दृष्टि डाली जाय तो केन्द्रीय बैंक की स्थापना का महत्व और भी अधिक स्पष्ट होगा। सन् १९१३ के पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के देशों एवं विदेशी व्यापार में एक भयानक क्रांति आ गयी थी। वह पतन की ओर चला जा रहा था। किन्तु सन् १९१३ में एक केन्द्रीय अधिकोषण प्रणाली की व्यवस्था हो जाने से अमेरिका आज विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है।

इन उपर्युक्त कारणों से सन् १९३४ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट पास किया गया। उसी के अनुसार अप्रैल सन् १९३५ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्थापना हुई।

सरकारी बैंक बनाम अशधारियों का बैंक—सन् १९३४ में की गयी प्रतिनिधि समिति की सिफारिशों पर ज्यों ही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट पास हुआ और बैंक ने सन् १९३५ में अपना कार्य प्रारम्भ किया, यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि यह सरकारी बैंक हो अथवा अशधारियों का बैंक। इस सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद चला। अशधारियों के बैंक के रूप में इसका समर्थन करने वालों ने निम्न तर्क प्रस्तुत किये।

१ विश्व के २८ केन्द्रीय बैंकों में से २२ तौँ अशधारियों के बैंक हैं। शेष ६ बैंक जो सरकारी बैंक के रूप में कार्य करते हैं उन में एक निश्चित सीमा के पश्चात् राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

२ देश के केन्द्रीय बैंक के कतव्य एवं अधिकारों पर किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव न पड़े तो अधिक उत्तम होगा। मुद्रा-प्रसार का काय मुद्रा-प्रकाशन के कार्य से अलग ही रखना ठीक होगा। मुद्रा का सब से अधिक उपयोग सरकार करती है किन्तु फिर भी रिजर्व बैंक का नियंत्रण सरकार के हाथ में चले जाने पर अनेक प्रकार की गड़बड़ियों की सम्भावनाएँ हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के समय बैंकों से अधिकाधिक मात्रा

में पत्र-मुद्रा प्रकाशित कराकर सरकार ने इस प्रकार का अनुचित लाभ उठाया था। अतः मुद्रा एव साख के कार्य में रिजर्व बैंक को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।

३ अशधारियों का यह विचार था कि सचालको द्वारा प्रदत्त धन के लिए वे पूर्ण सचालकता वहन करें तथा अशधारी भी अपने द्वारा दिये गये धन के लिए स्वयं उत्तरदायी हों।

४. अशधारियों के बैंक होने का एक गुण यह है कि इसके सचालको का चुनाव प्रत्येक प्रदेश से होगा। इससे देश के सभी प्रदेशों से रिजर्व बैंक को उचित सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

५ बैंक की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप एक अवैधानिक कार्य है।

६ विधान-सभा के सदस्यों को अपने कार्य के अतिरिक्त रिजर्व बैंक के सचालन का कार्य भी करना न तो सम्भव है और न वह ठीक से हो ही सकेगा।

७ रिजर्व बैंक पर केवल पंजीपतियों का ही एकाधिकार होना रोकने के लिए भी आवश्यक था कि बैंक के कुल अंशों को सारी जनता में बांट दिया जाय तथा अशधारियों के मतदान अधिकार पर समुचित प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

• इन सब तर्कों के फलस्वरूप सन् १९३५ में रिजर्व बैंक को अशधारियों का बैंक घोषित किया गया। किन्तु इसे सरकारी बैंक बनाने के पक्ष में वाद-विवाद चलता ही रहा। फरवरी सन् १९४७ में रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पुनः केन्द्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न युक्तियाँ पेश की गयीं।

१—रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों को निजी अशधारियों एवं निजी सचालकों के हाथ में रहने देना ठीक नहीं है, क्योंकि वे अपने हितों की ओर ही अधिक ध्यान देंगे।

२—रिजर्व बैंक के अधिकतर अशधारी यूरोपियन थे इस लिए बैंक पर यूरोपियनों का एकाधिकार हो जाने की सम्भावना थी।

३—जिन देशों में केन्द्रीय बैंक अशुधारियों के हाथ में हैं वहाँ इस बैंक की मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए केन्द्रीय सरकार को ओर से एक गवर्नर तथा एक डिप्टी गवर्नर रखना पड़ता है। इस लिए इसे एक राष्ट्रीय संस्था ही बना देना ठीक होगा।

४—विश्व के अधिकतर देशों में सरकार की आर्थिक एवं मौद्रिक नीति निर्धारण की सुविधा के लिए केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, इसलिए भारत में भी राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता महसूस की गयी।

५—युद्ध के पश्चात् जनसाधारण के जीवन-स्तर को ऊँचा करने एवं उसकी विषमता दूर करने के लिए आर्थिक नियोजन की अत्यन्त आवश्यकता हुई। ऐसी योजनाओं की सफलता के लिए भी केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो गया।

६—स्वदेशी बैंकों पर नियन्त्रण स्थापित करने तथा भारतीय मुद्रा-बाजार के दोषों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था। साथ ही साथ राष्ट्रीय महत्व वाली व्यापारिक संस्थाओं पर राज्य का ही स्वामित्व अपेक्षित था।

७—किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था का राजनीति से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जिस प्रकार आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार राजनीति में परिवर्तन करना पड़ता है उसी प्रकार राजनीतिक परिवर्तनों के अनुसार देश की आर्थिक एवं मौद्रिक नीतियों में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टिकोण से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वांछनीय ही गया।

इस प्रकार रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बैंकिंग का कार्य तथा मुद्रा नियन्त्रण का कार्य सरकार के अधीन कर देना अधिक विवेकपूर्ण लगता है।

८—युद्ध के पश्चात् बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर नियन्त्रण रखने के निमित्त भी रिजर्व बैंक को प्रकारी स्वामित्व में रखना आवश्यक था।

९—विदेशों से समुचित सहयोग प्राप्त करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कौष एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से सम्बन्ध स्थापित करने और उससे लेन-देन

करने के लिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होना ही ठीक था।

१०—देश की विभिन्न प्रकार की मौद्रिक सस्थाओं एवं अधिकोषणों से आवश्यक सूचनाएँ संगृहीत करने की सुविधा की दृष्टि से भी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया।

११—यह भी आवश्यक समझा गया कि जनता द्वारा बैंकों में जमा किये गये धन से होने वाला लाभ तथा पत्र-मुद्रा के प्रकाशन से होने वाला लाभ जन-हित की वृद्धि के विचार से जन-कोष (ट्रेजरी) में जमा किया जाय।

उपर्युक्त कारणों से १ जनवरी सन् १९४९ को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अशधारियों के १०० रुपये वाले अंश के लिए सरकार ने ११८ रुपया १० आना भुगतान देना स्वीकार किया। १०० रुपये के लिए तो ३६० वार्षिक ब्याज की दर वाले सरकारी बाण्ड निर्गमित किये गये और शेष राशि का नकद भुगतान किया गया। सन् १९३४ वाले रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट में भी आवश्यक संशोधन कर दिया गया।

रिजर्व बैंक का सङ्गठन

प्रारम्भ में इसका संगठन, प्रबन्ध एवं संचालन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, १९३४ के अन्तर्गत होता रहा है। परन्तु सन् १९४९ में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् अब इसका प्रबन्ध एवं संचालन १९४९ वाले संशोधित विध्याद के अनुसार होता है।

बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है और समय-समय पर उसकी सलाह से जनहित को ध्यान में रखकर बैंक को आवश्यक आदेश भी देती है। बैंक का केन्द्रीय बोर्ड उन आदेशों के अनुसार ही बैंक का संचालन करता है। बोर्ड के आदेशों का अनुगमन करते हुए बैंक के प्रबन्ध का अधिकार बैंक के गवर्नर को प्राप्त है।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व यह प्रतिबन्ध था कि बैंक के अंश भारतीय लोगों, भारत में निवासी करने वाले अंग्रेजों एवं भारतीय प्रमण्डल-विधान द्वारा पञ्जीकृत प्रमण्डलों द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं। अशधारियों को

वितरित किये जाने वाले अशो की सख्या पर भी प्रतिबन्ध था। किन्तु ध्यान रहे कि अब रिजर्व बैंक की सारी पूंजी सरकार की है, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है।

रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निम्न व्यक्ति होते हैं—

१ गवर्नर—रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होता है जिसको केन्द्रीय सरकार ५ वर्ष के लिए नियुक्त करती है। पर ५ वर्ष के पश्चात् उसको दुबारा नियुक्त किया जा सकता है। बैंक का केन्द्रीय बोर्ड ही सरकार की सलाह से इसका वेतन निश्चित करता है।

२ दो डिप्टी गवर्नर—इनको भी केन्द्रीय सरकार ही मनोनीत करती है। ये केन्द्रीय बोर्ड की बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु मतदान का अधिकार इन्हें नहीं प्राप्त है। हा, गवर्नर की अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर को मतदान अधिकार प्राप्त हो सकता है। किन्तु इसके लिए गवर्नर एक लिखित प्रमाणपत्र डिप्टी गवर्नर को देता है।

३ चार सचालक—केन्द्रीय बोर्ड के लिए चारों स्थानीय बोर्डों में चार सचालक नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार चुनता है।

४ छ सचालक और होते हैं जिनका चुनाव केन्द्रीय सरकार करती है। इनमें से प्रत्येक दो बारी बारी से—एक, दो, तीन वर्ष बाद अलग होते जाते हैं।

५ केन्द्रीय बोर्ड की देखरेख के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक सरकारी अधिकारी होता है, जो सरकार की आज्ञानुसार कितने ही समय तक कार्य कर सकता है। इसे भी मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।

इस प्रकार कुल १४ व्यक्ति केन्द्रीय बोर्ड में होते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त सचालक अवधि समाप्त होने पर फिर से चुन लिये जा सकते हैं। बैंक के प्रबन्ध की सुविधा के लिए चार स्थानीय बोर्ड भी कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में हैं। सीमा की दृष्टि से पूरे देश को चार क्षेत्रों में बांट दिया गया है जो उत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र हैं। इनका वर्णन रिजर्व बैंक विधान के प्रथम परिशिष्ट में किया गया है। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में ६५ सदस्य होते हैं जिन्हें सरकार

चुनता है। ये सदस्य अपने में से एक सभापति चुन लेते हैं। वैसे तो सदस्यों का कार्यकाल ४ वर्ष है किन्तु वे फिर नियुक्त किये जा सकते हैं।

इन सदस्यों की योग्यताएँ निम्न प्रकार से प्रतिबन्धित हैं।

(क) किसी बैंक का कर्मचारी अथवा सचालक इस बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता।

(ख) केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधानसभा का सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता।

(ग) कोई सरकारी अधिकारी बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता।

(घ) ऐसी फर्म का साझीदार, जो फर्म दिवालिया घोषित कर दी गयी हो, बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता।

स्थानीय बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देते हैं तथा केन्द्रीय बोर्ड के आदेशों का पालन करते हैं। यों तो गवर्नर ही आवश्यकतानुसार केन्द्रीय बोर्ड की बैठक बुलाता है, परन्तु कोई तीन सचालक मिलकर बैठक बुलाने के लिए गवर्नर से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रति वर्ष कम से कम छ बैठक बुलाना अनिवार्य है, किन्तु तीन महीने में एक बैठक अवश्य होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक की पूँजी ५ करोड़ रु० है। इसके कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर में हैं। इसकी एक शाखा लदन में है जो अप्रैल सन् १९४६ में खोली गयी थी। केन्द्रीय सरकार की आज्ञा प्राप्त करके रिजर्व बैंक अन्य स्थान पर भी अपनी शाखाएँ खोल सकता है।

रिजर्व बैंक के प्रमुख विभाग निम्न प्रकार हैं।

१. अधिकोषण विभाग—इस विभाग का सीधा सम्बन्ध सदस्य बैंको के अधिकोषण सम्बन्धी कार्यों से होता है। बैंको का निरीक्षण एवं उनकी साख की सीमा आदि निर्धारित करना इसी विभाग के अधीन है। बैंको की माग-देनदारी की ५ प्रतिशत एवं काल-देनदारी की २ प्रतिशत राशि इसी विभाग में जमा रहती है। यह विभाग सरकार के कार्यों में भी सहायता पहुँचाता है।

२ नोट-निर्गमन-विभाग—यह विभाग नोटों के निर्गमन एवं नोटों के बदले सिक्के प्रदान करने का कार्य करता है ।

३ कृषि-साख-विभाग—यह विभाग कृषि-साख सम्बन्धी समस्याओं के अनुभवी विशेषज्ञों की नियुक्ति करता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों और प्रान्तीय सहकारी सस्थाओं तथा अन्य अधिकोषण सस्थाओं को कृषि-साख की सुविधाएँ प्रदान की जा सकें ।

४ शोध एवं अक-विभाग—यह विभाग मुद्रा शोध का कार्य करता है । इस विभाग का मुख्य कार्य मुद्रा-मण्डी, बैंकिंग तथा उपादन एवं लाभांश सम्बन्धी आकड़े प्रकाशित करता है । इस विभाग के तीन उप-विभाग इस प्रकार हैं—

(क) आर्थिक शोध विभाग—जो बैंक की सम्पत्ति एवं दायित्वों, स्कध-विनिमय के कार्यों तथा रोजगार की नीति पर विचार करता है ।

(ख) अक विभाग—जो बैंक के मौलिक आकड़े तैयार करता है व औद्योगिक उत्पत्ति मूल्यों एवं संयुक्त प्रमण्डलों के मूल्यों का निर्देशक बनाता है ।

(ग) आर्थिक अर्थशास्त्र विभाग—जो कृषि मूल्यों की स्थिरता, ग्रामीण बीमा-आय, पक्ष एवं केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार की समस्याओं पर विचार करता है ।

५ विदेशी विनिमय विभाग—यह विभाग विनिमय दर (Exchange-rate) को स्थायी रखने तथा विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का कार्य करता है ।

रिजर्व बैंक के कार्य

रिजर्व बैंक के कार्यों को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं ।

(अ) केन्द्रीय अधिकोषण के कार्य—देश का केन्द्रीय बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक को केन्द्रीय अधिकोषण के सारे कार्य सम्पादित करने पड़ते हैं, जो निम्न प्रकार हैं ।

१ सरकारी बैंकिंग का कार्य—रिजर्व बैंक सरकार का राजकोषीय प्रतिनिधि है। इसलिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकार की राशि को यह अपने पास जमा रखता है तथा उनके द्वारा स्वीकृत दूसरी सरकारों की राशि भी जमा रखता है। यही नहीं, सरकार की आज्ञानुसार इस राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करता है और उनके लेखों पर भुगतान का कार्य तथा विदेशी विनिमय का कार्य करता है। सरकारी राशि की जमा पर बैंक को ब्याज नहीं देना पड़ता है। आवश्यकता के समय सरकार के ट्रेजरी बिलों का विक्रय करके सरकार के लिए ऋण का प्रबंध भी यही बैंक करता है। जब सरकार को अल्पकालीन ऋण (केवल ३ मास तक के लिए) की आवश्यकता होती है तब वह रिजर्व बैंक से ऋण ले लेती है।

समय समय पर रिजर्व बैंक सरकार को मुद्रा-नीति, बैंकिंग नीति तथा विनियोग नीति से सम्बन्धित सलाह भी देता है।

२ बैंकों का बैंक—देश के सभी बैंकों का बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक सभी बैंकों की कुछ निश्चित राशि अपने पास रखता है और आवश्यकता के समय उसी से उनकी सहायता करता है। देश की अधि-कोषण एवं साख प्रणाली के विकास एवं संगठन का पूर्ण अधिकार इसे प्राप्त है।

रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध रखने वाले सभी बैंकों को इसकी सदस्यता स्वीकार करनी पड़ती है और उनके नाम विधान के दूसरे परिशिष्ट में लिख लिये जाते हैं। ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं। इन अनुसूचित बैंकों को अपनी माग-देनदारी का ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक और काल-देनदारी का २ प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। किसी भी सकट के समय इसी जमा की राशि से इन बैंकों को सहायता दी जाती है। चारों तरफ से निराश अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक ऋण भी प्रदान करता है। प्रत्येक बैंक को अपनी मासिक या मासाहिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक को देनी पड़ती है।

रिजर्व बैंक अपने अनुसूचित बैंकों की प्रतिभूतियों एवं विपत्तियों के

ऋय-विक्रय का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त साख-सुविधाओं के दुरुपयोग पर कोई भी आवश्यक प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार इसको प्राप्त है।

३ नोट-निर्गमन का कार्य—देश की मुद्रा एवं साख-नीति पर नियन्त्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार दे दिया गया है। नोट निर्गमन के लिए एक नोट निर्गमन विभाग होता है जिसका अस्तित्व अन्य विभागों से पूर्णतया भिन्न रहता है। रिजर्व बैंक विधान की धारा २४ के अनुसार यह २, ५, १० और १०० रु० के नोट प्रकाशित करता है। सभी नोट विधि-ग्राह्य होते हैं और इन पर गवर्नर जनरल की मान्यता प्राप्त होती है।

विधान की धारा ३३ के अन्तर्गत नोट छापने के लिए सुरक्षित कोष रखना आवश्यक है। यह कोष स्वर्ण-मुद्रा, स्वर्ण-धातु, विदेशी प्रतिभूतियों, रुपये तथा रुपये की प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है। किन्तु ध्यान रहे कि कम से कम २०० करोड़ रुपये के मूल्य के सोने तथा विदेशी प्रतिभूतियों का होना आवश्यक है। इसमें ११५ करोड़ रुपये के मूल्य का तो सोना होना ही चाहिए। नोट-निर्गमन विभाग की विदेशी प्रतिभूतियाँ वे हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के सदस्य देशों में भुगतान की जा सकें। इनकी व्याख्या विधान ने इस प्रकार की है—

(क) वे प्रतिभूतियाँ जो किसी उक्त सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक के नोट-निर्गमन विभाग की जमा राशि की साख पर हो या उस देश के किसी अन्य बैंक की प्रतिभूतियाँ हों।

(ख) ९० दिनों तक की अवधि वाले बिल जो उक्त किसी भी देश में भुक्त हों तथा जिन पर दो विश्वसनीय हस्ताक्षर हों।

(ग) ५ वर्ष की अवधि वाली उक्त किसी भी देश की सरकारी प्रतिभूतियाँ।

४ विदेशी विनिमय का ऋय-विक्रय —रिजर्व बैंक विधान की धारा ४० के अन्तर्गत विदेशी विनिमय में मुद्रा-मूल्य को स्थिर रखने के लिए विदेशी विनिमय का ऋय-विक्रय कर सकता है। किन्तु यह ऋय-

विक्रय केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ ही हो सकता है तथा केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली कार्यालयों द्वारा ही हो सकता है । क्रय-विक्रय की दर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की शर्तों पर विचार करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है ।

अधिकृत व्यक्ति केवल वे हैं जिनको विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून, १९४७ के अनुसार विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का अधिकार प्राप्त है ।

५ अन्य केन्द्रीय बैंकिंग के कार्य—देश का शीघ्रस्थ होने के कारण रिजर्व बैंक को उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बहुत से और कार्य भी करने पड़ते हैं, उदाहरणार्थ, राशि का स्थानान्तरण, समाशोधन गृह का कार्य, आर्थिक एवं मोद्रिक विषयों पर सरकार, अधिकोषों या अन्य संस्थाओं को आवश्यकता पड़ने पर सलाह देना और सामान्य सूचना के लिए आर्थिक विषयों पर शोधपूर्ण आकड़े प्रकाशित करने का कार्य आदि करना ।

सामान्य अधिकोषण के कार्य—रिजर्व बैंक विधान की धारा १७ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को सामान्य बैंक के रूप में निम्न कार्य भी करने पड़ते हैं—

१ केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारों, अधिकोषों तथा अनेक संस्थाओं के लेखों पर बिना ब्याज के राशि जमा करना तथा उनकी आज्ञा पर राशि संग्रह करना या वसूलना ।

२ अनुसूचित बैंकों के साथ विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय । यह क्रय-विक्रय एक लाख रुपये से कम मूल्य का नहीं हो सकता है ।

३ भारत में भुक्त व्यापारिक विपत्रों एवं प्रतिज्ञा-पत्रों (प्रामेसरी-नोटों) का क्रय-विक्रय । ऐसे विपत्रों एवं प्रतिज्ञा-पत्रों पर दो अच्छे हस्ताक्षरों का होना आवश्यक है जिनमें से एक अनुसूचित अधिकोष के प्रतिनिधि का होता है । इन विपत्रों एवं प्रतिज्ञा-पत्रों की अवधि ९० दिनों से अधिक न होनी चाहिए ।

४ भारत में भुक्त कृषि सम्बन्धी विपत्रों एवं प्रतिज्ञा-पत्रों का क्रय-

विक्रय तथा कटौती करना। ऐसे विपत्र एव प्रतिज्ञा-पत्रों पर दो अच्छे हस्ताक्षरों का होना आवश्यक है जिन में से एक तो किसी तालिकाबद्ध अधिकोष या प्रान्तीय सहकारी अधिकोष के प्रतिनिधि का होता है। इन विपत्रों एव प्रतिज्ञा-पत्रों की अवधि ९ मास से अधिक न होनी चाहिए।

५ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को ९० दिन की अवधि का ऋण देना।

६ स्थानीय सरकारों, तालिकाबद्ध अधिकोषों, प्रान्तीय सहकारी अधिकोषों तथा लका-सरकार की प्रमुख मुद्रा-संस्थाओं को ९० दिन की अवधि का ऋण तथा पेशगी में राशि देना।

७ विदेशों में, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हों उनके भुक्त विपत्रों का क्रय-विक्रय एव कटौती करना। ये विपत्र ९० दिन की अवधि के हो सकते हैं और इनका क्रय-विक्रय तथा कटौती अनुसूचित अधिकोषों के ही साथ हो सकती है।

८ अपन कार्यालयों तथा अपनी एजेंसियों पर भुगतान होने वाले माग-पत्र चालू करना।

९ केन्द्रीय एव प्रान्तीय सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना।

१०—स्वर्ण-सिक्कों, स्वर्ण एव विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करना।

११ रुपये, प्रतिभूतियों, आभूषण तथा बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना। ऋण-पत्रों के भुगतान लेना और लाभांश वगैरह संग्रहीत करना।

१२ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंक में लेखा खोलना तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के साथ लेन-देन करना।

१३ विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना।

१० वर्ष से अधिक अवधि वाली प्रतिभूतियों का क्रय नहीं हो सकता।

१४ किसी भी तालिकाबद्ध अधिकोष एव किसी भी देश की प्रमुख मुद्रा-संस्था से, जो विधान से मान्यताप्राप्त हो, अधिकोषों के कार्य के लिए एक मास की अवधि तक जम नत पर रुपया उधार लेना। तालिका-

बद्ध अधिकोष से लिया जाने वाला उधार अधिकोष की पूंजी से अधिक नहीं हो सकता ।

१५ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, अधिकोष अध्यादेश विधान १९४५ तथा भारतीय अधिकोषण प्रमण्डल विधान १९४७ के अनुसार कार्य करना । रिजर्व बैंक समय समय पर आवश्यक आर्थिक एवं मौद्रिक आकड़ों का संग्रह तथा सकलन भी करता रहता है ।

बहुत से ऐसे कार्य हैं जो रिजर्व बैंक के लिए निषिद्ध हैं, अर्थात् जिन्हें वह नहीं कर सकता । ऐसे कार्य निम्नलिखित हैं ।

१ न तो कोई निजी उद्योग और व्यापार कर सकता है और न किसी उद्योग एवं व्यापार में भाग ले सकता है ।

२ किसी भी प्रमण्डल अथवा अधिकोष के अंश न तो खरीद सकता है और न उनके अंश की जमानत पर उन्हें उधार दे सकता है ।

३ अचल सम्पत्ति की जमानत पर उधार नहीं दे सकता । अपने कार्यालयों की सम्पत्ति को छोड़कर कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं खरीद सकता ।

४ ऊपर बतायी गयी परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य अवस्था में ऋण अथवा अग्रिम नहीं दे सकता । इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक चालू खातों पर ब्याज नहीं देता ।

तालिकाबद्ध अधिकोष और रिजर्व बैंक

देश के हमारे अधिकोष रिजर्व बैंक के साथ स्थापित होने वाले सम्बन्ध के विचार से दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—

(१) तालिकाबद्ध अधिकोष और (२) अतालिका बद्ध अधिकोष । रिजर्व बैंक-विधान की दूसरी तालिका में लिखे गये नाम वाले अधिकोषों को तालिकाबद्ध या अनुसूचित अधिकोष कहते हैं । इस तालिका में केवल उन्हीं अधिकोषों के नाम लिखे जाते हैं जो भारत में ही व्यवसाय करते हैं तथा जिनकी कुल पूंजी ५ लाख से कम नहीं है और जिनके ऊपर रिजर्व बैंक को यह विश्वास हो कि वे जमा रखने वालों के ही हित में व्यवसाय करते हैं । तालिकाबद्ध अधिकोषों को अपनी माग-देनदारी का ५ प्रतिशत

से २० प्रतिशत तथा काल-देनदारी का २ प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक रिजर्व बैंक के पाम जमा करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसे अविकोषो को प्रति सप्ताह एक विवरण-पत्रिका आवश्यक रूप से रिजर्व बैंक के पास भेजनी पड़ती है जिस पर दो सचालको-प्रबन्धक अथवा अन्य उत्तरदायी कर्मचारियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस पत्रिका में निम्नलिखित सूचनाएँ रहती हैं—

१ माग-देनदारी तथा काल-देनदारी की राशि।

२ बैंक नोट तथा सरकारी नोटों की भारत में होने वाली राशि।

३ रुपयों तथा अन्य सिक्कों की भारत में होने वाली राशि।

४ उधार दी हुई अग्रिम राशि, ऋण राशि तथा भुनाये हुए विपत्रों (बिलों) की राशि।

५ बैंक की रोकड़ बाकी।

इस विवरण के न भेजने पर १०० रु० प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना पड़ता है। रिजर्व बैंक अपने अनुसूचित अविकोषों को समय समय पर ऋण देता है। उनकी राशि का स्थानान्तरण करता है और उनके विपत्रों एवं प्रतिज्ञा-पत्रों का क्रय-विक्रय भी करता है। हा, इतना अवश्य है कि रिजर्व बैंक ऋण देते समय प्रतिभूतियों की जमानत भी रख सकता है। ये प्रतिभूतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं—

(अ) वे प्रतिभूतियाँ जिनमें एक प्रन्यासी (Trustee) को प्रन्यास-विधान द्वारा प्रन्यास का रुपया खर्च करने का अधिकार प्राप्त हो।

(आ) सोने, चादी अथवा उसके मूल्य की प्रतिभूतियाँ।

(इ) ऐसे विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा-पत्र जिनके पुनः भुगतान का अधिकार रिजर्व बैंक ने दे दिया हो।

(ई) किसी भी सदस्य बैंक अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक के प्रतिज्ञा-पत्र जिनकी रकम का सोना-चादी बैंक में जमा हो तथा जो कृषकों की सामयिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिखे गये हों।

रिजर्व बैंक तालिकाबद्ध अविकोषों की राशि स्थानान्तरण के लिए निम्न सुविधाएँ प्रदान करता है—

१ रिजर्व बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं द्वारा तालिकाबद्ध अधिकोष की १०,००० रु० तक की राशि का निशुल्क स्थानान्तरण ।

२ किसी स्थान से जहाँ रिजर्व बैंक की एजेन्सी है तथा तालिकाबद्ध अधिकोष का कार्यालय, उपकार्यालय, शाखा या शोध्य कार्यालय है, उस अधिकोष के रिजर्व बैंक स्थित प्रधान लेखे में ५००० रु० तक की राशि का प्रति सप्ताह एक बार निशुल्क स्थानान्तरण ।

३ तालिकाबद्ध अधिकोष के रिजर्व बैंक स्थित प्रधान लेखे में राशि स्थानान्तरण की अन्य सुविधा १/६४ प्रतिशत की दर पर दी जाती है । परन्तु इसकी न्यूनतम सीमा एक रुपया है ।

४ रिजर्व बैंक अथवा इसके प्रतिनिधि के कार्यालयों के खाते में ५००० रु० तक की राशि का स्थानान्तरण १/१६ प्रतिशत की दर पर होता है किन्तु शुल्क की न्यूनतम सीमा एक रुपया है । ५००० रु० से अधिक राशि का स्थानान्तरण १/३२ प्रतिशत की दर पर होता है किन्तु शुल्क की न्यूनतम राशि तीन रुपया दो आना है ।

कुल पूँजी ५ लाख से घटने पर अथवा अधिकोषण कार्य बंद कर देने पर अथवा सुचारु रूप से कार्य न कर सकने पर तालिकाबद्ध अधिकोषों का नाम तालिका से निकाला जा सकता है । भारतीय अधिकोषण प्रमण्डल विधान १९४९ की धारा ३५ के अन्तर्गत निरीक्षण करने पर यदि रिजर्व बैंक किसी तालिकाबद्ध अधिकोष के कार्यों से असन्तुष्ट हो जाय तो भी उसका नाम तालिका से निकाल सकता है ।

अतालिकाबद्ध अधिकोष और रिजर्व बैंक—जिनके नाम रिजर्व बैंक की तालिका में नहीं होते हैं वे अतालिकाबद्ध अधिकोष कहलाते हैं । इन अधिकोषों से भी रिजर्व बैंक अपना सम्बन्ध रखता है और समय समय पर उनकी स्थिति की जाच-पड़ताल करके उचित सलाह देता है । ऐसे अतालिकाबद्ध अधिकोषों को, जो भारतीय प्रमण्डल विधान १९१३ के अन्तर्गत पंजीकृत हो और जिनकी कुल पूँजी ५०,००० रु० या इससे अधिक हो तथा वे भारत में अधिकोषण का कार्य करते हों, राशिस्थानान्तरण के व्यय में रिजर्व बैंक कुछ सुविधाएँ देता है । ऐसे

अधिकोषो की सख्या जून सन् १९४६ मे ८२ थी। सन् १९४५ से अतालिकाबद्ध अधिकोषो को निम्न शर्तों पर रिजर्व बैंक मे खाते खोलने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

१ रिजर्व बैंक मे जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि १०,००० रुपये से कम न होगी।

२. इनके खाते चालू खाते नहीं हो सकते हे, किन्तु पारस्परिक समाशोधन के कार्य मे प्रयुक्त किये जा सकते है।

रिजर्व बैंक की कृषि-साख व्यवस्था

रिजर्व बैंक की स्थापना के समय ही कृषि-साख की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था। अतएव इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक मे एक कृषि साख विभाग का निर्माण किया गया। इस विभाग के निम्न-लिखित उद्देश्य थे।

१ कृषि-साख व्यवस्था के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति तथा साख-समस्याओं का अध्ययन एव हल निकालना तथा समय समय पर केन्द्रीय, प्रान्तीय एव स्थानीय सरकारों, प्रांतीय सहकारी अधिकोषो एव अन्य कृषि सस्थाओं को आवश्यक सलाह देना और उनका पथ-प्रदर्शन करना।

२ अपने काय-कलापो द्वारा प्रान्तीय सहकारी अधिकोषो एव अन्य ऐसी ही सस्थाओं के काय को सगठित करना।

रिजर्व बैंक ने सन् १९५१ मे कृषि-साख सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार कृषि-साख विभाग मे कृषि-साख के विशेषज्ञों की एक समिति बनायी गयी। यह समिति स्वयं तो ऋण देती नहीं किन्तु साख-विभाग को कृषि-साख सम्बन्धी समस्याओं पर सुझाव देती है।

कृषि-साख विभाग ने अनेकों बार साहूकारों तथा स्वदेशी बैंकरो को नियमबद्ध एव नियंत्रित रखने के लिए सरकार को सुझाव दिये तथा सहकारी आन्दोलनों के पुनर्निर्माण की माग की। परिणाम-स्वरूप रिजर्व बैंक ने देशी महाजनो के द्वारा कृषको को आर्थिक सुविधाएँ

पहुँचाने का प्रयास किया। रिजर्व बैंक ने सन् १९३८ में स्वीकृत महाजनरी द्वारा कृषकों को उनके कृषि-उत्पादन की साख पर पेशगी के रूप में उधार देने के लिए लिखे गये कृषि-विपत्रों को तालिकाबद्ध अधिकोषों द्वारा कम दर पर भुनाना स्वीकार किया, ताकि कृषकों को कटौती की बचत का लाभ हो तथा वे कृषि में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय तक आवश्यक ऋण भी प्राप्त कर सकें। रिजर्व बैंक ने यह योजना बनायी कि तालिकाबद्ध अधिकोष अपनी कटौती-दर सामान्य अधिकोषों की दर से दो प्रतिशत अधिक रखेंगे और महाजन दो प्रतिशत अधिक मिलाकर कृषकों को उधार देंगे। परन्तु तालिकाबद्ध अधिकोषों ने इसका विरोध किया। इस योजना से तालिकाबद्ध अधिकोषों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का भी भय था, इसलिए इस योजना को स्थगित कर देना पड़ा। रिजर्व बैंक ने दूसरी योजना यह बनायी कि सभी साहकारी अधिकोष उससे धन प्राप्त करके कृषकों को ऋण प्रदान करें। किन्तु सहकारी अधिकोषों ने इस योजना से लाभ न उठाया। सन् १९४२ में रिजर्व बैंक ने कृषि-साख व्यवस्था की योजना बनायी और कृषि-उत्पादन के विक्रय के निमित्त अपनी कटौती दरसे एक प्रतिशत कम पर ही सहकारी अधिकोष को धन देने का निश्चय किया। फिर भी सहकारी अधिकोषों ने इस योजना से पूरा लाभ न उठाया। इसी तरह रिजर्व बैंक विधान की धारा १७।४ (द) कृषि-साख के विकास के लिए अभी तक कार्यान्वित नहीं की जा सकी है, क्योंकि इसका उपयोग तभी हो सकता है जब कि देश में अनुज्ञाधारी भण्डारगृह हों। अनुज्ञाधारी भण्डारगृहों की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक ने एक आदेश भी जारी किया किन्तु अभी तक इनकी स्थापना नहीं हो पायी है।

सन् १९४९-५० में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकोषों की स्थापना करने के सम्बन्ध में जाच-पड़ताल करने के निमित्त एक समिति बनायी जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। सन् १९५१ में रिजर्व बैंक ने कृषि-साख के साधनों एवं इससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इस सम्बन्ध में

अनेक सुझाव दिये गये । ग्रामीण अधिकोषण जाच समिति तथा इस सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक ने पहली सितम्बर सन् १९५१ से व्यापारिक अधिकोषों, सहकारी अधिकोषों एवं स्वदेशी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक अथवा इम्पीरियल बैंक के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को स्थानान्तरित की जाने वाली राशि पर लगने वाले कमीशन की दर को कम कर दिया, और अब ५००० रुपये के स्थानान्तरण पर कमीशन की दर १/३२ प्रतिशत तथा इससे अधिक रुपये के स्थानान्तरण पर १/६४ प्रतिशत कर दी गयी । इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक को कृषि-साख सम्बन्धी अधिक सुविधाएँ प्रदान कर सकने में समर्थ बनाने के लिए नवम्बर सन् १९५१ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया विधान में आवश्यक संशोधन भी किया गया । कुछ और संशोधन करके सहकारी अधिकोषों को व्यापारिक अधिकोषों की भाँति ही विपन्नो, आहरण, क्रय-विक्रय एवं कटौती करने का अधिकार दिया गया । एक दूसरे संशोधन के अन्तर्गत सहकारी अधिकोषों द्वारा कृषि कार्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों की अवधि ९ महीने से बढ़ाकर १५ महीने कर दी गयी है ।

प्राचीन काल से ही भारतीय अधिकोषण प्रणाली के लिए भारतीय कृषि को उचित सहायता देना एक प्रधान समस्या बनी रही है । कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए रिजर्व बैंक ने कृषि-साख के क्षेत्र में सहकारी बैंकों को अनेक सुविधाएँ दी हैं । परन्तु सबसे प्रमुख सुविधा तो सहकारी अधिकोषों को ऋण प्रदान करना है, जिसके लिए ९० दिन वाली निम्न-लिखित प्रतिभूतियाँ जमानत के रूप में रिजर्व बैंक स्वीकार करता है ।

(१) सरकारी प्रतिभूतियाँ ।

(२) भूमि-बधक अधिकोषों द्वारा मान्य ऋण-पत्र ।

(३) कृषि के लिए लिखे गये प्रतिज्ञा-पत्र जिनका बेचान किसी प्रांतीय सहकारी अधिकोष ने किया हो ।

(४) प्रांतीय सहकारी अधिकोषों के प्रतिज्ञा-पत्र जिनको किसी गोदाम वाली संस्था ने सुरक्षित कर दिया हो ।

(५) ऐसा एक वैधानिक पत्र, जिसे केन्द्रीय सहकारी अधिकोष ने प्रमाणित किया हो तथा वह कृषि-कार्य के लिए लिखा गया हो ।

यदि प्रान्तीय सहकारी अधिकोष प्राप्त छूट की रकम केन्द्रीय अधिकोष के सहारे किसानों को देने के लिए उद्यत हो तो उसे प्रतिज्ञा-पत्र के पुनर्भुगतान में रिजर्व बैंक एक प्रतिशत की छूट देने को तैयार रहता है ।

चूँकि इसे लम्बी अवधि के ऋण देने का अधिकार नहीं प्राप्त है इसलिए यह ९० दिनों के लिए भूमि बंधक अधिकोषों को भी ऋण दे सकता है । इसके अतिरिक्त भूमि बंधक अधिकोषों के सरकार द्वारा सुरक्षित ऋण-पत्रों का क्रय करके भी रिजर्व बैंक उन्हें सहायता पहुँचाता है ।

अगस्त सन् १९५१ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने ग्राम्य-साख सुविधाओं के बृहत् प्रसार के निमित्त आवश्यक सुझाव देने के लिए एक ग्राम्य साख-समिति नियुक्त की । इस समिति ने सन् १९५४ के अन्त तक अपने सुझाव दिये । इन सुझावों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किया ।

१ सरकार ने भारत के राज्य अधिकोष—स्टेट बैंक आफ इण्डिया को स्थापना की घोषणा की । स्टेट बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट पास किया गया और पहली जुलाई सन् १९५५ से इस अधिकोष ने अपना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया ।

२ समिति ने सहकारिता का देश भर में प्रसार करने की सिफारिश की थी । इसलिए अप्रैल सन् १९५५ में सभी राज्यों के सहकारिता-मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करके यह निर्णय किया गया कि वे सभी राज्य-सरकारों, भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से सहयोग लेकर सहकारी विपणियों, सहकारी गोदामों एवं सहकारी साख के सम्बन्ध में एक योजना बनायें और उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रमुख रूप से लागू करें । तत्पश्चात् राज्य सरकारों ने ऐसा ही किया ।

३ समिति ने सुझाव दिया कि सभी राज्य-सरकारों का कार्य सहकारी साख-संस्थाओं के साथ एक वित्तीय साझेदार के रूप में होना

चाहिए। रिजर्व बैंक के पास एक विशिष्ट कोष होना चाहिए ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर राज्य-सरकारों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक एक और कोष रखे ताकि वह सहकारी साख के लिए दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर सके। बैंक ने ऐसे दोनों कोषों का निर्माण कर दिया है।

४ समिति ने भारत सरकार को राष्ट्रीय सहकारी विकास कोष (नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेन्ट फण्ड) और राष्ट्रीय सग्रह विकास कोष (नेशनल वेर हाउजिंग डेवलपमेन्ट फण्ड) स्थापित करके उन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी विकास एंव सग्रह बोर्ड के अधीन कर देने तथा इन कोषों के द्वारा कृषि-जन्य वस्तुओं के सग्रह एंव विपणन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। इसलिए सरकार ने कृषि-उत्पत्ति विकास एंव सग्रह नियम बिल १९५५ तैयार किया जो इस समय कार्यान्वित हो चुका है।

५ इस समिति ने सहकारिता से सम्बन्धित अधिकारियों की उचित शिक्षा की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया। पूना, मद्रास एंव पूसा में तो इस प्रकार की शिक्षण-संस्थाएँ भी थीं। इस समय कुल मिलाकर ३१ छोटी शिक्षण-संस्थाएँ विभिन्न राज्यों में स्थापित की जा चुकी हैं। इन सब संस्थाओं का प्रबन्ध केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति करती है।

६ सरकार ने ग्रामीण-साख-संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों को संगठित करने का भी प्रयास किया है। इसी उद्देश्य से अक्टूबर सन् १९५५ में एक समिति बनायी गयी है जिसके कार्य हैं — (१) गाँवों के विकास के साधन उपलब्ध कराना तथा अपव्यय रोकना, (२) ग्रामीण साख सम्बन्धी सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, (३) कृषि-जन्य वस्तुओं का सग्रह एंव विपणन करने वाली संस्थाओं के कार्य का संगठन करना, (४) सहकारिता तथा राष्ट्रीय विस्तार योजना और सामुदायिक विकास योजनाओं में पारस्परिक समन्वय स्थापित करना। इस समिति में केन्द्रीय कृषि एंव खाद्य मन्त्रालय के दो प्रतिनिधि तथा वित्त मन्त्रालय, उत्पादन

मन्त्रालय, सामुदायिक विकासयोजना प्रबन्ध, आयोजना आयोग और रिजर्व बैंक के एक-एक प्रतिनिधि हैं और सरकार का सहकारी सलाहकार सदस्य मंत्री है।

रिजर्व बैंक के पास कोई ऐसा विशिष्ट कोष नहीं था जिससे वह सहकारी समितियों एवं कृषि-वित्त-संस्थाओं को सहायताार्थ ऋण दे सके, किन्तु यह भी कमी अभी हाल में पूरी कर दी गयी है।

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया विधान में कुछ और भी संशोधन करके निम्न दो नये कोष स्थापित किये गये हैं—

(अ) राष्ट्रीय कृषि-साख दीर्घकालीन कोष,

(ब) राष्ट्रीय कृषि-साख स्थायित्व कोष।

राष्ट्रीय कृषि-साख दीर्घकालीन कोष

इस कोष ने ३० जून सन् १९५६ से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसकी प्रारम्भिक पूँजी १० करोड़ रुपये है किन्तु इसके कार्यारम्भ के समय से सन् १९६१ तक कम-से-कम ५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष इसमें जमा होता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर और भी राशि इसमें मिलायी जा सकेगी। यह कोष निम्नलिखित कार्यों में प्रयुक्त किया जायगा।

(क) राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम देने में। ताकि वे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहकारी साख समितियों को अशदान दे सके। इस ऋण की अधिकतम अवधि २० वर्ष हो सकती है।

(ख) निर्धारित जमानत रखने और राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि तथा उसके ब्याज के भुगतान की गारन्टी लेने पर कृषि-कार्यों में प्रयुक्त करने के लिए प्रान्तीय सहकारी अधिकोषों को ऋण तथा अग्रिम देने में। यह ऋण १५ महीने से ५ वर्ष तक की अवधि का हो सकता है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि तथा उसके ब्याज के भुगतान की गारन्टी लेने पर केन्द्रीय भूमि-बन्धक अधिकोष को ऋण तथा अग्रिम देने में। इस ऋण की अधिकतम अवधि २० वर्ष हो सकती है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा ऋणपत्र की राशि तथा उसके ब्याज

के भुगतान की गारन्टी लेने पर केन्द्रीय भूमि-बधक अधिकोष का ऋण-पत्र खरीदने में।

सहकारी-साख समितियों को सहयोग दे सकने में समर्थ बनाने के लिए मार्च सन् १९५७ तक ११ राज्यों को कुल मिलाकर २६८ २० लाख रुपया इस कोष से देना स्वीकृत किया गया।

राष्ट्रीय कृषि-साख स्थायित्व कोष

३० जून सन् १९५६ से १९६१ तक प्रति वर्ष इस कोष में कम-से-कम एक करोड़ रुपया जमा होता रहा है। आवश्यकता समझने पर इसके पश्चात् भी इस कोष में आवश्यक राशि जमा होती रहेगी। यह कोष प्रान्तीय सहकारी समितियों को १५ महीने से ५ वर्ष तक की अवधि वाले ऋण तथा अग्रिम देने के लिए बना है। ऋण देने के लिए निम्न दो शर्तें मान्य हैं—

(क) राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि एवं उसके ब्याज के भुगतान की गारन्टी प्राप्त हो।

(ख) रिजर्व बैंक विधान की धारा १७।२ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बेचे गये या पूर्व-प्राप्त कराये गये अपने विपत्रों के शोधन में। जब ऋण लेने वाले प्रान्तीय सहकारी अधिकोष, किसी प्रकृति-प्रदत्त कारण से असमर्थ हो तब इस कोष की राशि को प्रयोग में ला सकते हैं।

रिजर्व बैंक और विनिमय नियन्त्रण

द्वितीय महायुद्ध काल में सरकार ने विदेशी विनिमय के नियन्त्रण का अधिकार पाते ही यह कार्य रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को सौंप दिया। रिजर्व बैंक ने इस कार्य के लिए एक विनिमय नियन्त्रण विभाग स्थापित किया। विनिमय के नियन्त्रण के लिए उसने कुछ नियम रखे थे जिनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था। सन् १९४७ तक तो यही स्थिति रही। उसी वर्ष सरकार ने विदेशी विनिमय नियन्त्रण विधान स्वीकृत किया ताकि विदेशी विनिमय में सट्टेबाजी न हो सके।

अब विदेशी विनिमय का कार्य केवल विनिमय अधिकोष एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ आधिकारिक व्यक्ति कर सकते हैं। आधिकारिक

व्यक्तियों की नियुक्ति सरकार करती है तथा उन्हें इस कार्य के लिए अनुज्ञा-पत्र भी देती है। विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय सरकार की आयात एवं निर्यात नीति में निर्धारित कार्यों के लिए हो सकता है। आधिकारिक व्यक्तियों को समय-समय पर विदेशी विनिमय से होने वाले अपने आय-व्यय का लेखा रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है। रिजर्व बैंक को भी विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का अधिकार प्राप्त है।

निम्न कार्यों को छोड़कर कोई भी विदेशी विनिमय से सम्बन्धित कार्य स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर नहीं किया जा सकता—

- (१) आयात का भुगतान।
- (२) छोटे-छोटे व्यक्तिगत भुगतान।
- (३) यात्रा-व्यय।
- (४) अन्य व्यापारिक कार्य, जैसे किराया या लाभ देना।
- (५) पूजा का भुगतान।

रिजर्व बैंक और स्वदेशी बैंकर

हमारे देश के मुद्रा-बाजार में स्वदेशी बैंकरो को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसका कारण यह है कि कृषको एवं छोटे उद्योगपतियों को उनकी आवश्यकता के समय सरलतापूर्वक एवं बिना किसी विशेष पूछताछ के ही ये पूजा प्रदान करते हैं जिसे आधुनिक पद्धति वाले अधिकोष नहीं दे पाते हैं।

स्वदेशी बैंकरो का प्रमुख दोष यह है कि ये ब्याज की दर ऊँची रखते हैं। इनके लेन-देन की विधि एवं ब्याज की दर पर नियंत्रण रखने तथा इन्हें संगठित एवं संचालित करने के लिए कोई विधान तो है नहीं। अतः यह कार्य रिजर्व बैंक की स्थापना होते ही उसे सौंपा गया। सर्वप्रथम सन् १९३७ में एक योजना बनायी गयी और केन्द्रीय अधिकोषण जाँच समिति के प्रस्तावों के अनुसार यह सुझाव रखा गया कि अनुसूचित अधिकोषों की भाँति ही स्वदेशी बैंकरो को विनिमय-पत्र की कटौती की सुविधा रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। परन्तु स्वदेशी बैंकरो को यह सुविधा पाने के लिए भारतीय प्रमण्डल विधान के अनुसार अपना कार्यक्षेत्र सीमित

रखना होगा। स्वदेशी बैंकरो की बढ़ती हुई सख्या के कारण इनसे सीधा सबंध स्थापित करने मे रिजर्व बैंक ने अपने को असमर्थ पाया और इस कार्य के लिए कुछ सदस्य अधिकोषो को मध्यस्थ बनाया। रिजर्व बैंक की इस व्यवस्था से स्वदेशी बैंकर सहमत न हुए। इसलिए उनसे सीधा सम्बन्ध स्थापित करने का माँग रिजर्व बैंक से की गयी। परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक ने सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा अगस्त सन् १९३९ मे कर दी।

इसके अनुसार स्वदेशी बैंकरो को रिजर्व बैंक से पन्जीकृत होना आवश्यक था। निम्न शर्तों को पूरा करने पर किसी भी सदस्य अधिकोष मे खाता खोलने तथा तालिकाबद्ध अधिकोषो को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएँ ग्रहण करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो सकता था—

(१) उनके कार्यों की सीमा भारतीय प्रमण्डल विधान द्वारा निर्देशित व्यापार तक होगी।

(२) अपने कार्यों का समुचित लेखा समय-समय पर रिजर्व बैंक को देना होगा तथा खाता पुस्तको की जाँच करानी होगी। ऐसा न करने पर वे दण्ड के भागी होंगे।

(३) उनकी कार्यशील पूजी कम-से-कम २ लाख होगी जिसे कालान्तर मे धीरे-धीरे ५ लाख तक पहुँचाना है।

(४) आवश्यकता पडने पर अनुसूचित अधिकोषो की भाँति इन्हें अपने को रिजर्व बैंक के सम्मुख समर्पित करना होगा। ये अपने नाम रिजर्व बैंक की पुस्तको मे पाँच वर्षों तक लिखा सकते हैं। जब तक इनके दायित्व इनकी कुल पूजी के ५ गुने न हो जायँ इन्हें रिजर्व बैंक के पास कोई सुरक्षित कोष न रखना पडेगा।

यह योजना पाँच वर्ष के लिए थी। इसके अनुसार किसी भी स्वदेशी बैंकर को प्रमण्डल मे रहने वाले अश्वारियो के हितो का भी पूर्ण विवरण रिजर्व बैंक के पास देना था।

रिजर्व बैंक की इस योजना को स्वदेशी बैंकरो ने स्वीकार न किया। कुछ तो यह चाहते थे कि खाते नये ढंग से रखे जायँ और कुछ सट्टे का

व्यापार भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इन सब का कारण यह था कि वे केवल अधिकोषण व्यवसाय से सन्तुष्ट न थे। रिजर्व बैंक ने सन् १९४१ में बम्बई के सराफा सघ से यह पूछा कि अधिकोषण व्यवसाय के अतिरिक्त कार्यों को छोड़ सकने वाले बैंकरो की संख्या कितनी है। सघ ने ऐसे बैंकरो की संख्या न बताकर यह सुझाव दिया कि अगले पाँच वर्षों में अधिकोषण एवं गैर अधिकोषण के कार्यों को अलग किया जा सकेगा और तभी उन पर रिजर्व बैंक निरीक्षण भी रख सकेगा। रिजर्व बैंक ने इस योजना को कार्यान्वित करना ठीक न समझा क्योंकि वह तो इसे तत्काल ही व्यावहारिक रूप देना चाहता था। अधिकांश स्वदेशी बैंकरो द्वारा इस योजना के स्वीकार न किये जाने के कारण रिजर्व बैंक ने इसे स्थगित कर दिया और इससे सम्बन्धित कोई विधान भी न बनाया। इतना ही नहीं, इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने में असमर्थता भी प्रकट की।

किन्तु अब स्वदेशी बैंकरो को नियंत्रित एवं नियम-बद्ध कर देने की अतीव आवश्यकता प्रतीत हो रही है। ऐसा हो जाने पर रिजर्व बैंक सरलतापूर्वक विवृत विपणि^१ की समस्त क्रियाएँ कर सकेगा और देश में विपन्न-विपणि का विकास होगा। यह कार्य कठिन अवश्य है परन्तु रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह स्वदेशी बैंकरो के साथ इस कार्य के लिए विनम्र समझौता करे। एक तरफ तो रिजर्व बैंक अपनी शर्तों को कुछ ढीली करे और दूसरी तरफ स्वदेशी बैंकर भी रिजर्व बैंक के नियमों के अदर आने का प्रयास करे, तभी यह योजना पूरी हो सकेगी। देश की साख व्यवस्था को सगठित बनाने के लिए स्वदेशी बैंकरो को नियमबद्ध करना बहुत आवश्यक है। साख व्यवस्था को सगठित एवं विकसित करने के निमित्त ही धीरे-धीरे अधिकोषो का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। इसलिए रिजर्व बैंक को स्वदेशी बैंकरो के नियमबद्ध बनाने की दिशा में शीघ्र ही आवश्यक प्रयास करना चाहिए।

1. Wide market

रिजर्व बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण

रिजर्व बैंक देश के अन्यान्य अधिकोषों की मुद्रा तथा साख को नियन्त्रित रखकर मुद्रा मूल्य को स्थिर बनाये रखने का प्रयास करता है और कालान्तर में अधिकोष-दर (बैंक रेट) भी प्रकाशित करता रहता है। रिजर्व बैंक की साख के नियन्त्रण की विधि हम नीचे स्पष्ट रूप से देखेंगे।

सर्वप्रथम इम्पीरियल बैंक ने साख-नियन्त्रण के लिए अधिकोष-दर जैसे साधन का सहारा लिया, किन्तु निम्नलिखित कारणों से इम्पीरियल बैंक द्वारा प्रयुक्त अधिकोष-दर अधिक कार्यशील न रही।

(१) अन्य व्यापारिक अधिकोषों के साथ इम्पीरियल बैंक की प्रतिस्पर्धा का होना तथा भारतीय मुद्रा-विपणि के विभिन्न अंगों में सहयोग का अभाव होना।

(२) इम्पीरियल बैंक द्वारा अधिकोष-दर का सदैव अपने लाभ के अनुकूल निर्धारित किया जाना।

(३) इम्पीरियल बैंक पर देश के साख-नियन्त्रण का कोई वैधानिक उत्तरदायित्व न होना। मुद्रा का प्रबन्ध सरकार करती थी तो साख का प्रबन्ध इम्पीरियल बैंक करता था।

(४) देश के विदेशी विनिमय-अधिकोषों का विदेशी मुद्रा-मण्डियों से सीधा सम्बन्ध होने के कारण इम्पीरियल बैंक की विदेशी विनिमय सम्बन्धी सेवाएँ उनके लिए कोई महत्त्व न रखती थी। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक की स्थापना होते ही मुद्रा के प्रबन्ध एवं साख के नियन्त्रण का सारा भार रिजर्व बैंक को सौंपा गया। किन्तु रिजर्व बैंक साख-नियन्त्रण का भार पूर्ण रूप से न सँभाल सका। इसका कारण यह है कि हमारे देश में केन्द्रीय अधिकोष की सेवाओं पर न तो जनता ही अधिक निर्भर रहती है और न देश के सारे अधिकोष ही। देश के अधिकोषों द्वारा केन्द्रीय अधिकोष के पास रखा जाने वाला सुरक्षित कोष भी अनुपात में कम होता है और इसलिए वे अपने पास के सुरक्षित कोष से ही काम ले लेते हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक की अधिकोष दर की नीति अधिक सफल न रही और १९३५

मे रिजर्व बैंक ने अधिकोष दर ३ प्रतिशत निर्धारित की। सन् १९५१ में ज्यो ही बैंक आफ इंग्लैण्ड ने अपनी अधिकोष दर $३\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ प्रतिशत कर दी, त्यो ही रिजर्व बैंक ने भी अपनी अधिकोष दर $३\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी। फिर मई सन् १९५७ में रिजर्व बैंक ने इसको ४ प्रतिशत कर दिया। इस प्रकार देशी मुद्रा विपणियों में होने वाली मुद्रा की सामयिक दुर्लभता तथा उसके फलस्वरूप ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन पर रिजर्व बैंक ने नियंत्रण कर लिया और अधिकोष दर पूर्ववत् बनी रही।

साख-नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला दूसरा ढग विवृत विपणि की क्रियाओं का प्रयोग करना है। अपनी अधिकोष-दर को आवश्यकतानुसार नियंत्रित रखने के लिए रिजर्व बैंक को स्कध विनिमय विपणि (स्टॉक एक्सचेंज मार्केट^१) में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त है। किन्तु हमारे देश में सगठित मुद्रा मण्डी तथा सुसगठित बिल बाजार की कमी सदैव बनी रही है। यही कारण है कि विनिमय बिलों का प्रचलन अधिक मात्रा में नहीं होता है। स्कध विनिमय भी उन्नत अवस्था में सुलभ नहीं है। परिणाम स्वरूप विवृत विपणि की क्रियाएँ आवश्यक सीमा तक साख-नियंत्रण करने में सहायक नहीं हो पायी हैं।

रिजर्व बैंक को साख-नियंत्रण के सम्बन्ध में अन्य प्रकार के भी अधिकार प्राप्त हैं। यथा—अधिकोषों पर नियंत्रण रखना, जनता से सीधा लेन-देन करना और अधिकोषों को एक निश्चित सीमा के पश्चात् ऋण देने से रोकना आदि। किन्तु इस बैंक ने इन साधनों का समुचित प्रयोग अभी तक नहीं किया है। वैसे तो भारतीय अधिकोषण प्रमण्डल विधान १९४९ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को देश के अन्य अधिकोषों की ऋण-नीति को संचालित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, किन्तु उसका भी प्रयोग करने का अवसर रिजर्व बैंक को कभी प्राप्त नहीं हो सका है।

रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना

सन् १९३१ में भारतीय अविकोषण जॉच समिति ने भारतीय अविकोषण प्रणाली पर यह आरोप लगाया कि बिल बाजार अविकसित रूप में है। रिजर्व बैंक के अभाव में इम्पीरियल बैंक ही देश के अविकोषों के अविकोष का कार्य करता था जो कि स्वयं एक व्यापारिक अविकोष था, इसलिए अन्य व्यापारिक अविकोष उससे अपने बिलों की कटौती कराना अनादर समझते थे। परिणामस्वरूप व्यापारिक बिलों का प्रचलन अधिक नहीं होता था बल्कि सरकारी प्रतिभूतियाँ प्रधान रूप से बिल बाजार में दृष्टिगत होती थी। उन दिनों बिलों का प्रयोग करने की अपेक्षा नकद लेन-देन करने को लेनदार तम। अविकोष दोनों ही अधिक सुविधाजनक समझते थे।

रिजर्व बैंक की स्थापना होते ही यह आवश्यक समझा जाने लगा कि सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिलों को मुद्रा-प्रसार का आधार बनाया जाय। अविकोषों के पास वर्तमान व्यापार की बढ़ती हुई मौद्रिक माँग की पूर्ति के लिए राशि का अभाव बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण ये थे—अविकोषों की जमा राशि कम होना, मूल्य स्तर का ऊँचा होना, आयान का बढ़ना और अविकोषों के पास सरकारी प्रतिभूतियों का कम होना आदि। इसलिए आवश्यक समझा गया कि बिलों का प्रचलन अधिक करके तथा बिल बाजार को विकसित करके इस कठिनाई को दूर किया जाय। इसलिए रिजर्व बैंक ने १६ जनवरी सन् १९५२ को बिल बाजार की एक योजना प्रकाशित की। इस योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार की थी—

(क) रिजर्व बैंक अपने तालिकाबद्ध अविकोषों को उनकी माँग पर प्रतिज्ञा-पत्रों की जमानत द्वारा ऋण देगा। यह ऋण दो प्रकार का हो सकता है, एक तो प्रतिज्ञा-पत्रों की जमानत पर दिया जाने वाला ऋण जिसको ऋण लेने वाला कभी भी ले सकता है और कभी भी लौटा सकता है। दूसरा वह ऋण जो ९० दिन की अवधि के लिए ही दिया जा सकता है।

(ख) उपर्युक्त ऋण अधिकोष दर से १/२ प्रतिशत कम पर ही दिया जायगा।

(ग) इस ऋण के लिए लिखे जाने वाले बिलों अथवा पत्रों पर लगने वाले मुद्राक-कर का आधा व्यय रिजर्व बैंक स्वयं ही सहन कर लेगा। इस प्रकार केवल आधा व्यय ही ऋण माँगने वाले को देना पड़ेगा।

प्रारम्भ में यह योजना केवल उन्हीं अधिकोषों तक सीमित रखी गयी जिनकी जमा राशि १० करोड़ रुपये से अधिक थी। ऐसे अधिकोषों द्वारा एक बार में ली जाने वाली ऋण की न्यूनतम राशि २५ लाख रुपया निर्धारित की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें २५ लाख रुपये से कम राशि का ऋण मिलेगा ही नहीं। इसी प्रकार ऐसे बिलों पर जिनकी साख पर ऋण दिया जाता था, दिये जाने वाले ऋण की न्यूनतम सीमा १ लाख रुपया निर्धारित की गयी।

आगे चलकर इस योजना में बराबर परिवर्तन होते रहे। जिन अधिकोषों की न्यूनतम जमा राशि भारत में ५ लाख रुपये या इससे अधिक थी और रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञा-पत्र प्राप्त हो गया था उन पर भी यह योजना कार्यान्वित कर दी गयी। पहली अक्टूबर सन् १९५३ से १००० रुपये पर एक आना से अधिक मुद्राक कर अधिकोषों को दिया जाने लगा। सराफ समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप जुलाई १९५४ से सभी अनुज्ञा-पत्र-प्राप्त अनुसूचित अधिकोषों पर भी यह योजना लागू की गयी, चाहे उनकी जमा राशि कुछ भी हो। इतना ही नहीं, इस योजना के अन्तर्गत ऋण देने की न्यूनतम सीमा २५ लाख से घटाकर १० लाख कर दी गयी और प्रत्येक बिल की साख पर दिये जाने वाले ऋण की न्यूनतम सीमा १ लाख से घटाकर ५०,००० रुपये कर दी गयी।

किन्तु योजना को सफलता मिलते देख रिजर्व बैंक ने सुविधाओं को कम करना प्रारम्भ कर दिया। अब मुद्राक कर की पूरी रकम ऋण लेने वाले अधिकोष को ही देनी पड़ती थी। मार्च सन् १९५६ से योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की दर ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३½ प्रतिशत कर और फिर ३¾ प्रतिशत भी कर दी गयी।

फरवरी १९५७ से सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर ३½ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ प्रतिशत कर दी गयी। नवम्बर सन् १९५६ के पूरक बजट में सरकार द्वारा मुद्राक-कर की दर बढ़ा दी गयी इसलिए इस योजना के अन्तर्गत लिये गये ऋण पर ब्याज की दर ३½ प्रतिशत होते हुए भी वास्तविक व्यय ४ प्रतिशत ही होता था। इसका कारण यह था कि अधिकोषों को मुद्राक-कर भी सहन करना पड़ता था। १६ मई १९५७ से अधिकोष दर को ३½ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ प्रतिशत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत बिलों पर भी अब ४ प्रतिशत ब्याज लगने लगा। उसी समय सरकार ने बिलों के मुद्राक-कर को घटाकर १।५ प्रतिशत कर दिया। इस प्रकार १६ मई १९५७ से योजना के अन्तर्गत बिलों पर लिये गये ऋण पर ३ प्रतिशत ब्याज और १।५ प्रतिशत मुद्राक-कर अधिकोषों को देना पड़ता था।

इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों का विवरण इस प्रकार है—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	रिजर्व बैंक विधान की धारा १७।४। अ के अन्तर्गत प्रतिभूतियों की साख पर	रिजर्व बैंक विधान की धारा १७।४। स के अन्तर्गत योजना के अनुसार	योग
१९५१	७६ ५७		७६ ५७
१९५२	१६४ २५	८१ ४५	२४५ ७०
१९५३	१२९ ५८	६५ ८४	१९५ ४२
१९५४	१८८ ७०	१४७ ५२	३३६ २२
१९५५	१९९ ९४	२२५ ४४	४२५ ३८
१९५६	४६६ ९५	४३६ ८२	९०३ ७७
१९५७	३५३ ७८	४१४ ८१	७६८ ५९

उपर्युक्त आंकड़ों की तालिका से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना अपने विशेष उद्देश्य को पूरा करने में सफल

रही है। यद्यपि इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दर को ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३½ प्रतिशत, फिर ३¾ प्रतिशत और तत्पश्चात् ४ प्रतिशत भी कर दिया गया, तब भी अन्य अधिकोषों ने ऋण लेना जारी रखा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि इस योजना के प्रति अधिकोषों का विश्वास जम गया है तथा बिलों की लोक-प्रियता बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक ने इस योजना को अपनी नीति का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग मान लिया है।

जनता के प्रति रिजर्व बैंक की प्रत्यक्ष सेवाएँ

रिजर्व बैंक को विधानतः यह अधिकार प्राप्त है कि इस बैंक की केन्द्रीय समिति अथवा गवर्नर भारतीय व्यापार एवं उद्योग के हित के निमित्त इसकी साख-नीति को ढीली करने की सलाह दे। यह जन-साधारण और प्रमण्डलों के साथ भी प्रत्यक्ष लेन-देन करने के विचार से निम्न सेवाएँ प्रदान कर सकता है—

(१) विशेष परिस्थितियों में किसी असदस्य अधिकोष अथवा सरकारी अधिकोष की मान्यता-प्राप्त हस्ताक्षर वाले बिलों का क्रय-विक्रय तथा भुगतान सीधे जनता को कर सकता है।

(२) किसी भी सदस्य अधिकोष को पूर्व निश्चित शर्तों पर १० लाख रुपये तक ऋण दे सकता है।


द्वितीय विश्व-युद्ध एवं रिजर्व बैंक आफ इण्डिया

द्वितीय विश्व युद्ध के समय रिजर्व बैंक को अपनी कार्य-विधि में बहुत से आवश्यक परिवर्तन करने पड़े। युद्ध के प्रारम्भ में ही सरकार ने राशि के आयात एवं निर्यात के नियन्त्रण का भार रिजर्व बैंक को सौंप दिया और यह अधिकार प्रदान किया कि वह सिक्कों, धातुओं, प्रतिभूतियों तथा विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का नियन्त्रण करके उनके लेन-देन का नियमन भी करे। बैंक ने विदेशी विनिमय के नियमन के लिए अधिकृत व्यक्तियों को नियुक्ति की और ऐसे अधिकृत व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएँ भी दीं। बैंक ने विनिमय-नियन्त्रण विभाग की स्थापना की। युद्ध

को तेज होते देख इस विभाग के काय-क्षेत्र तथा अधिकार बढ़ा दिये गये। सन् १९४८ के पश्चात् भारत का भुगतान-संतुलन बहुत कुछ बिगड़ गया तथा विदेशी विनिमय की अत्यंत कमी पड़ने लगी। रिजर्व बैंक ने इस गंभीर स्थिति को भरसक सँभाला।

सरकार की युद्धकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रिजर्व बैंक को असीमित मात्रा में नोट निगमन करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में घोर मुद्रा-स्फीति छा गयी। सन् १९३९-४० में केवल १९० करोड़ रुपये के नोट चलते थे परन्तु सन् १९४५-४६ में उनकी संख्या बढ़कर लगभग १३०० करोड़ रुपया हो गयी। देश में भयंकर मुद्रा-स्फीति आने से इंग्लैंड का स्टर्लिंग ऋण बहुत बढ़ गया। यद्यपि यह मुद्रा-स्फीति रिजर्व बैंक के द्वारा ही लायी गयी थी पर इसके लिए वह दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

युद्धकाल में सरकार ने जनता से बहुत अधिक ऋण ले लिया था। उसका प्रबन्ध संचालन भी रिजर्व बैंक को करना पड़ा। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य में स्थायित्व रखने के लिए रिजर्व बैंक को अथक प्रयत्न करना पड़ा। सरकार की सस्ती राशि-नीति का संचालन भी इसी बैंक ने किया। सन् १९३९ में भारत सरकार के कुल जन-ऋण का योग लगभग ५०० करोड़ रुपये था और वही सन् १९४६ में बढ़कर लगभग २००० करोड़ रुपया हो गया। देश के पौण्ड पावने को स्थिर रखने में भी रिजर्व ने अत्यधिक सहयोग दिया।

रिजर्व बैंक के युद्धकालीन कार्यों के सम्बन्ध में यह आरोप लगाया जाता है कि उसने जनता के हितों की कुछ भी परवाह न करते हुए सरकार की नीति का अनुगमन किया और इस प्रकार देश में भयंकर मुद्रा-स्फीति छा गयी तथा वस्तुओं का मूल्य ऊँचा हो गया। किन्तु निष्पक्ष भाव से अवलोकन करने पर यह पूर्णतया स्पष्ट हो जायगा कि यह दोष आधार-रहित तथा निर्मूल है। सारा दोष सरकार को ही दिया जाना चाहिए। क्योंकि रिजर्व बैंक ने तो सदैव सरकार को देश में बढ़ने वाले  स्तर की

पर्याप्त सूचना देने का प्रयास किया, फिर भी सरकार ने रिजर्व बैंक की बातें अनसुनी कर दी।

रिजर्व बैंक की युद्धोत्तरकालीन समस्याएँ

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भी रिजर्व बैंक को शांति न मिली। उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा जो कि निम्न प्रकार की थी—

(१) मुद्रा-स्फीति—युद्ध के पश्चात् जून सन् १९४८ तक मुद्रा का प्रसार होता रहा। अगस्त सन् १९४६ के पश्चात् प्रतिभूतियों के मूल्य में एकाएक अवसाद या गिरावट हुई। इस अवसाद को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने विवृत विपणि की क्रियाओं का सहारा लिया। विवृत विपणि की क्रियाओं से यह लाभ हुआ कि अधिकोषों को राशि-संग्रह में सुविधा हो गयी और इस प्रकार मुद्रा की सामयिक आवश्यकता पूरी हो सकी। रिजर्व बैंक ने अन्य अधिकोषों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय किया जिससे उन अधिकोषों को ऋण देने के निमित्त राशि प्राप्त होती रही। सन् १९४८-४९ की अपेक्षा सन् १९४९-५० में अधिकोषों ने लगभग १० करोड़ रुपये का अधिक ऋण प्रदान किया और फिर ऋण की मात्रा क्रमशः बढ़ती गयी।

(२) देश का विभाजन—अगस्त सन् १९४७ में देश का विभाजन होते ही रिजर्व बैंक के दायित्वों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। जुलाई सन् १९४८ तक रिजर्व बैंक को भारत के साथ-ही-साथ पाकिस्तान के केन्द्रीय अधिकोष के रूप में भी कार्य करना पड़ा क्योंकि उस समय तक पाकिस्तान में किसी केन्द्रीय अधिकोष की स्थापना न हो सकी थी। दोनों सरकारों की राशियों का प्रबन्ध तथा जन-ऋण का संचालन भी रिजर्व बैंक को ही करना पड़ा। ज्यों ही पाकिस्तान में केन्द्रीय अधिकोष की स्थापना हुई रिजर्व बैंक की सम्पत्ति का विभाजन किया गया, जिसमें १५३ करोड़ रु० मूल्य के स्टॉक, सोना तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ पाकिस्तान के केन्द्रीय अधिकोष को दी गयी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में चलने

वाले भारत सरकार के नोटों के बदले में ८२ करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से पाकिस्तान के केन्द्रीय अधिकोष को और दिया गया। किन्तु यह ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक ने ये सारे हस्तांतरण एव लेन-देन के कार्य इतनी सावधानी एव कुशलतापूर्वक किये कि भारतीय मुद्रा एव साख व्यवस्था पर उसका कोई भी विपरीत प्रभाव न पड़ सका।

(३) अधिकोषण सकट—देश का विभाजन होने के कारण अनेक भारतीय अधिकोषों को महान् सकट का सामना करना पड़ा और उन्हें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे अपनी सम्पत्ति का हस्तांतरण कर लें। यह सकट विशेष कर उन अधिकोषों पर आया जिनके कार्यालय पाकिस्तान में थे। इस कार्य में रिजर्व बैंक ने उन अधिकोषों को पर्याप्त सुविधा एव सहयोग प्रदान किया। बंगाल के अधिकोष विशेष रूप से इस सकट से प्रभावित हुए थे। रिजर्व बैंक ने अपनी सेवाओं से देश को पुनः अधिकोषण सकट आने से बचा लिया।

(४) मुद्रा की दुर्लभता—सन् १९४८ के पश्चात् देश में मुद्रा की महान् दुर्लभता होने लगी थी। यहाँ तक दुर्लभता हुई कि देश का भुगतान सतुलन भी प्रतिकूल होने लगा। दिसम्बर सन् १९४८ से अगस्त १९४९ तक विदेशी मुद्रा का अभाव इतना बढ़ गया कि रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष में लगभग २१९ करोड़ रुपये की कमी हो गयी। एक ओर तो उत्पादन न बढ़ सका और दूसरी ओर आयात पर कोई प्रतिबन्ध न रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारी वर्ग ने भविष्य में माल के अभाव का अनुमान लगाकर विदेशों से अधिक मात्रा में माल एक साथ क्रय करना प्रारम्भ कर दिया। अधिकोषों से अधिक मात्रा में जमा की राशि निकाले जाने से भी सभी ओर मुद्रा का अभाव दृष्टिगोचर होने लगा। मुद्रा की मात्रा में कमी आने का एक कारण यह था कि उन दिनों लोगों की बचत कम हो गयी थी। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के विचार से रिजर्व बैंक ने तालिकाबद्ध अधिकोषों के पास वाली सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना प्रारम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रतिभूतियों की जमानत पर अपने अनुसूचित अधिकोषों को ऋण प्रदान करना भी प्रारम्भ कर दिया। १४ जनवरी सन् १९५१ को इस

प्रकार प्रदान किये हुए ऋणों की मात्रा २३ करोड़ रुपये थी। रिजर्व बैंक ने अन्य अधिकोषों की सट्टेबाजी को रोकने का प्रयास किया और उन्हें ऋण प्रदान करने से वंचित रखा। सितम्बर सन् १९४९ में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और इसके पश्चात् देश के मूल्य-स्तर को बढ़ने से रोकने का कार्य रिजर्व बैंक ने संपादित किया।

(५) साख नियंत्रण—सन् १९५१ में रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम साख नियंत्रण के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाये। एक तो यह कि नवम्बर के महीने से इसने अपनी कटौती-दर को ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३½ प्रतिशत कर दिया, और दूसरे, बैंक ने व्यापारिक अधिकोषों की सरकारी प्रतिभूतियों को केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर क्रय न करने का निर्णय किया तथा यह भी घोषित किया कि अब वह इन अधिकोषों को सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण न देगा। यह सब कुछ रिजर्व बैंक ने अपनी अधिकोष-दर अधिक प्रभावशील बनाने के निमित्त किया। अधिकोष-दर को ऊँची करने से यह लाभ हुआ कि साख-संकोचन होने लगा। इधर इम्पीरियल बैंक ने भी अपनी अधिकोष दर को २½ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत कर दिया और तत्पश्चात् ३½ प्रतिशत कर दिया। विनिमय अधिकोषों ने अपनी दर में १।२ प्रतिशत की वृद्धि की। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकोषों ने भी अपनी-अपनी ब्याज दर में १।४ प्रतिशत तथा १।२ प्रतिशत की वृद्धि की। अब अधिकोषों ने ऋण देते समय अत्यधिक सावधानी से काम प्रारम्भ कर दिया और ऋण-राशि में पर्याप्त कमी की। साथ-ही-साथ दिये हुए ऋणों को वापस माँगने लगे तथा ऋणों पर आनुषंगिक प्रतिभूतियों की मात्रा में वृद्धि करने पर जोर देने लगे। इस प्रकार चारों ओर मुद्रा-संकोच होने लगा। यद्यपि रिजर्व बैंक ने अन्य अधिकोषों को ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाने या अधिक सावधानी बरतने से सम्बन्धित कोई आदेश नहीं दिया था, फिर भी उसकी अधिकोष-दर में वृद्धि होने से इस प्रकार का वातावरण स्वयं ही सभी ओर बन गया। इन सब बातों से स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक का आधिपत्य सर्वत्र बढ़ता ही जा

इस महान् मुद्रा-सकोच के समय रिजर्व बैंक ने सभी अधिकोषों की सामयिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय न करते हुए भी उनकी साख पर ऋण देने की घोषणा तो कर ही दी। इससे अधिकोष-दर को अधिक बल एव प्रोत्साहन मिला। अधिकोष-दर बढ़ाने के पश्चात् ६ सप्ताहों में ही रिजर्व बैंक ने अन्य अधिकोषों को सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर लगभग १७ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुद्रा की सामयिक दुर्लभता दूर होती गयी और साथ-ही-साथ अधिकोष-दर भी प्रभावशाली बनती गयी।

आर्थिक आयोजन एव रिजर्व बैंक की साख नीति

रिजर्व बैंक की साख नीति को देश के आर्थिक आयोजनों में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि आर्थिक योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-ही-साथ देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि और मुद्रा की उपलब्धि भी इससे बढ़ जायगी। अधिकोषों द्वारा दी जाने वाली ऋण-मात्रा में भी वृद्धि होगी। इन सभी कारणों से तथा हीनार्थ-प्रबन्धन^१ की नीति को अपनाने के फलस्वरूप देश में वस्तुओं के मूल्य-स्तर के बढ़ने की सम्भावना की जाती है। अधिकोषों को चाहिए कि वे अपनी साख नीति को इतनी नियंत्रित रखें कि मूल्य-स्तर बढ़ने में पाये तथा आवश्यकता के समय पूँजी का अभाव भी न होने पाये। रिजर्व बैंक ने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु गुणात्मक साख-नियंत्रण नीतिका अनुसरण किया है। अधिकोषण प्रमण्डल विधान १९४९ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अधिकोषों के अहितकर कार्यों पर रोक लगा दे। आयोजन काल में रिजर्व बैंक ने इसी शक्ति की आड़ ली है। विशिष्ट वस्तुओं की साख पर उधार देने से अधिकोषों को वंचित किया गया ताकि इस प्रकार से ऋण लेकर लोग उन विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह करके उनके भाव में किसी प्रकार की वृद्धि न कर सकें। १७ मई सन् १९५६ को रिजर्व बैंक ने

अपने अनुसूचित अधिकोषो को धान और चावल की साख पर ५०,००० रुपये से अधिक रकम उधार देने पर रोक लगा दी तथा इनके लिए जमानत की सीमा को भी १० प्रतिशत बढ़ा दिया। इस नियन्त्रण के फलस्वरूप धान और चावल की साख पर दिये गये ऋण की राशि २७ अप्रैल १९५६ वाले २६ करोड़ से घटकर २६ अक्टूबर सन् १९५६ को केवल ४ करोड़ रुपये ही रह गयी। इसलिए १४ नवम्बर १९५६ को यह आदेश वापस ले लिया गया। आदेश को वापस लेते ही ८ फरवरी सन् १९५७ को फिर इस प्रकार ली जाने वाली ऋण की राशि २१ करोड़ रुपये हो गयी। अतः इस प्रकार का प्रतिबन्ध पुनः लगाया गया। १३ सितम्बर सन् १९५६ को गेहूँ, मोटे अन्न, चना, दाल और सूती कपड़े की जमानत पर ५०,००० रुपये से अधिक ऋण प्रदान करने के लिए अनुसूचित अधिकोषो पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इसलिए इन वस्तुओं की साख पर दिये गये ऋण की राशि में कमी आ गयी और इन वस्तुओं के मूल्य पुनः गिरने लगे।

७ जून सन् १९५७ को रिजर्व बैंक ने अपने तालिकाबद्ध अधिकोषो को खाद्यान्न की वस्तुओं की साख पर ऋण प्रदान करने की प्रवृत्ति को कम करने का निर्देश दिया। इस निर्देश की मुख्य बातें निम्न प्रकार की थीं।

(१) खाद्यान्न की जमानत की वर्तमान सीमा में कम-से-कम पाँच प्रतिशत की वृद्धि अवश्य की जाय ताकि जमानत की दर ४० प्रतिशत से कम न रहे।

(२) खाद्यान्न की जमानत पर प्रदान किये गये उधार की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि १२ जुलाई तक तथा उसके पश्चात् प्रति सप्ताह धान और चावल के रूप में दिये गये उधार की सीमा सन् १९५६ के तत्सम्बन्धी सप्ताह वाली सीमा के ६६ २/३ प्रतिशत से अधिक न हो तथा अन्य खाद्यान्नों के सम्बन्ध में ७५ प्रतिशत से अधिक न हो।

(३) धान और चावल की जमानत पर ५०,००० रुपये से अधिक ऋण ~~किन्हीं~~ को न दिया जाय।

रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों के फलस्वरूप अधिकोषों ने अपनी साख में कमी कर दी और वस्तुओं का मूल्यस्तर नियंत्रित हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक की यह नीति सफल रही। इस नीति की सफलता देश के सभी अधिकोषों से मिलने वाले सहयोग पर ही आश्रित है। अतः यदि अधिकोषों का सहयोग मिलता रहे तो गुणात्मक साख नीति आर्थिक आयोजन की सफलता का एक आवश्यक अंग बन सकती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय आयोजकों ने १२०० करोड़ रुपये के हीनार्थ-प्रबन्ध की आवश्यकता बतायी, क्योंकि इस योजना की व्यवस्था के लिए धन की कमी हो गयी। ऐसी हालत में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह नोट का निर्गमन करे और साख का उचित नियमन करे। अतः रिजर्व बैंक के विधान में कुछ संशोधन करने पड़े ताकि उसको तत्सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रदान किये जा सकें। ये संशोधन निम्नलिखित हैं।

१ रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग में विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम सीमा ४०० करोड़ रुपये मूल्य की हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर यह न्यूनतम सीमा ३०० करोड़ रुपये के मूल्य तक की जा सकती है। फिर भी केन्द्रीय सरकार कोई भी दण्ड नहीं लगायेगी।

२ नोट-निर्गमन विभाग में सोना तथा सोने के सिक्कों की न्यूनतम सीमा ११५ करोड़ रुपये मूल्य की रखी जा सकती है।

इस प्रकार नोट निर्गमन के लिए पत्र-मुद्रा कोष में कम-से-कम ४०० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ एवं ११५ करोड़ रुपये के मूल्य का सोना और सोने के सिक्के अर्थात् कुल मिलाकर ५१५ करोड़ रुपये मूल्य का न्यूनतम कोष रखना आवश्यक कर दिया गया। अब तक तो पत्र-मुद्रा का चलन आनुपातिक कोष-पद्धति के आधार पर होता रहा जिसके अनुसार निर्गमित मुद्रा के मूल्य का ४० प्रतिशत विदेशी प्रतिभूतियों, सोने और सोने के सिक्कों के रूप में रखना आवश्यक था एवं शेष चाँदी, चाँदी के सिक्के तथा देशी बिलों के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता था, परन्तु अब न्यूनतम कोष प्रणाली अपना ली गयी।

३ अब तक तो नोट निर्गमन विभाग में रखे गये सुरक्षित कोष के सोने का मूल्य १ रुपया ८४७५१२ ग्रेन, अर्थात् २१ रुपये १३ आने १० पाई प्रति तोला था। इस दर पर रिजर्व बैंक के पास ४० ०२ करोड़ रुपये के मूल्य का सोना था। किन्तु सशोधन के पश्चात् सुरक्षित सोने का मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा निर्धारित दर यानी ३५ डालर प्रति औंस, अर्थात् १ रुपया = २८८ ग्रेन या ६२ रुपये ८ आने प्रति तोला होने लगा है। इस दर पर बैंक के पत्र-मुद्रा कोष वाले सोने का मूल्य ११५ करोड़ रुपया हो गया है।

४ रिजर्व बैंक अपने अनुसूचित अधिकोषों द्वारा अपने पास जमा की जाने वाली राशि में वृद्धि कर सकता है। अब तक अनुसूचित अधिकोष अपनी माँग-देनदारी का ५ प्रतिशत तथा काल-देनदारी का २ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा करते थे परन्तु सशोधन के पश्चात् रिजर्व बैंक उन अधिकोषों से उनकी माँग-देनदारी का ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तथा काल-देनदारी का २ प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक अपने पास जमा कर सकता है।

सन् १९५७ में नोट-निर्गमन की पद्धति में और भी ढिलाई कर दी गयी। रिजर्व बैंक के पत्र-मुद्रा कोष में अब कुल मिलाकर २०० करोड़ रुपये की ही प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। जिसमें से ११५ करोड़ रुपये के मूल्य का सोना तथा शेष ७५ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ होंगी। इससे स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों ही विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम सीमा को भी समाप्त कर देना चाहते हैं। इसके लिए वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विदेशी प्रतिभूतियाँ विशेष अवसरों के लिए ही रखी जाती हैं और इस समय पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशी प्रतिभूतियों की आवश्यकता है, तो फिर उनका प्रयोग में अवश्य लाना चाहिए।

रिजर्व बैंक का आलोचनात्मक अध्ययन

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के कार्य-कलापों एवं विधान का पूर्ण अध्ययन

कर लेने के पश्चात् यह युक्ति-सगत प्रतीत होता है कि उन पर एक आलोचनात्मक दृष्टि भी डाली जाय।

रिजर्व बैंक को नोट-निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है अतः उसे देश की सम्पूर्ण मुद्रा एवं साख पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, किन्तु अपने सम्पूर्ण जीवन-काल में वह न तो देश की साख प्रणाली को व्यवस्थित कर सका है और न तो बिल-बाजार को ही सगठित और विकसित कर सका है। देश में एक व्यवस्थित बिल-बाजार के अभाव के कारण केन्द्रीय अधिकोषण की नीतियों को भी पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी दोष आलोचकों ने दिखाये हैं, जैसे रिजर्व बैंक स्वदेशी बैंकरो को नियमबद्ध नहीं कर सका है, युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति को रोक नहीं सका और न तो कृषि-साख की व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध ही कर सका है। परन्तु यदि तटस्थ होकर उन परिस्थितियों पर जिनमें यह बैंक अपना कार्य सम्पादन करता रहा है, निष्पक्ष भाव से विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इसने पूरी शक्ति और सावधानी से कार्य किया है और इसका बहुत कुछ कार्य सतोषप्रद रहा है। हाँ, जो कार्य रिजर्व बैंक न कर सका उसके लिए वह अकेला दोषी नहीं ठहराया जा सकता बल्कि उसके विधान का दोष माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी सरकार भी इस दोष की भागी रही है। साख पर पूर्ण नियंत्रण न रख सकने या साख-व्यवस्था को पूर्ण-रूपेण सगठित न कर सकने के निम्न कारण हो सकते हैं।

(१) विदेशी विनिमय के क्षेत्र में सोने तथा स्टर्लिंग की प्रतिभूतियों का क्रय करने के लिए रिजर्व बैंक की जमा राशि अपर्याप्त है। देश में सोने के सिक्के तो चलते नहीं इसलिए रुपये को सोने में बदल कर विदेशी लेन-देन का भुगतान किया जाता है। देश में सोने के प्रयोग को रोकने के लिए नोटों का निर्गमन किया जाता है। सुरक्षित रखे हुए सोने का प्रयोग केवल बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किया जाता है। किन्तु यह सुरक्षित स्वर्ण पूरा नहीं पड़ता।

(२) स्वदेशी बैंकर रिजर्व बैंक के नियमों से आबद्ध नहीं हैं। जब

भी रिजर्व बैंक अपनी अधिकोष दर के द्वारा साख के नियन्त्रण का प्रयत्न करता है ये देशी बैंकर अपने कार्य-कलापो से मुद्रा-मण्डी को प्रभावित कर डालते हैं। इनकी सख्या अधिक होने के कारण इनको नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के अनेक प्रयत्न विफल रहे हैं।

(३) रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित माँग-देनदारी और काल-देनदारी की न्यूनतम रकम को जमा कर देने के पश्चात् भी तालिकाबद्ध अधिकोषों के पास इतनी अधिक राशि बची रह जाती है कि वे जनता की 'सामयिक माँग' का भुगतान अपने ही पास से मनमाने ढंग पर कर देते हैं और इस प्रकार रिजर्व बैंक की नीति और नियन्त्रण व्यर्थ हो जाता है। यह दोष रिजर्व बैंक के विधान का माना जा सकता है।

(४) देश में व्यावसायिक बिलों का भी प्रयोग नहीं होता। स्वदेशी बैंकर अपनी निजी राशि से व्यापार करने के कारण मनचाहा ब्याज लेते हैं। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में विभिन्न ब्याज दर प्रचलित हैं इनका अन्य अधिकोषों की ब्याज दर से कोई सम्बन्ध ही नहीं स्थापित हो पाता। जब ये अधिकोष मुद्रा-मण्डी की ब्याज दर को नियन्त्रित नहीं कर पाते तो रिजर्व बैंक जो एक केन्द्रीय संस्था है और जिसका कोई सीधा सम्बन्ध मुद्रा मण्डी के इन अधिकोषों से नहीं है, साख नियन्त्रण करने में असफल हो ही जायगा।

(५) बहुत से छोटे-छोटे अधिकोष जो कि देश के विभिन्न भागों में अपना कार्य कर रहे हैं, रिजर्व बैंक के विधान से प्रभावित नहीं हो पाते हैं, उनको रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में लाने की आवश्यकता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि रिजर्व बैंक के विधान की शर्तों को पूरा करने में वे असमर्थ रहते हैं। इसलिए बैंक के विधान की उन शर्तों को कुछ ढीला करना आवश्यक है ताकि २० वर्ष से अधिक कार्य करने वाले अधिकोष जिनकी पूँजी १ लाख रुपये की हो, वे भी रिजर्व बैंक के सदस्य बन सकें।

आलोचकों का यह भी कहना है कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने मुद्रा मण्डी को आशातीत सीमा तक नियन्त्रित एवं सगठित नहीं किया है। मुद्रा मण्डी ~~बहुत~~ विकसित और सगठित होना बहुत कुछ इस बात पर आश्रित

होता है कि देश के सभी सदस्य अधिकोष किस सीमा तक ऋण लेने तथा बिलो की कटौती कराने के लिए रिजर्व बैंक पर आश्रित रहते हैं तथा मुद्रा-मण्डी की अन्य सस्थाएँ, जैसे विदेशी बैंकर किस सीमा तक ऋण लेने एवं बिलो की कटौती कराने के लिए रिजर्व बैंक की सहायता लेते हैं। यदि ये अधिकतम सीमा तक रिजर्व बैंक पर ही आश्रित रहते हैं तो निस्सदेह मुद्रा-मण्डी का सगठन अच्छा होगा। किन्तु भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक की स्थापना ही ऐसे समय में हुई जब कि अवसाद अपनी चरम सीमा पर पहुँचा था। रुपये की अधिकता थी ही इसलिए ब्याज दर भी गिरी हुई थी। तालिकाबद्ध अधिकोषों के पास राशि की इतनी अधिकता थी कि वे सदैव से स्वतन्त्र रहे हैं और उपर्युक्त कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की सहायता की आवश्यकता उनको नहीं हुई। छोटे अधिकोषों को यदि कोई परेशानी हुई भी तो उन्होंने अपने बड़े अधिकोषों की सहायता ले ली। यही सब कारण है कि रिजर्व बैंक मुद्रामण्डी को सगठित करने में असफल रह गया।

भारतवर्ष में व्यापारिक अधिकोषों की संख्या भी कम है और निकट भविष्य में उनकी संख्या बढ़ने की आशा भी नहीं की जाती है। मुद्रा मण्डी में बाजार-बिलो की दर बहुत अधिक है। कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बाजार-बिलो की दर अधिकोष-दर से भी अधिक हो जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक के सदस्य अधिकोषों का अन्य छोटे अधिकोषों तथा बिलो आदि पर बहुत कम नियन्त्रण है। इसलिए रिजर्व बैंक, जिसका स्वदेशी बैंकरो पर प्रत्यक्ष कोई नियन्त्रण नहीं है अपने सदस्य अधिकोषों की सहायता से भी कोई नियन्त्रण रख सकने में असमर्थ हो जाता है।

इसके पश्चात् आलोचकों का यह कहना है कि रिजर्व बैंक द्वारा लागू की हुई अधिकोष दर भी अधिक कार्यशील एवं प्रभावशाली नहीं रही है। किन्तु यही दशा तो आज विश्व के सारे देशों के केन्द्रीय अधिकोषों की भी है। हाँ, भारत की स्थिति इस सम्बन्ध में कुछ भिन्न अवश्य है, और वह यह कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न ब्याज दर प्रचलित है। कही तो ब्याज की दर ऊँची है और कही नीची। यदि कभी रिजर्व बैंक ने

अधिकोष-दर का सहारा लेने का प्रयास भी किया तो देश में प्रचलित विभिन्न-व्याज-दरों के कारण उसकी अधिकोष-दर देश भर की व्याज-दर में समानता स्थापित कर सकने में पूर्णतया असफल ही रही। इस दोष का भागी रिजर्व बैंक स्वयं नहीं बल्कि स्वदेशी बैंकर और उनकी कार्य-प्रणाली है।

प्रायः सदस्य अधिकोष रिजर्व बैंक से बिलों की कटौती कराने की अपेक्षा ऋण ही लेना अधिक पसन्द करते हैं। इसका कारण यह है कि ऋण के पुनर्भुगतान में उनको यह सुविधा होती है कि वे कभी भी ऋण को लौटा सकते हैं, परन्तु बिल के सम्बन्ध में यह बात नहीं है, क्योंकि बिल के भुगतान की तो अवधि होती है। इसके अतिरिक्त बिल पर व्याज दर भी ऊँची होती है। यद्यपि रिजर्व बैंक अपनी नीति स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि उसका लक्ष्य ऋणों के भुगतान की प्रवृत्ति को हतोत्साहित तथा बिलों के भुगतान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है।

रिजर्व बैंक की विवृत विपणि क्रियाएँ भी साख नियंत्रण का उद्देश्य पूरा कर सकने में असमर्थ पायी जाती है। यद्यपि उसे यह अधिकार प्राप्त है कि सोने और विदेशी प्रतिभूतियों की आड़ में नोटों का प्रकाशन इच्छित मात्रा में कर सकता है। परन्तु जैसा कि युद्धकाल में इस शक्ति का प्रयोग इस बैंक ने किया था उससे यह स्पष्ट है कि ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किसी असाधारण परिस्थिति में ही वाञ्छनीय होता है। इस सम्बन्ध में डा० मुरजन ने सुझाव दिया है कि सदस्य अधिकोषों को एक निश्चित राशि अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक के पास जमा के रूप में रखनी चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति ही अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए, ताकि उन दोनों सीमाओं के बीच ही सदस्य अधिकोष राशि जमा करते रहे।

विवृत विपणि क्रियाओं की पद्धति को अधिक प्रभावशील बनाने के लिए रिजर्व बैंक को अपने विधान में आवश्यक संशोधन करना चाहिए ताकि सदस्य अधिकोष चल सम्पत्तियों, गोदाम के बिलों, बीजक, रेलवे एवं गोदामों और सीदों पर भी ऋण प्रदान कर सके। इस सम्बन्ध में यह

प्रतिबन्ध लगाना अनिवार्य है कि इस विशेषाधिकार का प्रयोग लाभ कमाने के लिए नहीं वरन् तत्कालीन परिस्थितियों में अधिकोषण व्यवसाय के लिए लाभदायक होने पर ही व्यापारिक अधिकोषों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से हो सकता है।

रिजर्व बैंक की अधिकोष दर और विवृत विपणि क्रिया के प्रभावशील न हो सकने के सम्बन्ध में कुछ और भी ऐसी कठिनाइयाँ थी जिन्होंने उसके इन कार्यों में बाधा पहुँचायी। उदाहरणस्वरूप देश में विभिन्न ब्याज दरों का प्रचलित होना, अनियन्त्रित स्वदेशी बैंकरो और असंगठित मुद्रा-मण्डियों का होना। वास्तविकता यह है कि रिजर्व बैंक ने अपने थोड़े से तालिकाबद्ध अधिकोषों के भरोसे ही सम्पूर्ण देश की साख व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया किन्तु यह उसके लिए उपयोगी न सिद्ध हुआ। उसे चाहिए यह कि अपने विधान की ४२वीं धारा को कुछ ढीली कर दे ताकि देश के अधिक-से-अधिक अधिकोष उसकी तालिका में प्रवेश पा सके। इतना तो निस्सन्देह स्वीकार करना पड़ेगा कि उपर्युक्त अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी रिजर्व बैंक ने मुद्रा-मण्डी पर नियन्त्रण स्थापित कर सकने में अधिक सफलता पायी है, क्योंकि प्रति वर्ष बदलने वाली ब्याज दर को कई वर्षों तक एक समान बनाये रखा, जिससे मुद्रा मण्डी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। मुद्रा-मण्डी में प्रचलित ब्याज दरों की विभिन्नता में कमी तो आयी ही, साथ ही मुद्रा-मण्डी में प्रचलित ब्याज की दर भी नीची हो गयी। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के लिए सस्ती दर पर जन-ऋण प्राप्त किया तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को उचित आर्थिक सलाह भी दी। रिजर्व बैंक ने देश में अधिकोषण की सुविधाएँ भी बढ़ाने का प्रयास किया। रिजर्व बैंक के प्रयास का ही परिणाम है कि आज बम्बई और कलकत्ता की मुद्रा-मण्डियों में प्रचलित ब्याज दरों में बहुत कुछ समता आ गयी है।

हाँ, यह सत्य है कि रिजर्व बैंक न तो बिल बाजार को विकसित एवं संगठित कर सका और न तो स्वदेशी बैंकों को अपने नियन्त्रण में ला सका। पर इस दोष के लिए केवल रिजर्व बैंक को भागी नहीं बनाया जा

सकता। इसी प्रकार मुद्रा-स्फीति लाने का दोष भी केवल रिजर्व बैंक पर ही लगाना ठीक नहीं जँचता है। यह तो सरकार की कार्य-प्रणाली का दोष रहा है। यह सहर्ष स्वीकार करना होगा कि रिजर्व बैंक ने देश की अधि-कोषण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योग दिया है। फिर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाने तथा अधिकोषण प्रमण्डल विधान बन जाने के पश्चात् इसके कार्य और भी सराहनीय पथ पर अग्रसर हो गये हैं।

वर्तमान समय में रिजर्व बैंक तथा मुद्रा मण्डी के बीच स्टेट बैंक की स्थिति एक खाई के समान हो गयी है। परन्तु निम्न दो कारणों से स्टेट बैंक के द्वारा किये जाने वाले रिजर्व बैंक के कार्यों में कोई बाधा नहीं पड़ती—

(१) स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित है।

(२) यह बड़ी ही प्रशंसनीय बात है कि जब भी कठिनाइयों के समय रिजर्व बैंक मुद्रा एव साख प्रचलन करता है उस समय स्टेट बैंक थोक व्यापारी के रूप में सदस्य अधिकोषों तक तथा फुटकर व्यापारी के रूप में जनता तक उन रूपों तथा साख को पहुँचाने का कार्य करता है।

यद्यपि रिजर्व बैंक के सदस्य अधिकोष उसी में ऋण ले सकते हैं फिर भी वे स्टेट बैंक से ही सहायता लेना अधिक पसन्द करते हैं, इसके निम्न कारण हैं—

(१) साख के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की शर्तें बहुत कठोर हैं किन्तु स्टेट बैंक तो ऋण माँगने वाले अधिकोष की आर्थिक स्थिति से सतुष्ट हो जाने पर बिना किसी परेशानी के ही ऋण प्रदान कर देता है।

(२) रिजर्व बैंक के सदस्य अधिकोषों का स्टेट बैंक से पुराना सबन्ध रहा है और दोनों एक-दूसरे से भली भाँति परिचित रहे हैं।

(३) मुद्रा बाजार की परिस्थितियों का तथा उनके उतार-चढ़ाव का प्रभाव स्टेट बैंक को अन्य बैंकों की ही भाँति निभाना पड़ता है। अतः इन परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए स्टेट बैंक अन्य बैंकों को ऋण देने के लिए तत्पर रहता है।

अध्याय ५

द्वितीय महायुद्ध के बाद बैंकिंग का विकास

मन्दी के समय भारतीय बैंक व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गयी तथा मजोर और अव्यवस्थित बैंक दिवालिया हो गये। किन्तु बड़े-बड़े बैंको शाखाओं में वृद्धि होने के कारण व्यापार में बैंको की आर्थिक सहायता होती ही गयी। इन्ही दिनों सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक तथा पोस्टल विंग बैंक दृढतर हो गये तथा इनके कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक हो गये। जर्व बैंक की सहायता से देहाती क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ अधिक हो गयी। जून १९३८ में दक्षिण भारत के बैंको पर संकट आया और कई बैंक बन्द हो गये। परन्तु रिजर्व बैंक द्वारा सामयिक सहायता ऋण के रूप देने से अन्य बैंक सफलता पूर्वक कार्य करते रहे। संयुक्त पूँजी वाले बैंको खातों को अलग-अलग चालू खाता, मुद्दती खाता, विनिमय, हुण्डियाँ, थर पूँजी इत्यादि-इत्यादि खातों में अलग-अलग रखने की व्यवस्था योजना का समुचित आदान-प्रदान बनाये रखने के लिए और इनमें मन्दी का प्रभाव कम करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने कई प्रकार के बाड जारी किये। इन सब उपायों से रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक प्रणाली को कठ काल से बचाने में बड़ी सहायता की।

सन् १९३९ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, जिससे संसार के सभी देश अपनी आर्थिक स्थिति युद्ध के काल की उत्पन्न समस्याओं के समाधान अनुरूप बनाने का प्रयत्न करने लगे। युद्ध ने देश के आर्थिक स्रोतों को, उस समय शान्ति की तरफ लगे थे, युद्ध की तरफ मोड़ दिया। १९३८-९ व १९४२-४३ के बीच युद्ध पर खर्च पहले की अपेक्षा निम्नोक्त देशों आगे दी हुई गति से बढ़ा। अमेरिका में नौगुना, ब्रिटेन में पाँच गुना, नाडा में सात गुना, आस्ट्रेलिया में पाँच गुने व छ गुने के बीच जापान तीन गुना। अमेरिका व ब्रिटेन में सन् १९४२-४३ में सुरक्षा पर व्यय

कुल व्यय का ९० प्रतिशत हुआ, तथा कनाडा और जापान में ७५ से ८० प्रतिशत तक व्यय हुआ। भारत में १९३९-४० व १९४५-४६ में युद्ध पर व्यय ३,४८४ करोड़ रु० हुआ जिसमें भारत का हिस्सा १७४४ करोड़, ५० प्रतिशत रहा। इस समय के बीच भारत का सभी खर्च जिसमें युद्ध के व्यय व अन्य व्यय भी सम्मिलित है, ३९९६ करोड़ रुपये का हुआ, जिसमें से १४६२ करोड़ रु० या ३७ प्रतिशत व्यय सरकारी आय से किया गया, शेष कुछ तो पौड पावने से किया गया तथा कुछ भारतीय लोक-ऋण लेकर पूरा किया गया, जिससे भारतीय लोक-अंश १९४५-४६ में १०७७ करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गया। युद्ध की प्रारम्भिक अवस्था से ही उसकी सहायता के लिए भारत का महत्व माना गया, क्योंकि युद्ध की सफलता के लिए यहाँ से सभी उपयोग के सामान आसानी से तैयार करके भेजे जा सकते थे। यहाँ के उद्योगों ने युद्ध के आवश्यक सभी सामान बनाने शुरू कर दिये तथा भारत के युद्ध-जनित व्यय में आशातीत वृद्धि हुई—कुछ तो स्वयं के युद्ध-व्यय पर तथा कुछ अपने मित्र राष्ट्रों के लिए सहायता के रूप में। इसका स्वाभाविक प्रभाव यह हुआ कि मुद्रा में लगातार तीव्र गति से वृद्धि होने लगी क्योंकि इतनी बड़ी पूँजी की माँग ऋण से पूरी नहीं हो पाती थी। यह मुद्रास्फीति के कारण की विशेषता केवल भारत के लिए ही नहीं थी बल्कि ससार के सभी देशों में यही स्थिति थी। पर यह तो कहा ही जा सकता है कि प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा द्वितीय महायुद्ध में मुद्रा-प्रसार विवेकपूर्ण ढंग से हुआ।

आर्थिक समझौते के अनुसार भारत में होनेवाली युद्ध की सभी वित्तीय व्यवस्था का भार भारत सरकार पर आ गया, जिसे वह रुपये द्वारा पूरा करती थी। युद्ध कार्यों का सभी व्यय भारत सरकार देती थी। इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता था कि व्यय का भार अन्य देशों पर कितना है, कितना नहीं। वास्तव में भारत सरकार भारतीय मुद्रा में जब पूरा भुगतान कर देती थी तब बाद में ब्रिटिश सरकार व्यय का कुछ भाग भारतीय सरकार को देती थी। यद्यपि इन आर्थिक अनुबन्धों का प्रमुख उद्देश्य भारत के आर्थिक दायित्वों को सीमित करना था पर जैसे-जैसे पूर्वी

देशों में युद्ध का विस्तार होता गया, भारतवर्ष एक मात्र युद्ध सामग्रियों की पूर्ति करने वाला देश होता गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर इस प्रकार अत्यन्त अवाञ्छनीय भार लाद दिया तथा यहाँ से असीमित मात्रा में वस्तुओं का क्रय करना प्रारम्भ कर दिया और उनके भुगतान के लिए भारतीय सरकार को असीमित मात्रा में नये नोट जारी करने का आदेश दे दिया। यद्यपि इनके पीछे स्टर्लिंग सिक्यूरिटियों का पूरा-पूरा सहयोग था पर चूँकि ये प्रतिभूतियाँ युद्ध के कारण पूर्ण रूप से बन्द थी अतः मुद्रा-प्रसार होना स्वाभाविक हो गया तथा मुद्रा की क्रयशक्ति घटने लगी।

मुद्रा चलन की वृद्धि को हम निम्न तालिका के द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

वर्ष	छापे गये नोट करोड़ रु में	चलार्थ नोट करोड़ रु में
१९३८—३९	२१० ६४	१८२ ३६
१९३९—४०	२२८ ०१	२०९ २२
१९४०—४१	२५८ ६७	२४१ ४१
१९४१—४२	३१९ ८९	३०७ ६८
१९४२—४३	५२५ २४	५१३ ४४
१९४३—४४	७८७ ६७	७७७ १७
१९४४—४५	९७९ ६२	९६८ ६९
१९४५—४६	११७९ ०५	११६२ ६४

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि मार्च १९४२ के बाद मुद्रा के चलन के परिमाण में तीव्र गति से वृद्धि हुई। ऊपर की तालिका में धातविक मुद्रा को नहीं दिखाया गया है अन्यथा मुद्रा-प्रसार की मात्रा कहीं और अधिक हो जाती।

इस युद्ध-कालीन मुद्रा-प्रसार का प्रभाव भारतीय बैंको पर कई प्रकार से पड़ा। वास्तव में ससार के इतिहास में इस समय का काफी महत्व है, क्योंकि अन्य दिशाओं में उन्नति के साथ ही साथ बैंको की भी बहुमुखी प्रगति हुई। यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के पहले से भी भारतीय सयुक्त-स्कन्ध बैंक उन्नति कर रहे थे, तो भी इस युद्ध-कालीन परिस्थिति के कारण इनका विकास विभिन्न दृष्टियों से हुआ।

बैंको की जमा में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई उसका प्रमुख कारण मुद्रा का प्रसार है जो स्टॉलिंग के आधार पर हुआ, क्योंकि भारतीय सरकार को युद्ध सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए बहुत व्यय करना पड़ता था, कुछ अपने लिए तथा कुछ ब्रिटिश सरकार के लिए।

सन् १९३९ के आगे न केवल भारत में बल्कि ससार के अन्य बैंको की जमा में भी वृद्धि हुई, जैसा कि निम्न तालिका से मालूम होगा।

युद्ध कालीन बैंको की जमा में वृद्धि (राष्ट्रीय मुद्रा १० लाख में)

देश	१९३९	१९४०	१९४१	१९४२	१९४३	१९४४
इंग्लैण्ड	२४४१	२८००	३३२९	३६२९	४०३२	४५४५
अमेरिका	—	५६४३०	६१७१७	७८२७७	१२२६२	११०२७१
आस्ट्रेलिया	३३० ७	३५९	२३७९ ३	४१९ ४	४८८ ०	५३५ १
कनाडा	३२४८	३२०९	३५६६	४२०२	५०४९	५४५८
जर्मनी	७५९६	१०४१७	१३२२१	१५४०९	१८२४४	—
जापान	१९७९४	२४३८९	२९४०६	३५७३८	४३१३२	४७२२९

उपर्युक्त जमा वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जनता की मुद्रा, तरलता की प्रधानता, सरकारी हीनार्थ प्रबन्धन, बैंको द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय आदि।

उपर्युक्त सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि भारत की अपेक्षा अन्य देशों, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका व कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के बैंको की जमा में अधिक वृद्धि हुई। दूसरी प्रमुख विशेषता इस समय की जमा की यह थी कि सम्पूर्ण जमा का अधिकांश भाग सूची-बद्ध बैंको के पास था, विशेष कर बड़े बैंको के पास। उदाहरण के लिए इम्पीरियल बैंक के पास १९४५ में २६० करोड़ रु० जमा थी जब कि कुल जमा ९५३ करोड़ रु० थी। उसी समय विनिमय बैंको के पास १७९ करोड़ रु० की जमा थी। केवल थोड़ा सा बाकी हिस्सा अन्य छोटे बैंको के पास था। ऊपर की तालिका में जमा के जो अंक दिये हुए हैं उनके विवेचन से यह ज्ञात होता है कि १९३९-४५ के बीच निश्चित जमा में (जो कुल जमा का यह आधार था) ह्रास होकर वह चौथाई से भी कम हो गयी और इस प्रकार चालू खाते की अपेक्षा इसमें बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई। प्रथम तीन वर्षों में तो निश्चित जमा में बहुत ही कम वृद्धि हुई। केवल अक्तूबर १९३४ से मार्च १९४५ तक कुछ प्रगति हुई, जब कि चालू खाते का निर्देशांक ३५८ से ४६५ तक बढ़ गया। पर समय-दायित्व १२७ से २०४ तक ही बढ़ पाया। यह प्रवृत्ति प्रथम महायुद्ध की प्रवृत्ति के ठीक विपरीत थी जब कि उस समय निश्चित जमा ऊँची दर से बढ़ी थी।

उपर्युक्त दशा द्वितीय महायुद्ध तक चालू रही जिसके कई कारण हैं। प्रथम तो मदी काल में बैंको के प्रति शका हो गयी थी। युद्ध के कारण यह शका और बलवती हो गयी। लोग अधिक दिनों के लिए बैंक में जमा करने से डरते थे, इसके अतिरिक्त उस पर सूद की दर भी कम थी। अतः वे अपनी जमा चालू खाते में ही जमा करना पसन्द करने लगे। अनिश्चितता की आशका व असामान्य काल की दशाएँ भी इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। सरकार युद्ध के लिए जो क्रय करती थी उसके

भुगतान का ढग भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता था, क्योंकि सरकार उसका भुगतान किश्तों में करती थी, तथा कभी कभी अनुबन्धन के आधार-पूर्ण होने पर, जिससे व्यापारियों को बराबर बैंको से जमा निकालनी पड़ती थी। मुद्रास्फीति व मूल्यों के बराबर उतार-चढ़ाव के कारण लोग अपनी बचत को स्थायी सम्पत्ति के रूप में बदलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका अनुमान था कि युद्ध की समाप्ति के साथ ही पुन मूल्यों में कमी आ जायगी। नवीन औद्योगिक उपकरणों की कमी के कारण भी निर्माता अपनी कार्यशील पूँजी बढ़ाते गये, जिससे उपलब्ध मशीनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। पर जो अनुसूचित बैंक नहीं थे उनके बारे में यह धारणा गलत सिद्ध हुई। उनकी निश्चित जमा में चालू खाते की अपेक्षा वृद्धि ऊँची दर से हुई। अभियाचन देय-धन इन चार सालों में ४ ८७ करोड़ से १७ ५२ करोड़ हो गया, जब कि समय-जमा खाते में ११ ०९ करोड़ ६० से १७ २७ करोड़ ६० तक की वृद्धि हुई। इस असमानता का प्रमुख कारण यह था कि जो अनुसूचित बैंक नहीं थे उनके ग्राहक अपेक्षाकृत अल्प आय वाले होते थे, जो सूद पर अधिक ध्यान देते थे, क्योंकि ये बैंक समय-जमा पर ऊँची दर से सूद देते थे।

जैसे-जैसे चालू खाते में जमा की रकम बढ़ती गयी बैंको के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपनी नकद की स्थिति सुदृढ़ बनायें, जिससे वे अपने माग-दायित्व को किसी भी समय पूरा कर सकें। सामान्य नकद जमा का, जिसमें रिजर्व बैंक के यहाँ का बाकी भी सम्मिलित है, १९३८-३९ में २२ ५८ करोड़ पर ९ ५० प्रतिशत कुल दायित्व था। वह बढ़कर १९४२-४३ तक ६८-७० करोड़ कुल दायित्व का १६ ७३ प्रतिशत हो गया। सभी बैंक बड़ी आसानी से अपनी माग के दायित्व को पूरा कर सकते थे। निम्न वार्षिक आकड़ों से यह और स्पष्ट हो जायगा।

वर्ष	कुल नकद और जमा राशि, करोड़ रु० मे	प्रतिशत दायित्व
१९३८—३९	२२ ५८	९ ५०
१९३९—४०	२४ ५१	९ ९८
१९४०—४१	४४ ७९	१६ ६६
१९४१—४२	४६ ५१	१४ ५८
१९४२—४३	६८ ७०	१६ ७३
१९४३—४४	८४ २०	१४.०५
१९४४—४५	११६ ५६	१४ ९६

पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नकद जमा का रखना उस समय परम आवश्यक था, क्योंकि प्रथम महायुद्ध में इसके अभाव के कारण बैंको को बहुत कठिनाई पड़ी। दूसरे, अनुसूचित बैंको की रिजर्व, बैंक के पास जमा रखने की न्यूनतम जमा की रकम भी निर्धारित कर दी गयी थी। अनुसूचित बैंको ने भी अपनी नकद जमा की स्थिति को सुधारा। १९३९ में कुल दायित्व का केवल ६ ८ प्रतिशत था जब कि १९४३ तक वह बढ़कर १४ प्रतिशत हो गया।

भारत में बैंको की तरल सम्पत्ति में नकद रकम, स्वतन्त्र विनियोग व विपन्न सम्मिलित है। इनका अनुपात कुल जमा का १९३९ में ५६ प्रतिशत था पर १९४३ तक वह बढ़कर ७५ प्रतिशत हो गया।

बैंको की जमा की उत्तरोत्तर वृद्धि का अन्य प्रभाव यह हुआ कि उनकी जमा के अनुपात की अपेक्षा चुकता पूंजी का प्रतिशत धीरे-धीरे कम होता गया। १९३९ में अनुसूचित बैंको की चुकता पूंजी कुल जमा का १३ १ % थी पर वही १९४४-४५ में घटकर ६ १% हो गयी

तथा अनुसूचित बैंको की भी पूँजी २५ प्रतिशत से घटकर १९४५ में ११ प्रतिशत तक आ गयी। यह अनुपात तो अनुसूचित बैंको का और कम होता, पर कुछ बैंको की स्थापना से रुक गया, जैसे—भारत बैंक, दी हिन्दुस्तान कर्माशियल बैंक लि०, दो युनाइटेड कर्माशियल बैंक लि०। ये सभी बैंक एक करोड़ या इससे कुछ अधिक पूँजी से खुले। वास्तव में देखा जाय तो बैंकिंग कम्पनियों की चुकता पूँजी व रक्षित पूँजी इसलिए रखी जाती है कि बैंक के विघटन होने पर जमा करने वालों के हित की रक्षा हो। सामान्यतः चुकता पूँजी व संचित की मात्रा जमा की रकम पर निर्भर न होकर अपने ही स्वभाव व गुण की इस बात की द्योतक होती है कि बैंक उचित मात्रा में जमा आकर्षित करने में असमर्थ है। जमा करने वालों की सुरक्षा के हेतु कम पूँजी व संचित रखकर भी काम चलाया जा सकता है, पर ऐसी अवस्था में उसे पूर्ण रूप से तरल रखना पड़ेगा। इसलिए उस समय भारत सरकार की आज्ञा लेकर कुछ बैंको ने नये अशपत्र जारी किये। सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया जैसे पुराने बैंको ने तो प्रीमियम पर अशपत्र जारी कर इस कमी को पूरा किया।

बैंको को अपनी साधन-सामग्री तरल रखने के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपने पास नकद की मात्रा बढ़ाये या सरकारी प्रतिभूतियों में कम व्याज की दर पर विनियोग करें। बैंको ने थोड़ी अवधि के लिए उद्योग व व्यापार में रुपया लगाने के स्थान पर सरकारी प्रतिभूतियों में दीर्घकालीन विनियोजन करना शुरू कर दिया। निम्न तालिका से बैंको के विनियोग की प्रकृति स्पष्ट हो जायगी।

भारतीय संयुक्त स्कन्ध धनाधारो का विनियोग, लाख रुपये में

द्वितीय महायुद्ध के बाद बैंकिंग का विकास

१४३

बैंक	१९३८	१९३९	१९४०	१९४१	१९४२	१९४३	१९४४	१९४५
इम्पीरियल बैंक	४३,७२	३८,०२	४८,५७	६४,३९	११६,४१	१३०,२०	१४८,६३	१५४,१८
अनुसूचित बैंक	४०,२४.	३६,५१	४२,४५	५८,५२	१०१,७७	१६७,०३	२३२,०८	२७९,०३
नानुसूचित बैंक	३,४१	४,५९	४,८३	५,८०	८,३२	१०,०४	१६,५६	२९,७९

उपर्युक्त आकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि बैंकों के विनियोग में बराबर एक गति से वृद्धि होती चली गयी। सूची-बद्ध बैंक तो अपनी सम्पत्ति का करीब ६० प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगाते थे तथा इम्पीरियल बैंक इससे भी ज्यादा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करता था। फिर भी यह अवस्था अधिक दिनों तक न रह सकी। जमा की गति तीव्रगति से बढ़ने लगी तथा विनियोग का अनुपात जमा की अपेक्षा तेजी से घटने लगा। १९४२ में जो ५९ ३ प्रतिशत था वही १९४३ में ५३ प्रतिशत रह गया। सारांश में हम कह सकते हैं कि युद्ध के वर्षों में अग्रिम की मात्रा कम हुई तथा दूसरा प्रभाव यह हुआ कि सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों का विनियोग बढ़ा।

बैंकों के आर्थिक चिट्ठे में सरकारी प्रतिभूतियों का आधिक्य इस बात का द्योतक है कि सरकार की ऋण लेने की क्षमता अच्छी थी। भारत सरकार स्वयं देश की सब से अधिक ऋण लेने वाली व कर्जदार संस्था हो गयी, विशेष कर बैंकों की तो और अधिक। इस प्रकार उस का नियंत्रण भी अधिक होना स्वाभाविक हो गया। मुख्यतः बैंकों को अपनी बढ़ती हुई जमा का विनियोग करने के लिए इसी पर निर्भर रहना पड़ता था, इसी के ऊपर इनकी सफलता भी निर्भर थी।

यह स्वाभाविक है कि जब विनियोग के माध्यम व विपत्र (बिल) भुनाने के क्षेत्र सीमित हो तो लाभ की न्यून ही आशा रहती है, पर अनुभव इसके विपरीत है। बहुत से बैंकों ने अच्छा लाभ कमाया व ऊँची दर पर लाभांश वितरण किये। मुख्य बैंकों के लाभांश की दर निम्नलिखित है।

प्रति शेयर पर बाटा या दिया हुआ प्रतिशत धन

	१९३९	१९४२	१९४३	१९४५
इम्पीरियल बैंक	१२	१२	१२	१४
बैंक आफ इण्डिया	११	१२	१२	१३
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	—	१२	१२	१४
पंजाब नेशनल बैंक	—	६	६	९
दि इण्डिया बैंक	—	१०	१२	१४
इलाहाबाद बैंक	—	१८	१८	—

यह ऊपर से देखने में तो बहुत आश्चर्यजनक है पर अगर ध्यान से देखा जाय तो पता चलेगा कि बैंको के जमा धन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, विशेष कर चालू खाते में, और चालू खाते पर बहुत कम दर से सूद नाम मात्र को दिया जाता है। फिर बैंक उसका जो विनियोग करते थे उस पर सूद ऊँची दर से मिलता था, जिसमें वे ऊँची दर पर लाभांश वितरण में समर्थ हो सके। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि पूरे युद्ध-काल तक बैंको का अतिरिक्त व्यय कम हुआ, क्योंकि बैंक कर्मचारियों का वेतन बहुत ही कम रहा। फिर भी यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि जिस गति से बैंको के साधन में वृद्धि हुई उस गति से वे लाभ न पा सके, जिस का प्रमुख कारण यह है कि विनियोग के क्षेत्र की भी सरकारी प्रतिभूतियों पर कम ब्याज व बैंको के स्थापनव्यय अधिक रहो गये, विशेष कर उन बैंको के लिए जो निरपेक्ष रूप से शाखाएँ खोलने के पक्ष में थे।

बैंकिंग संस्थाओं का विकास—अन्य स्वाभाविक युद्ध-काल की परिस्थिति का यह प्रभाव हुआ कि नयी-नयी बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना हुई। १९३९ से ४१ के बीच तो इनका कम विकास हुआ पर १९४२-४६ के बीच बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। १९३९ में सूची-बद्ध बैंको की संख्या ६१ थी जो १९४६ के जून तक ९३ हो गयी। इसमें इम्पीरियल बैंक के विनिमय बैंक भी सम्मिलित हैं और उनके दफ्तरों

की सख्या १९४६ मे १२७८ से ३४८० हो गयी, जब कि अनुसूचित बैंको की सख्या १९४६ मे ६७३ से २०४१ हो गयी ।

बैंकिंग सस्थाओ के इस तीव्र गति से विकास का कारण यह है कि भारत जैसे विशाल देश मे बैंकिंग के विकास के लिए अधिक क्षेत्र है और सरकार की उदार व्यय नीति ने तो विनियोग करने लिए तमाम साधन उपलब्ध कर दिये । सरकार की व्यय नीति से जो अपरम्पार द्रव्य बाजार मे आ गया उससे अन्य नया कोई उद्योग तो खोला नहीं जा सका, कारण कि मशीनो का आयात बिलकुल बन्द हो गया । देश मे नये बैंको की स्थापना आसानी से की जा सकती थी । युद्ध के समय निम्न मुख्य बैंको की स्थापना हुई—बैंक आफ बीकानेर १९४४, बैंक आफ जयपुर १९४३, भारत बैंक १९४२, हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक १९४४, जोधपुर कर्मशियल बैंक १९४४, नारग बैंक आफ इण्डिया १९४२, नेशनल बैंक आफ लाहौर १९४३, प्रताप बैंक १९४४, प्रभात बैंक १९४४, युनाइटेड कर्मशियल बैंक १९४३, युनाइटेड इन्डस्ट्रीयल बैंक १९४० एव युनाइटेड सिंध और पंजाब बैंक १९४५ । ये सभी बैंक भारत बैंक की स्थापना के बाद खुले जो सन् १९४२ मे सेठ डालमिया द्वारा खोला गया था । सब से बड़ा सफल व विस्तृत बैंक युनाइटेड कर्मशियल बैंक रहा जो सेठ बिरला द्वारा खोला गया था । छोटे छोटे बैंको की तो कोई सीमा न रही । बंगाल और पंजाब मे सबसे अधिक बैंक खुले । अगर भारतीय सरकार का १९४३ का अध्यादेश लागू न हुआ होता तो और बैंक खुलते पर इसके द्वारा पूंजी निर्गमित होने पर रोक लगा दी गयी । बैंको की अधिकृत पूंजी के अनुपात मे काफी अंतर रहा । इन दिनो कुछ बैंक एक लाख की पूंजी से २० करोड तक की अधिकृत पूंजी द्वारा खोले गये । फिर भी हम यह तो कहेगे कि बैंको का विकास अव्यवस्थित रूप से हुआ । जैसे कुछ स्थानो पर जहाँ पहले से बैंक थे वहाँ नयी-नयी शाखाएँ खोली गयी तथा जहाँ पहले से कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध न थी वहाँ कोई बैंक नहीं खोला गया । इससे बैंको मे अवाञ्छनीय प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया ।

सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि गुण-ग्राहकता की अपेक्षा बैंको की सख्या में ही वृद्धि हुई और सभी बैंको ने कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुभव किया। कुछ बैंको ने तो पुराने बैंकिंग कर्मचारियों को अपने यहाँ अधिक वेतन पर रख लिया।

युद्ध-कालीन अवाञ्छनीय दशाएँ—युद्ध के समय में भारतीय बैंकिंग हमारे सामने उत्साहवर्धक व स्वस्थ उदाहरण प्रस्तुत करता है। फिर भी यह समस्त दोषों से मुक्त भी नहीं है। कुछ दोष तो युद्ध के समय ही दृष्टिगोचर होने लगे थे, पर उन्हें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अपने तत्कालीन प्रयत्न से रोक दिया। उन्हीं दिनों कुछ नये बैंको ने अवाञ्छनीय रीतियाँ अपनाकर अपनी पूँजी का ढाँचा खड़ा किया था तथा प्रबन्ध-संचालकों से कुछ शर्तें तय की थी जो स्वस्थ बैंकिंग के दृष्टिकोण से भ्रमात्मक थी। इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट में संशोधन करके यह दोष दूर कर दिया गया, इससे अधिकृत पूँजी तथा निर्गमित व चुकता पूँजी में अधिक अन्तर नहीं किया जा सकता था तथा ऐसे अश-पत्रों के निर्गमन पर भी रोक लगा दी गयी जिनसे असमान मताधिकार प्राप्त होता था। उद्देश्य यह था कि बैंको का नियंत्रण एव प्रबन्ध कुछ ही लोगों के हाथ में न रह सके। बैंको के अतिरिक्त और किसी को प्रबन्ध-अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता, यह बन्द कर दिया गया तथा उन्हें जो ऊँचा-ऊँचा पारिश्रमिक मिलता था, वह भी सीमित कर दिया गया, जो केवल शुद्ध लाभ में से ही देय था। उनकी नियुक्ति की अधिकतम सीमा २० वर्ष कर दी गयी। पर ये नियम बड़े बैंको के जनरल मैनेजर पर व प्रमुख अभिकर्ताओं पर ही, जो प्रबन्ध-अभिकर्ता द्वारा नियुक्त थे, लागू होते थे।

इसके अतिरिक्त कुछ और दोष भी पाये गये। जैसे कुछ बैंको ने गैर बैंकिंग कम्पनियों पर नियंत्रण पाने के लिए उनके अश-सीमित मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया, बिना इस बात का विचार किये कि उनकी स्थिति कैसी है एव उनका मूल्य क्या है। इस प्रकार जनता के जमा धन का वे अवाञ्छनीय रूप से उपयोग करने लगे जो बैंक के

मूलभूत सिद्धान्त सुरक्षा, लाभ व तरलता से बिल्कुल विपरीत है ।

बैंको ने नयी शाखाएँ खोलने में भी अपनी सूझ-बूझ का परिचय नहीं दिया, जहाँ पहले से बैंकिंग की सुविधाएँ प्राप्त थी वही पर शाखाएँ खोली तथा अवाञ्छनीय प्रतिस्पर्धा मोल ली और इस प्रकार जनता की जमा आकर्षित करने के लिए ऊँची दर पर ब्याज देना प्रारम्भ कर दिया । जमा को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए वे अग्रिम बहुत उदारता से देने लगे तथा उन्होंने ग्राहकों को सट्टे आदि के लिए भी उधार देना शुरू कर दिया जिससे उन्हें अधिक लाभ हो, साथ ही सभी शाखाओं का व्यय मुख्य दफ्तर को ही सहन करना पड़ता था तथा उन्हें उचित कुशलता से चलाने के लिए मुख्य दफ्तर को अपना व्यय करके कुशल कर्मचारियों को रखना पड़ता था ।

बैंक अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपरी साज-सज्जा से छिपाने लगे जिससे उनकी वास्तविक स्थिति, रोकड का ज्ञान अशधारियों को नहीं रहता था । कुछ बैंक अपनी अप्रत्याशित आय से, जो कभी-कभी उन्हें सट्टे आदि के व्यापार से प्राप्त हो जाती थी, अपनी आर्थिक दशा सुदृढ़ न करके लाभांश के रूप में उसे वितरित कर देते थे ।

अगर हम युद्ध के पहले की दशाओं से युद्धकालीन दशाओं की तुलना करें तो पता चलता है कि ये सभी लक्षण नये नहीं थे बल्कि थोड़े बहुत अंश में पहले भी मौजूद थे । उस समय बहुत से ऐसे बैंक थे जो अपर्याप्त पूँजी व सचय से काम कर रहे थे, जिन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । जैसे जमा को आकृष्ट करने के लिए उन्हें ऊँची दर पर ब्याज देना पड़ता था जिसके लिए उन्हें जमा को जोखिम के काम में लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था । जमा प्राप्त करने के लिए वे दूर दूर शाखाएँ खोलते थे जिससे उन्हें बड़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था । साधन-हीन होने के कारण वे योग्य तथा कुशल कर्मचारियों को नियुक्त भी नहीं कर सकते थे ।

उपर्युक्त बातें ऐसी हैं जो कि सामान्यतः उन संस्थाओं के सामने आती ही हैं जिनके पास साधन हैं तथा जो बड़े पैमाने पर काम करना

चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि छोटे बैंको का हमारे समाज में बहुत महत्व है बशर्तें वे अपना कार्य-क्षेत्र सीमित पर गहरा रखें।

बैंको का राष्ट्रीयकरण—द्वितीय महायुद्ध के बाद बढ़ती हुई आर्थिक उन्नति के लिए केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के विषय में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जाने लगे तथा राष्ट्रीयकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया जाने लगा।

(१) द्वितीय महायुद्ध के बाद सभी देशों ने अपने-अपने केन्द्रीय बैंको पर विभिन्न रूप से नियंत्रण रखना शुरू किया तथा इनका संचालन सदैव देश की समृद्धि के लिए किया गया जिससे राष्ट्रीयकरण के लाभ स्वतः प्रकट होने लगे।

(२) महायुद्ध के बाद से कई देशों ने योजनाओं को कार्यान्वित कर रखा था तथा उनकी नियोजित नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपने देश के केन्द्रीय बैंक पर आवश्यक नियंत्रण रखें।

(३) हीनार्थ प्रबन्धन (डेफिसिट फाइनेंसिंग) को आजकल पूर्ण-वृत्ति रोजगारी के लिए बहुत आवश्यक मान लिया गया है। इस रीति का मुख्य उद्देश्य सूद की दर को कम व स्थिर रखना है जिसको प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित बैंकिंग नीति अति आवश्यक है। अगर सूद की दर बढ़ने दी गयी तो सरकार की व्यक्तिगत विनियोग की वृद्धि की नीति सफल न हो सकेगी तथा रोजगार की वृद्धि भी नहीं हो पायेगी। इसलिए सरकार का नियंत्रण केन्द्रीय बैंक पर राष्ट्रीयकरण के रूप में होना चाहिए।

(४) युद्धोत्तर काल में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की स्थापना हुई है। जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष व अन्तर्राष्ट्रीय बैंक जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर स्थापित हुए हैं और जिनका ध्येय देशों में शान्ति व आर्थिक प्रगति की सुविधा प्रदान करना है। चूँकि इनकी स्थापना सभी देशों की सहमति से हुई है अतः केन्द्रीय बैंक ही केवल अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में इनका कार्य कर सकता है, अतः सरकारी काम करने के लिए यह आवश्यक समझा जाने लगा कि केन्द्रीय बैंक का देश के हित में राष्ट्रीयकरण किया जाय।

(५) बहुत से देशों ने द्वितीय महायुद्ध के बाद से अपने यहाँ के आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया है, जैसे खान, यातायात व बैंक। क्योंकि उनका सामाजिकीकरण नियोजित आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना जाने लगा है।

(६) अतः मे इस पुरानी विचार-धारा का अब अन्त हो गया है कि अर्थ-व्यवस्था को राजनीति से सर्वदा दूर रहना चाहिए। यह आजकल न संभव है और न वाछनीय। राष्ट्रीयकरण से देश का अधिक कल्याण हो सकता है।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण—वास्तव में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता और आशा भारत में बहुत पहले से की जाती थी तथा जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, यह प्रश्न उठा कि इस पर नियंत्रण सरकार का होगा कि अशधारियों का? पर जैसा कि पहले हम देख चुके हैं उस समय राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध अनेक तर्क प्रस्तुत किये जाते थे तथा उस समय सत्तार में केवल ग्यारह ऐसे केन्द्रीय बैंक थे जिन पर सरकार का नियंत्रण था। इन परिस्थितियों के कारण सर्वप्रथम यह अश-धारियों का बैंक रहा है। पर इसके बाद से परिस्थितियों में अन्तर होते गये और इसके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा।

इसके कार्यों का अगर विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि नाम मात्र को यह अशधारियों का बैंक रहा है। शुरू से ही इसके प्रमुख पदों पर सरकार के द्वारा मनोनीत व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे। अपने जीवन काल से ही यह सरकार के आदेशों के अनुसार कार्य करता रहा तथा उससे सम्पर्क स्थापित किये रहा। इसी से इसके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता और भी मानी जाने लगी।

यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पहले तक इसके राष्ट्रीयकरण की बात ने अधिक जोर नहीं पकड़ा था क्योंकि सरकार ही अराष्ट्रीय थी। और किसी जिम्मेदार व योग्य सरकार के अभाव के कारण सरकारी कार्य-प्रणाली में अनावश्यक विलंब, असफलता व दुर्गुण मौजूद थे। राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत जनता का उस

विदेशी सरकार मे कोई विश्वास न था तथा केन्द्रीय बैंक का उस समय अशधारियों के हाथ मे नियंत्रण रहने से उन्हें एक प्रकार का सतोष ही मिलता । पर ज्यों ही अपनी राष्ट्रीय सरकार आयी इसके राष्ट्रीयकरण का जोर बढ़ा । हमारी राष्ट्रीय सरकार ने देश मे विस्तृत आधार पर योजनाओं को कार्यान्वित किया । इसके लिए केन्द्रीय बैंक का पूर्ण सहयोग अपेक्षित हो गया तथा इस पर व्यक्तिगत नियंत्रण को अब अच्छा नहीं समझा जाने लगा, क्योंकि अगर केन्द्रीय बैंक व सरकार एक दूसरे की उन्नति मे बाधक होते हैं तो हमारी योजनाएँ कभी सफल नहीं हो सकती थी । सरकार के अवाञ्छनीय कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए दूसरे क्षेत्र है, जैसे सविधान मे सशोधन व चुनाव आदि की प्रणाली मे परिवर्तन करके इसके कार्य-सम्पादन पर अकुश रखा जा सकता है । चाहे कोई भी दल सत्तारूढ हो, देश के हित मे सर्वदा यह अनिवार्य है कि उसे केन्द्रीय बैंक का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त रहे । सर्वप्रथम १९४७ के बजट के भाषण मे भारतीय वित्तमन्त्री ने रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की नीति का संकेत किया । ४ फरवरी १९४८ के बजट भाषण मे पुन घोषणा की गयी कि सरकार सितम्बर १९४८ के बाद रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए विचार करेगी । जहाँ तक अशधारियों की क्षति पूर्ति का प्रश्न है सरकार अशो के मासिक बाजार के औसत मूल्य के बराबर क्षति पूर्ति करेगी । १ जनवरी १९४९ को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया तथा १,१०० रु० के प्रत्येक अश पर ११८ रु० १० आने क्षति पूर्ति दी गयी और उसके तुरन्त बाद भारत सरकार ने सचालको का नया बोर्ड नियुक्त किया तथा उनका नाम १५ जनवरी तक प्रकाशित भी हो गया । इसके प्रबन्ध के सम्बन्ध मे कानून ने केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वह गवर्नर से सलाह करके जनता के हित मे आदेश दे सकती है ।

चूँकि रिजर्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के साथ किये गये सभी अनु-बन्धों को पूरा करता था जिसमे इसे विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय करना पड़ता था, अतः इस बिल से पुराने एक्ट की १७ व ३३ धाराएँ बदल दी

गयी जिससे इसे अधिकार मिल गया कि यह स्टॉलिंग सिक्कूरिटियो के साथ साथ उत देशों की मुद्रा व सिक्कूरिटियो का भी क्रय-विक्रय करे, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य हों ।

सरकार की आधुनिक आर्थिक व वित्तीय नीतियों को देखने से पता चलता है कि सरकार बैंकों के क्रमशः राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है । एक ही बार सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण उत्तम न होगा । इम्पीरियल बैंक का तो राष्ट्रीयकरण हो ही गया । अभी कुछ वर्षों का समय उसके विस्तार में लगेगा । फिर उसके बाद अन्य बड़े बैंकों की राष्ट्रीयकरण की सम्भावना हो सकती है जिसमें सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया व युनाइटेड कमर्शियल बैंक इत्यादि हैं । अगर इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो करीब करीब बैंकिंग सुविधा का ८० प्रतिशत भाग सरकार के नियंत्रण में आ जायगा । तब इन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण आसानी से हो सकता है और इस प्रकार मुद्रा व साख में सम्बन्ध एवं प्रभाव स्थापित किया जा सकता है और देश में बैंकिंग सुविधा का विस्तार सुचारु रूप से किया जा सकता है ।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से तथा १९४९ के बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट के पास हो जाने से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गयी है । देश में संयुक्त स्कंध बैंकों को सुचारु रूप से चलाने व उन पर उचित नियंत्रण रखने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि एक अलग विभाग इसके लिए खोला जाय, जिसमें एक संयुक्त स्कंध बैंक के संचालक की नियुक्ति की जाय । इससे यह आशा की जाती है कि रिजर्व बैंक का बोझ कुछ हलका हो जायगा । इसी प्रकार का एक अन्य विभाग खुल गया है जिससे भारतीय बीमा कम्पनियों की प्रगति का निरीक्षण किया जाता है । इस प्रकार का प्रयास बहुत सफल होगा और इस प्रकार रिजर्व बैंक अपना समस्त ध्यान ग्रामीण वित्त-व्यवस्था को सुधारने में लगा सकता है, जिससे भारत की सबसे महान् ग्रामीण वित्त की समस्या हल हो सकती है ।

जैसी कि आजकल भारतीय सयुक्त-स्कन्ध बैंको की दशा चल रही है, उस को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय बैंको के एकीकरण की बहुत आवश्यकता है। रिजर्व बैंक को यह चाहिए कि वह छोटे छोटे बैंको के क्षेत्रीय आधार पर एकीकरण के लिए प्रयत्नशील हो, क्योंकि यह सुधार राष्ट्रीयकरण से अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से भारतीय बैंको की नौति व उनकी उन्नति—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अर्थात् १९४७ से भारतीय बैंको का विकास क्रमिक व सुदृढ़ आधार पर हुआ है तथा वे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण हाथ बँटा रहे हैं। उनके साधनों में वृद्धि के साथ ही साथ उनके द्वारा व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए प्रदान की गयी सुविधाएँ प्रशंसनीय हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से इनके क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ है। सूची-बद्ध बैंको की जमा राशि जो १९५१ में ८६० करोड़ थी, बढ़कर १९५६ तक १,०४३ करोड़ हो गयी तथा उनके द्वारा प्रदान की गयी ऋण की मात्रा १९५६ तक ४४७ करोड़ से ६१२ करोड़ हो गयी तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित बैंको की रकम ३०३ करोड़ से ३८२ करोड़ हो गयी। इन बैंको का विदेशी विनिमय का कार्य भी काफी बढ़ गया। प्रारम्भ काल से ही हमारे देश में इन बैंको ने अमूल्य सेवाएँ प्रदान की हैं जो सर्राफ़ नाम से जाने जाते हैं तथा अपने कार्य को एक पवित्र कर्तव्य मानकर करते रहे हैं। आज कल वही कार्य आधुनिक सयुक्त-स्कन्ध बैंको द्वारा किये जा रहे हैं। यह सच है कि इस सदी के प्रारम्भ तक विदेशी बैंक विदेशी व्यापार पर अपना आधिपत्य जमाये हुए थे। पर ज्यों ही स्वदेशी आदोलन ने जोर पकड़ा इस प्रकार के बैंक भी कई केन्द्रों में खुल गये। पर स्वतन्त्रता के साथ ही दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप भारतीय बैंको पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा कई बैंको को अपना दरवाजा हमेशा के लिए बन्द कर देना पड़ा। तो भी जो बैंक बच गये उन्होंने शीघ्र ही अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली।

१९४९ में भारतीय बैंकिंग ऐक्ट के आ जाने के कारण बैंको की गति

सुदृढ़ आधार पर चलने लगी तथा देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बैंको का विकास होने लगा, क्योंकि व्यापार व वाणिज्य की गति में एक नया मोड़ आ गया था। बैंको को भी उसी के अनुरूप होना अनिवार्य था। उनके उद्देश्य भी देश के सामूहिक विकास की पूर्ति की तरफ लग गये जिससे उनको अपनी कार्य-विधि में भी परिवर्तन करना पड़ा।

बैंकिंग कम्पनी कानून द्वारा भारतीय बैंको के विकास की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया पर आ गयी जो कि भारत का केन्द्रीय तथा राष्ट्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक इन बैंको के विकास के लिए सतत प्रयत्न करता रहा है। इस कार्य को वह दो प्रकार से करता है। पहले तो वह बैंको पर उचित पर कड़ा नियंत्रण रखकर उनकी नीति व कार्यविधि को मजबूत आधार पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे अपनी उदार आर्थिक सहायता देकर मुद्रा की गति में काफी लोच पैदा करता है तथा काफी हद तक इसने सट्टे की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण कर रखा है। विल-बाजार की सुविधा भी प्रदान की गयी है तथा समय समय पर बैंको की कार्य विधि का निरीक्षण कर रिजर्व बैंक बहुत ही रचनात्मक कार्य कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का प्रचार करने के लिए इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक की स्थापना की गयी, जो अपनी ४०० नयी शाखाएँ खोलने के लिए वचनबद्ध है तथा जिससे देश के प्रत्येक कोने में बैंकिंग सुविधा प्राप्त हो सकती है। स्टेट बैंक की ऋण देने की नीति पर फिर से विचार किया जा रहा है तथा व्यापार व वाणिज्य की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उसे बनाने का कार्य रिजर्व बैंक ने अपने हाथ में ले लिया है, जिससे समूचे देश का विकास सन्तुलित रूप से हो सके। उसके बाद भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ आती हैं जिनके कारण भारत के आर्थिक विकास को एक नया दृष्टिकोण मिलता है। इन बैंको ने सरकार के उक्त योजना सबधी विभिन्न उद्योगों में अपना रूपया लगाकर देश के विकास में काफी मदद की है।

जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र की सहायता करने का प्रश्न है, ये बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करके उसकी सहायता करते हैं। यह राशि जो १९५१ में ३०३ करोड़ थी १९५६ तक बढ़कर ३४२ करोड़ हो गयी। निजी क्षेत्र की व्यापारिक बैंको ने अपनी उदार अग्रिम नीति द्वारा सहायता की है। व्यापारिक बैंको द्वारा दिया गया अग्रिम जो १९५१ में ४४७ करोड़ था, बढ़कर १९५६ तक ६१२ करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि भारत में बैंको की गति पंचवर्षीय योजनाओं के कारण कुछ वर्ष से उन्नति पर है।

इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत उद्योगों को और सहायता देने के लिए एक वित्त-निगम की भी स्थापना की गयी, जिसके द्वारा मध्य स्थिति के उद्योगों को उत्साहित किया जाता है। इस योजना में १५ बैंको ने भाग लिया है तथा यह विचार अमेरिकन बैंको की आधुनिक प्रवृत्तियों से ग्रहण किया गया है। इसके द्वारा प्रदान किये गये अग्रिम की अवधि न तो दीर्घकालीन होती है और न अल्प-कालीन, बल्कि मध्य की स्थिति रहती है। क्योंकि भारत में आजकल इस प्रकार की सेवाओं की अधिक आवश्यकता है। इन पंच-वर्षीय योजनाओं का जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे ही वैसे बैंको के अग्रिम प्रदेय की नीति औद्योगिक सस्थाओं में रुपया लगाने की हो रही है। अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में भी ऐसी ही प्रवृत्ति पायी जा रही है। साख ही एक ऐसी कीली है जिसके चारों तरफ तमाम आर्थिक विकास का झूरा चक्र घूमता है तथा इस कीली को मजबूत व महत्वपूर्ण बनाना बैंको का काम है। विशेष कर औद्योगिक साख की सुदृढ़ स्थापना बैंक ही कर सकते हैं। इस प्रकार बैंको के विस्तार तथा उनके तन्त्रीकरण (टेकनीक) में आवश्यक सुधार करना है जिससे वे और अधिक उपयोगी हो सकें। यह आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है।

करीब-करीब यही स्थिति अमेरिका के बैंको की कुछ समय पहले थी। पर उन्होंने अब समयानुसार अपने में परिवर्तन कर लिये हैं तथा अपने ग्राहकों के प्रति उनका व्यवहार उत्तरोत्तर सहानुभूतिपूर्ण हो

रहा है जो भारतीय बैंको के लिए अनुकरणीय है। यही नहीं, ये बैंक केवल आर्थिक सहायता देकर ही उद्योगों की मदद नहीं करते बल्कि अन्य बहुमूल्य व्यावसायिक सेवाएँ करके भी उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण हाथ बटा रहे हैं। हमारे देश में भी सफल बैंकिंग और चैतन्य बैंकिंग के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया जा रहा है तथा अमल में लाने का प्रयत्न हो रहा है। पर इस दिशा में हमें बहुत काम करना है। भारतीय बैंको को अपनी सकीर्ण मनोवृत्तियों का त्याग कर विस्तृत व उदार नीति अपनाना चाहिए, तभी देश के सन्तुलित विकास में सहायता मिल सकती है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत व्यवसाय में बैंको का क्या स्थान होना चाहिए, इसके निर्धारण के लिए पुन विचार करना पड़ेगा। इसका अध्ययन कर नये दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। कुछ लोगों का विचार है कि देश में बैंकिंग की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंको की भी एक नियोजन विधि अपनायी जाय। यह विचार वास्तव में अनुकरणीय है। आज कल देश में बैंको के विकास की आवश्यकता तो है पर वह विकास नियोजित व सुदृढ़ आधार पर होना चाहिए, तभी वह हमारी सभावित आवश्यकताओं के पूर्ण करने में सफल होगा।

अध्याय ६

बैंकिंग संविधान

१९३७ के पूर्व बैंको के लिए अलग से कोई विधान नहीं था। १९१३ के इंडियन कम्पनी ऐक्ट के अनुसार ही ये शासित होते थे तथा इनका पजीकरण भी उसी के अन्तर्गत होता था। सामान्यतः ये उसी प्रकार शासित होते थे जैसे सामान्य सयुक्त-स्कन्ध कम्पनियाँ होती हैं। कहीं-कहीं अपवादस्वरूप कुछ विशेष नियम केवल बैंको पर लागू होते थे जा बैंको व सामान्य कम्पनियों को पृथक् करते थे।

साधारणतः लोगो की धारणा थी कि यह ऐक्ट बैंको के लिए बहुत अपर्याप्त है और बहुत से बैंक सर्वथा इस नियम के अन्तर्गत आते ही नहीं। सभी देशों में बैंको के लिए अलग से कानून थे क्योंकि इनका स्वरूप अर्ध सरकारी है। बैंक जनता की बचत अपने पास रखकर तथा उसके उपयोग द्वारा जनता के आर्थिक जीवन को बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक समझा जाने लगा कि बैंको के लिए एक अलग विधान हो जिससे जमा करने वालों के हित को संरक्षण मिले और बैंको के प्रति जनता का विश्वास बढे। जनता का विश्वास बढने पर ही बैंको का विकास सुदृढ़ आधार पर हो सकता है। यह सत्य है कि इंग्लैण्ड में बैंको के लिए कोई अलग कानून नहीं है परन्तु इसका उद्देश्य लोक-सम्मति तथा परम्पराओं आदि से पूरा हो जाता है जो शताब्दियों पहले से विकसित हो चुकी है।

यह सच है कि कभी-कभी बैंकिंग विधान कितने ही सुलझे हुए क्यों न हों, बैंको की कार्यविधि व उनकी सूझ-बूझ को कुठित कर देते हैं। यह भी देखा गया है कि यह कार्य अगर उन पर छोड़ दिया जाय तो उसे वे अपना उत्तरदायित्व समझकर भली-भाँति निभाने का प्रयत्न कर सकते

हैं। अकेक्षक (स्टैटिस्टिसियन) का निरीक्षण व रिजर्व बैंक का नियंत्रण कानून से कहीं अधिक प्रभावशाली देखा गया है। बैंक-विशेष की आवश्यक-कतानुसार सीमा-पार्षद-नियम व सीमा-अन्तर्नियम में आवश्यक सशोधन करके भी उनकी कार्य-विधि को सतोषजनक रूप से चलाया जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कोई-न-कोई ऐक्ट या विधान होना ही चाहिए जिससे बैंको की कार्य-क्षमता का एक सामान्य स्तर स्थापित किया जा सके। इस विचार को सामने रखते हुए केन्द्रीय बैंकिंग-कमेटी ने एक सुझाव दिया था कि एक विशेष बैंकिंग कानून होना चाहिए जिससे सभी बैंको पर सामान्य नियंत्रण हो और संभव हो तो कुछ दशा तक विदेशी बैंको पर भी नियंत्रण किया जाय। इसके विपरीत कुछ विदेशी विशेषज्ञों का मत था कि अलग से कानून न पास करके कम्पनी ऐक्ट १९१३ में ही आवश्यक सशोधन कर दिया जाय, क्योंकि इससे वास्तविक संरक्षण बैंको को मिल नहीं पायेगा। उदाहरण-स्वरूप अमेरिका में अनेक बैंक असफल हो रहे थे जब कि वहाँ बैंको के लिए अलग से कानून विद्यमान था और यह आशा की जाती थी कि अगर अलग से कानून पास होने पर भी बैंक असफल होते रहे तो जनता का विश्वास विधान के प्रति हट जायेगा, जिससे कानून की मर्यादा कम होगी।

भारतीय कम्पनी सशोधन विधान १९३६—देश में विदेशी सरकार होने के नाते उसके लिए विदेशी विशेषज्ञों की सलाह मानना स्वाभाविक था। परिणामस्वरूप सरकार ने केन्द्रीय बैंक की सलाह की अवहेलना करके पुराने कम्पनी कानून १९१३ में ही निम्न सशोधन किये।

(१) बैंकिंग कम्पनियों को सामान्य कम्पनियों से अलग करने के लिए बैंक की यह परिभाषा की गयी कि बैंकिंग कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय जनता की जमा को स्वीकार करना है जिसे चेक, ड्राफ्ट या आर्डर द्वारा निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह निम्न कार्यों में से कुछ अन्य कार्य तथा उनके सहायक कार्य भी कर सकती है, यथा—

(क) बिलो, प्रतिज्ञा-पत्रो, स्टॉक इक्सचेंज, प्रतिभूतियों तथा रेलवे रसीद पर रुपये का लेन-देन व उनका स्थानान्तरण करना।

(ख) सरकार या स्थानीय सत्ता की तरफ से अभिकर्ता का काम करना, पर प्रबन्ध-अभिकर्ता की तरह से वह किसी भी व्यवसाय में कार्य नहीं कर सकती है।

(ग) राजकीय व व्यक्तिगत ऋण के लिए प्रसविदा व व्यवहार तथा लेन-देन करना।

(घ) सरकारी व म्युनिसिपल शेयर आदि की गारंटी लेना तथा उनको नीलाम करना।

(ङ) गारंटी व क्षतिपूरक बन्धन के सभी व्यवहार करना।

(च) किसी भी प्रकार के व्यवसाय की आर्थिक सहायता करना।

(छ) ऐसी परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय सम्पत्ति का नीलाम व विक्रय करना जो उसे ऋण के शोधन हेतु प्राप्त हुई हो।

(ज) ट्रस्ट के कार्यों को हाथों में लेना तथा उसके कार्यों को निभाना।

(झ) कम्पनियों के शेयर आदि प्राप्त करना।

(ञ) अपने कर्मचारियों के हित की सस्थाओं की स्थापना करना व उनको आर्थिक सहायता देना।

(ट) कम्पनी के हितार्थ निम्न कार्य करना—

१ भवनों को खरीदना एवं उनको सुरक्षित रखना।

२ कोई-किसी ऐसा काम करना जो आकस्मिक रूप से कम्पनी के हित के लिए अनिवार्य हो जाय।

३ कोई-किसी कम्पनी उस समय तक पजीकृत नहीं की जा सकती जब तक वह अपनी सीमा-पार्षद-नियम में अपना प्रमुख उद्देश्य जनता से स्वीकार न कराए और ऊपर लिखे कार्यों में से कुछ के उद्देश्य स्पष्ट न कर दे।

४. कोई भी बैंकिंग कम्पनी ऊपर लिखे कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं कर सकती चाहे वह भारत में स्थापित हो या विदेश में। केवल गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह उन कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य करने की आज्ञा अत्यन्त आवश्यक होने पर दे सकता है।

५ प्रबन्ध-अभिकर्ता किसी भी बैंकिंग कम्पनी का प्रबन्ध नहीं कर सकता है।

६ कोई भी रजिस्टर्ड बैंकिंग कम्पनी अपना व्यवसाय तब तो चालू नहीं कर सकती जब तक ५०,००० रु० के शेयर कार्य-शील पूँज के रूप में आवंटित न कर दिये जायें और इस प्रकार का घोषणा-पत्र डाइरेक्टर व प्रबन्धक द्वारा रजिस्ट्रार के पास पहुँच न जाय कि आवंटित किये गये अंशों का रुपया प्राप्त हो गया है।

७ कोई भी बैंकिंग कम्पनी अपनी भुगतान न हुई पूँजी पर कोई वर्तन (कमीशन) नहीं ले सकती है, या उसकी अधिकारी नहीं हो सकती है।

८ प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को, जो रिजर्व बैंक से अनुसूची-बद्ध नहीं है, अपने समयानुसार जमा का क्रमशः १॥ प्रतिशत और नकद ५ प्रतिशत जमा रखना पड़ेगा और प्रत्येक महीने में पिछले महीने के दायित्व व नकद जमा का लेखा रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचाना चाहिए। अगर इस कार्य में विलम्ब हुआ तो उत्तरदायी व्यक्ति को प्रत्येक विलम्बित दिन के लिए जुर्माना देना पड़ेगा।

९ बैंकिंग कम्पनी किसी ऐसी सहायक कम्पनी का अंश नहीं ले सकती जिसका उद्देश्य उपर्युक्त कार्यों में से नहीं है।

रिजर्व बैंक द्वारा १९३९ में पृथक् कम्पनी अधिनियम को माँगः पुनः कम्पनी कानून में संशोधन—

१९३९ में रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के समक्ष एक ड्राफ्ट बिल पेश किया जिसमें निम्न तथ्यों पर प्रकाश डाला गया था—

(१) उत्तर भारत में कतिपय बैंकों के असफल होने के कारण बैंक पर कड़े वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता है।

(२) अनुसूचित बैंकों में से अधिकांश, आवश्यक सूचनाएँ रिजर्व बैंक (आर० आई० बी०) को नहीं भेजते हैं और न निश्चित नकद जमा रखते हैं, अतः वे बैंक की परिभाषा (सन् १९३६) में नहीं आते

(३) १९३६ का ऐक्ट कमजोर है और जिन्हे आवश्यकता है उन्हें वह आवश्यक व उचित सरक्षण प्रदान नहीं करता है। इसलिए, और विशेष कर जमा करने वालों के हित की रक्षा के लिए पृथक् अधिनियम की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने तत्कालीन युद्ध के कारण ड्राफ्ट में दिये गये सुझावों को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की। उसने सुझाव दिया कि भारतीय कम्पनी कानून में बैंक से सम्बन्धित धाराओं का ही केवल सशोधन किया जाय। फलतः १९४२ में एक सशोधन पास हुआ, जिसके अनुसार वे सभी कम्पनियाँ जो अपने नाम के आगे या पीछे बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करती हैं, बैंक की परिभाषा के अन्तर्गत आ गयी, चाहे वे चालू खाते में जमा रखती हों या चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करती हों या नहीं। उन पर सभी सामान्य नियंत्रण, जो बैंकिंग के लिए बनाये गये हैं, लागू हुए। यह कानून १ नवम्बर १९४३ से लागू हुआ। कुछ सशोधन १९४४ में भी किये गये जो निम्न हैं—

(१) कोई भी बैंकिंग कम्पनी ऐसे मनेजिंग एजेंट को नियुक्त नहीं कर सकती जिसे प्रारम्भिक कम्पनी के लाभ में से देना नियत हुआ हो एवं जिसका कार्य-काल पाँच वर्ष से अधिक हो।

(२) कुछ नियंत्रण उन बैंकों पर लागू हुए जो १५ जनवरी १९३७ के बाद स्थापित हुए थे, यथा—

(क) परिदत्त पूँजी कुल पूँजी के अर्ध भाग से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) पूँजी सामान्य अंशों में विभक्त होनी चाहिए और वे ही पूर्वाधिकारी अंश चालू रह सकते हैं जो १ जुलाई १९४४ से पहले निगमित किये गये हों।

(ग) जहाँ तक मत-दान का प्रश्न है उसे चुकता पूँजी के उस भाग तक ही नियंत्रित रखना चाहिए जितना कि अशधारियों का अंश हो। अर्थात् चुकता अंश के अनुपात तक ही मतदान सीमित होना चाहिए।

भारत सरकार ने यह बिल १९४४ के अन्त में केन्द्रीय विधान सभा

में पेश किया, पर युद्ध काल की असामान्य स्थिति के कारण तथा विधान सभा में अनेक परिवर्तन होने के कारण यह लागू न हो सका तथा १९४८ में भारतीय पार्लियामेंट में यह पुनः पेश किया गया जिसमें निम्नलिखित संशोधन और किये गये।

(१) बैंकिंग को “जमा स्वीकार करने वाली तथा माँग पर पुनः भुगतान करने वाली संस्था” परिभाषित किया गया।

(२) इस कानून के कार्यान्वित होने के दो साल बाद कोई कम्पनी बैंकिंग का कार्य नहीं कर सकती है, जब तक वह अपने नाम के साथ बैंकिंग, बैंक या बैंकर शब्द न युक्त करे। बैंकिंग कम्पनी के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था माँग पर देय जमा को स्वीकार नहीं कर सकती।

(३) अगर अपनी कार्य-पद्धति के अन्तर्गत कोई बैंकिंग कम्पनी ऐसी स्थायी सम्पत्ति प्राप्त करती है जिसे वह अपने व्यापार के साथ समायोजित नहीं कर सकती, तो ऐसी सम्पत्ति को उसे सात वर्ष के अन्तर्गत बेच देना होगा।

(४) मतदान की क्षमता किसी एक अशुधारी के कुल मतदान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

(५) कोई भी बैंकिंग कम्पनी अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दे सकती।

(६) पूँजीकृत व्यय चुकाने या काटने के बाद ही अंशों पर लाभांश वितरण किया जा सकता है।

(७) कोई भी बैंकिंग कम्पनी किसी ऐसे व्यक्ति को डाइरेक्टर नहीं नियुक्त कर सकती जो अन्य किसी बैंकिंग कम्पनी का डाइरेक्टर हो।

(८) समयानुसार देय धन का १ प्रतिशत नकद जमा रखने की अपेक्षा २ प्रतिशत बढ़ा दिया गया।

(९) कोई भी बैंकिंग कम्पनी किसी ऐसी कम्पनी को अपनी सहायक नहीं बना सकती जिसका बैंकिंग व्यवसाय न हो।

(१०) बैंकिंग कम्पनी किसी अन्य कम्पनी के २० प्रतिशत से अधिक अंश का क्रय नहीं कर सकती और न उस कम्पनी का

अश खरीद सकती है जिसमे उसके प्रबन्धकर्त्ता (मैनेजर) का हित निहित हो।

(११) प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी इस ऐक्ट के लागू होने के छ महीने बाद रिजर्व बैंक आफ इंडिया से कार्य करने की अनुमति लेगी। अतः प्रत्येक नये बैंक को कार्य प्रारम्भ करने के पहले रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया, चाहे वह किसी भी प्रान्त में स्थापित हुआ हो। रिजर्व बैंक उस बैंक के बारे में निम्न स्थिति से सतुष्ट होकर ही लाइसेंस दे सकता था—

(क) वह बैंक अपने जमा करने वालों की माँग को पूरा करने के योग्य है, चाहे जब वे माग करे।

(ख) जमा करने वालों के हित की बैंक द्वारा पुष्टि हो गयी है। अर्थात् उस बैंक के किसी भी कार्य से जमा करने वालों के हित को क्षति नहीं पहुँचती है।

(ग) रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि उपर्युक्त किसी भी शर्त के पूर्ण न होने पर वह लाइसेंस नहीं दे सकता और दिये हुए लाइसेंस को वापस ले सकता है।

भारतीय कम्पनी बिल १९४९—सन् १९४६ का पुराना बैंकिंग बिल वापस ले लिया गया तथा २२ मार्च सन् १९४८ को एक नया बिल प्रस्तुत किया गया जो १६ मार्च १९४९ को पास हुआ। इस प्रकार जो प्रस्ताव १९३९ ही से रखे जा रहे थे तथा १९४६ और ४९ के बीच भिन्न-भिन्न आज्ञाएँ प्रकाशित की गयी थीं उन सब को सम्मिलित रूप से इस ऐक्ट के द्वारा पास कर दिया गया। इसकी प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित हैं।

बैंकिंग व्यापार का अर्थ है जनता को उधार देने तथा विनियोगों में लगाने के विचार से जमा प्राप्त करना और चेक, ड्राफ्ट, आज्ञा-पत्र द्वारा या अन्य प्रकार से माँगने पर तथा और किसी तरह वापस भुगतान देना। अतः बैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो बैंकिंग का कार्य करे।

ऐसा इसलिए किया गया कि बहुत सी बैंकिंग कम्पनियों के विकास

का प्रमुख कारण यह था कि वे व्यापार करने लगी थी जिसे धारा ८ के द्वारा रोक दिया गया।

भारतीय बैंकिंग ऐक्ट १९४९ की धारा १० के अन्तर्गत किसी भी बैंक का प्रबन्ध किसी प्रबन्ध-अभिकर्ता के द्वारा नहीं होना चाहिए तथा कोई भी बैंकिंग कम्पनी अपने यहाँ ऐसे व्यक्ति को नहीं नियुक्त करेगी जो कभी अदालत द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या जिसका प्रतिफल कम्पनी के लाभ पर कमीशन या लाभ के कुछ भाग के रूप में हो अथवा जिसका प्रतिफल कम्पनी के समस्त साधनों से अधिक हो।

धारा ११ के अनुसार जो बैंकिंग कम्पनी विधान पास होने के पहले से कार्य कर रही थी वह विधान पास होने के तीन साल पश्चात्, तथा विधान पास होने के पश्चात् स्थापित कोई भी बैंकिंग कम्पनी स्थापना के समय से ही भारत में उस समय तक व्यापार नहीं कर सकती जब तक कि उसकी पूंजी तथा रिजर्व दोनों का मूल्य नीचे लिखे प्रकार से न हो।

(क) यदि उसका कार्य एक से अधिक राज्यों में है तो पाँच लाख रुपये और यदि वह बैंक कलकत्ता या बम्बई अथवा दोनों में कार्य करता है तो दस लाख रुपये हो।

(ख) यदि उसका कार्यालय एक ही राज्य में है और कलकत्ता तथा बम्बई में नहीं है तो प्रमुख कार्यालय में एक लाख रुपये तथा अन्य कार्यालयों में प्रत्येक में १० लाख रुपये हो। जिस बैंक का सिर्फ एक ही कार्यालय एक ही स्थान पर होगा उसके लिए कम-से-कम ५० हजार रुपये हो।

(ग) जब किसी बैंक के समस्त कार्यालय एक ही प्रान्त में हों और कुछ कलकत्ता या बम्बई में हों तब उसे पाँच लाख रुपये के मूल्य की पूंजी और रिजर्व, तथा बम्बई या कलकत्ता से बाहर किसी भी कार्यालय में २५ हजार रुपये के मूल्य की पूंजी और रिजर्व रखना आवश्यक है।

इस कानून की धारा १२ के अनुसार किसी भी बैंक की प्रार्थित पूंजी उस की अधिकृत पूंजी की आधी से कम नहीं होगी और उसकी प्राप्त

पूँजी उस की प्रार्थित पूँजी की आधी से कम नहीं होगी। यदि कोई बैंक अपनी पूँजी बढ़ाना चाहे तो रिजर्व बैंक की आज्ञा से दो साल के भीतर इन शर्तों की पूर्ति करके ऐसा कर सकता है। पूँजी रचना के उपर्युक्त नियम उन बैंकों पर लागू नहीं है जो १५ जनवरी १९३७ के पहले स्थापित हो गये थे।

धारा १५ के अनुसार कोई भी बैंक अपने पूँजी-व्यय का अपलेखन किये बिना कोई लाभांश नहीं दे सकता, जो कि प्रारम्भिक व्यय, संगठन-व्यय, अशो को बेचने पर कमीशन, दलाली आदि हैं।

धारा १७ के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह लाभांश वितरण करने के पूर्व लाभ का कम-से-कम २० प्रतिशत भाग प्रति वर्ष संचित कोष में तब तक जमा करता रहे जब तक वह कोष परिदत्त पूँजी के बराबर न हो जाय।

धारा २० के अनुसार कोई भी बैंक अपने हिस्सों की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता है, न बैंक किसी ऐसे साझे या निजी कम्पनी को ऋण दे सकता है जिसमें बैंक का संचालक साझीदार हो।

धारा २१ के अनुसार जनहित के विचार से रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह बैंकिंग कम्पनियों की ऋण-नीति का निर्धारण कर सकता है। व्याज दर आदि के लिए भी वह सुझाव दे सकता है। इस नियम का ध्येय सट्टेबाजी तथा मूल्य-वृद्धि रोकने के लिए साख पर नियंत्रण करना है।

धारा २३ के अनुसार कोई भी बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भारत के किसी भी भाग में न तो किसी नयी जगह पर अपना कार्यालय खोल सकता है और न अपना कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान को बदल सकता है। कानून की धारा २४ के अनुसार इस कानून के लागू होने के दो वर्ष उपरांत प्रत्येक बैंक को अपनी कुल मुद्दती तथा माँग जमाओं के २० प्रतिशत मूल्य का नकद रुपया सोने तथा अन्य अनुमोदित सिक्क्याँ के भारत में रखना पड़ेगा। इस नियम का मुख्य ध्येय यह है कि बैंक अपने

जमा करने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उचित रूप से तरल द्रव्य अपने पास रखें। भारतीय बैंकिंग का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि छोटे-छोटे बैंक तरलता को नष्ट कर अपना व्यापार करने लगते हैं। इन नियमों का पालन किया जाता है या नहीं इसके लिए प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को प्रति मास या तीन महीने में इसका विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ेगा।

धारा २७ के अन्तर्गत प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को महीने के अन्तिम शुक्रवार के दिन अपनी देय तथा पूँजी का विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। रिजर्व बैंक किसी भी समय किसी बैंकिंग कम्पनी को लिखित रूप में सूचना देकर एक निश्चित समय के अन्दर अपने कार्य का विवरण प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा दे सकता है।

रिजर्व बैंक कुछ सीमित काल के लिए उपर्युक्त प्रतिबन्धों व नियमितताओं से, उचित कारण होने पर, छूट दे सकता है।

बैंकों के विघटन की रीतियों के लिए इस कानून में कुछ व्यवस्था की गयी है और हाईकोर्ट को कुछ विशेष अधिकार भी दिये गये हैं।

अन्य कुछ धाराएँ भी हैं जिनमें बैंकिंग कम्पनी के अकेक्षण तथा एकाउन्ट के विषय में विस्तार से नियम बतलाये गये हैं।

इस कानून के उद्देश्य ये हैं—(१) अशुधारियों व रकम जमा करने वालों के हित की रक्षा करना, जो कुप्रबन्ध व बेईमानी के कारण जोखिम में था। इस कानून की दो प्रकार से आलोचना की गयी—(क) राष्ट्रीयकरण की नीति में विश्वास करने वालों का कहना था कि यह कानून काफी शिथिल है जिससे बैंकिंग संस्थाओं की कार्यक्षमता व योग्यता घट सकती है तथा (ख) जो व्यक्तिगत व्यवसाय को प्रोत्साहन देने वाले थे उनका कहना था कि इसके द्वारा बैंकों की उत्थिति में अनावश्यक रूप से बाधा पड़ेगी। कुछ अन्य आलोचनाएँ भी इस कानून पर की गयीं, यथा—एक तो इस कानून में देशी बैंकरो को पृथक् रखा गया है,

जो कि भारतीय बैंकिंग व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

दूसरी आलोचना धारा ५४ के कारण है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार व रिजर्व बैंक के किसी पदाधिकारी पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता।

विधान सभा के कुछ सदस्यों ने इस बात का उल्लेख भी किया कि इस धारा के कारण सुदृढ़ बैंकिंग नीति पर आघात पहुँचेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक को इस धारा द्वारा अवाञ्छनीय स्थिति प्राप्त हो जाती है तथा अन्य बैंकों के अधिकार रिजर्व बैंक की दया पर निर्भर हो जाते हैं।

विदेशी विनिमय बैंक

जिस प्रकार देश के भीतर भुगतान की क्रियाएँ देश में स्थित विभिन्न बैंको द्वारा होती हैं, उसी प्रकार एक देश का भुगतान दूसरे देश के साथ विदेशी विनिमय बैंक द्वारा होता है। विदेशी विनिमय बैंको का प्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी भुगतान करना होता है। ये बैंक विदेशी विनिमय बिलों तथा आयात-निर्यात सम्बन्धी भुगतान की बड़े पैमाने पर व्यवस्था करते हैं। विदेशी विनिमय बैंक भुगतान के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के ऋण की भी व्यवस्था करते हैं। मुद्रा विनियोग तथा साख-पत्र परिवर्णित करने का कार्य भी ये करते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका बहुत अधिक महत्व है।

इन बैंको को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(१) ऐसे बैंक जो विदेशों में अपनी ही शाखाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान का कार्य करते हैं, जैसे भारत में लायड्स बैंक।

(२) ऐसे बैंक जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से कुछ देशों के बैंकिंग कार्य के लिए एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे चार्टर बैंक आफ आस्ट्रेलिया एन्ड न्यूज़ीलैंड। जिन देशों का भारत से व्यापार होता है उन सभी की ओर से भारत में यह कार्य या तो कोई बैंक करता है या किसी बैंक की शाखाएँ करती हैं। परन्तु भारत का कोई बैंक विदेशों में कार्य नहीं करता अतः भारत का सभी विदेशी व्यापार विदेशी विनिमय बैंको के सहारे ही होता है। बैंकिंग प्रणाली के आरम्भ से ही इस ओर भारत का ध्यान नहीं गया। साथ ही भारतीय बैंको के पास सीमित साधन थे और वे अपनी शाखाएँ विदेशों में स्थापित नहीं कर सकते थे। देश में बढ़ते हुए उद्योग और व्यापार की पूर्ति भी ये पूरी तौर पर नहीं कर पाते थे। इस प्रकार विदेशों में भारतीय व्यापार का एकाधिकार विदेशी विनिमय बैंको

के ही हाथ रहा। इधर कुछ वर्षों से बैंक आफ इंडिया ने अपनी एक शाखा लन्दन में स्थापित की है और यूनाइटेड कर्माशियल बैंक आफ इंडिया ने इंग्लैण्ड और मलाया में शाखाएँ स्थापित की हैं। यदि भारत के अन्य बैंक भी अन्य देशों में शाखाएँ स्थापित करके भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का भुगतान करने में सफल हो सकें तो जो लाखों रुपये की राशि विदेशी विनिमय बैंकों को मिलती है वह भारतीय बैंकों को ही प्राप्त हो जायगी।

विदेशी विनिमय बैंक के काय तीन भागों में बाँटे जा सकते हैं—

(१) एक देश को दूसरे देश से आयात-निर्यात करने में सहायता प्रदान करना।

(२) एक देश का माल दूसरे देश के बन्दरगाहों से लाकर उस देश के विभिन्न भागों में वितरित करने की सुविधा देना।

(३) एक सामान्य बैंक के लेन-देन सम्बन्धी कार्य करना।

जब कोई भारतीय व्यापारी किसी अन्य देश में माल भेजता है तो वह माल मँगाने वाले के नाम विदेशी विनिमय बिल बनाकर माल के साथ भेजता है। जैसे यदि कोई व्यापारी अपना माल इंग्लैण्ड भेजे तो वह विदेशी विनिमय बिल ऐसे विनिमय बैंक को देगा जिसकी शाखा इंग्लैण्ड में हो। इंग्लैण्ड में माल प्राप्त करने वाला व्यापारी इस बैंक की शाखा में मूल्य जमा कर देगा और भारतीय व्यापारी को यह मूल्य भारत में स्थित उस बैंक के द्वारा प्राप्त हो जायगा। ये बिल दो प्रकार के होते हैं—

(क) भुगतान बिल, (ख) स्वीकृति बिल। भुगतान बिल का मूल्य माल प्राप्त करने पर दे दिया जाता है, परन्तु स्वीकृति बिल माल प्राप्त करने की स्वीकृति होती है, अर्थात् व्यापारी माल प्राप्त करने पर उसकी स्वीकृति की सूचना पर हस्ताक्षर कर उसे विनिमय बैंक को लौटा देगा और या तो स्वीकृतिपत्र में लिखे निश्चित समय के बाद माल प्राप्त करने वाला व्यापारी उस माल का मूल्य विनिमय बैंक में जमा करेगा या इसी अवधि के भीतर उतने मूल्य का माल उस व्यापारी को भेज देगा जिससे उसने माल खरीदा था। स्वीकृति बिल प्रथा उन देशों में अधिक सफल

होती है जिनका आपस में लेन-देन कई वस्तुओं में होता है तथा जिनमें विनिमय बैंक की शाखाएँ कार्य करती हैं, जैसे भारत और इंग्लैंड का व्यापार ।

बन्दरगाहों से भीतरी स्थानों तक माल ले जाने की सुविधा— विनिमय बैंक सामान्यतः यह सुविधा इसलिए देते हैं ताकि वे किसी देश में बैंकिंग के साधारण कार्य भी कर सकें । जैसे कोई कानपुर का व्यापारी लन्दन से सामान आयात करता है तो उसके नाम का लिखा हुआ विनिमय बिल चार्टर्ड बैंक आफ इंग्लैंड की कानपुर शाखा को भेज दिया जायगा । कानपुर में चार्टर्ड बैंक की यह शाखा होने से भुगतान करने में सुविधा होगी । इसी प्रकार यदि इस व्यापारी को कोई माल इंग्लैंड के किसी नगर में भेजना होगा तो चार्टर्ड बैंक की यही शाखा उसका विदेशी विनिमय बिल भी बना देगी और इस व्यापारी को किसी भी बन्दरगाह तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी । इन्हीं आन्तरिक शाखाओं द्वारा ये विदेशी विनिमय बैंक किसी देश के आन्तरिक स्थानों में व्यापार की सुविधाएँ देते हैं । जैसे यदि किसी बैंक की शाखाएँ कानपुर और कलकत्ता में हैं तो कानपुर और कलकत्ते के बीच व्यापारिक लेन-देन इन शाखाओं द्वारा हो जाता है ।

इस प्रकार विदेशी विनिमय बैंक अपनी शाखाओं की सहायता से किसी देश के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार करते हैं, अतः कुछ बड़े व्यापारी इन सुविधाओं के कारण अपना व्यापारिक लेन-देन, आन्तरिक और बाह्य दोनों तरह का विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा ही करते हैं । विदेशी विनिमय बैंकों की पूँजी भी अन्य बैंकों से बहुत अधिक होती है जिससे वे लम्बे समय के भुगतान की सुविधाएँ भी दे देते हैं । इस प्रकार भारत में बैंकिंग कार्य का पर्याप्त लाभ इन विदेशी बैंकों को प्राप्त हो जाता है । भारत सरकार ने विदेशी विनिमय बैंकों की इस कार्य-प्रणाली की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है परन्तु विदेशी बैंकों की इस गतिविधि को रोकना बहुत आवश्यक है, नहीं तो भारतीय बैंक सुदृढ़ नहीं हो पायेंगे ।

भारत में बैंकिंग प्रणाली स्थापित होने के पूर्व से ही विदेशी विनिमय बैंक यहाँ कार्य करते थे। १८९३ ई० में जब भारतीय रुपये का स्वतन्त्र टकन बन्द हो गया तब इन बैंकों ने ही विदेशी विनिमय के समय, जब विनिमय-दर ऊँची थी और भारतीय बैंकों के पास साधन की कमी थी, आयात-निर्यात की बैंकिंग सुविधा प्रदान की थी। भारत का विदेशी व्यापार भी इन्हीं विदेशी बैंकों द्वारा ही बढ़ा है। इस प्रकार प्रारम्भिक अवस्था में भारत के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी विनिमय बैंक सहायक हुए हैं। परन्तु देश में व्यापार और उद्योग की उन्नति के बाद यहाँ कई अच्छे बैंक कार्य करने लगे जिनकी शाखाएँ देश भर में फैली हुई हैं। इन बैंकों को यदि उपयुक्त संरक्षण और सुविधाएँ दी जायँ तो विदेशी विनिमय बैंकों का बहुत कुछ कार्य ये देश में कर सकते हैं।

केन्द्रीय बैंकिंग जॉच कमेटी ने सर्व-सम्मति से यह सुझाव दिया था कि भारत में विदेशी बैंकों के कार्यों की खुली छूट भारतीय आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। इन बैंकों को देश में कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करना आवश्यक कर दिया जाय। इस अनुज्ञापत्र की शर्तें देश की औद्योगिक और व्यापारिक नीति के अनुसार समय-समय पर बदलनी चाहिए। इस पत्र द्वारा रिजर्व बैंक का इन विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण रहेगा तथा जनता द्वारा इन बैंकों में जमा की गयी राशि की सुरक्षा होगी। परन्तु तत्कालीन भारत सरकार ने यह सुझाव नहीं माना जिसका भारतीय बैंकों के विस्तार पर प्रतिकूल असर पड़ा। स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने जब इस ओर ध्यान दिया तो कोई भारतीय बैंक बिना विशेष सुविधा पाये विदेशी विनिमय बैंक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि विदेशी विनिमय बैंक के कार्यों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लम्बे समय तक के लिए धन की व्यवस्था करनी होती है।

भारत में विदेशी विनिमय बैंकों के द्वारा लगभग सभी निर्यात व्यापार होता है। ये बैंक अपने देश के व्यापारियों को भारतीय व्यापारियों के मुकाबले में अधिक सुविधाएँ देते हैं जिससे भारतीय व्यापार अपेक्षाकृत कम लाभ का हो पाता है। कई विदेशी विनिमय बैंक अपने देश के व्यापारियों

को भारत में अपना माल भेजते समय कम ब्याज पर अधिक समय के भुगतान की सुविधा देते हैं, परन्तु ये ही बैंक भारतीय व्यापारियों को यही सुविधा नहीं देते। विदेशी विनिमय बैंक अपने देश के व्यापारियों को समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार सम्बन्धी सूचनाएँ देते रहते हैं परन्तु ये सुविधाएँ भारतीय व्यापारियों को प्राप्त नहीं होती। विदेशी विनिमय बैंक माल के इन्डोरेन्स तथा जहाजों द्वारा उसके भेजने की व्यवस्था अपने ही देश की कम्पनियों को देते हैं। ये बैंक आयात-निर्यात व्यापार भारतीय व्यापारियों के मुकाबले में विदेशी व्यापारियों को देने में बहुत सहायता करते हैं। आयात-निर्यात विनिमय-बिल का चिट्ठा स्टर्लिंग अथवा डालर में चलने के कारण ये बैंक उसकी कटौती व भुगतान विदेशी मुद्रा-बाजार में ही करते हैं, जिससे भारतीय मुद्रा-बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय विकास का प्रोत्साहन नहीं मिलता। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में विदेशी हुण्डी बहुत समय से प्रचलित रही है। यह हुण्डी बिना किसी शर्त के एक लिखित आज्ञा-पत्र होता है जो एक व्यक्ति दूसरे को किसी निश्चित समय के बाद उसकी आज्ञानुसार निश्चित राशि चुका देने की आज्ञा देता है। इसका ढग इस प्रकार होता है—

साठ (६०) दिन के बाद विलियम जेम्स अथवा उनकी आज्ञानुसार दूसरे व्यक्ति को पचास डालर दे दे। मूल्य प्राप्त किया जा चुका है।

५० डालर

२ ए० सी० किंग

सेवा में, डी० सी० बेकर,

लन्दन

इस उदाहरण में ए० सी० किंग इस हुण्डी का लिखने वाला है। वह डी० सी० बेकर के नाम लिखता है कि विलियम जेम्स, जो धन प्राप्त करने का अधिकारी है, साठ दिन बाद पचास डालर उसको या उसके द्वारा बतलाये गये किसी अन्य व्यक्ति को दे दिये जायँ। विदेशी हुण्डियों के भुगतान में समय का बड़ा महत्व होता है। ऊपर लिखित हुण्डी में भुगतान करने

वाले को इस कार्य के लिए साठ दिन का समय दिया गया है ताकि वह इस अवधि में इस धन की व्यवस्था कर ले। यदि प्राप्तकर्ता को धन की शीघ्र आवश्यकता होती है तो वह यह हुण्डी किसी बैंक या दलाल को कटौती पर बेचकर जल्दी रुपया प्राप्त कर सकता है। विदेशी विनिमय बैंक अपने धन का अधिक भाग हुण्डियों को खरीदने और बेचने में लगाते हैं। ये हुण्डियाँ तीन प्रकार की होती हैं—

- (१) स्वीकृति पत्र,
- (२) भुगतान पत्र,
- (३) माल प्राप्त करने के पत्र।

ये हुण्डियाँ प्रायः उन व्यापारियों के नाम लिखी जाती हैं जो आयात-निर्यात काय करते हैं। माल प्राप्त करने के पत्र आजकल बहुत कम प्रयोग में आते हैं। इनके अनुसार माल प्राप्त करने पर तथा उस की जाँच के बाद भुगतान किया जाता है। सामान्यतः हुण्डियों का भुगतान मूल्य की राशि में नहीं होता। जब किसी देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल मँगाता है तो वह उसका भुगतान सामान्यतः उस देश को अपने देश से भेजे हुए माल के मूल्य द्वारा पारस्परिक विनिमय से करता है और वर्ष के अन्त में जो राशि बचती है वह उस देश के व्यापारी के नाम कर दी जाती है।

एक देश का दूसरे देश की मुद्रा में भुगतान विनिमय दर द्वारा निश्चित होता है। प्राचीन काल में जब शुद्ध सोने या चाँदी के सिक्के चलते थे तब एक देश की मुद्रा द्वारा दूसरे देश की मुद्रा का विनिमय दर आसानी से निश्चित हो जाती थी। परन्तु आजकल ये भुगतान इस प्रकार होते हैं—

- (१) सोना बाहर भेजकर,
- (२) विदेशी मुद्रा में बैंक-पत्र द्वारा,
- (३) विदेशों में चुकायी जाने वाली सूद की राशि द्वारा और निश्चित विनिमय दर द्वारा।

सामान्यतः किन्हीं दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर इस बात पर आधारित होती है कि उनकी मुद्राओं द्वारा कितना सोना प्राप्त किया जा

सकता है। यदि भारत का रुपया अमेरिका के डालर के अनुपात में उसके १।५ भाग का सोना प्राप्त कर सकता है तो भारत के पाँच रुपये अमेरिका के एक डालर के बराबर माने जायेंगे। विनिमय की यह दर किसी देश की मुद्रा की माँग पर भी निर्भर होती है। यदि किसी समय सभी देशों में अमेरिका के डालर की माँग बढ़ जाय तो यह विनिमय दर भी उसी अनुपात में बदल जाती है।

मुद्रा की क्रय-शक्ति कई बातों पर निर्भर होती है। कई वस्तुओं की क्रय-शक्ति के सूचक अंक का औसत ही मुद्रा की क्रय-शक्ति मानी जाती है। मुद्रा की यह क्रय-शक्ति लगभग प्रति वर्ष आँकी जाती है और इस क्रय-शक्ति के घटने-बढ़ने का सतुलन विदेशी मुद्रा के अनुपात में किया जाता है। इस प्रकार क्रय-शक्ति का सिद्धान्त एक काल्पनिक व्यवस्था है जो लम्बी अवधि में निर्धारित होती है और इससे हम यह मान लेते हैं कि अन्य वस्तुएँ अपरिवर्तित रहे। परन्तु सामान्यतः विनिमय की दर और मुद्रा की क्रय-शक्ति व्यापार की गति-विधि से भी बदल जाती है। बहुधा यह देखा जाता है कि दो देशों के व्यापारी गैरसरकारी विनिमय दर के द्वारा अपना लेन-देन करते हैं।

विनिमय दर पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रभाव पड़ते हैं। अल्पकालीन प्रभाव हुण्डियो की माँग और पूर्ति पर निर्भर होते हैं। आयात की अपेक्षा अधिक निर्यात करने वाले की मुद्रा की क्रय-शक्ति ऊँची मानी जाती है। अतः विदेशी हुण्डियो के बाजार का किसी देश की मुद्रा के विनिमय पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है। देश की घटती या बढ़ती आर्थिक परिस्थितियाँ भी उस देश की मुद्रा के विनिमय पर प्रभाव डालती हैं। यदि अ देश ब देश को बड़ी मात्रा में पूँजी का निर्यात करे तो ब देश की मुद्रा की दर ऊँची हो जायगी। इस प्रकार जब कोई देश विनिमय योग्य विदेशी प्रतिभूतियों को मोल ले अथवा अन्य देश वाले हमारी प्रतिभूतियाँ मोल ले तो विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है।

किसी देश की राजनीतिक और औद्योगिक अवस्थाओं का भी प्रभाव मुद्रा के विनिमय पर पड़ता है। देश की आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय आय-

व्यय से मालूम हो जाती है। यदि किसी देश का वार्षिक बजट लाभप्रद होता है तो उस देश की मुद्रा की धाक विश्व भर में मानी जाती है। विनिमय क्षेत्र में सट्टा करने वाले व्यक्ति ऐसे देश की चलार्थ मुद्रा (सरकुलेटिंग मनी) प्रायः ऊँचे मूल्यों में खरीदते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में ऐसी मुद्रा का सभी देश सम्मान करते हैं। इसके विपरीत यदि किसी देश में चलार्थ मुद्रा उसके व्यापार के अनुपात में अधिक बढ़ जाती है तो उस देश की मुद्रा की क्रय-शक्ति घट जाती है और मूल्य ऊँचे हो जाते हैं। इसका निर्यात-व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दर गिर जाती है तथा निर्यात कम हो जाता है और आयात बढ़ जाता है ऐसी परिस्थिति में देश का सोना बाहर जाने लगता है और साख कम हो जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान निम्नलिखित लेन-देन से होता है।

(१) वस्तुओं के आयात-निर्यात से,—वस्तुओं का यह आयात-निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा होता है। आयात-निर्यात की मात्रा देश की आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर होती है।

(२) सेवाओं के मूल्य से—ये सेवाएँ एक देश दूसरे देश के लिए कई ढंगों से करता है, जैसे बैंकिंग सेवाएँ जहाजों द्वारा माल ले जाने की सेवाएँ, भेजे गये माल के इन्डोरोन्स की सेवाएँ तथा विदेश में व्यक्तियों द्वारा काम करने की सेवाएँ। इन सभी प्रकार की सेवाओं का मूल्य भी अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय द्वारा होता है। इनके अतिरिक्त पर्यटन और शिक्षा प्राप्त करने का व्यय भी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का भाग है। राष्ट्र द्वारा गृहीत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विदेशी ऋण तथा उसका व्याज और व्यापार में लगी हुई विदेशी पूँजी तथा उसका व्याज, ये सभी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान माने जाते हैं।

देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक बनाये रखने के लिए विदेशी विनिमय का सतुलन बहुत आवश्यक होता है। विदेशी विनिमय की दर आर्थिक परिस्थिति पर ही निर्भर होती है। अतः देश का केन्द्रीय बैंक अपनी साख-मुद्रा-नीति द्वारा आर्थिक परिस्थितियों को स्थिर बनाये रखता

है। व्याज की दर द्वारा भी पूँजी का नियंत्रण होता है। कुछ देश अपनी मुद्रा का मूल्य किसी ऐसे देश की मुद्रा के अनुपात में स्थिर रखते हैं, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में आर्थिक महत्व अधिक हो। जैसे भारतवर्ष अपनी मुद्रा की स्टर्लिंग में विनिमय-दर सन् १९३१ से अब तक १ शिलिंग ६ पेन्स किये हुए है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण और स्थिरता देश का निर्यात व्यापार बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। कभी-कभी निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए मुद्रा की विनिमय-दर कम कर दी जाती है। विशेष रूप से उस देश की मुद्रा के अनुपात में यह विनिमय-दर कम होती है। जैसे १९४९ में अमेरिका से निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने डालर के अनुपात में अपनी मुद्रा की विनिमय दर घटा दी थी।

कभी-कभी विनिमय पर नियंत्रण देश से पूँजी बाहर जाने को रोकने के लिए भी किया जाता है। देशवासियों द्वारा दूसरे देश में सम्पत्ति अथवा सिक्यूरिटियाँ तथा दूसरे देशों के बैंक में राशि जमा करने पर नियंत्रण रखा जाता है और बहुत कम परिमाण में सरकार इसकी अनुमति देती है। सन् १९२९ की आर्थिक मन्दी के बाद जर्मनी ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और निर्यात बढ़ाने के लिए अपने देश की पूँजी बाहर जाने से रोक दी थी और अपने देश में लगी विदेशी पूँजी को स्वायत्त करने के लिए विदेशी पावने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और आयात-निर्यात के लिए आदान-प्रदान की प्रथा का प्रयोग किया था। ऐसे नियंत्रण द्वारा देश का सोना बाहर कम जा पाता है और आर्थिक सकट के समय किसी देश की अवस्था का पूरा-पूरा ज्ञान अन्य देश को नहीं हो पाता।

देश का सोना बाहर जाने से रोकने के लिए वहाँ विनिमय-नियंत्रण के कई ढंग अपनाये गये। इनमें सबसे अधिक नियंत्रण आयात पर किया गया। हर उपाय से आयात कम किया जाने लगा और निर्यात बढ़ाने के ढंग अपनाये गये। वस्तुओं को निर्यात करने की सुविधाएँ सरकारी सहृदयता और आर्थिक सहायता द्वारा दी गयीं। कभी-कभी करों की छूट भी दे दी गयी। इसके विपरीत आयात को निश्चित करने के लिए वस्तुओं की कोटा प्रणाली अमल में लगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने केन्द्रीय बैंक द्वारा

विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय अपने हाथ में ले लिया। हुण्डियो का खुले बाजार में व्यवसाय केन्द्रीय बैंक की सरक्षकता में होने लगा। इसके अतिरिक्त आयात-निर्यात के वस्तु-विनिमय के द्विदेशीय समझौते होने लगे तथा भुगतान में विनिमय समीकरण फण्ड की स्थापना की गयी। द्विदेशीय व्यापारी समझौते भारत के लिए बहुत सफल सिद्ध हुए। द्वितीय महायुद्ध के पहले भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए इस प्रकार के कई समझौते किये।

भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् भारतीय बैंको ने विदेशों में अपनी शाखाएँ खोलना प्रारम्भ किया। परन्तु इनकी पूँजी बहुत थोड़ी होने के कारण ये बड़ी मात्रा में व्यापार को सहायता न दे सके। भारतीय बैंको की विदेशों में लगभग १०० शाखाएँ हैं जिनकी कुल पूँजी ६५ करोड़ रुपये है। किसी देश के दूसरे देश से व्यापार को आर्थिक सहायता देने में विनिमय बैंको का सहयोग तथा इन्श्योरेन्स कम्पनियों और जहाजों द्वारा माल बाहर ले जाने वाली कम्पनियों का भी सहयोग आवश्यक होता है। अतः विदेशी विनिमय बैंक इन कम्पनियों को भी आर्थिक सहायता देते हैं। परन्तु भारतीय बैंको का सहयोग अभी इन कम्पनियों से बहुत कम है। विदेशी विनिमय बैंको के भारत में बैंकिंग कार्य को कम करने के लिए समाशोधन-गृह की व्यवस्था की गयी है। सन् १९४९ के भारतीय बैंकिंग विधान के अनुसार विदेशी बैंको के देश के भीतर काम करने पर कई नियंत्रण लगा दिये गये हैं तथा इनके लिए रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग संस्थाएँ

विदेशी व्यापार आर्थिक उन्नति का एक मुख्य अंग माना जाता है। प्राचीन काल से ही समृद्ध देश अपने यहाँ की वस्तुएँ विदेशों में बेचकर धनोपार्जन करते रहे हैं। उस समय विदेशी व्यापार सभ्यता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था पर आधुनिक ढंग के उत्पादन के साधन न होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा बहुत सीमित रहती थी और देश की आर्थिक अवस्था पर उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त विदेशी व्यापार का महत्व बहुत बढ़ गया और वह आर्थिक उन्नति का बहुत बड़ा साधन माना जाने लगा। बड़ी मात्रा में कच्चा माल तथा तैयार की हुई वस्तुएँ एक देश से दूसरे देश जाने लगी, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्याएँ उत्पन्न होने लगी।

प्रथम और द्वितीय महायुद्धों के समय भारत में उद्योगीकरण बहुत तेजी से हुआ। द्वितीय महायुद्ध काल में भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत बढ़ गया और कच्चा माल तथा तैयार किया हुआ सामान भारत से विभिन्न देशों को जाने लगा। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर यूरोप के देशों में पुनर्निर्माण की समस्या आयी, क्योंकि इस युद्ध में लगभग सभी देशों का आर्थिक ढाँचा जर्जर हो गया था और बिना तीव्र उद्योगीकरण के आर्थिक विषमता मिटना कठिन था। अतः बड़ी मात्रा में उत्पादन तथा भुगतान के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता बढ़ गयी। उद्योगों के विकास के लिए कुछ देशों को अन्य देशों पर कच्चे माल या बने हुए सामान के लिए निर्भर होना पड़ा। अतः बड़ी मात्रा में एक देश से दूसरे देश को माल भेजने की व्यवस्था आवश्यक हो गयी।

स्वतन्त्रता के बाद भारतवर्ष ने आर्थिक नियोजन की नीति अपनायी और उद्योगीकरण के लिए कई अन्य देशों से मशीनें तथा अन्य सामान

बड़ी मात्रा में मँगाने की व्यवस्था की, जिसके लिए भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ा। युद्ध-काल में भारत द्वारा कई देशों को बना हुआ सामान भेजा गया था जिससे इंग्लैन्ड, कनाडा तथा मध्य पूर्व के देशों पर भारत का ऋण हो गया। इन देशों से यह ऋण किस प्रकार वापस लिया जाय, यह भी समस्या बन गयी थी। इन सभी प्रकार के भुगतानों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और मौद्रिक संस्थाएँ बड़ी सहायक हुईं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना १९४४ में ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस में की गयी थी। भिन्न-भिन्न देशों में उनकी प्रचलित मुद्राओं का समन्वय करना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत आवश्यक था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् देशों के पुनरुत्थान तथा उनका आर्थिक सकट कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत हितकर माना गया। कई देशों के लिए मुद्रा को स्वर्ण-प्रमाण पर लाना असम्भव हो गया। अतः अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए उन्हें बड़ी कठिनाई होने लगी। इन परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बहुत कठिन हो गया। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का संगठन किया गया। इस कोष के निम्न-लिखित कार्य हैं—

(१) जो देश इस कोष के सदस्य होंगे उनमें उनकी मुद्राओं की पारस्परिक विनिमय दर स्थापित करना।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायता देना और किसी सदस्य देश द्वारा लगाये गये विनिमय नियंत्रणों को दूर करने का प्रयत्न करना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो।

(३) सदस्य देशों की भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए विदेशी मुद्राओं को उन देशों के लिए उपलब्ध करना।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए सदस्य देशों को उत्पादन के साधनों के लिए कोष से सहायता देना।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए मौद्रिक एकता स्थापित करना जिससे वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने में कठिनाई न हो।

यह कोष केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ही स्थापित किया गया है। कोष की पूँजी का उपयोग कोई भी सदस्य देश राजनीतिक अथवा देश की आन्तरिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता। युद्ध-कालीन ऋणों के भुगतान और आर्थिक पुनर्निर्माण में यह कोष विशेष रूप से सहायक रहा है। इस कोष की स्थापना में जिन ४४ देशों ने भाग लिया था वे इसके मौलिक सदस्य माने गये और १ मार्च १९४६ से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस कोष को बड़ी सफलता मिली और १९५८ तक इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या ६८ हो गयी।

इस कोष में प्रत्येक सदस्य देश अपनी आर्थिक योग्यता के अनुसार कुछ निर्धारित राशि जमा करता है जिसे उस देश का कोटा कहते हैं। इस कोष की मुद्रा डालर के रूप में आकी जाती है। भारत का कोटा ४० करोड़ डालर, अमेरिका का कोटा २ अरब ७५ करोड़ डालर, इंग्लैंड का कोटा १ अरब ३० करोड़ डालर, फ्रान्स का कोटा ४५ करोड़ डालर है। अन्य सभी देशों के कोटे कम ही होते गये हैं। प्रत्येक सदस्य देश अपने कोटे का १० प्रतिशत स्वर्ण के रूप में कोष में जमा कर देता है और शेष भाग अपनी मुद्रा की प्रतिभूतियों के रूप में जमा करता है। सामान्यतः प्रत्येक सदस्य देश किसी एक वर्ष में अपने निर्धारित कोटे की राशि का ही व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा कर सकता है।

कुछ वर्षों पश्चात् यह देखा गया कि कई सदस्य देशों को अपना व्यापार निर्धारित कोटे तक सीमित रखना कठिन हो रहा है इसलिए उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से इसमें वृद्धि करने की अनुमति माँगी। अतः १९५८ में कोष के सचालको ने निश्चय किया कि सभी सदस्य देशों के कोटे में ५० प्रतिशत वृद्धि कर दी जाय ताकि वे अपने व्यापार का अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार कर सकें। कोष की कुल जमा पूँजी १ अरब ४४ करोड़ १० लाख डालर के मूल्य का सोना है। सभी सदस्य देशों की मुद्राओं के सम मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं जो अमेरिका के डालर के अनुपात में हैं। जब कोई सदस्य देश इस कोष में से विदेशी मुद्रा खरीदता या बेचता है तो

उसका मूल्य इन्ही सम मूल्यों के हिसाब से चकाया जाता है। भुगतान की कठिनाइयों को कम करने के लिए इस मुद्रा-कोष ने तीन ढंग अपनाये हैं—

(१) सभी सदस्य देशों के मनोनीत सचालको का समय-समय पर सम्मेलन करना, जिसमें विनिमय सम्बन्धी सभी कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया जाय।

(२) सदस्य देशों की वित्तीय अथवा मौद्रिक जाँच पड़ताल विशेषज्ञों द्वारा कराना।

(३) सदस्य देशों को अल्पकालीन भुगतान की विशेष सुविधा प्रदान करना। इसके लिए विदेशी मुद्राओं को प्राप्त करने की सुविधा यह कोष सदस्य देशों को उपलब्ध करता है।

यदि किसी सदस्य देश की मुद्रा की बहुत कमी हो जाय अथवा मुद्रा की माँग बहुत बढ़ जाय तो उस मुद्रा को यह कोष दुर्लभ मुद्रा घोषित कर देता है और सभी सदस्य देशों को उसके कारणसहित सूचना दे देता है। ऐसी परिस्थिति में उस देश की मुद्रा को प्राप्त करने के लिए कई नियन्त्रण लगा दिये जाते हैं, परन्तु आवश्यक कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष सोने के बदले में दुर्लभ मुद्रा खरीद लेता है अथवा उधार ले लेता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का प्रबन्ध गवर्नरों के बोर्ड द्वारा होता है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधि गवर्नर होता है। यह बोर्ड एक सचालक समिति तथा एक प्रबन्ध-सचालक नियुक्त करता है। सचालक समिति के १२ सदस्य होते हैं जिनमें ५ स्थान उन देशों के प्रतिनिधियों के लिए निश्चित होते हैं जिनका कोटा सबसे अधिक होता है। कोष का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है।

लगभग १२ वर्षों के कार्य-कलाप में इस कोष ने २ मिलियन डालर के मूल्य की विदेशी मुद्राओं का आदान-प्रदान किया था। प्रारम्भ में लगभग ५ वर्षों तक कोष का कार्य बहुत कम रहा क्योंकि युद्ध के तुरन्त पश्चात् भुगतान में कई विषमताएँ आ गयी थीं। कोरिया युद्ध तथा स्वेज

नहर के 'सकट' से अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान तेजी से बढ़ा और कोष के द्वारा मुद्राओं का क्रय-विक्रय भी बढ़ता गया।

इस कोष में रूस के सम्मिलित न होने से भारत का पाँचवाँ स्थान हो गया। इसका कोटा चार अन्य देशों को छोड़कर सबसे अधिक है। भुगतान के हिसाब से भारत इस कोष में तीसरा बड़ा ग्राहक है। विदेशी मुद्राओं के भुगतान के लिए भारत ने इस कोष से सबसे पहले १९४८ में ६ करोड़ ८३ लाख डालर की और उसके एक वर्ष बाद ३ करोड़ १७ लाख डालर का सहायता ली थी। धीरे-धीरे भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने पर उस ने यह सभी राशि चुकता कर दी और इस कोष में भारतीय मुद्रा का प्रभाव बढ़ने लगा। इस कोष के मौलिक सदस्य होने के नाते भी भारत का हाथ नीति निर्धारित करने में तथा उसकी कार्य प्रणाली में काफी रहा है।

यह मुद्रा-कोष एक प्रकार का चक्रीय कोष भी माना जाता है जिसमें सदस्य देश अपनी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा लेते हैं और बाद में विदेशी मुद्रा के बदले में पुनः अपनी मुद्रा ले लेते हैं। इस प्रकार विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय सोने के अनुपात में होता तो अवश्य है परन्तु सोने के आदान-प्रदान की आवश्यकता नहीं होती और इस अन्तर्राष्ट्रीय कोष में सदस्य देशों की मुद्राओं का उनके खातों द्वारा समाशोधन कर लिया जाता है। इस कोष ने आर्थिक उन्नति तथा पुनर्निर्माण में बड़ी सहायता की है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक

द्वितीय महायुद्ध की हानियों के कारण विश्व के अधिकांश देशों ने यह विचार किया कि युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति सभी देशों के सहयोग से पूरी की जा सकती है। अपने पुनर्निर्माण तथा विकास की सभी देशों ने आवश्यकता समझी तथा उन्होंने यह भी अनुभव किया कि कोई व्यक्तिगत संस्था उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती है। अतः १९४४ में ब्रेटन वुड्स में सभी देशों की एक बैठक हुई और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौते के तीन मुख्य उद्देश्य थे -- (पहला)

दीर्घ-कालीन पूँजी को एक देश से दूसरे देश को गतिशील बनाना । (दूसरा) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नति करना, (तीसरा) भुगतान के सन्तुलन की समानता रखना । इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति एवं अन्य देशों द्वारा दिये गये ऋण की जमानत करना । संक्षेप में बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक सहायता करना है । कभी-कभी यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत ऋणों की गारंटी लेकर उन्हें प्रोत्साहन देता है और यदि ऐसे ऋण उपलब्ध न हों तो स्वयं उत्पादन कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है । इससे सदस्य देशों की उत्पादक शक्ति, जीवन-स्तर तथा श्रमिकों की कार्य-दशा में उन्नति हो सकती है । बैंक का एक उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों को उचित सुविधाएँ प्रदान करके प्रोत्साहन देना भी है जिससे इनका व्यापारिक स्थिति पर ठीक प्रभाव पड़े । यह बैंक केवल उत्पादन कार्यों के लिए ऋण दे सकता है । बैंक से ऋण लेकर सदस्य किसी भी देश में वस्तु क्रय करने के लिए स्वतन्त्र होता है । उस पर ऐसा कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता कि वह किसी खास देश में वन व्यय न करे ।

बैंक की पूँजी

बैंक की अधिकृत पूँजी १,००० करोड़ डालर है जिसको एक-एक लाख डालर के हिस्सों में बाँटा गया है । प्रत्येक देश को अपने चन्दे का २० प्रतिशत सदस्यता ग्रहण करते समय ही देना पड़ता है और शेष २० प्रतिशत बैंक आवश्यकता के समय अपने सदस्य से लेता है । प्रत्येक सदस्य को अपने अभ्यश का २ प्रतिशत सोने में और १८ प्रतिशत अपनी मुद्रा में देना होता है । सदस्यों के इस अभ्यश में तीन चौथाई बहुमत से वृद्धि की जा सकती है और इस बड़ी हुई राशि को सदस्य या तो सोने में, या डालर में, या बैंक द्वारा बतायी गयी किसी मुद्रा में चुका सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने प्रत्येक देश से उसके भाग की केवल २० प्रतिशत रकम ही प्राप्त की है । यही अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की कार्यशील पूँजी है । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ऋण की गारंटी देने अथवा सीधा ऋण देने के अतिरिक्त

आवश्यकता पड़ने पर किसी सदस्य देश के बाजार में अपनी प्रतिभूति बेचकर धन प्राप्त कर सकता है तथा उस धन को ऋणस्वरूप अन्य देश को दे सकता है।

इसको भारतवर्ष ने ४० करोड़ डालर पूँजी क्रय करने का वचन दिया है जिसमें से कुछ डालर में, कुछ भारतीय रुपये में तथा कुछ ब्याज रहित अविनिमय साध्य मॉग-पत्रों में लगायी गयी है।

बैंक का संचालन एवं प्रबन्ध

इस बैंक का संचालन एक गवर्नर-मण्डल, कार्यकारिणी समिति और सभापति द्वारा होता है। बैंक का प्रमुख संचालक गवर्नर-मण्डल होता है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश अपना एक-एक प्रतिनिधि भेजता है। बैंक की कार्यकारिणी समिति में १२ सदस्य होते हैं, जिनमें से ७ सदस्य मुद्रा-कोष की तरह प्रतिनिधि-निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। प्रतिनिधि-निर्वाचन-प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य देश २५० मत तथा एक लाख डालर चन्दे के पीछे एक और मत प्राप्त कर सकता है। सभापति की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति द्वारा होती है। कार्यकारिणी समिति की अवधि दो वर्ष होती है। इसके अतिरिक्त गवर्नर-मण्डल समय-समय पर बैंक को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति करता है, जिसमें कम-से-कम ७ सदस्य हो सकते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य सामान्य नीति का निर्माण करते समय बैंक को सलाह देना होता है। ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्रों की जाँच-पड़ताल एक विशेष समिति द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति कार्यकारिणी समिति करती है।

बैंक की कार्यविधि

बैंक सदस्य देशों को उनके विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बैंक व्यक्तिगत विनियोग-कर्त्ताओं से भी ऋण दिलाता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। बैंक अपना व्यवसाय केवल सदस्य देशों की सरकारों द्वारा करता है। बैंक के ऋणों की मात्रा सदस्यों के चन्दे पर निर्भर नहीं रहती। चन्दे का

महत्व केवल शासन से सम्बन्ध रखता है। बैंक का कभी यह ध्येय नहीं रहता है कि वह ऋण के विनियोग के लिए देशों से प्रतिस्पर्धा करे बल्कि तटस्थ रूप से वह सब देशों की मदद ही करता है और स्वयं तभी ऋण देता है जब व्यक्तिगत ऋण नहीं मिलते हैं। बैंक अपने ऋणों पर ब्याज प्राप्त करने के अतिरिक्त देशों के व्यक्तिगत ऋणों की जिम्मेदारी लेने पर भी कमीशन लेता है। यह कमीशन एक अलग कोष में जमा होता है तथा किसी सदस्य देश द्वारा ऋण का भुगतान न करने पर इसका उपयोग किया जाता है। बैंक ऋण प्रदान करते समय या व्यक्तिगत ऋणों की जिम्मेदारी लेते समय पूर्ण रूप से यह निश्चय कर लेता है कि ऋणी देश की माँग उचित है या नहीं और ऋणदाता देश की शर्तें न्यायपूर्ण हैं या नहीं। बैंक निम्न शर्तों पर ऋण प्रदान करता है।

(१) बैंक तभी ऋण देता है जब कि सलाहकार समिति ऋण माँगने वाले देश की आर्थिक दशा व उसके उद्देश्य की पूर्ण रूप से जाँच कर लेती है।

(२) ऋण माँगने वाली सरकार जब तक जमानत नहीं देती, यह बैंक ऋण नहीं दे सकता है।

(३) यदि बैंक ऋण-दाता देश के ब्याज की दर और शर्तों से सन्तुष्ट है और ऋण वापस करने के नियम उचित हैं तभी वह ऋण प्रदान करता है।

(४) ऋण देते समय बैंक यह भी ध्यान में रखता है कि सदस्य देश में उस ऋण को चुकाने की क्षमता है या नहीं।

(५) ऋण लेने वाला देश जिस योजना के लिए ऋण लेना चाहता है यह बैंक उस योजना की विशेषज्ञों से जाँच कराता है तथा उसकी उपयोगिता के बारे में सन्तुष्ट होने पर ही ऋण देता है।

(६) बैंक बराबर यह देखा करता है कि जिस उद्देश्य के लिए ऋण दिया गया है वह पूरा हो रहा है कि नहीं। आवश्यकता पड़ने पर प्राविधिक सहायता व परामर्श भी बैंक देता है।

(७) किसी भी समय बैंक अपनी कुल पूंजी व संचित कोष से अधिक ऋण नहीं दे सकता है।

(८) ऋणी देश दाता देश द्वारा वस्तुओं के रूप में ऋण चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

(९) दिये गये ऋणों की जोखिम सदस्य देशों को उनके हिस्सों के अनुपात में सहन करनी होगी।

(१०) बैंक केवल विकास तथा पुनर्निर्माण के लिए ऋण देता है परन्तु असाधारण परिस्थितियों में यह शर्त कुछ ढीली की जा सकती है।

(११) जिम्मेदारी लेते समय बैंक ऋणी, दाता और अन्य देशों के हितों का भी ध्यान रखता है।

बैंक की आलोचना

कुछ देशों के अनुसार बैंक ऋणी देशों का पक्ष करता है और इसलिए उसके सदस्यों में ऋण-दाता देशों की अपेक्षा ऋणी देश अधिक है तथा यह आशंका की जाती है कि इस पर ऋणी देशों का नियंत्रण हो सकता है। परन्तु यह आलोचना न्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि ऋण प्रदान करने की योजना सदस्यों की व्यक्तिगत एवं संयुक्त जिम्मेदारी पर आधारित है। यह सच है कि ऋण-दाता देश कम है, फिर भी उनके ऋणों की जोखिम सभी सदस्यों पर रहती है।

कुछ लोगों का कहना है कि बैंक की अपेक्षा ऋण प्रदान करने का कार्य और पिछड़े हुए देशों में पूंजी के विनियोग करने का कार्य व्यक्तिगत देशों द्वारा अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। पर यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि बैंक व्यक्तिगत देशों के बीच किसी प्रकार से भी कठिनाई उत्पन्न नहीं करता और न प्रतियोगिता ही करता है। जैसे ही इस बैंक की १९४४ में स्थापना हुई, डालर ऋण के लिए देशों से आवेदन-पत्र आये तथा सन् १९४७ में जाकर कहीं बैंक ने पहला ऋण दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को ऋण देने के लिए अमेरिका के द्रव्य-बाजार में ऋण लेना होगा।

ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन मे लोगो का यह विचार था कि प्रत्येक देश जो डालर ऋण लेना चाहेगा, अपने बाड अमेरिका मे बेचेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उनकी अदायगी की गारंटी देगा। लोगो का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की गारंटी अमेरिकन पूँजीपतियो को उन देशो के बाडो मे अपना धन लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। परन्तु बैंक ने द्रव्य-बाजार की अव्यवस्थित दशा के कारण अन्य देशो के बाडो की गारंटी न देते हुए स्वयं अपने बाड सयुक्त-राज्य अमेरिका के द्रव्य-बाजार मे बेचकर धन प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया।

बैंक की १९५० मे समाप्त होने वाली वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्च १९५० मे इस ने रिज़र्व बैंको और बैंक-फार-इन्टरनेशनल सेटिलमेन्ट को भी अपने बाड बेचे। लन्दन के बाजार मे भी इस बैंक ने ब्रिटिश प्रतिभूतियाँ बेची।

बैंक ने ३१ मार्च १९५८ तक कुल मिलाकर २ अरब १२ करोड ७० लाख डालर का ऋण देना स्वीकार किया जिसमे से २ अरब से अधिक वास्तव मे दे दिया गया था। इसमे से ५२ करोड ६० लाख डालर के ऋण का भुगतान वापस मिल गया है तथा कुछ व्यक्तिगत विनियोग-दाताओ ने बैंक से ऋण कर लिया है। कुल ऋण मे से १ अरब ८१ करोड ३५ लाख डालर का ऋण डालर मे दिया गया है। अधिकांश ऋण फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, बेलजियम, फिनलैंड, टर्की, युगोस्लाविया, चिली, मैक्सिको, ब्राजिल, कोलम्बिया, इराक, पाकिस्तान, भारत को दिये गये है।

भारत और विश्व बैंक

भारत ने विश्व बैंक से बहुत अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त की है। आर्थिक विकास के लिए भारत को पहला ऋण ४ प्रतिशत ब्याज की दर पर ३४ मिलियन डालर का प्राप्त हुआ, जिसकी अवधि १९५०-५४ थी। यह ऋण रेलो के इंजन खरीदने के लिए लिया गया था। दूसरा ऋण १० मिलियन डालर का ट्रेक्टर खरीदने के लिए सन् १९५२-५६ तक की अवधि के लिए ३ प्रतिशत ब्याज की दर पर लिया गया है। तीसरा

ऋण १८५ मिलियन डालर का ४ प्रतिशत ब्याज की दर पर बोकारो में विद्युत् सयंत्र के लिए लिया गया है। इसके अतिरिक्त १९५४-५५ में भारत को दो ऋण और प्राप्त हुए। पहला ऋण टाटा कम्पनी द्वारा ट्राम्बे विद्युत् योजना के लिए १६२ लाख डालर का था और दूसरा १ करोड़ डालर का औद्योगिक साख व विनियोग कारपोरेशन के लिए था। भारत सरकार ने इन दोनों ऋणों के लिए जिम्मेदारी ली है क्योंकि ये व्यक्तिगत सस्थाओं द्वारा लिये गये हैं। १९५६ में ७ करोड़ ५० लाख डालर का एक ऋण १५ वर्ष की अवधि के लिए ३ प्रतिशत ब्याज की दर से टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी को प्राप्त हुआ।

सन् १९५६ में बैंक ने अपने से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग को बढ़ावा देने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की। इस की पूंजी ७ करोड़ ८० लाख डालर है जो ३१ सदस्य देशों द्वारा लगायी गयी है। इस निगम द्वारा दिये गये ऋण के लिए सरकार की जमानत की आवश्यकता नहीं है। यह आशा की जाती है कि यह निगम व्यक्तिगत पूंजी को भिन्न-भिन्न देशों के उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए प्रोत्साहन देगा। विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि ऋण की सारी मात्रा उसी काम पर व्यय की जानी चाहिए जिसके लिए बैंक ने दी है। इस नियम का कठोरता से पालन होने के कारण भारत पूरे स्वीकृत ऋणों का प्रयोग नहीं कर सका है। अप्रैल सन् १९५६ में विश्व बैंक का एक विशेषज्ञ दल भारत की प्रार्थना पर द्वितीय योजना की आवश्यकताओं व कार्यक्रमों का निरीक्षण करने आया था। इस दल ने अनुकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अत आशा है कि शीघ्र ही भारत को और ऋणों की स्वीकृति विश्व बैंक से प्राप्त हो सकेगी।

यद्यपि विश्व बैंक ने अधिकांश ऋण पाश्चात्य देशों को ही प्रदान किये हैं, फिर भी इसका कार्य सराहनीय है। भारत को इस बैंक से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो रही है। आज भी भारत में ऐसी कई योजनाएँ विचाराधीन हैं, जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी

तथा भविष्य में भारत को और सहायता इस बैंक से मिलती रहेगी ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि परिस्थितियाँ अब अनुकूल हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम—उद्योगों के विकासार्थ बड़ी मात्रा में वित्त की व्यवस्था करने के लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय सस्था १९५६ में विश्व बैंक की पूरक सस्था के रूप में बनी। इस सस्था का उद्देश्य ससार के उन सभी उद्योगों के लिए पूँजी की व्यवस्था करना है जिन का निजी क्षेत्र में निर्माण होता है और एक देश से दूसरे देश में उनके बने हुए सामान भेजे जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (कारपोरेशन) निम्न बातों में विश्व बैंक से भिन्न है—

(१) यह एक विनियोगी सस्था है। यह निजी पूँजी तथा प्रबन्ध से मिलकर उत्पादन कार्यों में केवल पूँजी का विनियोग करता है, जब कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक प्रधानतः उधार देने का काम करता है।

(२) इस सस्था का कार्य-क्षेत्र केवल अर्ध-सिकसित देशों तक ही सीमित है, जैसे अमेरिका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के देश।

(३) यह सस्था केवल छोटी तथा मध्य श्रेणी की उन औद्योगिक सस्थाओं को वित्त की सहायता देती है, जिन्हें सरकार द्वारा न संरक्षण प्राप्त हो और न कोई विशेष सुविधा मिली हो।

(४) यह सस्था निजी उद्योगपतियों से सीधा लेन-देन करती है और उनके देश की सरकार किसी प्रकार से गारन्टी देकर या प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की वर्तमान पूँजी लगभग १० करोड़ डालर है। इसके सदस्य देशों की संख्या लगभग ६० है। यह निगम निजी क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार के लिए लगभग आधी पूँजी तक ऋण देता है जिसकी अवधि ५ से १५ वर्षों तक की होती है। भारत में कुछ देशी और विदेशी मिश्रित पूँजी से बनी औद्योगिक सस्थाओं ने इस निगम से १५ लाख डालर ऋण लिया है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही अन्य उद्योगों को भी इस निगम द्वारा वित्त-सहायता प्राप्त हो सकेगी।

आयात-निर्यात बैंक—बड़ी मात्रा मे विभिन्न देशो द्वारा किये गये आयात अथवा निर्यात के भुगतान के लिए इस बैंक की स्थापना हुई है। यह सस्था अमेरिका मे १९४५ मे एक कानून द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित की गयी कि जिन देशो का आयात-निर्यात व्यापार अमेरिका से होता है उनके भुगतान की सुविधा यह बैंक कर सके। इसकी समस्त पूँजी जो लगभग १ अरब डालर है अमेरिका की सरकार द्वारा लगायी गयी है और इस बैंक को ६ अरब डालर तक का ऋण लेने का अधिकार है। अमेरिका की सरकार ने यह बैंक मुख्यतः अमेरिका के आयात-निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए स्थापित किया था, क्योंकि अर्ध-विकसित देशो मे पूँजी की कमी होने के कारण ये देश अमेरिका से माल बहुत कम मँगवा पाते थे। इस बैंक द्वारा अब अमेरिका का निर्यात व्यापार बहुत बढ़ गया और अर्ध-विकसित देशो को भी अमेरिका से आवश्यक माल मँगाने मे सुविधा मिल गयी है।

भारत को इस बैंक से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो रूपो मे सहायता प्राप्त हुई है। विकास-ऋण फण्ड से लगभग ८ करोड डालर भारत को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए प्राप्त हुआ है। अमेरिका से आये हुए गेहूँ का भुगतान इसी आयात-निर्यात बैंक द्वारा होता है। औद्योगिक विकास तथा कृषि सम्बन्धी मशीनो का आयात यहाँ इसी आयात-निर्यात बैंक द्वारा होता है। इस बैंक के द्वारा भारत का आयात-निर्यात व्यापार काफी सुगम हो गया है, क्योंकि भारत सरकार निजी उद्योगो के इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर पाती।